अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3 सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का इक्कीसवां दिवस संख्या: 7

गुरुवार,

20 फरवरी 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण

93. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु किस प्रकार का तंत्र विकसित किया गया है? क्या उक्त तंत्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है?

(2) सरकार द्वारा उक्त तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब तक कौन-कौन से कारगर कदम उठाए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए कितनी हेल्पलाइन सेवाएं संचालित हैं? उक्त हेल्पलाइन सेवाओं की सफलता दर और प्रतिक्रिया समय क्या है?

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

प्रश्न काल में माननीय सदस्य सीधे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं
अथवा माननीय मंत्री से उत्तर चाह सकते हैं

श्री अध्यक्ष: चूंकि पहली व्यवस्था के बाद प्रश्नकाल आज शुरू हो रहा है, पहले अपन ने दो-तीन बार अलग व्यवस्था दी हैं। इसमें मेरा स्पष्ट कहना यह है कि जिस सदस्य ने उत्तर पढ़ लिया है और अगर वह चाहे तो सीधा पूरक प्रश्न पूछे। जो सदस्य चाहता है कि मंत्री जी से मैं पूरा उत्तर सुनना चाहता हूं, उसमें मंत्री जी बोल लें। दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी है, पढ़ना आवश्यक भी नहीं है और यह भी नहीं है, दोनों को फ्रीडम है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप पूछोगे, यदि आपने पढ़ लिया है, तो पूरक प्रश्न पूछोगे तो अधिक प्रश्न आयेंगे। फिर भी मैं

सदस्य को अपनी ओर से पूरी छूट देता हूं कि वह चाहे तो मंत्री जी से उत्तर पढ़वा लें, चाहें तो सीधा पूरक प्रश्न पूछें। अब शुरू कीजिए।

राज्य मंत्री, गृह (श्री जवाहरसिंह बेढ़म): (1) राज्य में साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक पुलिस, साइबर क्राइम तथा पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में दोनों अधिकारी कार्यरत है। वर्तमान में राज्य में कुल 36 साइबर पुलिस थानों का गठन किया हुआ हैं। जिनमें नियमित रूप से साइबर अपराध से संबंधित प्रकरणों को दर्ज कर प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में संचालित साइबर पुलिस थानों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य में साइबर धोखाधड़ी निवारण तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब तक केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) राज्य में साइबर धोखाधड़ी और अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में वर्तमान साइबर क्राईम हेल्प लाईन 1930 में 25 कॉल - टेकर की सेवाऐं 24X7 आमजन के लिए उपलब्ध हैं। उक्त सभी 25 साइबर हेल्प लाईन रेंज मुख्यालयों पर स्थित हैं।

दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 से पूर्व प्रदेश में साइबर क्राईम हेल्प लाइन 1930 पर 7 कॉल टेकिंग लाइंस थीं, जिसकी कॉल रिसीव कर शिकायत निवारण करने की सफलता दर 33 प्रतिशत थी। वर्तमान में 1930 साइबर क्राइम हेल्प लाइन पर 25 कॉल टेकिंग लाइंस हैं, जिनकी कॉल रिसीव कर शिकायत निवारण करने की सफलता दर दिनांक 12 फरवरी, 2025 को बढकर 69 प्रतिशत हो गई है। उपरोक्त साइबर क्राइम हेल्प लाइन की संख्या अधिक करने से आम-जन हेतु कॉल रिप्लाई कर राहत प्रदान करने में बढ़ोतरी हुई है।

प्रकरण पर पुलिस प्रतिक्रिया समय परिवादी के द्वारा बताये गये समय व बैंक खातों/अकाउण्ट के पूर्ण विवरण पर निर्भर करता है। पोर्टल पर प्रतिक्रिया समय पृथक से उपलब्ध नहीं है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या राजस्थान में साइबर अपराधों में सबसे अधिक प्रभावी जिलों की पहचान की गई है? यदि हां, तो इन जिलों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं?

दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, साइबर अपराधों से निपटने के लिये क्या राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है? यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव पडा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में जितना भी साइबर अपराध होता है, उसका सबसे ज्यादा डीग, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर जिलों में

अब तक अंकित किया गया है। इसका प्रभाव राजस्थान के अन्य जिलों में भी पडा, लेकिन उसके रोकथाम के उपाय के लिये राजस्थान सरकार ने समय-समय पर साइबर थानों का गठन किया, अन्य स्टेटो से सामंजस्य स्थापित करके 27 प्रदेशों के साइबर एक्सपर्ट्स को राजस्थान में बुलाकर उनकी दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई और नये इनोवेशन करके, हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करके साइबर पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, उसके समय-समय पर प्रयास किये गये हैं। इसमें चाहे एंटी वायरस अभियान चलाया गया हो, चाहे साइबर शील्ड अभियान चलाया गया हो, उनके तहत अपराधियों की पहचान करके हमने यहां तक किया है कि साइबर के द्वारा ठगी करके लोगों ने संपत्तियां अर्जित की थीं, उनकी पहचान करके उन पर पीला पंजा चलाकर तोड़ने का काम किया, जिससे साइबर अपराधों पर रोकथाम लगी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसके खंड ब में जवाब दिया कि जो हेल्प लाइन 1930 नंबर गठित की है, जिसको 2021 में हमारी सरकार ने शुरू की थी, 2022 में हमने 1,11,823 IMEI नंबर ब्लॉक किये, 1,02,244 सिम ब्लॉक कीं। 2023 में हमने 1,05,554 IMEI ब्लॉक कीं और 1,01,854 सिम ब्लॉक कीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर क्राइम बढ़ा है या घटा है? पिछले साल 2024 में जो संख्या लाख से ऊपर थी, उसको घटा दिया है। आपने IMEI ब्लॉक की हैं मात्र 16,739 और सिम आपने ब्लॉक की हैं 46,494, यानी कि आप 15-16 परसेंट पर आ गये और साइबर क्राइम कितना बढ़ा है, इसका भी आंकड़ा आप बता दीजिए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह प्रश्न ही है, इसका जवाब दें कि क्राइम बढ़ा है या घटा है और यह आंकड़ें सही हैं या गलत है, पहला प्रश्न।

दूसरा प्रश्न, जिस प्रकार से पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, इसके लिये सरकार कोई कानून बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती है?

तीसरा मैं और पूछना चाहूंगा...

श्री अध्यक्षः दो बहुत है, उनको भी दो की ही इजाजत है, आप भी दो ही पूछो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने अभी जो भरतपुर, डीग, अलवर का नाम लिया, आप मेरे को यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपने साइबर फ्रॉड के नाम पर 50-50 लोगों को अरेस्ट किया, सिर्फ दो लोगों को मुकदमे में रखा और बाकी को 151 में दिखा कर छोड़ दिया, आप बताने का कष्ट करें कि कितने लोगों को अरेस्ट किया था और कितनों पर मुकदमे दर्ज किये?

श्री अध्यक्षः विराजिए आप। माननीय मंत्री जी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष के समय पर जो अपराध हुए थे और अपराधों पर ये अंकुश नहीं लगा पाये थे, इनके राज में

पुलिस जब साइबर अपराधियों के घर पर दबिश देने जाती थी तो पुलिस पिटती थी और सत्ता पक्ष के लोग उनका समर्थन करते थे। आज उस अपराध पर अंकुश लगा है, हां यह सही है ....(व्यवधान)....

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इस घटना की यह तारीख बताएं। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: नो, नो, हरिमोहन जी, हरिमोहन जी, और किसी को अनुमति नहीं है।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): यह जो आंकड़ा पेश किया है, यह सही है कि हमने 2024 में 46,994 सिम ब्लॉक की हैं। हमारा अपराध पर अंकुश लगाने का तंत्र प्रभावी हुआ है और प्रभावी होने के साथ उन लोगों को वह काम छोड़ने को मजबूर होना पडा है। यह बात भी सही है कि वह अपराध दूसरे जिलों में ज्यादा फैला है, उस पर प्रभावी तरीके से कार्यवाही करने के लिये हमारा साइबर क्राइम का तंत्र पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं कि गांव में पुलिस दबिश दे, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिये आये और वहां पुलिस पिटे और इनके कांग्रेस के नेता उनको बचाने के लिये जाएं, ऐसा अब नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गुरवीर सिंह। हो गया, तीन प्रश्न पूछ लिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पोलिटिकल भाषण नहीं चाहिये, मेरे प्रश्न का जवाब तो दें।

श्री अध्यक्ष: आ गया, आ गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक भी जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: आ गया, आ गया। नहीं आया तो आप अलग नियम में आ जाइए। उत्तर के लिये मैं यह तो कह नहीं सकता कि यही दो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ....(व्यवधान).... यह जवाब तक नहीं दे सकते। वहीं भरतपुर से आते हैं। ....(व्यवधान)....

भांकरोटा अग्निकांड की जांच हेतु गठित कमेटी

94. श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा भांकरोटा अग्निकांड की जांच हेतु कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (डॉ. मंजू बाघमार): (1) जी हां। सरकार की ओर से भांकरोटा अग्निकांड घटना की विस्तृत जांच हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा दिनांक 20.12.2024 को संयुक्त जांच दल का गठन किया किया गया था (संलग्न परिशिष्ट-1)। इस संयुक्त जांच दल द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20.01.2025 को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को प्रेषित कर दी गई, तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति संलग्न परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) सड़क दुर्घटना कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास एवं नवाचारों का विवरण परिशिष्ट-3 एवं 4 पर संलग्न है।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ गया है, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछो।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, भांकरोटा अग्निकांड को लेकर मेरा प्रश्न है, जो अग्निकांड वहां हुआ, उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो पूरे देश ने देखा। वहां 20 लोगों की जान गईं, जल कर मर गये, 42 साधनों का नुकसान हुआ। पूरे देश ने वह मंजर देखा और जो संभावित कारण जवाब में दिये गये हैं, उसके पेज नंबर 3 पैरा 4 सब पैरा 1 में लिखा है कि यू टर्न सावधानी पूर्वक नहीं लिया गया।

Bhs/Rtm/20.02.25/11.10/1b

उसी के साथ जो जवाब दिया गया है पेज नं. 4 पैरा 4 सब पैरा 7 में, दोनों वाहन चालकों के लापरवाही से वाहन चलाने से एक्सीडेंट हुआ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि इसमें जो कट है नेशनल हाईवे पूरे राजस्थान का जो सबसे व्यस्त सबसे बिजी रहने वाला हाईवे है उसके ऊपर आपने ब्लेक स्पोट्स छोड़ दिये। इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां कोई स्पीड ब्रेकर नहीं हैं, वहां यू-टर्न के लिए कोई मार्केशन नहीं है। मेरा निवेदन है कि सारी की सारी जिम्मेदारी सारी की सारी लापरवाही सिर्फ ड्राइवर्स पर छोड़ दी गई, किसी सम्बन्धित अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये। भाषण नहीं।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): मैं मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूंगा कि इस पर सारे अधिकारियों को क्लीन चिट किस वजह से दे दी गई?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी जो यह भांकरोटा का कांड हुआ था उसमें प्रमुख कारण तो ड्राइवर्स की लापरवाही रही थी, लेकिन फिर भी यदि हम अन्य कोई सेफ गाड्र्स लगाते तो निश्चित रूप से इस दुर्घटना को टाला जा सकता था, इस दुर्घटना की जो सम्भावना थी उसको हम टाल सकते थे, उसमें ट्रेफिक साइलेंस लगा होता, टी.बी.एम. रोड मार्किंग लगी होती, हाईवे स्ट्रीट लाइट्स लगी होती तो शायद इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। अनधिकृत कट जो थे, यदि हम इस रोड की बात करें तो इसके ऊपर करीब 33 अनधिकृत कट लगे हुए थे, जो कई सालों से लगे हुए थे और उसमें अभी हमने उन कट्स को करीब 32 कट्स को बन्द कर दिया है और केवल एक कट जो रहा है दूदू से आगे उसको बन्द करवाया जाना शेष

है और राज्य सरकार इसके बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा जो कार्यवाही की गई है दोषी अधिकारियों के ऊपर, जो एक एन.एच.ए.आई. के आर.ओ. अधिकारी थे उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया और सरकार इसको लेकर बहुत गम्भीर है और सरकार यह चाहती है कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न और पूछ सकते हो।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): एक पूरक प्रश्न और पूछ लेता हूं। ट्रांसफर से पूर्ति हो जायेगी क्या? उसके लिए जब तक सबक नहीं सिखाओगे तो और कोई नुकसान होगा। कोई भी सरकार आये, इतनी बड़ी घटना हो गई, आगे से ऐसा न हो, जब तक आप ऐसा उदाहरण सेट नहीं करोगे, कोई बात सुनने वाला नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि यह जो हाइली इन्फलेमेबल प्रोडक्ट्स को लेकर के साधन चलते हैं इनकी स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर क्या गाइड लाइन है और सरकार को इनकी मॉनिटरिंग के लिए क्या इनके पास कोई डेश बोर्ड है? आज जी.पी.एस. टैक्नॉलोजी के साथ पूरे ट्रकों का जो सिस्टम है उसकी स्पीड मॉनिटर कर सकते हो, उसकी लोकेशन मॉनिटर कर सकते हो, तो सरकार ने क्या कोई ऐसी रणनीति कोई तैयारी या कोई ऐसा किया है, प्लेटफोर्म आपके पास है जिससे आगे इन घटनाओं को रोका जा सके?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ज्वलन पदार्थ को जो परिवहन करते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन वाले उनके लिए ऐसी कोई समयावधि तो निर्धारित नहीं की गई है लेकिन भविष्य में इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट करने वाले जो परिवहन वाहन हैं उनको सुरक्षित बनाने के लिए, उनकी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा रूल्स बनाये जाते हैं, तो मोर्थ के द्वारा भी इसमें नोर्म्स को रिव्यू किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने जैसा कि पिछली बार हम केवल एक सप्ताह मनाते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह एक सप्ताह मनाते हैं, एक पखवाड़ा मनाते हैं लेकिन इस बार 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरे महीने का सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया और सरकार उसके लिए सड़क सुरक्षाओं को लेकर पूरी तरह से संकल्पित है। आगामी दस वर्षों की भी इसमें कार्य योजना बनाई गई है कि वर्ष 2030 तक पचास प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में कमी आये और 2033 तक 75 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में कमी आये इसके लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट का प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। सुरक्षा ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया। आईरेड से भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनका इन्द्राज करना सुनिश्चित किया जा रहा है। आई.टी.एस. प्रणाली को लागू किया जाता है। वेब पोर्टल लांच कर दिया गया है। माई भारत पोर्टल को भी अपलोड करना सुनिश्चित किया है। ब्लेक स्पोट्स के सुधारीकरण और निगरानी का भी कार्य किया जा रहा है, तो हमारी सरकार ने आगामी वर्षों के लिए इस प्रकार की कोई दुर्घटनाएं न हों, दुर्घटनाओं को लेकर बहुत

संवदेनशील है और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं रेगुलर बढ़ रही हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से हमें इसमें कमी दिखायी देगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हर प्रश्न पर नहीं। हर प्रश्न पर अधिकार नहीं है। कोई इम्पोर्टेंट हो, रह गया हो। अभी तो पहला ही हुआ है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इम्पोर्टेंट ही है। पचास लोग मर गये हैं दुर्घटना में जल कर और एक को भी दोषी नहीं माना इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा। एक व्यक्ति को भी दोषी नहीं माना गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलवाओ कि जो कमेटी आपने बनाई उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी और अवैध कट कितने दिन में बन्द करने के निर्देश दिये थे और कितने दिन बाद वह बन्द किये हैं?

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि पूरे राजस्थान में अवैध कट्स की बात की जाए...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसी की प्रोपर।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): तो इसकी तो जैसे ही हमारे पास जांच रिपोर्ट आई थी, 33 कट थे इसी रोड के ऊपर उनमें से हमने 32 बन्द कर दिये हैं, केवल एक कट बाकी रहा है और इसमें जो डी.पी.एस. के पास कट था उसमें भी वैकल्पिक मार्ग निकाल दिया है नरसिंगपुरा फ्लाईओवर से।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कितने दिन में कट बन्द करने की कही थी और कितने दिन बाद वो कट बन्द हुए हैं? इतना ही पूछ रहा हूं बस।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच कमेटी तुरन्त बना दी गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक महीने में दी थी और तुरन्त ही इसके ऊपर कार्यवाही करके जो 33 कट थे...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो महीने तक कट बन्द नहीं हुए हैं और एक कट तो आज तक भी बन्द नहीं हुआ है। यह तो मॉनिटरिंग है सरकार की।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा।

केशोरायपाटन के चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन

95. श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) प्रदेश में चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के क्या नियम व मानदण्ड निर्धारित

हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के उप स्वास्थ्य केन्द्र लबान, पीपल्या, जेतपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाडाखेडा, झालीजी का बराना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) प्रदेश में चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के नियम व मापदण्ड परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) ग्राम लबान पंचायत समिति केशोरायपाटन एवं ग्राम पीपल्या एवं जैतपुर पंचायत समिति नैनवा जिला बूंदी के अन्तर्गत आते है। उक्त ग्रामों में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रो में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति केशोरायपाटन में 7 प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति केशोरायपाटन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र लबान को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति नैनवा में 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विरुद्ध 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध हैं।

चालू/आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्र पीपल्या/ जैतपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

ग्राम बडाखेडा एवं झालीजी का बराना पंचायत समिति केशोरायपाटन जिला बूंदी के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति केशोरायपाटन में 2 सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरूद्ध 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। इस प्रकार पंचायत समिति केशोरायपाटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडाखेडा एवं झालीजी का बराना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे

पास आ गया है।

श्री अध्यक्षः ठीक है। माननीय मंत्री जी, ये कह रहे हैं कि जवाब आ गया है। पूरक प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 12 साल से समिधि और बलकासा में पी.एच.सी. स्वीकृत हुई थी लेकिन आज तक अभी तक 12 साल के बाद वहां बिल्डिंग नहीं बनी और न पैसा आया है तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इतना लम्बा पीरियड कैसे हो गया? भवन क्यों नहीं बना? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी। पहले उत्तर सुन लीजिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने परिशिष्ट अ पर माननीय सदस्य को एन.एच.एम. के जितने भी रूल्स हैं उनके बारे में अवगत करा दिया है। आपके जो नोर्मल एरिया में सब सेन्टर 5000 की आबादी पर बनते हैं और हिली एरियाज और डेजर्ट व ट्राइबल के अन्दर 3000 की आबादी पर होते हैं। पी.एच.सी. 30 हजार की आबादी पर होती है नोर्मल में और यह जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें 20 हजार पर होती है।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): मैंने तो भवन की बात की है। यह भवन क्यों नहीं बना?

श्री अध्यक्षः आप उत्तर सुन लीजिये। माननीय सदस्य, उत्तर सुनने के बाद दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये, उसकी आपको अनुमति देंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने जो प्रश्न पूछा है, आपने कहा कि लबान और पीपल्या और जेतपुर को आप अपग्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरा आपने पूछा है कि जो पी.एच.सी. बाड़ाखेड़ा और झालीजी का बराना को आप सी.एच.सी. बनायेंगे क्या? यह आपने दोनों प्रश्न भाग 2 में पूछे हैं। नियमानुसार केशोरायपाटन की जो पंचायत समिति है उसमें 7 होनी चाहिये और आपके पी.एच.सी. 8 हैं परन्तु नैनवा पंचायत समिति में गुंजाइश है कि पीपल्या या जेतपुर में एक अपग्रेड हो सकती है, इसकी हम शीघ्र ही केन्द्र से स्वीकृति लेकर आपके लिए इसको अपग्रेड कर देंगे।

श्री अध्यक्षः दूसरा प्रश्न पूछो।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लाखेरी, केशोरायपाटन, इन्द्रगढ़ और करवर ये चार सी.एच.सी. हैं लेकिन डॉक्टर्स की बहुत कमी है। केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पद हैं 9 लेकिन 5 ही हैं 4 की कमी है और महिला डॉक्टर नहीं हैं। लाखेरी में 11 पदों की स्वीकृति है लेकिन 3 ही डॉक्टर हैं 8 डॉक्टर्स की कमी है और महिला डॉक्टर नहीं हैं। ऐसे ही इन्द्रगढ़ में 6 डॉक्टर्स की पोस्ट है लेकिन 4 है वहां 2 डॉक्टर कम हैं तो वहां जो -जो भी पी.एच.सी. या पूरे बून्दी डिस्ट्रिक्ट में यही स्थिति है डॉक्टर्स की बहुत कमी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी ही रिक्रूटमेंट करके और डॉक्टर्स की पोस्टिंग करके और जहां मैं कह रहा हूं वहां महिला डॉक्टर्स

की पोस्टिंग की जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहली बार चिकित्सा विभाग में लगभग पचास हजार गजेटेड और नॉन-गजेटेड ऑफिसर्स को हायर किया जा रहा है जिसमें से 23 हजार आ चुके हैं जिसमें आपके ए.एन.एम., नर्सिंग ऑफिसर्स, लैब टेक्निशियंस, असिस्टेंट रेडियोग्राफर्स और मैं इस सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि हमने लगभग 85 प्रतिशत जो एफ.आर.यूज हैं हमने उनको भर दिया है। एफ.आर.यू. तभी चलता है जब वहां पर बच्चों का डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट और 3 डॉक्टर ऑर्थोपीडिक, एनेस्थेटिस्ट, बच्चों का डॉक्टर जब होते हैं तब वह एफ.आर.यू. चलता है, सब बन्द पड़े हुए थे। ट्रोमा सेन्टर्स को भी हमने चालू कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि मई जून तक जब हमारी भर्तियां हो जायेंगी, आप लोगों के गजटेड और नॉन-गजेटेड पद हैं लगभग 75 प्रतिशत आपके सबके भर दिये जायेंगे।

Msk/rtm/20.02.25/1120/1c

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री विनोद कुमार।

पीलीबंगा मुख्यालय पर सत्र न्यायालय की स्थापना

96. श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपों करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के पीलीबंगा मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नवीन न्यायालय खोलने हेतु कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): (1) वर्तमान में पीलीबंगा में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना का मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है।

भविष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पीलीबंगा क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

(2) जी हां। नवीन न्यायालयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा लंबित प्रकरणों का मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

1. जिला/अपर जिला न्यायालय- 1000-1200 लंबित प्रकरण।

2.वरिष्ठ न्यायाधीश एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय- 1200-1500 लंबित प्रकरण।

3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय- 1700-2000 लंबित प्रकरण।

निर्धारित मानदण्ड के अनुसार लंबित प्रकरण होने के साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी की अनुशंसा व वित्तीय संसाधन की उपलब्धता भी आवश्यक है

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है। मैं पूरक प्रश्न करना चाहूंगा।

माननीय उच्च न्यायालय के मापदण्ड के अनुसार एडीजे कोर्ट के लिए 750 केसों का मापदण्ड है और राजस्थान सरकार कह रही है कि 1000-1200 का आंकड़ा होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसमें राजस्थान सरकार और माननीय उच्च न्यायालय का जो डिफरेंस है, उसको स्पष्ट करें कि क्या मापदण्ड है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य का यह फरमाना सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी मापदण्ड निर्धारित है और राजस्थान सरकार द्वारा भी मापदण्ड निर्धारित है। इन मापदण्डों में करीब 1000-1200 प्रकरण सिविल के और इतने ही क्रीमिनल के प्रकरण होते हैं तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर खोलने पर विचार किया जा सकता है। ये मापदण्ड पुराने समय से निर्धारित किये हुए हैं। आवश्यकता अब महसूस भी की जा रही है कि मापदण्डों में सुधार किया जाये और थोड़ा ठीक किया जाये, लेकिन इसमें भी विचार हो रहा है। आपके क्षेत्र में चूंकि मामला हाइकोर्ट की कमेटी के पास में लंबित था, हाइकोर्ट की कमेटी ने उस पर रिकमंडेशन दिया और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए आपने अपनी जो मांग रखी है, अपनी जनता की मांग रखी है, उस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): मंत्री महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा अगर 'यस' किया जाता है तो क्या आप खोलने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा रिकमंड करने उपरान्त राजस्थान सरकार के मापदण्ड, राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन, इन पर समग्र विचार करने के बाद खोलने पर निर्णय लिया जाता है, धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामकेश।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप कह रहे हैं कि पांच साल में नहीं खोले, आपने खोल दिये क्या? एक भी नहीं खोला।

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं बोलें, उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

गंगापुर में उज्ज्वला योजना के तहत जारी कनेक्शन

97. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में उज्ज्वला योजना लागू है? यदि हां, तो विगत छह माह में कितने कनेक्शन जारी किये गये? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में विगत एक वर्ष में उक्त योजना के तहत कितने कनेक्शन जारी किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना की क्या-क्या शर्तें निर्धारित हैं तथा लाभार्थी को प्रतिमाह कितने गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) जी हां। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना प्रदेश में भी लागू है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले कनेक्शनों का लक्ष्य पूरा होने के कारण नए उज्ज्वला कनेक्शन जारी करना स्थगित है। इसलिए विगत छह माह में उज्ज्वला गैस कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं।

(2) विगत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत कुल 1668 गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं।

(3) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना भारत सरकार की योजना है। वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के कनेक्शन ऐसी गरीब महिलाएं जो उज्जवला कनेक्शन की पात्रता को पूरी करती हैं, को ही दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में जारी पात्रता एवं मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत, उज्ज्वला कनेक्शनधारक को रिफिल के लिए हर साल 12 सब्सिडी वाले गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये जाते हैं।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माननीय मंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने उज्जवला योजना में पात्रता की जो शर्त बतायी है, उस शर्त में आपने 14 बिन्दु लिखे हैं। 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार इसमें जो भी पात्र लोग हैं उनको आप उज्जवला में गैस सिलेण्डर देंगे। मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया। इसमें एसटी, एससी, एमबीसी, प्रधानमंत्री आवास, अंत्योदय, एसईसीसी और इसमें इन सारे के सारों को लिया जाए तो राजस्थान की करीब 5 करोड़ जनसंख्या इसमें कवर हो जाती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): मैं आपसे पहला सवाल तो यह करना चाहता हूं कि 5 करोड़ में से आपने उज्ज्वला के कितने कनेक्शन दिये हैं?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने गंगापुर विधान सभा क्षेत्र का लगाया, गंगापुर विधान सभा का आपने बताया कि 1668 कनेक्शन दिये हैं, जबकि इसकी पात्रता को अगर देखते हैं तो करीब पौने 2 लाख जनसंख्या इसकी पात्रता में आती है। पौने 2 लाख में से आपने केवल 1668 कनेक्शन दिये हैं। बाकी के कनेक्शन कब तक दे देंगे? सरकार का क्या विचार है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय उप नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने पांच करोड़ का रखा। पात्रता यह नहीं है। राजस्थान में अभी कुल 1 करोड़ 83 लाख कन्ज्यूमर को कनेक्शन दिया जा चुका है, सबके पास। जिसमें से उज्जवला योजना में 73 लाख 82 हजार कनेक्शन दिये गये। यह योजना जब 1 मई, 2016 में लायी गयी थी तब इसका टारगेट 5 करोड़ का था, उसके बाद लक्ष्य बढ़ाते हुए, अभी उज्जवला योजना में पूरे भारत में 10 करोड़ 33 लाख के कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इसका लक्ष्य पूरा हो चुका है और राजस्थान में 73 लाख 82 हजार कनेक्शन हैं।

आपका दूसरा प्रश्न गंगापुर सिटी के लिए है। गंगापुर सिटी जो पुराना जिला था, अब नहीं है, उसमें 74 हजार कनेक्शन थे। आपके अभी उज्जवला योजना में लंबित कनेक्शन साढ़े पांच सौ हैं, जिन्होंने आवेदन किये हुए हैं। इसमें एचपीसीएल में 130, बीपीसीएल में 92, आईओसीएल में 328, कुल 550 कनेक्शन लंबित हैं। हम सबको यह बात माननी पड़ेगी कि ऐसी योजना भारत में आयी, जिसने 2016 के बाद पिछले आठ साल में ही लगभग 10 करोड़ 33 कनेक्शन दिये। यह पूरे भारत में बदलाव लायी। यह एक ऐसी योजना, जो भारत में असंभव थी। ...(व्यवधान)... मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं। कितनी खुशी की बात है। अध्यक्ष जी, इस योजना से, हम जिस रेगिस्तानी क्षेत्र से आते हैं, माताएं-बहनें कितनी परेशान होती थीं, एक समय था जब विपक्ष वाले ही मजाक बनाते थे कि गांवों में कैसे गैस कनेक्शन जायेंगे? इन्होंने गांव की महिलाओं को कम आंका था और माताओं और बहनों ने ऐसी योजना को जोरदार सफल बनाया कि उप नेता प्रतिपक्ष यह प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 में गैस का सिलेण्डर 410 रुपये में मिलता था। इस 410 रुपये के सिलेण्डर को सरकार ने 810 रुपये का कर दिया, दुगना।

श्री अध्यक्षः यह प्रश्न में नहीं है, आपने केवल गैस कनेक्शन का पूछा है।

श्री रामकेश (गंगापुर): दुगने में भी, आपने इसमें पात्रता के जो 14 बिन्दु बनाये हैं, इन 14 बिन्दु में राजस्थान की करीब 5 करोड़ जनसंख्या कवर होती है। क्या आप इसमें कनेक्शन देने की स्थिति में हो? आप आज इसमें कनेक्शन देंगे? यह पहला प्रश्न है।

दूसरा बताइये, गंगापुर में मात्र 1668 कनेक्शन, बाकी के लोगों को आप कनेक्शन कब देंगे? दूसरी बात यह है।

श्री अध्यक्षः विराजिये, हो गया, एक ही प्रश्न पूछें।

श्री रामकेश (गंगापुर): आप इसका ही जवाब दीजिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उप नेता जी ने कहा कि 410 में सिलेण्डर मिलता था। आपने उज्जवला का प्रश्न पूछा है तो उज्जवला लाभार्थियों को आज भी...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः केवल उज्जवला की चर्चा होगी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप उत्तर सुनिये। माननीय जी

आप सम्माननीय है। आप कह रहे थे कि आज से 15 साल पहले 410 में सिलेण्डर मिलता था। उज्जवला के जो 73 लाख 82 हजार लाभार्थी हैं, उन्हें आज भी भजन लाल जी शर्मा की सरकार में 450 में मिल रहा है, 15 साल बाद भी। आपने गंगापुर सिटी का पूछा, गंगापुर सिटी के 74 हजार कनेक्शन हैं। आप राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी बता रहे हैं, तो मैंने आपको इसीलिए आंकड़ा बताया कि 1 करोड़ 83 लाख 68 हजार कनेक्शन राजस्थान में टोटल हैं, जिसमें से उज्जवला योजना में 73 लाख 82 हजार हैं, ज्यादातर का कवरेज हो रहा है। आप विश्वास कीजिये, मोदी जी और भी उज्जवला में लेकर आयेंगे, किसी को बाकी नहीं रहने देंगे।...(व्यवधान)...

श्री रामकेश (गंगापुर): क्या आपने सब्सिडी दे, कितने लोगों को सब्सिडी दे दी। आप बताइये कितनी सब्सिडी बाकी है?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी नहीं आयी, वही तो पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब अगला प्रश्न हो गया, माननीय मंत्री जी।...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो फॉर्मेलिटी हो रही है। यहां लगने के बाद भी, साहब, नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। सरकार की तरफ से कोई जवाब सुनने के लिए थोड़े ही बैठे हैं। कोई क्वेश्चन माननीय सदस्य ने लगाया, जवाब तो आये।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक भी जवाब नहीं आया, यह बता दें कि आज की तारीख में कितने कनेक्शन देने की स्थिति में है और कितनी सब्सिडी पैंडिंग है?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया है। आप नियमों में आइये, उत्तर ठीक नहीं है। नियम में आइये, आपकी चर्चा करवाऊंगा। यदि किसी को उत्तर से संतुष्टि नहीं है, अलग नियम बने हुए हैं। आप नियमों में आइये, मैं चर्चा करवाऊंगा।

कपासन के शनि महाराज धार्मिक स्थल हेतु स्वीकृत कार्य

98. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के विकास एवं संरक्षण के लिए कोई नीति बनायी गयी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में शनि महाराज का धार्मिक स्थल है? यदि हां, तो सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में उक्त स्थल के विकास हेतु कौन-कौनसे कार्य, कितनी-कितनी राशि के करवाये गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी हां। नीति की प्रति परिशिष्ट -1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। यह मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित एवं प्रबंधित नहीं होकर एक अराजकीय मंदिर है, जो कि विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम आली तहसील चित्तौड़गढ़ में

स्थित है। विगत पांच वर्षों में इस मंदिर में सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया जाकर कोई राशि भी व्यय नहीं की गई है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछली भाजपा सरकार के समय शनि महाराज मन्दिर के विकास के लिए डीपीआर बनाने की स्वीकृति हुई और डीपीआर बनी? यदि डीपीआर बनी तो फिर मन्दिर के विकास के लिए कार्य क्यों नहीं किये गये?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में जानकारी देना चाहूंगा कि तत्कालीन वसुन्धरा राजे जी की सरकार ने कपासन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आली, तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित शनि महाराज मन्दिर, जो कि एक अराजकीय मन्दिर है, इस मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों हेतु वर्ष 2018-19 में बजट घोषणा बिन्दु संख्या 193 के तहत घोषणा की थी। जिसकी पालना में डीपीआर बनायी गयी थी, डीपीआर की अनुमानित लागत 76.93 लाख थी एवं डीपीआर बनाने पर 93 हजार रुपये का व्यय हुआ, लेकिन बाद में सरकार बदल गयी और इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिससे मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं विकास हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि डीपीआर की विभागीय स्तर पर परीक्षण कराकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

mdp/rtm/20.02.2025/11:30/1d

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: दो हो गये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): नहीं, एक ही हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार शनिदेव मन्दिर, आली को अधिग्रहण करके देवस्थान विभाग में लेकर विकास करवाने की मंशा रखती है?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमारे देवस्थान विभाग के 593 मन्दिर हैं, जिसमें 552 मन्दिर राजस्थान में स्थित हैं और 41 मन्दिर राजस्थान से बाहर दूसरे प्रदेशों में स्थित हैं। ये जो देवस्थान विभाग को मिले हुए मन्दिर हैं, राजा-महाराजाओं के समय से जो मन्दिर थे, उनको देवस्थान विभाग को सुपुर्द किया था। नये मन्दिर देवस्थान में लेने का कोई प्रावधान नहीं है और नया मन्दिर अभी तक कोई लिया भी नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि शनि महाराज का जो मन्दिर है आपके क्षेत्र में, उसके विकास के लिए दूसरी तरह से आपकी मदद करेंगे, लेकिन देवस्थान विभाग में नहीं लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हंसराज मीना।

करौली में वन संरक्षण कार्यों पर व्यय

99. श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये नेवा सिस्टम में प्रश्न संख्या 99 है। नेवा सिस्टम में जो आंसर दिया है, वह गंगानगर, हनुमानगढ़ का आंसर दे रखा है। आप इस ओर ध्यान आकर्षित करवाएं। करौली का है, लेकिन आंसर इसमें हनुमानगढ़, गंगानगर का आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: इसमें केवल करौली लिखा है। प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): प्रश्न संख्या 99 करौली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर जब मैं इसमें पढ़ता हूं तो गंगानगर, हनुमानगढ़ का आता है। आप ओपन करके देखेंगे तो आपके सामने शो होगा।

क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जिला करौली में विगत तीन वर्षो में वन संरक्षण से संबंधित क्या-क्या कार्य करवाये गये तथा उक्त पर कितनी- कितनी राशि व्यय की गई है? करवाये गये कार्यों की व्यय राशि का वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जिले में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में वन सुरक्षा समिति एवं ईको डवलपमेट कमेटी क्रियाशील हैं? उक्त कमेटी के उद्देश्य, दायित्व एवं कर्तव्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला करौली में विगत तीन वर्षों में उक्त समितियों द्वारा कितनी कितनी राशि व्यय कर कौन-कौनसे कार्य करवाये गएं? कार्यवार व्यय राशि का वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, वन:(श्री संजय शर्मा): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जिला करौली में विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा वन संरक्षण से संबंधित कराये गये कार्यों एवं उन पर व्यय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) करौली जिले में क्रियाशील ग्राम वन सुरक्षा समिति एवं ईको डवलपमेट कमेटी का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है एवं उनके उद्देश्य, दायित्व एवं कर्तव्यों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जिला करौली में विगत तीन वर्षों में उक्त समितियों द्वारा किये गये कार्य एवं व्यय राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में समाहित है।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: जब अगला संतुष्ट है तो कोई बात नहीं है। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में।

श्री अध्यक्ष: अगला संतुष्ट है तो नहीं बनता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में आपने कमेटियों के लिए

बोला है, ..(व्यवधान).... आपकी कमेटियों के पिछले एक साल में चुनाव हुए हैं, वह आप सदन को बता दीजिए।

श्री अध्यक्षः माननीय, विपक्ष के नेता। ..(व्यवधान).... माननीय, अंकित नहीं हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्षः माननीय विपक्ष के नेता, जब सामने वाला सदस्य ही, जिनका प्रश्न है, वह संतुष्ट है तो इस पर कुछ नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता संतुष्ट है ..(व्यवधान).... अगला प्रश्न पुकार लिया, फिर नेता, प्रतिपक्ष कैसे बोल सकते हैं?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न पुकार लिया। विराजिए। अगले ने बंद कर दिया, विषय खतम।

अजमेर में नवजीवन योजना के अंतर्गत व्यय

100. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शराब से प्राप्त आय का एक प्रतिशत हिस्सा अवैध शराब के कारोबार में लिप्त परिवारों पर व्यय किया जाता था? यदि हां, तो सरकार को विगत पांच वर्षों में शराब से कितनी आय हुई तथा नवजीवन योजना के माध्यम से कितना व्यय किया गया? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अजमेर में विगत पांच वर्षों में शराब से कितनी आय हुई? उक्त आय से नवजीवन योजना के माध्यम कितनी राशि व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी नहीं। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि में कुल आबकारी राजस्व राशि रु. 57,802.78 करोड़ प्राप्त हुआ तथा नवजीवन योजना के माध्यम से व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) विगत पांच वर्षों में (वर्ष 2019-20 से 2023-24) अजमेर जिले में कुल राशि रु. 2898.45 करोड आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ तथा नवजीवन योजना के अन्तर्गत कुल राशि रु. 330.52 लाख का व्यय किया गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या यह योजना वर्तमान में भी संचालित हो रही है और यदि संचालित हो रही है तो पिछले दो वर्षों में इस योजना में कितनी धनराशि व्यय हुई? पहला प्रश्न, दूसरा मैं बाद में पूंछ लूंगी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, नवजीवन योजना जो थी, वह आबकारी विभाग के माध्यम से चालू की गयी थी 31 अगस्त, 2009 में।

इसके बाद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 2011-12 के अन्दर दे दी गयी थी। नवजीवन योजना अभी-भी चालू है। ये उन लोगों के लिए चालू की गयी है जो अवैध शराब का निर्माण करते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं और उसके विक्रय में लिप्त होते हैं, ताकि इन लोगों को एक वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाए और समाज की मुख्य धारा के अन्दर जोड़ा जाए। इस तरह से ये योजना अभी-भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चालू है।

जहां तक अजमेर जिले के लिए माननीय सदस्य ने पूछा है, अजमेर जिले में 2019-20 से 2023-24 तक 3.30 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। 2024-25 में राज्य के बजट के अन्दर जो प्रोवीजन रखा गया था, वह 6.83 करोड़ का दिया था और राज्य में 4.34 करोड़ रुपये खर्च हुए और अजमेर में 19.66 लाख रुपये खर्च हुए।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मंत्री महोदय ने पहले ही जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण जी।

आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिये जा रहे पोषाहार की जांच

101. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कुपोषित बच्चों का जिलेवार, वर्षवार, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? सरकार वृद्धि की रोकथाम हेतु क्या प्रयास कर रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुपोषण दूर करने के लिए दिया जा रहा पोषाहार गुणवत्ता की दृष्टि से ठीक नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार पोषाहार की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (डॉ. मंजू बाघमार): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) प्रदेश में गत 5 वर्षों में कुपोषित बच्चों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उविभाग द्वारा कुपोषण को दूर करने हेतु किये जा रहे समेकित प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में निरंतर कमी हो रही है, जैसा कि बिन्दु संख्या 1 पर संलग्न परिशिष्ट-अ में प्रदर्शित है।

(3) प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से पूरक पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है। पूरक पोषाहार की रेसिपियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय एवं पोषणीय मापदण्डों के अनुसार तय की गई है। विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा

पूरक पोषाहार माईक्रोन्यूट्रियन्ट फोर्टिफाईड एवं गुणवत्तापूर्ण है। पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयोगशाला जांच उपरान्त ही आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूनों की प्रयोगशाला जांच निम्नानुसार पांच स्तरों पर की जाती है-

1.पोषाहार उत्पादन स्थल पर स्थित इन हाउस लैब में।

2.पोषाहार उत्पादनकर्ता द्वारा एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच ।

3.विभागीय अधिकारियों द्वारा उत्पादन स्थल से नमूने एकत्रित कर एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच।

4.कॉनफेड द्वारा स्वयं के स्तर से उत्पादन स्थल से नमूने एकत्रित कर एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच।

5.आंगनबाडी केन्द्रों पर आपूर्ति के उपरान्त विभागीय अधिकारियों द्वारा रेण्डमली नमूने एकत्रित कर एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच ।

उक्त प्रयोगशाला जांचें पृथक्-पृथक् एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराई जा रही है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सही गुणवत्ता का ही पोषाहार स्वीकार करने के निर्देश दिये गये हैं। आपूर्ति के दौरान यदि गुणवत्ता में कमी देखी जाती है तो तुरन्त सामग्री बदलवा कर ही प्राप्त की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि प्रश्न के उत्तर में आप द्वारा विभिन्न स्तरों पर लेब से जांच के सन्दर्भ में जानकारी दी गयी है, क्या सेम्पल सब-स्टेण्डर्ड पाये गये और यदि पाये गये तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जैसा कि मैंने बताया कि पांच स्तर पर इसमें लेबोरेट्री चैक की जाती है। यदि पोषाहार अमानक पाये जाते हैं तो उस पर जरूर कार्यवाही की जाती है। यदि उसकी जांच कर ली जाती है और अमानक पाये जाते हैं, यदि उसे यूज में नहीं लिया गया है तो जो पूरा बैच है, उसकी कोस्ट का हम पांच परसेंट पेनल्टी लगाते हैं। यदि वह यूज में नहीं लिया जाता है तो पूरा ही उसको रिप्लेस किया जाता है।

साथ ही, जैसा अभी माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या इस प्रकार की कोई जांच की गयी है तो मैं आपको बता दूं कि दिसम्बर, 2023 में जयपुर जिले में और जनवरी, 2024 में भरतपुर जिले के अन्दर कुछ नमूने लेकर हमारी राजकीय प्रयोगशालाओं में हमने जांच करवायी थी और कुछ 9 नमूने अमानक पाये गये। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए 44 लाख 72 हजार रुपये की पेनल्टी भी आपूर्तिकर्ता पर लगायी गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न। हो गया। अगला प्रश्न। श्री शान्ती धारीवाल।

कोटा में कोचिंग छात्रों की काउंसलिंग हेतु साइकोलोजिस्ट की नियुक्ति

102. श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा में विगत एक वर्ष में कोचिंग कर रहे कितने छात्रों द्वारा आत्महत्या की गई?

(2) क्या यह सही है कि छात्रों की काउंसलिंग के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोटा द्वारा पांच साइक्लोजिस्ट की नियुक्ति का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था? यदि हां, तो वर्तमान में डेडिकेटेड साइक्लोजिस्ट काउंसलिंग एण्ड ट्रीटमेंट सेंटर में कितने साइक्लोजिस्ट कार्यरत हैं तथा कितने छात्रों का उपचार किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) विगत एक वर्ष में कोटा में कोचिंग प्राप्त कर रहे कुल 19 छात्रों ने आत्महत्या की है।

(2) जी हां। विभागीय स्वीकृति दिनांक 06.07.2023 द्वारा साइक्लोजिकल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना कर तीन पद क्लीनिकल साइक्लोजिस्ट एवं 6 पद काउन्सलर के सृजित करने की स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में नवीन चिकित्सालय कोटा में स्थित सॉइकोलोजिकल काउन्सलिंग सेन्टर में 01 साइक्लोजिस्ट एवं 4 काउन्सलर संविदा पर कार्यरत है। साइक्लोजिकल काउन्सलिंग सेन्टर में काउन्सलिंग का कार्य साइक्लोजिस्ट विभाग में पदस्थापित फैकल्टी, रेजीडेंट चिकित्सकों एवं क्लिनिकल साइक्लोजिस्ट द्वारा संपादित किया जा रहा है। वर्ष 2024 में उक्त सेन्टर में कुल 462 छात्रों की काउंसलिंग/उपचार किया गया है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी का जवाब मिल गया।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): उस प्रश्न को मैं दोबारा से, फिर भी कुछ पोर्शन को पढ़ना चाहता हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया 10/07/24 का है।

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछिए। अख़बार का नहीं, प्रश्न पूछिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपका इसमें स्टेटमेंट है।

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया है, मंत्री जी।

Ans/rtm 11.40 1e 20.02.2025

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप मेरी बात सुनिये। नियमों की जानकारी ले लो, उसके बाद एतराज किया करो। आपका स्टेटमेंट है कि, "when Contractor in the State, the Health Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat..."

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछिये। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये। अख़बार का वाचन नहीं करना है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पूछ रहा हूं ना। वही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये। अख़बार का नहीं है, अख़बार नहीं पढ़ेगे। अख़बार नहीं पढ़ा जाता।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं यह कह रहा हूं कि गजेन्द्र सिंह जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई प्रस्ताव मेरे पास आता है तो मैं निश्चित तौर पर अविलम्ब उसको मंजूर करूंगा, ठीक है ना। अब सवाल यह आता है..

श्री अध्यक्ष: हां, सवाल पूछो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सवाल पूछ रहा हूं, और क्या कर रहा हूं?

श्री अध्यक्ष: आप तो अख़बार पढ़ रहे हो, अख़बार नहीं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अख़बार क्या पढ़ रहा हूं, मैं तो अख़बार में स्टेटमेंट है वह बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो। नहीं तो मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): हमारा अधिकार है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठो। कोई अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपने प्रश्न में मान लिया कि 06.07.2023 को जब हमारी सरकार थी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आपका प्रश्न आये तब बोलिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): साइक्लोजिकल कांउसलिंग सेंटर की स्थापना, तीन पद क्लीनिकल साइक्लोजिस्ट एवं 6 पद काउन्सलर के सृजित करने की स्वीकृति जारी कर दी थी। कब की थी, 2023 के सातवें महीने में, ठीक है ना। यह काम तब से चल रहा था।

अब मेरा सवाल यह था कि कोटा से आपको प्रस्ताव प्राप्त हुआ। कोटा के प्रिसिंपल मेडिकल कॉलेज ने आपको प्रस्ताव दिया कि यहां पर 05 साइक्लोजिस्ट की जरूरत है तथा 10 काउन्सलर की जरूरत है, उसके बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सिर्फ एक साइक्लोजिस्ट वहां भेजी गई और चार काउन्सलर संविदा पर लगाये गये। एक साइक्लोजिस्ट भेजी गई, उसको भी आपने जयपुर बुला लिया। आपने अपने जवाब में यह कहा कि इस काम को कौन कर रहा है, साइक्लोजिस्ट फैकल्टी का डॉक्टर, रेजीडेंट चिकित्सक, क्लिनिकल साइक्लोजिस्ट द्वारा संपादित, यह कर रहे है। डॉक्टर का काम तो दवाई देने का है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रश्न क्या है। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ठहरो तो सही, सुनो तो सही। ये क्या करते हो आप। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो पूछो। माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरा निवेदन यह है कि साइक्लोजिस्ट तो थैरेपी देता है, जांच करता है, डाइग्नोसिस करता है और वह बताता है कि कौनसी दवाई कितने समय के

लिए दी जानी चाहिए और डॉक्टर उसकी राय पर दवाई देता है। डॉक्टर के पास मरीज चला गया..

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो, भाषण नहीं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): तो साइक्लोजिस्ट की जरूरत ही क्या थी? मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि साइक्लोजिस्ट एवं काउन्सलर की नियुक्ति करेंगे या नहीं करेंगे, आपके पास सारे प्रस्ताव आ चुके। मेरा दूसरा प्रश्न है, चाहे सीकर हो, जयपुर हो, कोटा हो सब जगह कोचिंग इंस्टीटयूट्स हैं। सेंट्रल की गाइड लाइन कि हर कोचिंग संस्थान में साइक्लोजिस्ट व काउन्सलर का होना अनिवार्य है। मेरा प्रश्न है..

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): प्रश्न क्या है ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्री खड़े हो रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिये, प्रश्न के उत्तर आएंगे ना। ...(व्यवधान)... आपको किसने कहा, आपको किसने कहा। नो, रामकेश, मिस्टर श्रवण सिंह, यह बर्ताव नहीं होगा। आप बैठिये ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, सरकार के मंत्री खड़े हो रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नो, आप बैठिये। I don't allow it. अंकित नहीं हो। यह नहीं चलेगा।

श्री रामकेश (गंगापुर): 000

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार के मंत्री कैसे खड़े होते हैं। कितना गंभीर विषय है, कोटा के अन्दर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कितना गंभीर विषय है और यह मजाक बना रहे हैं ...(व्यवधान)... मंत्री जी सुन रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं, जबरदस्ती बीच में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः पहले उत्तर आने दो। आप भाषण कर रहे हो। बैठिये। इधर के लोग बैठते हैं तो इधर के खड़े हो जाते हो। ...(व्यवधान)... यह क्या तमाशा है, नो। मंत्री जी बोलिये। मंत्री जी उत्तर देने में सक्षम हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर, जयपुर, कोटा के अन्दर साइक्लोजिकल काउन्सलिंग सेंटर्स खोले गये हैं। अभी कोटा के अन्दर कांट्रेक्चुअल बेसेज पर आउटसोर्सिंग चल रही है, ऑलरेडी हमारा स्टाफ है। यह मानते हैं कि कम है,वहां इनोविजन एजेंसी है इन्होंने ऑलरेडी हायरिंग शुरू कर दी है। जो भी कमी है शीघ्र ही वहां पूर्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा एनएचएम है, 105 साइक्लोजिस्ट तथा 270 काउन्सलर्स के लिए भी हरी झण्डी आ गई है, तो यह भी हमारे स्टेट में आएंगे। कोटा के अन्दर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, टेलीमानस

हैल्पलाइन है जिसका नम्बर 1889 व 14416 है, यह बहुत ही इफेक्टिव रहा है। इसको कोटा या जयपुर में होने की जरूर नहीं है, राजस्थान में जो भी स्टुडेंट्स हैं, 27 हजार कॉल्स डेढ़ साल में यहां आए हुए हैं और उनको कांउसलिंग भी मिली है।

इसके अलावा आपने गाइड लाइन के बारे में बात की थी, 'The Guidelines for Regulation of Coaching Centers', एवरी इंस्टीटयूट हैं, कोचिंग सेंटर के अन्दर काउन्सलर होना अनिवार्य था, यह केन्द्र सरकार की गाइड लाइंस थी। स्टेट ने भी गाइड लाइंस जारी की, इसका ड्राफ्ट बिल पब्लिश हो गया जुलाई, 2024 में, 06 अगस्त को सुझाव मांगे स्टेकहोल्डर से, कोचिंग सेंटर्स से। अब यह बिल बिलकुल तैयारी पर है, to be presented in the House.

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब सेंट्रल की गाइड लाइन बन गई और राज्य सरकार ने भी गाइड लाइन बना दी कि हर कोचिंग इंस्टीटयूट में साइक्लोजिस्ट का अपाइंटमेंट जरूरी है, आप लोगों ने कितने कोचिंग इंस्टीटयूट के लिए अधिकारियों को भेजा कि जाकर देखिये कि साइक्लोजिस्ट अपाइंट किये गये या नहीं, काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्या कारण थे?

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लीगली हम बाइंड नहीं कर सकते कि जाकर चेक करे कि आपका कौन काउन्सलर है, काउन्सलर क्या करे, जब तक यह बिल पास नहीं होगा, उसके बाद में यह लागू हो जाएगा। अभी बाइडिंग ही नहीं है। हम कोचिंग सेंटर्स पर जाकर दादागीरी नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बिल पास होना जरूरी नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये, हो गया। माननीय सदस्य, हो गया। ...(व्यवधान)... पूछ लिया। दस मिनट हो गये आपके प्रश्न को। अगला प्रश्न, श्री गोपीचंद मीना।

जहाजपुर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय को स्थायी करने की योजना

103. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय, शाहपुरा में 60 प्रतिशत से भी ज्यादा न्यायिक प्रकरण विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में जहाजपुर एवं उक्त न्यायालय के अन्य क्षेत्राधिकार से आने वाले प्रकरणों की वर्षवार निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय का कैम्प जहाजपुर में एक माह में मात्र 6 दिन के लिये लगाये जाने के पश्चात् भी जहाजपुर न्याय क्षेत्र के अत्यधिक प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने व कब से? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार जहाजपुर मुख्यालय पर उपलब्ध भूमि एवं भवन तथा लम्बित

न्यायिक प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए जहाजपुर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल):(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय शाहपुरा में 60 प्रतिशत से ज्यादा प्रकरण जहाजपुर न्याय क्षेत्र के हैं। जहाजपुर न्याय क्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय स्तर के 54 प्रतिशत प्रकरण शाहपुरा में लंबित हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि एक माह में मात्र 6 दिन के लिये अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय का कैम्प कोर्ट जहाजपुर में आयोजित होता है, जिसमें यथासंभव अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। जहाजपुर कैम्प कोर्ट के कुल 1073 प्रकरण लंबित हैं जिसका विवरण प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

(3) जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में संचालित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के कैम्प कोर्ट को नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय में स्थापित करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 11.02.2020 प्राप्त होने पर प्रकरण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया गया। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण जहाजपुर में स्थायी अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकी।

भविष्य में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर जहाजपुर में संचालित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के कैम्प कोर्ट को नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के रूप में स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में अतिरिक्त जिला सेशन एवं आपने न्यायालय में 54 प्रतिशत प्रकरण बताये हैं जो शाहपुरा में लंबित है। इसके साथ ही खण्ड ब में बताया कि जहाजपुर क्षेत्र के 1073 प्रकरण लंबित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मापदण्ड पूर्ण होने के बाद भी कांग्रेस सरकार में पिछले चार साल तक, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी न्यायालय की स्थापना नहीं की। तो मैं आपसे चाहता हूं कि न्यायालय की स्थापना करना चाहते हैं नियमित?

VPS-RTM-20.02.2025-11.50-1f

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कथन सही है कि पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी का प्रस्ताव 11

फरवरी, 2020 को प्राप्त हुआ था परंतु तत्कालीन समय में तत्कालीन सरकार ने वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं होने के आधार पर न्यायालय की स्थापना नहीं की। अब मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए शीघ्र ही आपके वहां आपके द्वारा मांगे गये न्यायालय की स्थापना पर विचार करेगी। धन्यवाद।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह शेखावत।

कोटपूतली-बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवार

104. श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटपूतली-बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा योजना में माह दिसम्बर, 2024 तक नाम नहीं जुड़ने से जरूरतमंद परिवार योजना का लाभ नहीं उठा सके? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ऐसे कितने परिवार हैं, जो खाद्य सुरक्षा योजना से तो जुड़े हुए हैं, किन्तु उक्त योजना के लाभ से वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वंचित परिवारों को उक्त योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) जिला कोटपूतली-बहरोड में दिसम्बर 2024 तक खाद्य सुरक्षा योजना में 2,11,678 परिवार एवं 9,05,719 यूनिट जुड़े हुये हैं जो नियमित रूप से योजना का लाभ उठा रहे हैं।

जिला कोटपूतली-बहरोड में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोडने हेतु 26,702 आवेदन लंबित है। आवेदन प्रदेश की सीलिंग सीमा समाप्त होने के कारण लंबित रहे।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कुल 58,596 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं। जिनको E-PoS मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है।

(3) वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु विभागीय आदेश से दिनांक 26.01.2025 को पोर्टल खोला जा चुका है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,61,960 के अनुसार उपलब्ध रिक्त स्थान के विरुद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु कार्यवाही जारी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से

मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिला कोटपूतली-बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 26702 आवेदन प्रदेश की सीलिंग सीमा समाप्त होने के कारण लंबित बताये हैं तो उनके समाधान हेतु क्या कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी से यह पोर्टल खोल दिया गया है और लोग लगातार इस योजना का लाभ लेने हेतु ई-मित्र के माध्यम से और इस पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर रहे हैं और मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगले चार-पांच महीने में हमारा यह प्रयास है कि राजस्थान में कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री कालूराम। आपको कोई और पूछना है? एक सेकण्ड।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि यह 26,702 आवेदन किन-किन तारीख को इनके आवेदन प्राप्त हुए, इनकी सूची उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्षः सूची आप बाद में इनसे ले लेना, सूची पढ़ी थोड़े ही जायेगी।

अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

झालावाड़ जिले में गौशालाओं को देय अनुदान

105. श्री कालूराम (डग)(श्री गोविन्द प्रसाद के स्थान पर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में पंजीकृत गौशालाएं कितनी हैं तथा उक्त गौशालाओं को विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कितना-कितना बजट आवंटित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के कितने जिलों में जिला स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय नंदीशालाओं की स्थापना की गई तथा कितनी पंचायत स्तरीय क्षेत्र में नंदीशाला खोला जाना शेष है?

(3) सरकार द्वारा जिला एवं पंचायत स्तरीय नंदीशाला की स्थापना के लिए किस प्रकार एवं कितना सहयोग किया जाता है? विगत एक वर्ष में नंदीशालाओं की स्थापना पर कितना व्यय किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जिला झालावाड़ में पंजीकृत गौशालाओं की संख्या 67 है तथा उक्त में से पात्र गौशालाओं को विगत पांच वर्षों में दी गई सहायता राशि का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	वर्ष	सहायता प्राप्त पात्र गौशालाओं की संख्या	गौवंश की संख्या	प्रदत्त सहायता राशि (करोड़ में)

1.	2019-20	24	8042	4.35
2.	2020-21	26	8393	5.26
3.	2021-22	30	10403	6.53
4.	2022-23	32	13193	9.57
5.	2023-24	42	16605	14.37
महायोग				40.08

(2) प्रदेश में 15 जिलों में जिला स्तरीय नंदीशाला एवं 16 जिलों की 53 पंचायत समितियों में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला की स्थापना की गई है तथा 299 पंचायत समितियों में शेष है।

(3) जिला स्तरीय नंदी गौशाला जन सहभागिता योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय नन्दीशाला स्थापित करने हेतु राशि रुपये 50.00 लाख (90 प्रतिशत राजकीय अंशदान एवं 10 प्रतिशत संस्था का अंशदान) का प्रावधान था।

पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त करने एवं पात्र संस्था (गौशाला) का चयन करने के लिए जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। चयनित संस्था के साथ अनुबंध किया जाता है। योजना अन्तर्गत प्रावधित राशि 1.57 करोड़ (10 : 90) का तख्मीना प्राप्त किया जाता है। तख्मीना अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के स्तर पर जारी की जाती है। चयनित संस्था द्वारा योजना में प्रावधित राशि 1.57 करोड़ का 10 प्रतिशत हिस्सा राशि का कार्य करवाया जाता है। 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के उपरान्त राज्यांश की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त क्रमशः 40 : 40 : 10 के अनुपात में जारी किये जाने का प्रावधान है।

विगत 01 वर्ष में 35 पंचायत स्तरीय नंदीशाला की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि रुपये 22.04 करोड व्यय किया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले में कुल 67 गौशालाएं हैं, उनमें से आपने 2019-20 में 24, 2020-21 में 26, 2021-22 में 30, 2022-23 में 32 और 2023-24 में 42 गौशालाओं को करीब 40 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। शेष बची हुई 25 गौशालाओं को आप कब तक अनुदान देंगे?

नम्बर-दो, प्रदेश में 15 जिलों में 53 गौशालाएं खोली गयी हैं और 299 गौशालाएं बाकी हैं। पिछली सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलेंगे पर अभी तक 299 बाकी है। पिछली सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिये।

श्री कालूराम (डग): मंत्री महोदय, यह 299 गौशालाएं आप कब तक खोल देंगे?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पहला प्रश्न यह है कि झालावाड़ जिले में 67 गौशालाएं हैं और 67 में से वर्ष 2022-23 में 42 गौशालाओं को अनुदान मिला है, तो माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि पूरे जिले में 67 गौशाला है लेकिन जो पात्र गौशाला है वह 42 ही थी 2023-24 में और अभी जो 2024-25 का सर्वे हुआ है उसमें 41 गौशाला पात्र है, बाकी पात्र नहीं है। गौशाला की पात्रता के लिए एक गौशाला में 100 गायें होना अनिवार्य होता है और दूसरी जो गौशाला है जो अपात्र है उसमें 100 गायें नहीं हैं, इसलिए वह अनुदान की श्रेणी में नहीं आता है।

दूसरा, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि झालावाड़ जिले में जो पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला खुली है उसमें अभी 299 बाकी हैं, तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021-22 में 15 पंचायत समिति पर नंदीशाला खुली है जिसमें 9.81 करोड़ रुपये की राशि जारी हुई है। 2022-23 में 10 पंचायत समितियों पर नंदीशाला खुली जिसमें 6.32 करोड़ रुपये की राशि जारी हुई है। 2023-24 में 35 नंदीशाला खुली, जिसमें 22.4 करोड़ की राशि जारी हुई और 2024-25 में 35 नंदीशालाएं खुलीं और उसमें 21 करोड़ रुपये की राशि जारी हुई। जो पंचायत समितियां बाकी हैं, उनकी भी हम वहां पर नंदीशाला खोलने के लिए हमारी राजस्थान सरकार की जो योजना है, चार तरह की यह योजना है। एक योजना है जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने की, दूसरी योजना है पंचायत समिति स्तर पर खोलने की, तीसरी योजना है हर पंचायत स्तर पर नंदीशाला/गौशाला खोलने की और चौथी योजना है गौशाला विकास योजना तो ये चारों योजनाएं हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा कि इन योजनाओं की आप जानकारी लें। मैं आप सबको प्रपत्र भी भेज दूंगा और इन योजनाओं की जानकारी लेकर अपने-अपने क्षेत्र में ये गौशालाएं ज्यादा से ज्यादा खुलवायें। गौ-माता की सेवा के लिए हम सब लोग समर्पित लोग हैं, उनका लाभ जनता को मिल सके, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री जब्बर सिंह सांखला। आपके दो प्रश्न हो गये। श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं।

रूपाहेली ग्राम (आसीन्द) में संचालित फैक्टरी पर कार्यवाही

106. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ग्राम पंचायत-रूपाहेली कलां, तहसील-हुरड़ा में संचालित सिन्यॉल ग्रीन एनर्जी पावर लिमिटेड फैक्ट्री में पुराने टायरों को जलाकर ऑयल बनाने के कारण प्रदूषण फैल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्री को

प्रतिबंधित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इसी प्रकार के प्लांट व फैक्ट्रियां कई राज्यों में प्रतिबंधित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में ऐसे उद्योगों को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री संजय शर्मा): (1) जी हां। उक्त उद्योग में अपशिष्ट टायरों को जलाया नहीं जाता हैं अपितु वैज्ञानिक तरीके से बंद रिएक्टर में इन्हें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाकर पायरोलायसिस प्रक्रिया से पायरोलायसिस ऑइल (ईंधन तेल) का निर्माण किया जाता है। उपरोक्त उद्योग राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से वैध संचालन सम्मति प्राप्त कर ही कार्यरत है।

उद्योग में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16/01/2024 को जारी नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में उल्लेखित एवं संचालन सम्मति की शर्तों के अनुसार वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/ व्यवस्था स्थापित कर संचालित है।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यों में इस तरह के टायर पायरोलायसिस उद्योगों पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल द्वारा टायर पायरोलायसिस उद्योगों के संबंध में कार्यालय आदेश दिनांक 17/08/2023 को जारी किया गया। जिसके अनुसार राज्य में नये टायर पायरोलायसिस उद्योग जो केवल सतत प्रक्रिया (Continuous Process) पर आधारित होंगे, उन्हें ही जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति प्रदान की जायेगी।

बैच प्रक्रिया पर आधारित नये टायर पायरोलायसिस उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध जारी रहेगा।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस तरह के जो प्लांट है वह गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में बंद हो चुके हैं और यह प्लांट नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जहरीली मौत की फैक्ट्री है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करायें। पिछली सरकार ने भी इसकी जांच करवायी थी लेकिन वह पूरी नहीं हो पायी थी। उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाकर आप इसको बंद कराने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका? माननीय मंत्रीजी, आप बोलें।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर जो बात रखी है, उसको लेकर मैं इस सदन के अन्दर तीन सदस्यीय जांच समिति बनाने की घोषणा करता हूं जिसमें मुख्य

पर्यावरण अभियंता, अतिरिक्त जिला कलक्टर और क्षेत्रीय अधिकारी पॉल्यूशन बोर्ड का या किसी अन्य क्षेत्र का, वह तीन सदस्यीय कमेटी जांच करेगी और एक माह के अन्दर रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट आने के बाद विभाग कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्षः और कोई प्रश्न है? माननीय सदस्य, कोई पूछना है? अगला प्रश्न पूछना नहीं है? चलो अब समय हो गया, फिर भी आप प्रश्न संख्या बोल लें। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अब तो समय हो गया। ...(व्यवधान)...

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप नाम तो बोल दो। ...(व्यवधान)...

ssy/rtm/20.02.2025/12.00/1g

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त। विराजिये। शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुईं पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती कमला भील एवं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री गंगाजल मील के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

कमला भील, श्रीमती, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती कमला भील का जन्म 7 जनवरी, 1946 को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में हुआ। आपने एम.ए. व एल.एल. बी. की उपाधियां तथा श्रम विधि में डिप्लोमा प्राप्त किया।

श्रीमती कमला भील सातवीं, आठवीं एवं नौंवी राजस्थान विधान सभा में सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुईं। आप सातवीं विधान सभा में कांग्रेस (आई) तथा आठवीं एवं नौंवी विधान सभा में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की विधायक रहीं। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति तथा जन लेखा समिति की सदस्य रहीं। आप जुलाई, 1981 से मार्च, 1985 तक राज्य सरकार में विभिन्न विभागों की उप मंत्री रहीं। श्रीमती कमला भील जनवरी, 1988 से दिसम्बर, 1989 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, परिवार कल्याण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, वन विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य मंत्री भी रहीं।

राज्य सेवा से कैरियर प्रारम्भ करने वाली श्रीमती कमला भील राजस्थान समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति, राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल, राजस्थान राज्य अल्प बचत परामर्शदात्री मण्डल एवं उदयपुर विश्वविद्यालय सिण्डीकेट की सदस्य रहीं। आप राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रहीं। आदिवासियों के उत्थान के लिये प्रयत्नशील रही श्रीमती कमला भील ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई।

श्रीमती कमला भील का दिनांक 12 फरवरी, 2025 को निधन हो गया।

गंगाजल मील, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री गंगाजल मील का जन्म 15 मई, 1945 को सूरतगढ़ के निरवाणा ग्राम में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से पी.यू.सी. (कला) तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री गंगाजल मील तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में सूरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति के सदस्य रहे। श्री मील विधान सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री मील ग्राम सेवा सहकारी समिति, निरवाणा के अध्यक्ष तथा श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक, श्रीगंगानगर के निदेशक रहे। समाज कल्याण एवं शैक्षिक उत्थान के लिये समर्पित रहे श्री मील ज्ञानदान ट्रस्ट, हनुमानगढ़, वीर तेजाजी कन्या छात्रावास, सूरतगढ़ एवं श्री मोटाराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल, निरवाणा के अध्यक्ष रहे। आप स्वामी केशवानन्द चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी भी रहे। इण्डियन नेशनल कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री मील ने पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया। खेलों में रुचि रखने वाले श्री मील राष्ट्रीय महिला फुटबाल संघ के उपाध्यक्ष एवं संरक्षक रहे। आप राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति के संरक्षक भी रहे।

श्री गंगाजल मील का दिनांक 17 फरवरी, 2025 को निधन हो गया।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

ओम शांति। विराजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में नव नियुक्त नर्सिंग कर्मियों की प्रतिनियुक्ति से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों में सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत

बिलड़ी एवं ग्राम पंचायत पालवाड़ा में आदिवासियों की भूमि के अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री नरेन्द्र बुडानियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तारानगर में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव के गिराब में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की आदर्श पीएचसी राजलदेसर में चिकित्सकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

7. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी एवं श्री टीकाराम जूली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, देवानाड़ा, केडली में वाटर टैंक की पट्टियाँ टूटने से हुई तीन बालिकाओं की मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धरियावद में कृषि उपज मण्डी के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमित चाचाण, श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी, श्री टीकाराम जूली एवं श्री थावर चन्द को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के घिलौठ औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से होने वाले गैस रिसाव से नष्ट फसलों का मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

2. श्रीमती गीता बरवड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की मुख्य फसल सिन्धीसुआ को अधिसूचित फसल सूची में सम्मिलित करने तथा वाणिज्यिक फसल घोषित किए जाने के संबंध में।

3. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना की उप तहसील गच्छीपुरा को तहसील में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

4. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से जिला चिकित्सालय राजसमन्द में हृदय रोग चिकित्सा इकाई की स्थापना के संबंध में।

5. श्री लादु लाल पितलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा हेतु जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कार्यादेश शीघ्र जारी करवाने के संबंध में।

6. श्री विश्वराज सिंह मेवाड़, सदस्य की ओर से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता पर विपरीत असर पड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री रामावतार बैरवा, सदस्य की ओर से पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय को माधोराजपुरा में यथावत रखे जाने के संबंध में।

8. श्री पब्बाराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलोदी के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री राधेश्याम बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में प्रचलित एवं शामलाती खातों के रास्तों के विवादों का निस्तारण किये जाने के संबंध में।

10. श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से धौलपुर शहर में वर्षा जल निकासी हेतु समुचित ड्रेनेज सिस्टम के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री हरलाल सहारण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चूरू में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

12. श्री लक्ष्मण राम, सदस्य की ओर से बस स्टेण्ड मेड़ता की चारदीवारी का पुनर्निर्माण एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्री जेठानन्द व्यास, सदस्य की ओर से बीकानेर संभाग मुख्यालय पर निदेशालय, आयुष शिक्षा की स्थापना के सम्बन्ध में।

14. श्री प्रताप लाल भील, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर स्थित ग्रामों हेतु सर्विस रोड न होने एवं निरन्तर हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

15. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को विकास राशि नहीं दिये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 20/02/2025 को शून्यकाल में बोलने हेतु 34 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई, जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पर्ची सं.	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	12	श्री शंकर सिंह रावत	जस्साखेडा से दूधालेश्वर तक सड़क निर्माण हेतु अपूर्ण बजट को पूर्ण करने बाबत्।
2.	34	श्री संजीव कुमार	भादरा विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पेयजल कनेक्शन से वंचित रखे जाने एवं योजना में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3.	8	श्री हमीर सिंह भायल	राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित करके मान्यता दिलवाने के सबंध में।
4.	33	श्री अरुण चौधरी	पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कों की घोषणा के संबंध में।

श्री अमित चाचाण।

spp/rtm/20.**02.2025/12:10/1h**

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नोहर में किसानों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। आज चाहे वह नोहर विधान सभा क्षेत्र की बात हो या पूरे बीकानेर संभाग की बात हो, किसानों के सामने और किसानों का सबसे बड़ा ज्वलन्त मुद्दा आज सिंचाई के पानी का है। किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलने की वजह से किसानों के खेत में जो फसलें खड़ी हैं, आज उनकी आंखों के सामने वह फसलें बरबाद हो रही हैं, वह फसलें जल रही हैं। हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं और राजस्थान के हिस्से का पानी आज किसानों को नहीं दिया जा रहा है। आज नोहर के साथ-साथ पूरे बीकानेर संभाग के अन्दर किसानों का धरना-प्रदर्शन चल रहा है। बाजार बंद किये जा रहे हैं। आमरण अनशन किये जा रहे हैं। यहां तक कि टोल-नाकों पर जाम लगा रखा है, लेकिन इस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मैं नोहर विधान सभा क्षेत्र के नोहर फीडर की बात करूं, अमरसिंह ब्रांच की बात करूं, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की बात करूं या इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करूं, किसी भी नहर में पानी नहीं आ रहा है और किसानों की फसलें खड़ी हैं। यह पहली बार हुआ है जब जनवरी के माह में ही यह कह दिया गया कि 01 फरवरी से पानी नहीं मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी-बड़ी बातें करने वाली यह सरकार, किसानों के लिये घड़ियाली आंसू बहाने वाली यह सरकार जहां यमुना जल समझौते के लिये राजस्थान को असत्य सपने दिखाने वाली यह सरकार और मौजूदा जो हमारा सिंचाई का तंत्र है, मौजूदा जहां हमारी नहरें हैं, उन्हीं नहरों में हम किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं दे पा रहे हैं और यह किस तरह की सरकार है? बजट में बड़ी-बड़ी बातें तो किसानों के लिये की जा रही हैं, लेकिन पूरे बीकानेर संभाग का किसान आज आंदोलन के लिये मजबूर है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 2005 में भी इस तरह का आंदोलन हुआ था। आप रावला-घड़साना को याद कीजिए। आपने किसानों को पानी देने के बजाय उन पर गोलियां चलाने का काम किया था और साढ़े तीन लाख हैक्टेयर भूमि, जो इंदिरा गांधी नहर की की थी, उसको असिंचित करने

का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो फसलें आज इनकी वजह से जल रही है, हरियाणा से हमें पानी नहीं मिला। आज यह कई इंजनों की सरकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई इंजनों की सरकार होने के बावजूद भी किसानों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? फिर आप राजस्थान की जनता को क्यों असत्य सपने यमुना जल समझौते के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य आपको आंखें दिखाने का काम कर रहा है, पड़ोसी राज्य आपको पानी नहीं दे रहा है और आज हमारे किसान की हालत क्या हो चुकी है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए और इस बार कम से कम एक पानी किसानों को आप दिलाएं जिससे कि किसानों की फसल पकाई जा सके। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी।

नोखा के देवानाड़ा केडली विद्यालय में वाटर टैंक की
पट्टियां टूटने से तीन बालिकाओं की मृत्यु

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बीकानेर जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवनाड़ा केडली में जलकुण्ड के ऊपर खेलने के दौरान कुण्डी की पट्टियां गिरने से कक्षा 3 में पढ़ रही मासूम प्रज्ञा, कक्षा 2 में पढ़ रही भारती जाट और रवीना की हुई दर्दनाक मृत्यु से जुड़े संवेदनशील मामले पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवनाड़ा केडली के विद्यालय परिसर में एक जलकुण्ड बना हुआ है, जो जर्जर व पुराना है व धंसा हुआ है। जलकुण्ड की ऐसी स्थिति की जानकारी बी.ई.ई.ओ. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पांचू विकास अधिकारी, पंचायत समिति पांचू तथा शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में थी। परंतु यहां का सरकारी तंत्र पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। प्रारम्भिक शिक्षा पंचायती राज का विषय है। दुर्घटना प्राथमिक विद्यालय में घटित हुई। ऐसे में दुर्घटना के लिये सबसे अधिक ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते विकास अधिकारी पंचायत समिति पांचू की ही बनती है। यह अधिकारी कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाह है और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के चलते इनको निलम्बित भी किया जा चुका है। इनके निलम्बन पर माननीय न्यायालय का स्थगन अभी पंचायती राज विभाग मुख्यालय जयपुर के स्तर से स्वीकार भी नहीं किया गया है, फिर भी इनको वित्तीय अधिकारों के साथ पंचायत समिति पांचू का नियम विरूद्ध विकास अधिकारी बना रखा है। इनका स्थानांतरण भी हो चुका है, जोकि सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पता नहीं क्यों इस विकास अधिकारी पर सरकार पूरी तरह मेहरबान है? (समय समाप्ति सूचक घंटी)

पंचायत समिति पांचू में वर्तमान में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की जा चुकी है। इसके पर्याप्त सबूत मेरे पास हैं। जरूरत पड़ने पर हम आपको सदन के सामने पेश कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर के टोप टू बॉटम अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद भी ऐसे जर्जर जलकुण्ड को सही नहीं करवाया गया और न ही जर्जर स्थिति के बाहर कोई बैरीकेडिंग की गयी है। इस वजह से अपनी होने वाली मौत के अंदेशों से अंजान यह तीन बालिकाएं यहां खेलने लगी और जलकुण्ड की पट्टियां टूटीं और तीनों मासूम बच्चियां काल-कवलित हो गयीं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ हादसा नहीं, सिस्टम की नाकामी की वजह से हुई है। इसके लिये सरकार का तंत्र जिम्मेदार है। पूरे मामले को लेकर नोखा मुख्यालय पर धरना चल रहा है एवं जनता में आक्रोश की लहर है। पुलिस स्टेशन नोखा में मुकदमा संख्या 103/2025 भी दर्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, हो गया। स्थगन प्रस्ताव पर तो बोलते हैं, पढ़ते नहीं हैं।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): मेरी मांग है कि सभी दोषी अधिकारी और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाये और उनके खिलाफ आपराधिक मुदकमा चलाया जाये। उनको तत्काल सेवा से निलम्बित किया जाये। प्रत्येक मृतक बालिका के परिजनों को आर्थिक सहयोग दिया जाये। परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाये। साथ ही पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जलकुण्डों व जर्जर भवनों की स्थिति तलब करके उनमें सुधार के लिये तत्काल बजट आवंटित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगी। इस मामले में सरकार का जवाब सदन में दिलाया जाये। तीन मासूम बालिकाओं की हत्या हुई है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय टीकाराम जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो स्थगन के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान नोखा क्षेत्र में जो तीन बच्चियां प्रज्ञा, भारती और रवीना, जोकि विद्यालय के अन्दर खेल रही थी और खेलते-खेलते वह टांके के अन्दर गिर गयी। टांका इस जर्जर स्थिति के अन्दर था कि बच्चियां वहां खेल रही थीं तो उसकी सारी पट्टियां टूट गयीं और बच्चियां इस टांके के अन्दर गिर गयीं। यह एक लचर सिस्टम है और सिस्टम की लापरवाही से तीन मासूम बच्चियों की जान लेली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ महिलाओं को बच्चियों की सुरक्षा की बड़ी-बड़ी बात करने वाली सरकार और दूसरी तरफ जब विद्यालय की तरफ से यह संज्ञान में ला दिया गया था उच्चाधिकारियों को, चाहे वह बी.ई.ओ. हो, चाहे डी.ई.ओ. हो, विकास अधिकारी हो, सभी के संज्ञान में यह बात ला दी गयी थी कि यहां पर टांका जर्जर अवस्था में है और कभी भी यहां कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका अंदेशा था, वही

हुआ। दुर्घटना घटी और तीन बच्चियों की जान चली गयी। परसों मंगलवार से बच्चियों के अभिभावक ही नहीं, पूरे इलाके के लोग धरने पर बैठे हैं। लेकिन यह सरकार जो सिर्फ भाषण देने में पीछे नहीं रहती, आज उन बच्चियों के लिये कोई जवाबदेही तय करने से बच रही है। क्या उन परिवारों के लिये आपने मुआवजे की व्यवस्था की? क्या आप जो दोषी लोग हैं, उन पर कार्यवाही करने की बात आपने की, क्या उस परिवार को आपने नौकरी देने की बात की? कोई बात आप करना नहीं चाहते। तीन दिन से बच्चियों की डेड बॉडी वहां पर रखी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संज्ञान चाहिए और इस सरकार को आदेशित करें कि इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाये और उन परिवारों के सदस्यों को नौकरी दे और मुआवजा दे और जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। आज तय करके सरकार इस सदन के अन्दर जवाब दे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर हम रोक लगाने के काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संरक्षण आपसे चाहते हैं। धन्यवाद।

jyg/rtm/20.02.25/12.20/1j

श्री अध्यक्षः श्री थावर चन्द।

धरियावद में नवीन कृषि उपज मण्डी की स्थापना

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

चीर के जमीन को उम्मीद के बीज बोते हैं,
हम किसान के बेटे हैं, चैन से नहीं सोते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के नजदीक में जाखम का बांध बना हुआ है, जिससे पूरे धरियावद को पानी मिलता है और पूरे उदयपुर संभाग के अन्दर रबी और खरीफ की फसलें बेहतर होती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 के अन्दर जब कृषि उपज मण्डी की घोषणा हुई थी तो इस क्षेत्र में किसानों को खुशी हुई। 1998 के बाद में 2001 के अन्दर कृषि उपज मण्डी के नाम पर 35 बीघा जमीन अलॉट हुई थी और उसके बाद 2001 से कई सरकारें आयीं और गयीं लेकिन वो मामला कोर्ट में चला गया था। हमने आज भी और पिछले साल भी कई जन प्रतिनिधियों के माध्यम से किसानों ने सरकार से आक्रोश जताया और सरकार को वह बात भी बतायी गयी लेकिन इस कृषि उपज मण्डी के लिए कोई फैसला नहीं हुआ। हमने पूर्व में भी मांग की थी लेकिन उक्त कृषि उपज मण्डी धरियावद के खाते में दर्ज भूमि पर न्यायालय में पैरवी में शिथिलता बरती गयी। सरकार की ओर से कानूनी विशेषज्ञों की टीम और अधिवक्ता लगायें जिससे इस कृषि उपज मण्डी के लिए जोरदार पैरवी हो सके और वहां के किसानों को फायदा हो सके। किसान फुटकर व्यापारियों के माध्यम से लूटे जा रहे हैं, मेहनत करके पूरे देश का पेट भरने वाला किसान मजबूरी में है, उसकी मेहनत और खून-पसीने की कमाई को कोई और खाये जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार इस पर जोरदार पैरवी

करेगी और योग्य अधिवक्ताओं की टीम लगाकर कृषि उपज मण्डी के मामले को सुलझायेगी जिससे आने वाले समय में किसानों को फायदा होगा।

धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः 295

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री ललित यादव। श्री ललित यादव। (अनुपस्थित)।

श्रीमती गीता बरवड़।

सिन्धीसुआ (सुआ) फसल को राज्य की अधिसूचित एवं वाणिज्यिक फसल घोषित करना

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ के भोपालगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत बासनी हरिसिंह, सुवाणा, कुकड़दा, गजसिंहपुरा सहित 16 गांवों में सदियों से सिन्धीसुआ की खेती रबी फसल के रूप में की जाती है। यह फसल वर्तमान में हजारों हेक्टेयर में उगाई जाती है। इसका उपयोग दवाईयों के निर्माण में होता है, तथा मेड़ता मंडी में इसका बड़े पैमाने पर व्यापार होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि राज्य/केंद्र सरकार की अधिसूचित फसल सूची में शामिल न होने के कारण किसानों को फसल बीमा, आपदा राहत, कृषि ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड) और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृषि विभाग द्वारा इस फसल के लिए कोई तकनीकी या वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि सिन्धीसुआ को राजस्थान सरकार की "अधिसूचित फसलों" की सूची में शामिल किया जाए। इसे वाणिज्यिक फसल का दर्जा देते हुए, किसानों को बीमा, ऋण, और आपदा प्रबंधन योजनाओं से जोड़ा जाए। कृषि विपणन विभाग को निर्देश दिए जायें कि वह इस फसल के मूल्य संवर्धन और बाजार व्यवस्था हेतु नीतिगत कदम उठाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फसल स्थानीय किसानों की आजीविका और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। अतः मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करती हूँ कि सरकार इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सिन्धीसुआ को अधिसूचित एवं वाणिज्यिक फसल घोषित करें।

श्री अध्यक्षः श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

गच्छीपुरा उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मकराना की उप

तहसील कार्यालय गच्छीपुरा है। मेरा विधान सभा का क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसकी आबादी 07 लाख से ज्यादा है तथा गच्छीपुरा से मकराना तहसील की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल भी काफी बड़ा और लम्बा है। उल्लेखनीय यह है कि आमजन को राजस्व, कृषि, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा आदि कार्यालयों के लिये मकराना आना-जाना पड़ता है, जिसके लिये आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पडता है तथा समय एवं आर्थिक नुकसान भी उठाना पडता है। प्रशासनिक कार्यो का केन्द्रीकरण करने हेतु गच्छीपुरा को उप तहसील से तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत करना जनहित में अति आवश्यक है।

उल्लेखनीय यह भी है कि अभी नवीन परिसीमन कार्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। मकराना में अभी 39 ग्राम पंचायतें जो कि अभी के मापदण्ड के हिसाब से करीब 55-60 ग्राम पंचायतें बनने की संभावना है। उक्त उप तहसील विगत 12-13 वर्षो से संचालित है। जिसको देखते हुए गच्छीपुरा उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द में आर. के. जिला चिकित्सालय में हृदय रोग चिकित्सा इकाई की स्थापना एवं हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि राजसमन्द जिला चिकित्सालय में हृदय रोग चिकित्सा इकाई की आवश्यकता है। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। राजसमन्द जिले में हृदय रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिला चिकित्सालय में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर इतनी गंभीर स्थिति है कि 2024 में अस्पताल में 21,964 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 732 हृदय रोगी थे। ICU में भर्ती 1,527 मरीजों में से 469 को हृदय संबंधी समस्याएँ थी। ओपीडी में आए 4,28,396 मरीजों में से 14,880 में हृदय रोग के लक्षण पाए गए। यह स्पष्ट करता है कि जिले में हृदय रोग गंभीर समस्या बन चुका है। विशेषज्ञों और सुविधाओं का अभावः हृदय रोग का सही समय पर इलाज आवश्यक होता है, लेकिन राजसमंद जिला चिकित्सालय में हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं हैं। मरीजों का इलाज सामान्य चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है, जिससे जटिल मामलों में गंभीर जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा, टीएमटी, 2D ईको, एंजियोग्राफी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का अभाव है, जिससे समय पर रोग की पहचान नहीं हो पाती और मरीजों को उदयपुर या अन्य शहरों में रेफर करना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति न केवल हृदय रोगियों बल्कि अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए भी आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं

और जटिल सर्जरी वाले मरीजों को भी इसकी जरूरत होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूँ कि राजसमन्द जिला चिकित्सालय में हृदय रोग चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाए एवं विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त किए जाएं, जिससे मरीजों को अपने जिले में ही समुचित और समय पर उपचार मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री लादु लाल पितलिया। श्री लादु लाल पितलिया। (अनुपस्थित)।

श्री विश्वराज सिंह मेवाड़।

मूलभूत सुविधाओं की कमी से पुलिस की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर

श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के कर्तव्य निभाने में अनदेखी एवं भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लगे हैं, ऐसा व्यवहार मेरे साथ भी हुआ है लेकिन यह अनुरोध भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि कुछ उदाहरण देकर महत्वपूर्ण सुविधाओं के अभाव के कारण पुलिस कर्मियों की सक्षमता में कमी, और पूर्ति करने के लिए भ्रष्ट तरीकों को अपनाने में विफल किए जाने पर है।

1. साइबर अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं, AI आने से अपराध और भी बढ़ेंगे। अनिवार्य है कि तकनीकी योग्यता वार्तो को पुलिस में भर्ती कराया जाए और इन्हें तकनीकी सुविधाएँ भी मिले। आज, अपराधिक क़ानून लागू होने से संपूर्ण अनुसंधान ऑनलाइन है मगर अधिकारियों को अनुसंधान में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं। कई बार तो स्टेशनरी भी उपलब्ध नहीं होती है।

2. पुलिस सिपाहियों को 150/- रुपये भत्ता मिलता है जो आज के समय, अप्रासंगिक है। फील्ड पोस्टिंग का भता है, पर यह भी अप्रासंगिक।

3 सालों से कांस्टेबल का ग्रेड पे 2400/- रुपये ही है, और सिपाही से निरीक्षक का मेस भत्ता केवल 2400/- रुपये प्रति माह मिलता है।

4. 24 घंटे ड्यूटी की पाबंदी होने और कम अवकाश के कारण पुलिसकर्मियों को क्वार्टर की ज़रूरत है, परंतु ज़िला मुख्यालय में इनकी कमी और थाना स्थान पर तो वे ना के बराबर है। एक तरफ़ घर से आने जाने के लिए ना हीं वाहन या वाहन भता और दूसरे तरफ़ ड्यूटी के स्थान पर क्वार्टर नहीं। ऐसी स्थिति में पुलिस, परिवार के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभाये?

अत: पुलिस प्रक्रिया में संतुलन और आधुनिकीकरण की ज़रूरत सामने है।

Bhs/Rtm/20.02.25/12.30/1k

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रामावतार बैरवा।

माधोराजपुरा (जयपुर ग्रामीण) के पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की यथास्थिति

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे नियम 295 के तहत सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र चाकसू के माधोराजपुरा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय पिछले 18 माह से संचालित था, जिसे राजकीय आदेशों के द्वारा माधोराजपुरा से हटाकर फागी कर दिया गया है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों में आक्रोश व्याप्त है।

उप अधीक्षक कार्यालय माधोराजपुरा के अधीन मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीन पुलिस थाने आते हैं, जिनमें माधोराजपुरा, रेनवाल व सेज का काफी बड़ा हिस्सा शामिल है एवं विधान सभा क्षेत्र दूदू का मात्र एक थाना फागी आता है। ऐसे में 3 पुलिस थानों के कार्यों का माधोराजपुरा से दूर फागी में होने पर पुलिस सेवाओं के लिये लोगों को असुविधाओं का सामना करना पडेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र का उक्त क्षेत्र काफी संवेदनशील इलाका है, जिसके कारण पुलिस थानों पर नियंत्रण के लिए पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का माधोराजपुरा में स्थापित होना नितान्त आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था एवं लोगों को पुलिस सेवाएं सुचारु रूप से देने के लिए उक्त राजकीय आदेशों को निरस्त फरमाने एवं पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय माधोराजपुरा, जयपुर ग्रामीण को यथावत माधोराजपुरा में ही रखा जावे, इस बाबत् आदेश जारी करवाकर आमजन एवं मुझे अनुगृहीत करें।

बस यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आभार।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम विश्नोई।

फलौदी के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फलोदी के सभी राजकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में विषय अध्यापकों के पद रिक्त होने से बच्चों की पढ़ाई चौपट होती जा रही है इस तरफ करना चाहता हूं। फलौदी विधान सभा क्षेत्र के ब्लॉक फलोदी में 1205 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 953 पद पर कार्यरत हैं एवं 252 पद रिक्त हैं। ब्लॉक बाप में 1275 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 986 पदों पर कार्यरत हैं और 289 पद खाली हैं। घंटियाली ब्लॉक में 944 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 797 पर कार्यरत हैं और 147 पद रिक्त हैं। कई स्कूलों में बच्चों, अभिभावकों सहित आंदोलन भी हुए हैं।

मान्यवर, स्वतंत्र राजस्थान के इतिहास में शिक्षा की ऐसी दुर्दशा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजनीतिक द्वेषता के कारण एक साथ भारी संख्या में विषय अध्यापकों को स्थानांतरित कर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को लगभग खाली कर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मेरी आसन के माध्यम से सरकार से मांग हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरा जावे ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो।

श्री अध्यक्षः श्री राधेश्याम बैरवा। श्रीमती शोभारानी।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): बोल रहा हूं। बोल रहा हूं न, सर। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः तो इतनी देर में खड़े क्यों नहीं होते? सदन में सचेत रहें। आप भी सचेत रहें।

बार-अटरू में प्रचलित एवं शामलाती खातों के रास्तों के विवादों का निस्तारण

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रचलित एवं शामलाती खातों के रास्तों के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अन्तर्गत आने वाले किसानों के खेतों में अवागमन हेतु प्रचलित एवं शामलाती खातों के रास्तों को लेकर अधिकांश विवाद होता है। विशेष रूप से एक ही परिवार के सदस्यों में जमीन का बंटवारा होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण खेतों पर आवागमन मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में सहमति से बनाये गये रास्तों को प्रभाव शाली किसान बन्द कर देते हैं। वहीं कई मामलों में खेत खाली रहने पर तो किसान अपने खेत तक पहुंच जाता है लेकिन खेतों में फसल खड़ी होने पर किसान अपने खेत से दूसरे किसानों को नहीं निकलने देते। आवागमन के अभाव मे छोटे किसानों के खेत बंजर रह जाते हैं, या फिर वे सब की फसल कटने के बाद अपनी उपज निकाल पाते हैं जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

प्रायः यह भी देखा गया है कि ऐसे प्रकरणों में किसानों की पीढियां गुजर जाने के बाद भी इस का कोई समाधान नहीं निकलता है। अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि किसानों की पीड़ा को देखते हुए प्रचलित एवं शामलाती खातों के रास्तों के विवादों के निस्तारण को लेकर ठोस कदम उठाये जायें। वहीं केम्प लगाकर ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाये और किसानों को रास्ता देकर उसे राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकित किया जाये।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्रीमती शोभारानी।

धौलपुर शहर में वर्षा जल निकासी हेतु समुचित ड्रेनेज सिस्टम का अभाव

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत प्रस्ताव हेतु आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय को इस सदन के माध्यम से मैं धौलपुर शहर की एक गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराना चाहती हूं।

नगर परिषद, धौलपुर शहर में विगत 10 वर्षो से वर्षा जल निकासी हेतु कोई भी स्ट्राम वॉटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जिससे धौलपुर शहर की 30-35 कॉलोनियों जैसे नारायण शिवनगर कॉलोनी, मानसरोवर कॉलोनी, कमला कॉलोनी, जगदम्बा कॉलोनी, शोभाराम नगर, दारासिंह नगर, लौंगश्रीपुरम कॉलोनी, हुण्डावाल नगर, पुष्पांजली विहार, कॉलोनी फेस 1, 2, 3, मोहन कॉलोनी, प्रकाश कॉलोनी, महाराणा प्रताप कॉलोनी, पोखरा कॉलोनी, ईदा कॉलोनी,

गोविन्द नगर, जगदम्बा कॉलोनी, सुरजीत नगर, महमदपुर, उर्मिला बिहार कॉलोनी, सहमति नगर, नर्सरी रोड़ गोशाला कॉलोनी, अम्बेडकर नगर, गिरीश विहार कॉलोनी, राजा विहार, जिरौली, रीको, शास्त्रीनगर सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, जिरौली का पुरा, जिरौली का अड्डा, गणेश नगर, अयोध्याकुंज, रामकुंज, गोकुल चंदन विहार, सीताराम कॉलोनी, गौशाला, ओमनगर, हाऊसिंग बोर्ड, मित्तल कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी, न्यू आदर्श नगर, मधुवन, मंगल बिहार कॉलोनी इत्यादि कॉलोनियों में सीवरेज ओवर फ्लो एवं अल्प वर्षा होने पर पानी भरा रहता है जिससे आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं उनका आवागमन का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। वर्षा जल का निकास उचित तरीके से नहीं होने के कारण लगभग शहर की 50 प्रतिशत आबादी को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है एवं शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों जैसे बाड़ी रोड एवं भरतपुर रोड पर भी पानी भर जाता है जिससे शहर में आने-जाने वाले आमजन का आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और स्कूल के बच्चों की पढ़ाई और लोगों का व्यवसाय ठप हो जाता है। धौलपुर प्रशासन और नगर परिषद धौलपुर द्वारा भी सन् 2017 में वर्षा जल निकासी हेतु डी.पी.आर. तैयार करवायी गई थी जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास संलग्न है। जिसमें वर्षा जल निकासी परियोजना की लागत लगभग 159 करोड़ (एक सौ उनसठ करोड़) रुपये थी लेकिन नगर परिषद, धौलपुर के पास पर्याप्त मात्रा में बजट की कमी होने के कारण वर्षा जल निकासी का कार्य नहीं कराया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस समस्या के तुरंत निदान हेतु आवश्यक बजट मंजूर करने का श्रम करें एवं धौलपुर शहर की इस समस्या से निजात दिलाने हेतु आरयूआईडीपी (RUIDP) (राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना) के माध्यम से उक्त वर्षा जल निकासी परियोजना के अन्तर्गत मंजूर कराये जाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हरलाल सारण।

Kas/rtm/20.02.2025/12.40/1l

चूरू में पेयजल समस्या

श्री हरलाल सहारण (चूरू): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र आज भी पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल के लक्ष्य के साथ वर्ष 2019 में शुभारंभ किया, जिसकी समयावधि हाल के केन्द्रीय बजट 2025-26 में बढ़ाते हुए 2028 कर दी है। प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उक्त योजना में घोटाला करते हुए आमजन के साथ खिलवाड़ किया। घटिया सामग्री का प्रयोग किया तथा क्षतिग्रस्त सड़कों का पूर्ण रूप से भराव नहीं किया, जिसके कारण कहीं तो पानी पहुंचा ही नहीं और कहीं अकारण ही पानी बहता रहा। इनके द्वारा जल जीवन मिशन का ठेका उन्हीं ठेकेदारों को दिया जिन्हें घोटाला करने का गहरा अनुभव था।

मेरे विधानसभा क्षेत्र चूरू की पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु जल जीवन मिशन के

अंतर्गत निम्नलिखित मांगों को पूर्ण करना अत्यावश्यक है:-

1. गांवों का सर्वे कर उच्च गुणवत्ता के पाइप लाइनें डाली जाएं तथा योजना से वंचित ढाणियों को योजना का लाभ दिया जाए।

2. गांव कुणसिसर, आसलखेडी, चलकोई आदि में टंकियों का निर्माण।

3. सूखे नलकूपों के स्थान पर नए नलकूप स्वीकृत करवाए जाएं।

अतः मेरे विधान सभा क्षेत्र चूरू में व्याप्त पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपर्युक्त मांगों को पूर्ण करवाया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मणराम मेघवाल।

मेड़ता बस स्टैंड की चारदीवारी का पुनर्निर्माण

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि बस स्टेण्ड मेडता हेतु पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के शासन में भूमि आवंटित की गई थी उक्त स्थान पर चारदीवारी एवं एक कमरा ऑफिस हेतु निर्माण भी किया गया था, किन्तु इस स्थान पर बस स्टेण्ड संचालित नहीं होने के कारण चारदीवारी जगह-जगह पर काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा कमरा भी खंडहर हो चुका है। बस स्टैण्ड की इस भूमि पर कई लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया है। वर्तमान में संचालित बस स्टेण्ड में जगह अपर्याप्त है तथा बसों के आवागमन से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे यात्रियों एवं आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे जनहित में आग्रह है कि बस स्टैण्ड हेतु आवंटित भूमि में ऊंची चारदीवारी का निर्माण करवाने तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु बजट आवंटित कर इसी स्थान से बसों का संचालन करने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जेठानन्द व्यास।

बीकानेर संभाग मुख्यालय पर आयुष निदेशालय की स्थापना

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि हमारा राजस्थान देश के उन अग्रणी राज्यों में से एक है, जिनमें आयुष चिकित्सा पद्धति हेतु पृथक से निदेशालय, आयुष शिक्षा के क्षेत्र में देश का प्रथम स्वतंत्र आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित है और प्रत्येक कोने में आयुष चिकित्सा के औषधालय और चिकित्सालय संचालित हैं।

राज्य में आयुष चिकित्सा शिक्षा का अत्यधिक विस्तार हुआ है। राज्य में वर्तमान में राज्य सरकार के अथवा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त 30 से अधिक आयुष शिक्षा महाविद्यालय एवं नर्सिंग महाविद्यालय/पाठ्यक्रम एवं 50 से अधिक निजी आयुष महाविद्यालय व नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है, लेकिन आयुष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक संस्था/निदेशालय के अभाव में राजकीय/निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों पर पूर्ण नियंत्रण

स्थापित नहीं हो पा रहा है।

राज्य में वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में 06 निदेशालय संचालित है, जो कि अपने अपने क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण करते है एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रशासनिक कार्यवाही कर रहे हैं।

अतः राज्य के समस्त राजकीय व निजी क्षेत्र के आयुष शिक्षण संस्थानों को प्रभावी रूप से संचालित किये जाने एवं आयुष चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में प्रभावी प्रशासन स्थापित किये जाने हेतु निदेशालय, आयुष शिक्षा विभाग का गठन प्रस्तावित है।

अतः इस बजट वर्ष 2025-26 में बीकानेर संभाग मुख्यालय पर राज्य में आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निदेशालय आयुष शिक्षा विभाग का गठन किये जाने एवं पूर्व में संचालित हो रहे प्रस्तावित सोसायटी के कॉलेजों को राजकीय कॉलेज में परिवर्तित कराने का अनुरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप लाल गमेती।

गोगुन्दा में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित ग्रामों हेतु सर्विस रोड

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र से नेशनल हाईवे सड़क संख्या 27 गुजरती है, जो कि गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर में गुजरता है। लगभग 100 किलोमीटर पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। इस पर जो हाईवे बनाया गया है वह पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। साथ ही इस हाईवे पर कई उतार-चढ़ाव, कई विकट मोड से होकर गुजरता है। उक्त हाईवे पर कई नाले भी आते हैं, उन नालों पर कई बड़े पुलों का निर्माण भी करवाया गया था। इसके साथ-साथ कई जगह पर सर्विस रोड का भी निर्माण करवाया गया था, मगर जिस समय उक्त नेशनल हाईवे 27 का निर्माण करवाया गया उस समय सड़क हाईवे के आस-पास जो गांव लगे हुए हैं। उन स्थानों पर न सर्विस रोड बनाया गया है ना ही अण्डरपास बनाया गया है, जिससे इस हाईवे पर प्रत्येक दिन दुर्घटना होती है। पिछले 6 माह का आंकड़ा देखा जावे तो प्रत्येक दिन कई जाने गई हैं तथा पिछले 6 माह से हाईवे पर मालवा का चोरा पुलिया पर निर्माण कार्य चल रहा है एवं हाईवे को एकतरफा कर रखा है और जिस स्थान पर निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर बहुत लम्बा ढलान पड़ता है, जिससे लम्बे भारी वाहनों के ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटना होती है तथा दुर्घटना होने के बाद तुरन्त इलाज की आवश्यकता पड़ती है और जिला अस्पताल उदयपुर में है। उसके लिए कम से कम 70 किलो मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इस हाईवे सड़क पर नये सिरे से सर्वे करवाया जावे व अण्डरपास, सर्विस सड़क व ट्रोमा सेन्टर बनाया जावे तथा कार्य में लापरवाही बरतने पर नेशनल हाईवे पर कानूनी कार्यवाही की जावे व जो पिछले 6 माह में मालवा का चोरा स्थान पर जो दुर्घटनाएं हुई है उन सभी को नेशनल हाईवे मुआवजा दे।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार।

ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को विकास राशि

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा के गठन के पश्चात पंचायतों व पंचायत समिति व जिला परिषदों में विकास राशि नहीं भेजी जा रही है। साहब, वही पढूंगा जो लिखा हुआ है, कोई बेइमानी नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पढ़ो ना, मैंने आपको कब टोका? चैक करना तो मेरा काम है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जिससे पंचायतों व पंचायत समिति जिला परिषदों के कार्य में विकास की गति शून्य हो गई है। एस.एफ.सी., टी.एफ.सी. की राशि सरकार भेज ही नहीं रही है और गावों के विकास की कुन्जी पंचायत व पंचायत समिति व जिला परिषदों से ही प्रभावित होता है। सरकार नगरपालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों में पैसा भेज रही है। उल्लेखनीय यह है कि 70 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि गांवों का विकास ..

श्री अध्यक्ष: आगे से पढ़ो, बाकी अंकित नहीं। दांये-बांये होंगे, मुझे पता था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि तत्काल पंचायतों की बकाया राशि खातों में भेजी जावें जिससे गावों विकास की गति बढ़ाई जावें।

श्री अध्यक्ष: बस यहीं तक है। अगला, श्री लादुलाल।

सहाड़ा में जल जीवन मिशन में कार्यादेश

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा भीलवाड़ा (राजस्थान) में जेजेएम (जल जीवन मिशन योजना) में 277 करोड़ के कार्यादेश जारी करवाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र जी मोदी का सपना है, कि हर घर नल यॉजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का है। परन्तु मेरे विधानसभा क्षेत्र सहाडा जिला भीलवाडा राजस्थान में जेजेएम (जल जीवन मिशन योजना) के तहत चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना के फेज द्वितीय पैकेज चतुर्थ (गंगापुर क्लस्टर) के सहाडा रायपुर और भीलवाडा तहसील के 261 गांव लगभग 435 से अधिक ढाणियों के रेटोफिटिंग कार्य की स्वीकृति 25वीं एसएलएसएससी की बैठक दिनांक 02.07.2021 द्वारा राशि 277.00 करोड के टेण्डर तो जारी हो गए, वर्तमान निवीदा मे दिनांक 30.09.2024 को वित्तीय बिड खोली जाकर विभागीय समिति की 889वीं बैठक दिनांक 05.09.2024 में अनुमोदन के पश्चात श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अपेक्स कमेटी में अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। अनुमोदन कि प्रक्रिया में काफी समय लगने से कार्यादेश में बहुत विलम्ब हो रहा है, जबकि पूरे भीलवाडा जिले के कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी होकर काम भी शुरू हो गए तथा कई जगह कार्य पूर्ण भी हो गए हैं। श्रीमान जी मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाडा में पानी की बहुत समस्या है, परन्तु

अब तक मेरे विधानसभा क्षेत्र जल जीवन मिशन योजना से वंचित है। अगर समय से जल जीवन मिशन योजना के अनुमोदन होकर कार्यादेश जारी हो जाएं तो योजना को धरातल पर लाने में समय की बचत होगी तथा जनता कि पानी जैसी विकट समस्या का समाधान हो पाएगा, धन्यवाद।

Kas/rtm/20.02.2025/12.50/1m

श्री अध्यक्षः पर्ची। श्री शंकर सिंह रावत।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जस्ससाखेड़ा से दूधालेश्वर तक सड़क निर्माण

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची पर बोलने का मौका दिया, आपका आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में धुधालेश्वर महादेव से जसाखेड़ा तक सड़क 8 मीटर चौड़ाईकरण के लिये 45 करोड़ का एस्टीमेट था, जिसका मात्र 15 करोड़ ही बजट पास हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसी बजट सत्र में इसमें 30 करोड़ रुपये और पास हो जाये, तो यह सड़क पूरी बन जायेगी, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से अगर आप कहलवा दें तो इसी बजट में पूरी हो जायेगी, यह गत वर्ष का है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री संजीव कुमार।

भादरा में जल जीवन मिशन योजना में अनियमितताएं

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन योजना का आगाज किया था। निश्चित रूप से पूरे देश में उस योजना का लाभ मिलना था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन योजना को शुरू करने में भी अनावश्यक विलंब किया। उसकी वजह से बहुत से काम भी लंबित रह गये और उसमें मेरा भादरा विधान सभा क्षेत्र भी इस अनियमितता से अछूता नहीं रहा। भादरा विधान सभा क्षेत्र में राजनीतिक रंजिश की वजह से अनेक ढाणियों, घरों व गांवों को उस योजना से वंचित कर दिया गया। पाइप लाइन से वंचित कर दिया गया, जल के कनेक्शन से वंचित कर दिया गया और उसके साथ-साथ इस योजना में घटिया और अमानक सामग्री का इस्तेमाल हुआ। योजना में बड़ी भारी अनियमितताएं हुईं, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय भादरा विधान सभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में जिस तरह की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच करवाई जाये और इसके साथ-साथ मेरा यह भी अनुरोध रहेगा कि मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र से करीब डेढ़ दर्जन रिवाइज स्कीमें इस योजना के लिये भेजी गई हैं, तो कृपया करके आप उसमें स्वीकृति प्रदान करें, क्योंकि

2028 तक हमारेप्रधान मंत्री जी ने उस योजना की अवधि को भी बढ़ा दिया है। मैं अनुरोध करूंगा कि उन लोगों को आप लाभ देने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः सरकार के ध्यान में आ गया। श्री हमीर सिंह भायल।

राजस्थानी भाषा को मान्यता

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्थान सहित 14 करोड़ लोगों द्वारा बोली जानी वाली भाषा की मान्यता की मांग पर बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद, आभार। कल 21 फरवरी को सारी दुनिया में विश्व मातृ भाषा दिवस मनाया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के निवासियों का पहला काम अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी को मान्यता दिलवाना है। राजस्थान प्रदेश जब से अस्तित्व में आया है, तभी से राजस्थानी भाषा को मान्यता की मांग आ रही है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, इतनी दूर से न बोलें, पास जाकर बात करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 30 मार्च, 1947 को राजस्थान की सभी रियासतों ने एकीकरण करके वर्तमान राजस्थान का रूप दिया था। राजस्थानी भाषा दुनिया की बढ़िया भाषा में से एक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से अभी तक इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान में जन-जन की यही भाषा है, जबकि भारतीय संविधान में 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। राजस्थानी को शिकागो, मास्को, कैम्ब्रिज में भी पढाई जाती है, तो भारतीय संविधान में मान्यता क्यों नहीं हो सकती है? यह भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से 17 भाषाओं से बड़ी है। राजस्थानी में कई ग्रन्थ, उपन्यास, पुस्तकें छपी हैं। यहाँ तक कि विद्यालयों में भी राजस्थानी विषय हैं। महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी अलग से फेकल्टी है। एक साजिश के तहत राजस्थानी भाषा को विभिन्न भाषा में विभक्त करके इसको मान्यता नहीं दी जा रही है। इसमें हाड़ोती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी, जयपुर आदि भाषाओं में अलग-अलग करके भाषा के साहित्यकारों, यथा वो लोग जो राजस्थानी को मान्यता नहीं दिलवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): दो मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्षः पर्ची पर बोलते हैं, लिख कर थोड़े ही लाते हैं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): उन्होंने इस भाषा राजस्थानी को विभक्त करके पेश किया है। जबकि राज्य विधान सभा द्वारा 2003 में प्रस्ताव केन्द्र को भेज रखा है। केन्द्र ने ओडीसा के वरिष्ठ साहित्यकार एस.एस. महापात्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसने दो साल बाद इस भाषा की अनुशंसा भी की है कि राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जावे। वर्ष 2006 में तत्कालीन गृह मंत्री जी ने लोकसभा में भी आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक राजस्थानी को मान्यता नहीं मिली है।

श्री अध्यक्षः श्री अरुण चौधरी। हो गया, चार मिनट हो गये, अंकित नहीं। आप सभापति

भी हैं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

पचपदरा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की खराब सड़कों की स्थिति के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सिमरखिया, मेगावास, मंडली, गंगावास कोरना आगोलाई रोड और पादरू फाटा से बुड़ीवाड़ा जागसा पादरू बावतरा रोड को स्टेट हाई-वे के अंतर्गत लिया जाये, क्योंकि इस रोड पर काफी यातायात रहता है। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र की कल्याणपुर से डेमो की ढाणी, कल्याणपुर से धौला भाटा चुना भाटा, जसोल से तिलवाड़ा, पारलू, काकराला, सरूपरा, मुंगड़ा भिटूजा, आसोतरा, ब्रह्मा जी का मन्दिर, आकड़ली बक्शीराम से सुथारो की ढाणी, चंदेसरा से बटाला पुरोहितान, वरीया तग़जी से वरिया भगजी, ब्लाउ जाति से बलाणिया, दुधवा से दुधवा डेर, दुधवा से बडला, गोल स्टेशन एवं तिलवाड़ा के बीच बंद हुए संपर्क अंडरपास को अति शीघ्र बनाने के लिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री विकास चौधरी, पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन, एक मिनट में।

सूचना

किशनगढ़ में दलित युवती की हत्या

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन के माध्यम से इस गंभीर विषय पर बात रखने का अवसर दिया, आपका आभार प्रकट करता हूं। आपके गृह जिले अजमेर की किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बोराला पुलिस थाने के अंतर्गत धसू ग्राम पंचायत के पांडरवाला गांव में कल शाम को दलित समाज की बेटी की गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या करना, एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय हमारे सामने आया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 20 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी अस्पताल में पूरा परिवार धरना दे रहा है और शव मौर्चरी में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार निवेदन करूंगा कि पीड़ित परिवार के साथ त्वरित न्याय करें और उस बैरवा समाज की बेटी के साथ न्याय करें, धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सरकार कार्यवाही करें। कल मर्डर हुआ है, सब लोग धरने पर हैं। इस पर सरकार कुछ संज्ञान लें।

श्री अध्यक्ष: सरकार ने संज्ञान में ले लिया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): किसी पर जवाब ही नहीं है सरकार का।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 14.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

MLS/RTM/20.02.2025/14:00/2c

(समयः 14:00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः जय सिया राम। राम-राम। विराजिये। श्री जोगेश्वर गर्ग। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 9)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के नौवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2025 को मध्याह्न पश्चात् 01.50 बजे माननीय अध्यक्ष के वेशम (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 2025 से गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2025 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:-

गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 2025 शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2025	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद।
शनिवार, दिनांक 22 फरवरी, 2025 रविवार, दिनांक 23 फरवरी, 2025	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2025 मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2025	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद।
बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2025	बैठक नहीं होगी।
गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2025	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नौवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नौवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्रीमती मंजू बाघमार।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनएं

वित्त (कर) विभाग

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (कर) विभाग की 10 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2025-107 दिनांक 19.02.2025, एस.ओ. 120 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार, किसी राजकीय उपक्रम या प्राधिकरण द्वारा खातेदार या भू-स्वामी के पक्ष में, उसकी भूमि के अर्जन के बदले में, आवंटित विकसित भूमि के अन्तरण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है;

2. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2025-108 दिनांक 19.02.2025, एस.ओ. 121 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत ऋण हेतु निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के परिहार के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है;

3. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2025-109 दिनांक 19.02.2025, एस.ओ. 122 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत पति और पत्नी के पक्ष में संयुक्त रूप से निष्पादित पचास लाख रूपये तक की स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण लिखत पर स्टाम्प शुल्क में रियायत के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है;

4. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2025-110 दिनांक 19.02.2025, एस.ओ. 123 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9-क के अन्तर्गत बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट हेतु एमनेस्टी योजना के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है;

5. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2025-111 दिनांक 19.02.2025, एस.ओ. 124 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत रिप्स-2024 के अन्तर्गत विक्रय, पट्टे या उप-पट्टे की लिखत पर स्टाम्प शुल्क में रियायत के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है;

6. अधिसूचना संख्या: प.12(7)वित्त/कर/2025/121 दिनांक 19.02.2025, एस.ओ. 125 जिसके द्वारा निरसित अधिनियमों के लिये एमनेस्टी स्कीम, 2025 के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है;

7. अधिसूचना संख्या: प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 19.02.2025, एस.ओ. 126 जिसके द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 200 के अन्तर्गत खान विभाग के ई-रवन्ना की सूचना के आधार पर कारित अतिभरन के मामलों में प्रशमन राशि की दरों में रियायत के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है;

8. अधिसूचना संख्याः प.6(179)परि/कर/मु./2025/1 दिनांक 19.02.2025, एस.ओ. 127 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 6(1) के अन्तर्गत समय से कर जमा नहीं कराने वाले वाहनों पर देय शास्ति की दर को विनिर्दिष्ट करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है;

9. अधिसूचना संख्याः प.6(179)परि/कर/मु./2025/2 दिनांक 19.02.2025, एस.ओ. 128 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 22 के अन्तर्गत राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 2(ढ) एवं 26-क में संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है; एवं

10. अधिसूचना संख्याः प.6(179)परि/कर/मु./2025/3 दिनांक 19.02.2025, एस.ओ. 129 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत नष्ट हो चुके वाहनों हेतु एमनेस्टी के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है।

श्री अध्यक्षः डॉ. मंजू बाघमार।

सांख्यिकी विभाग

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सांख्यिकी विभाग की निम्नांकित अधिसूचना सदन की मेज पर रखती हूंः-

अधिसूचना संख्याःएफ.13/1/3/रूल-2024/वीएस/डीइएस/2024/107, दिनांक 31.01.2025 एस.ओ. 118 जिसके द्वारा राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्षः वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्रीमती मंजू बाघमार।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य महिला आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1999-2000 से 2024)

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 14(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य महिला आयोग के वर्ष 1999-2000 से 2024 तक के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्षः श्री जोगाराम पटेल।

लोकायुक्त राजस्थान का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(4) के अन्तर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन (01.01.2024 से 31.12.2024) मय स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (वर्ष 2023-24)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2023-24;

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24;

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का

24वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2023-24)

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2023-24; एवं

राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड

का नवम वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

4. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड का नवम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, डॉ. मंजू बाघमार।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञ प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान माल और सेवा

कर अध्यादेश, 2024 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025, जोगाराम जी।

राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन में लगे आइपैड्स का नाजुक उपकरण होने के कारण अपेक्षित सावधानी से उपयोग

श्री अध्यक्ष: अपने वाद-विवाद से पहले एक जो जानकारी देनी थी कि अपनी सबकी सीटों पर ये आईपैड टैबलेट्स लगे हैं। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं, काफी कहने के बावजूद भी उनका उपयोग ढंग से नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग तो इसे स्टैंड के रूप में काम में ले रहे हैं। उस पर रखकर पढ़ते हैं, उस पर दबाव रखते हैं। चार लोगों के तो टूट चुके हैं, जो मुझे वापस उन्हें रिपेयर कराना पड़ा है। ये स्टैंड नहीं हैं, जरा टैक्निकल हैं, डिजिटल हैं। मैं नाम नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन नाम भी मेरे पास हैं।

कुछ लोग जो इन्हें लॉक करके जाते हैं, कोई भी इन्हें लॉक करके न जाये, नहीं तो इसमें कुछ पुट ही नहीं होगा। फिर लॉक करने के अलावा एक समस्या और है। लोग इसे हटाकर फोन कनेक्शन से चार्ज करने लग जाते हैं। यह फोन कनेक्टर नहीं है भई। अपन सब समझदार हैं। बार-बार मुझे सदन में ये बातें दोहरानी पड़ें, यह ठीक नहीं है। मेरी तीनों बातें हैं। कोई भी सदस्य लॉक करके न जाये, इनके साथ फोन कनेक्ट न करे और स्टैंड के रूप में इनका उपयोग न करे। ये नाजुक चीजें हैं। जब इन्हें हिलाएं-ढुलाएं, जैसे अपन घर की चीज को करते हैं, नहीं तो बार-बार, यह कोई सस्ती चीज नहीं है, बड़ी मुश्किल से, 16-17

करोड़ रुपये अपन ने खर्च किये हैं। ...(व्यवधान)... अभी आसन पांवों पर है।

मैं कुछ और व्यवस्था दूं, उसकी तुलना में, मेरा आप सब सदस्यों से कहना है, मैं रिकॉर्ड भी रख रहा हूं, कौन एक दिन में या एक घण्टे में कितनी बार खड़ा हो रहा है। अपन यहां आये हैं, कोई विशेष बात कहनी हो, जरूर अनुमति लेकर एक बार खड़े हों, दो बार खड़े हों, लेकिन यदि हर मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में कोई खड़ा होगा तो मैं समझता हूं, सदन की गरिमा भी कमजोर होगी। चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो। विपक्ष में से भी हैं।

दूसरा, यहां बैठे-बैठे बोलते भी हैं और फिर अपनी सीट से इतनी जोर से बोलते हैं कि आवाज यहां तक आती है। दो लोगों को आपको आपस में बैठकर बात करनी है, आप नजदीक से करिये, कोई मना नहीं है, लेकिन इतनी आवाज नहीं हो कि सदन गूंजे। सदन में आपको जनता ने चुनकर भेजा है। अपने नेचर या आदतों को बदलिये। सदन के अनुरूप रखिये। यह मेरा सबसे आग्रह है, निवेदन है। बैठे-बैठे, जो पहली बार आये हों, उनको तो मैं समझाऊं, लेकिन दो-दो, चार-चार बार के सदस्य हों और वे बैठे-बैठे बोलें, चाहे आप कितने भी ज्ञानवान होंगे, लेकिन आपका ज्ञान आप तक रखें, सही जगह पर उस ज्ञान का उपयोग भी करें। सदन में जब अनुमति दी जाये, पूरा ज्ञान आप बिखेरें। हम भी आपको सुनेंगे, आपसे मार्गदर्शन लेंगे। इन दो-चार बातों का अपन ध्यान रखेंगे तो सदन ठीक ढंग से चलेगा, अच्छी तरह चलेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस बात पर चिन्ता प्रकट की, वह वास्तव में एक चिन्तनीय विषय है। आपस में बैठकर हम बातें करते रहते हैं, जोर-जोर से बोलते हैं, उससे सदन की कार्यवाही बाधित होती है और कई बार लोग खड़े-खड़े भी बात करते हैं। बार-बार खड़े हो जाते हैं, उससे भी व्यवधान होता है। आपकी इस बात को सत्तापक्ष गम्भीरता से लेता है और मैं एक सचेतक के नाते आपको आश्वस्त करता हूं, सत्तापक्ष के सारे विधायक आपके निर्देशों का पालन करेंगे।

mkd/rtm/20.02.2025/14:10/2d

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मैं समझता हूं, दोनों सचेतक इसका ध्यान रखें। उनका कोई सदस्य इस तरह करे तो तुरन्त जाकर उन्हें रोकें। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। यह मेरा सब से आग्रह है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम तो बोलते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलते हैं तो रुकते नहीं हैं। बैठिये, श्रवण कुमार जी।

घोषणा

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

मुझे सदन का सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 20 घंटे, यह पहली बार है, हमेशा तीन दिन बहस होती है, चौथे

दिन रिप्लाई होता है। इस बार सदस्यों के आग्रह पर कि साहब बजट पर हम लोग भी बोलना चाह रहे हैं, संख्या अधिक हो जाती है तो उस नाते इस बार चार दिन बहस होगी और पांचवें दिन इसका जवाब आयेगा, जैसा सलाहकार समिति ने किया है, ताकि अधिक से अधिक लोग बोल सकें। उसके तहत पार्टियों के समय का बंटवारा इस प्रकार है।

क्र.सं.	पार्टी/दल का नाम	आवंटित समय
1.	भारतीय जनता पार्टी (119)	11 घण्टे 54 मिनट
2.	इंडियन नेशनल कांग्रेस (66)	6 घण्टे 36 मिनट
3.	भारत आदिवासी पार्टी (04)	24 मिनट
4.	बहुजन समाज पार्टी (02)	12 मिनट
5.	राष्ट्रीय लोक दल (01)	6 मिनट
6.	निर्दलीय (08)	48 मिनट
कुल आवंटित समय		20 घंटे

इसके अनुसार ही अपन अपना समय आवंटित करें। यदि ज्यादा लोगों को बुलाना चाह रहे हो तो कम समय दो और यदि ज्यादा समय देते हो तो फिर आपके लोग कम बोलेंगे, इसमें कोई वृद्धि, आग्रह, दुराग्रह न हो और एक समय भी तय कर लें, शादियां भी बहुत हैं, सभी जाना भी चाहते हैं। आज भी जो संख्या और समय, आप लोगों ने लिखा है, उस हिसाब से साढ़े आठ-नौ आज भी बज रहे हैं और कल शुक्रवार भी है। इसलिए मैं सोचता हूं कि या तो संख्या समिति करें या फिर जो है, समय आप कम निर्धारित करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, लंच टाइम आधा घंटा कर दें।

श्री अध्यक्ष: लंच के बाद आपके लोग अब घर से आये हैं, बाद में विचार करेंगे, आपके सुझाव चैम्बर में दे देना। अब कल जैसे मैंने व्यवस्था दी थी कि पिछली बार विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया था, फोन टैपिंग वाले पर, उस पर सरकार अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करे। माननीय जोगाराम जी, आप करेंगे या बेढ़म जी करेंगे। गृह राज्य मंत्री जी, नहीं एक ही करेगा।

शासकीय वक्तव्य

किरोड़ी लाल, श्री, मंत्री के कथित फोन टैपिंग का प्रकरण

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): हममें तारतम्य है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि अधिकृत एजेंसियों द्वारा वर्षों से टेलीफोन इंटरसेप्शन, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता रहा है। वर्ष 2023 में केन्द्र सरकार द्वारा दूरभाष अधिनियम, 2023 टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पारित किया गया, जो 21 जून, 2024 को लागू हुआ। वर्तमान में टेलीफोन इंटरसेप्शन इस अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है। दोनों ही कानूनों में राज्य की सुरक्षा हेतु लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपराधों को रोकने जैसे अति

महत्वपूर्ण कार्यों के लिए टेलीफोन इंटरसेप्शन अनुमत किया गया है।

केन्द्र सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दूरसंचार संदेशों के विधिपूर्ण अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय नियम, 2024 को दिनांक 8 दिसम्बर, 2024 को अधिसूचित किया है। इस विशेषाधिकार का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कानून एवं नियमों में ही सभी आवश्यक प्रावधान निहित हैं, जिनकी सदैव कड़ाई से पालना की जाती है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य में इंटरसेप्शन किये जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग सक्षम प्राधिकारी हैं, जो अधिकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रेषित एवं निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों के आधार पर ही इंटरसेप्शन किये जाने के आदेश देते हैं। ऐसे इंटरसेप्शन आदेशों को रिव्यू किये जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग व प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग भी सदस्य हैं। रिव्यू समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार आयोजित किये जाने का भी प्रावधान है।

कुछ दिन पूर्व मीडिया के माध्यम से माननीय श्री किरोड़ी लाल मीणा जी, जो हमारे मंत्री महोदय हैं, का एक बयान संज्ञान में आया, जिसमें उन्होंने, उनके मोबाइल फोन सर्विलांस की बात उसमें छपी है। विपक्ष ने इस बिन्दु पर सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जबकि स्वयं किरोड़ी लाल मीणा जी द्वारा इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है।

मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ी लाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष: अब हो गया। आप दो मिनट बोल लो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जवाब से हम संतुष्ट हैं। बात यह आती है कि जब आपके कैबिनेट मंत्री ने आप पर आरोप लगाये और आपने कहा आप फोन टेप नहीं कर रहे हैं तो आप उस पर कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे पहली बात। आप उस पर कार्यवाही करिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हो रहा था, उससे पहले भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाये गये थे कि मुख्य मंत्री जी को मेरे ऊपर संशय है कि मैं उस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी हुड़दंग करवा सकता हूं। यह बात भी उनके द्वारा मीडिया के अन्दर आ गई थी तो मेरा आपसे आग्रह है कि दो बातें नहीं हो सकतीं, जब कैबिनेट मंत्री ने आपको इस्तीफा दे रखा है और वह आपको कह रहा है कि मेरे फोन टैप हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उसको नोटिस दिया है, उन्होंने नोटिस में यह नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, नोटिस में उन्होंने यह कहा है कि मुझे ये बातें सार्वजनिक स्तर पर नहीं कहनी चाहिए थीं, उन्होंने यह माफी नहीं मांगी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने जो

रिप्लाई भेजा है, उसमें उन्होंने यह नहीं कहा कि मैंने गलत आरोप लगाये हैं। उन्होंने यह कहा कि मेरे पास इनपुट है, तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मालिक हैं यहां सदन के, विधान सभा चल रही है और मुझे बड़ा दुःख हुआ, आपने पूरे दिन की कार्यवाही उस दिन बाधित कर दी। आप बाहर मीडिया में आकर, गृह राज्य मंत्री यह बात बोलकर आये कि हम फोन टैप नहीं करवा रहे, और, यह बात यहां कह देते तो हल्ला ही नहीं मचता और आप मेरी स्पीच जो है, पूरी उसके अन्दर आप लोगों ने वह करवा दी कि भाई टीकाराम जूली बोलेगा तो सरकार को धोयेगा।

श्री अध्यक्षः चूंकि आपने मेरे को किया है तो स्थिति बता दूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपको नहीं किया साहब, आपको नहीं किया। आपसे तो आग्रह है।

श्री अध्यक्षः सारे दिन स्थगित करने से पूर्व मैंने दो बार विपक्ष को बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया और जब विपक्ष नहीं आया तब मैंने आखिरी सवा तीन बजे और स्थगित करके, ताकि आपका भाषण हो, आपका भाषण नहीं हो, ऐसी कोई न तो मेरी मंशा थी न शायद पक्ष की रही होगी। आप लोग आयें, बोलें और अभी भी चाह रहा हूं। आपने अपनी बात कह दी, इन्होंने कह दी, अपन सदन चलायें, अच्छा चले।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके लिए तो कहा ही नहीं, सरकार की मंशा थी। आप तो चाहते थे, प्रतिपक्ष बोले लेकिन आपके कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं बोलूं और मुख्य मंत्री का भाषण भी शान्तिपूर्वक हो। मेरा आपसे आग्रह है..। ये देखो..। ..व्यवधान..

(श्री संजय शर्मा, राज्य मंत्री, वन द्वारा सदन में तख्ती लहराई गई।)

श्री अध्यक्षः श्रीचन्द जी, मैंने आपको दस बार कहा है। आप विराज जाया करो। यह मेरा काम है। मैं इनको सम्भालूं या आपसे बात करूं? मंत्री जी, नीचे। मंत्री जी, ये नहीं। यहां पर कोई कार्ड, फ्लैग सदन में नहीं होगा और जब मंत्री जी करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। नो, इधर भी नहीं, कोई इधर भी करता है तो गलत है, कोई नहीं बोलेगा, इनकी बात हो गई। अब सदन की बहस शुरू करते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मंत्री का इस प्रकार से यहां पर, आप सुबह तो धारीवाल जी को अख़बार के लिए मना कर रहे थे और मंत्री खुद यहां पर किस प्रकार, ये तख्तियां विधान सभा में अलाउड है या नहीं है? यह क्या गदर मचा रखा है सरकार ने, नहीं तख्तियां अलाउड हैं क्या, संसदीय मंत्री बता दें, तख्ती अलाउड है? आपका मंत्री तख्तियां लेकर आता है। यह मंत्री का व्यवहार है? मंत्री तख्तियां लेकर आ रहा है।

श्री अध्यक्षः सब लोग अपनी सीटों पर बैठें। शान्तिपूर्वक सदन चले, सहयोग करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि सरकार अगर किरोड़ी मीणा जी का आपने फोन टैप नहीं किया तो आपने जवाब दे दिया और जवाब जो दिया तो फिर क्यों न मीणा जी पर आप कार्यवाही करिये। आप उनको इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इस कार्यवाही पर बहिर्गमन करते हैं।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्षः सरकार ने स्पष्टीकरण कर दिया है। सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मैं बर्दाशत नहीं करूंगा। I am sorry to say, माननीय सचेतक महोदय, संसदीय मंत्री, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर विपक्ष को क्या कहूंगा? सदन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, सत्ता पक्ष का इसमें रोल होता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सर, हम सब माफी चाहते हैं।

श्री अध्यक्षः मैं कहूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं-नहीं, हम माफी चाहते हैं। अब नहीं करेंगे।

Bhs/Rtm/20.02.25/14.20/2e

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सरकार का वक्तव्य दिलाया। सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कथन किया गया विधान सभा के पवित्र सदन में कि ऐसा फोन टेपिंग करना वर्तमान कानून के अनुसार सम्भव ही नहीं है और वास्तव में भी कोई नहीं किया गया है। जहां तक प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने आरोप लगाया कि अगर यह बात थी तो उसी दिन कह देते, मेरा अभिभाषण नहीं हुआ। यह कांग्रेस अन्तर्कलह से जूझ रही है। न इनके पास वीजन है न इनके पास कोई दिशा-निर्देश है सिर्फ अपनी बात झेंप मिटाने के लिए आरोप लगाये जा रहे हैं। मैं आक्षेप लगाता हूं प्रतिपक्ष के नेता पर कि अगर उनके पास फोन टेपिंग का कोई मैटेरियल नहीं है तो किस आधार पर पूरे दिन सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, बिना कोई मैटेरियल, बिना कोई लॉजिक। वे माफी मांगें और नहीं तो विधान सभा की प्रक्रिया के अनुसार बिना नोटिस दिये सीधे ही आपके वेश्म में कही गई बात को विदड्रा करके गलत कार्यवाही की है इसलिये प्रतिपक्ष को पूरी प्रताड़ना भी देनी चाहिये, यह मेरा आपसे अनुरोध है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हो गया। आपके संसदीय मंत्री ने जो कुछ कहा है मैं सोचता है कि अब इस पर पर्याप्त चर्चा हो गई, आपका स्पष्टीकरण आ गया, आपके मंत्री महोदय ने भी अपनी बात रख दी है। विपक्ष को भी इस पर विश्वास करना चाहिये, सरकार ने जब सदन में कहा है तो मैं समझता हूं कि इस विषय का यहीं पटाक्षेप करते हैं और आज बजट पर जो बहस शुरू होनी है उसको शुरू करते हैं। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2025-26 के आय-व्ययक पर चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 फरवरी को राजस्थान का जो बजट आया है वह मैं

समझता हूं कि बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है जिसमें उन्होंने युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, आमजन को और पूरे राजस्थान के विकास को सम्मिलित करते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह बजट है जिसमें सरकार ने किसी प्रकार के टैक्स का कोई प्रावधान नहीं रखा है, इन फेक्ट इन्होंने छूट दी है। ऐसी कई स्कीम्स हैं माइनिंग पर हो, एक्साइज पर हो, या जी.एस.टी. पर हो, एमनेस्टी स्कीम लागू करके उनका वन टाइम सेटलमेंट करके उनके पेनल्टी, इंटरेस्ट माफ करके उनको रियायत दी है। उसके बावजूद राजस्थान का जो हमारा बजट है, अगर आप उसका जी.एस.डी.पी. देखें तो वह 19.8 करोड़ पहुंच गई है जो आपके टाइम में मात्र 4-4.5 परसेंट की ग्रोथ की है हमने एक वर्ष में लगभग 16.75 प्रतिशत की ग्रोथ राजस्थान की जी.एस.डी.पी. में की है।

(समय : बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति पदासीन।)

सभापति महोदय, दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि अगर एक्चुअल आर.ई. देखें आप तो हमने लगभग 30 प्रतिशत जो हमने बजट पेश किया 2024-25 उसमें जो बजट एट ए ग्लांस पेश किया था उसमें हमारा 30 प्रतिशत से ज्यादा एनुअल प्लान बढ़ा है और यह जो बजट हमने पेश किया है यह लगभग 15 प्रतिशत प्रिवियस बजट से हमारा प्लान बढ़ा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इस पूरे बजट को हम देखें तो हमारा जो बजट पर कैपिटल एक्सपंडीचर है वह लगभग 40 प्रतिशत है। आपका कैपिटल एक्सपंडीचर जो आपका लास्ट बजट था 2023-24 में उसमें लगभग 23 हजार करोड़ के आस-पास आपका कैपिटल एक्सपंडीचर था और हमारा यह जो कैपिटल एक्सपंडीचर बजट का है वह लगभग 57 हजार करोड़ का है इससे साफ जाहिर होता है कि कैपिटल एक्सपंडीचर के तहत हमने पूरे राजस्थान में भले ही वह रोड का इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो, ईरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पानी की स्कीम्स हो, मेडिकल एंड हैल्थ हो, रूरल डवलपमेंट हो, अरबन डवलपमेंट हो या कोई भी विकास की दृष्टि से राजस्थान में जो कैपिटल एक्सपंडीचर का ग्रोथ हमने किया है पिछले एक साल में वह आने वाले टाइम में मील का पत्थर साबित होगा राजस्थान में।

सभापति महोदय, आपके पूरे पांच साल के कार्यकाल में तीन साल तो आपने खाली घोषणाएं ही कीं और घोषणाएं करके उसमें अधिकांश बजट क्रियान्वित किया ही नहीं। हमारा पहला बजट जो था उसमें 73 प्रतिशत हम आज जमीन पर लेकर के आ गये और हमारी जो जन घोषणाएं थीं, जो इलेक्शन लड़ने से पहले हमने जो घोषणा पत्र बनाया था उसमें से लगभग 58 प्रतिशत घोषणाओं पर हमने काम प्रारम्भ कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने जो पहला बजट दिया, मैंने भी नहीं सोचा था कि यह पहला बजट इतना बड़ा बजट होगा। मैं समझता हूं कि जितने भी सदस्य विराजमान हैं दो विधान सभा क्षेत्र जो हैं उनमें हर एक में बजट में कोई न कोई रोड मिली होगी, स्कूल मिला, हॉस्पिटल मिला होगा, कॉलेज मिला होगा, पानी की स्थिति में सुधार मिला होगा और

इस बजट में पूरा एट ए ग्लांस पूरे राजस्थान को उन्होंने कवर किया है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आपके टाइम में आपने बजट को पहले तीन साल में तो लागू किया नहीं और लास्ट में, दो साल में आपने कैपिटल एक्सपंडीचर पर तो ध्यान दिया नहीं। आपने तो लोन लेकर रेवड़ियां बांटने का काम किया। लास्ट में आपको याद आया जब आपने लोगों को मोबाइल देना स्टार्ट किया। अन्नपूर्णा योजना के तहत हमारी रसोई चल रही थी उसको आपने तीन साल तो बन्द कर दी लास्ट में आपने इन्दिरा गांधी रसोई योजना से प्रारम्भ किया। इससे पहले बिजली में हमने 17 सौ रुपये प्रत्येक दो महीने के माफ किये थे, आपने तीन साल तक जो बिजली के बिल माफ हुए थे लोगों के वो आपने बन्द कर दिये। बन्द करने के बाद आपने लास्ट में इलेक्शन आने से पहले आपने 6 महीने पहले 2000 यूनिट माफ किये।

सभापति महोदय, हमारे टाइम में हमने 50 यूनिट बिजली माफ की थी, आपने आने के बाद में लास्ट 6 महीने में 100 यूनिट माफ की। आपने जाते-जाते गैस सिलेंडर में 500 रुपये माफ करने की बात की पर आपके टाइम में गैस सिलेंडर में आपने कोई पैसा माफ नहीं किया। मुख्य मंत्री भजन लाल जी की सरकार में 450 रुपये में सिलेंडर देने का काम हमने किया है। आपने तो खाली घोषणा ही की थी। आपने लास्ट में खाद्य किट बांटने का काम किया है वह खाद्य किट ऐसा था कि गरीब आदमी उसको घर ले जाने का तैयार नहीं था। उसका तेल बदबू मारता था और जो दाल आपने दी थी उस दाल में सड़न पैदा हो रही थी। वह जो किट आपने दिया था वह गरीबों के साथ एक मजाक किया था। आपने तो लास्ट में जाते-जाते किसी प्रकार से महानरेगा शहरी योजना शुरू की तो ये आपको पांच साल मिली थे, पांच साल में अगर आपने पहले शुरू कर दी होती तो हो सकता हम वापस वहीं बैठते। आपने तो जाते-जाते प्रारम्भ की है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्य मंत्री जी को कि जिस दिन से पहला बजट पेश किया है उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं भी स्टार्ट की। पेन्शन हम जो 1000 रुपये दे रहे थे उसको 1150 रुपये की और इस बार बजट में घोषणा कर 1250 कर दी। मुझे आज भी मालूम है, मैं जब वहां बैठता था तो सबसे बड़ी तकलीफ गांवों में थी, लोगों को एन.एफ.एस.ए. में नाम नहीं जुडता था, खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्य मंत्री जी को कि आज फिर से प्रारम्भ हो गये। आज गांवों में जो गरीब आदमी है, जो विधवा है, बेरोजगार है, जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, आज उसको एन.एफ.एस.ए. में वापस उसका नाम जोड़ने का काम प्रारम्भ है और दस लाख यूनिट आज हमारे एन.एफ.एस.ए. में नाम जुड़ रहे हैं।

सभापति महोदय, पेन्शन हमने बढ़ाई। आज हम गैस दे रहे हैं 450 रुपये में। आपने तो घोषणा की थी 2 हजार यूनिट माफ करने की परन्तु 2 हजार यूनिट आज हम दे रहे हैं। 2 हजार यूनिट के पैसे माफ कर रहे हैं हम भुगत रहे हैं, सरकार भुगत रही है। हम ऊर्जा विभाग को सब्सिडी दे रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने तो खाली एक वाहवाही

लेने के लिए बजट में लास्ट में घोषणाएं की। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जल जीवन मिशन, जो मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी,

Msk/rtm/20.02.25/1430/2f

जैसे उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत हर घर को रोशनी दी। उन्होंने हर गरीब जिसके कच्चा मकान है, उसका पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रखी। इसी प्रकार उन्होंने ऐसे कई काम, उज्जवला योजना के तहत गरीबों को गैस कनेक्शन देने, इसी प्रकार जल जीवन मिशन के तहत पूरे हिन्दुस्तान में प्रत्येक घर को हम शुद्ध पेयजल देने, आप शुरू में दो साल तो करते रहे कि 90-10 होना चाहिए, 90 परसेंट तो केन्द्र सरकार दे, 10 परसेंट राज्य सरकार दे। फिर आपको लगा कि पूरे देश में 50-50 परसेंट है तो हमको उसमें जाना पड़ेगा। अंतिम तीन साल में तो आपने काम प्रारंभ किया, जिससे राजस्थान बहुत पीछे रह गया। आपने जो काम प्रारंभ किये, केन्द्र सरकार का पैसा, राजस्थान सरकार का भी पैसा, आपने ऐसे टेण्डर किये, आज आप जल जीवन मिशन की हालत देखें, आपके कार्यकाल में जल जीवन मिशन में जहां-जहां काम हुए हैं, उनमें खाली भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिखता है। पाइपलाइनें हैं ही नहीं, पाइपलाइन के पैसे उठ गये। पाइपलाइन एक फीट नीचे है, कहीं पाइपलाइन दो फीट नीचे है। आपके पास सोर्स नहीं है। मैं हमारे देश के प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर घर को शुद्ध पेयजल पहुंचाने की यह जो महत्वाकांक्षी योजना थी, उन्होंने 2028 तक इसको एक्सटेंड किया है, ताकि आने वाले समय में 20 लाख कनेक्शन हमारे लोगों को मिल सकें, 20 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन आम जन को मिल सकें।

मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने शहरी क्षेत्र पर भी पूरा ध्यान दिया है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में लोड बढ़ रहा है, शहरी क्षेत्र में अमृत-2 योजना के तहत इन्होंने 5103 करोड़ से प्रत्येक नगर निकाय को जोड़ा है, ताकि आने वाले समय में अरबन क्षेत्र में भी पानी मिल सके। जिस तरह से अरबन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, अरबन क्षेत्र बढ़ रहा है, उसको शुद्ध पेयजल कैसे दिया जाये, उसके लिए उन्होंने अमृत-2 के तहत 5103 करोड़ का 181 नगर निकायों के लिए बजट में प्रावधान रखा है।

साथ ही, जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र में भी उन्होंने प्रारंभ करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने बजट का प्रावधान 5800 करोड़ रुपये रखा है, जो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे अरबन क्षेत्र में, जिस तरह से लोग माइग्रेट होकर अरबन क्षेत्र में बसते हैं, जिस तरह से शहर बढ़ रहे हैं, 25 साल पहले जयपुर की पापुलेशन 30 लाख से ज्यादा नहीं थी। आज अगर जयपुर की पापुलेशन अगर हम माने तो मैं समझता हूं कि 80 लाख से ऊपर पापुलेशन होगी। 2001-2002 में जयपुर की 30 लाख से ज्यादा पापुलेशन नहीं थी, पर

पिछले 20 साल के अन्दर जिस तरीके से जो माइग्रेशन हो रहा है। जिस तरीके से लोग रूरल एरिया से अरबन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, हर छोटा-मोटा कस्बा दिनोंदिन बढ़ रहा है, उस पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने पूरा ध्यान दिया है और ध्यान देकर मुख्य मंत्री जी ने शहरी जल जीवन मिशन योजना 5800 करोड रुपये की रखी है। पूरे क्षेत्र में 1 हजार ट्यूबवैल और 15 सौ हैंडपम्प आने वाले टाइम को ध्यान में रखते हुए रखे हैं। कंटीजेंसी के तहत गर्मी के टाइम को ध्यान में रखते हुए 142 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। कंटीजेंसी में कहीं भी कोई ट्यूबवैल फेल हो जाये, कुआं खुदवाना पड़े तो तुरन्त प्रभाव से हम उसको खोद सकें।

सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हम इस बजट को देखें तो यह बजट तीन-चार चीजों पर इम्फेसाइज करता है। सबसे पहले इस बजट में आपने कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं करने के बाद भी रेवेन्यू जनरेट किया है। रेवेन्यू जनरेट करके सुनिश्चित किया है कि हमारी योजना का कार्य पूर्ण हो सके। दूसरा, अगर हम देखें तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने अरबन डवलपमेंट पर पूरा ध्यान दिया है। अरबन एरियाज पर पूरा ध्यान दिया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, एलिवेटेड रोड हो, आर.ओ.बीज. हों, आर.यू.बीज. हों, सिटीज में फ्लैट्स बनाने में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, इसी प्रकार उन्होंने अरबन क्षेत्र का भी पूरा ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़े बजट का प्रावधान रखा है, जो मैं समझता हूं कि आपने अपने कार्यकाल में पहले कभी इस पर ध्यान दिया नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय शहरी क्षेत्र विकास के लिए उन्होंने लगभग साढ़े 12 हजार करोड़ का प्रावधान रखा है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे अरबन क्षेत्र में लोगों की जो जिन्दगी है, उसमें काफी सुधार आयेगा।

तीसरा, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान एक पहला प्रदेश होगा, जिसने ग्रीन बजट दिया है। ग्रीन बजट 27 हजार करोड़ से ऊपर का बजट है और यह वेरियस डिपार्टमेंट्स को कवर करता है। आज हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमको जो रिसोर्सेज दिये हैं, उन रिसोर्सेज के तहत आज हम अच्छी जिन्दगी जी रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि आज अगर हम जलवायु परिवर्तन का देखें। सभापति महोदय, अगर आप पिछली गर्मी देखें तो गर्मियों में हमारा टेम्प्रेचर 50 डिग्री तक पहुंच गया था। 100 साल में कभी इतना बड़ा टेम्प्रेचर नहीं पहुंचा। इस साल की सर्दी अगर आप देखें। हमारे यहां दो-तीन महीने तक सर्दियां होती थीं, आज मात्र 15-20 दिन में सर्दी खतम होगी। अगर इस पर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हमने पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी के साथ हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। हम यह जो विकास नीचे स्थापित करना चाहते हैं। यह विकास तभी संभव है, जब तक हमने पर्यावरण पर कंट्रोल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे काफी ऐसी चीजें लायी हैं, जिससे पर्यावरण खराब नहीं हो, आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पेयजल, शुद्ध वायुमण्डल मिले। विकास की दृष्टि से हमारे स्टेट को आगे पहुंचाने के लिए उन्होंने कई, जैसे अरावली को वापस हरा करने 250 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इलेक्ट्रिक बस लाने, कुकिंग इंडेक्शन गरीबों को देना, एसटीपीज को डवलप करना, सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करके कैसे

मैन्योर के रूप में काम में ले सकते हैं। पूरे पर्यावरण को ध्यान रखते हुए उन्होंने 'हरियाला राजस्थान' के तहत 10 करोड़ का प्रावधान रखा, हम पूरे राजस्थान में वृक्ष लगायेंगे, जिससे हम पूरे राजस्थान को हरा-भरा कर सकें और हमारे पर्यावरण को हम बचा सकें।

चौथा, कृषि बजट, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कृषि बजट खाली नाम का नहीं है। उन्होंने 1 लाख 10 हजार करोड़ के कृषि बजट का प्रावधान रखा है। हमारे पूर्ण बजट का लगभग 15 परसेंट से ज्यादा कृषि बजट पर खर्च हो रहा है। इसमें इरिगेशन के प्रोजेक्ट, ईआरसीपी प्रोजेक्ट हमारे 15 जिलों से निकलता हुआ जायेगा, इससे कई लाखों हेक्टेयर इरिगेट होने वाली है, कई हजारों हेक्टेयर इरिगेट होगी। कई गांवों, कस्बों को शुद्ध पेयजल, पानी मिलेगा। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार आते ही, राजस्थान जो पिछले कई सालों से ईआरसीपी की मांग कर रहा था, उसके लिए नेशनल प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए, आज धरातल पर काम प्रारंभ हो गया। लगभग 9 हजार 400 करोड़ के प्रोजेक्ट तो हमने प्रारंभ कर दिये हैं। 12 हजार करोड़ की निविदा सूची जारी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले पांच साल के अन्दर ईआरसीपी के लगभग 15 जिलों के किसानों को और आम जनता को इसका फायदा मिलेगा, भू-जल स्तर बढ़ेगा, सिंचाई होगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। हमारे प्रदेश की पर-कैपिटा इनकम आने वाले समय में निश्चित रूप से बढ़ेगी, इस ईआरसीपी के माध्यम से।

मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंनें, हमारा लंबे समय से यमुना के पानी का जो विवाद था, उसकी भी डीपीआर बनने जा रही है। यमुना का पानी सीकर और झुझुनूं, आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं और उसका भी एमओयू हुआ है। उसकी डीपीआर बन रही है। हो सकता है कि सीकर और झुझुनूं से हमारे साथी विधायक श्रवण जी हैं, मैं समझता हूं कि आपको सबसे बड़ी जरूरत होगी। झुझुनूं में पीने के पानी बहुत बड़ी समस्या है। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): यमुना का नाम ही नहीं है, साहब। इस बजट में यमुना का नाम नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): नाम नहीं दिया, पर उसका एमओयू हो गया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। प्लीज। माननीय आप इधर देखकर बात करें।

Kas/rtm/20.02.2025/14.40/2g

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, इसके अलावा आज हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो मैं समझता हूं कि जिस स्थिति में आपने ऊर्जा विभाग को खड़ा करके हमको दिया, हमारे कार्यकाल में उदय योजना के तहत 62 हजार करोड़ रुपये हमने हमारे खाते में लिये। हमने उसमें ब्याज दरें कम कीं, हमारे डिस्कॉम पर जो कर्जा था, उसको कम किया। उस कर्जे

को वापस आपने एक लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। डिस्कॉम एक लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान में चल रहा था और उत्पादन में भी 30 हजार करोड़ से ऊपर लॉस में चल रहे थे। मुझे आज भी याद है कि आपके कार्यकाल में आपने कई घोषणाएं कीं कि हम इतना बिजली उत्पादन शुरू करेंगे। आपके कार्यकाल में आपने एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की। जो काम चल रहे थे, वो हमारे कार्यकाल के चल रहे थे। आपके कार्यकाल में आपने एक भी बिजली सेंटर प्रारम्भ नहीं किया, जिससे हमको बिजली के भयंकर संकट से गुजरना पड़ रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्री जी एवं हमारे ऊर्जा मंत्री जी को जिन्होंने इसका पूरा ध्यान रखते हुए 6400 मेगावाट बिजली इस साल उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रधान मंत्री जी की दूर दृष्टि थी कि सोलर को कैसे आगे बढ़ाना है। इस हेतु 10 गीगा वाट सौर ऊर्जा राजस्थान में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इससे हम राजस्थान में सरप्लस बिजली की स्थिति में आ जायेंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्य मंत्री जी को कि आपने आते ही कुसुम योजना के एलओआई जारी कर दिये और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सीजन से पहले हमारे प्रत्येक 33 केवी जीएसएस पर सोलर लग जायेंगे, जिससे किसानों को हम दिन में बिजली दे सकेंगे।

सभापति महोदय, मुझे आज भी याद है, 2021 में आपने यहां घोषणा की थी कि हम पूरे राजस्थान को आने वाले दो साल के अन्दर-अन्दर दिन में बिजली उपलब्ध करायेंगे, लेकिन आपके कार्यकाल में तो दिन में बिजली उपलब्ध हुई नहीं, क्योंकि आपने ऐसा कोई काम किया नहीं। फीडर सैपरेशन का कोई काम किया नहीं। हमने कहा कि हम दिन में बिजली देंगे, उसके लिये हमने इस पर काम प्रारंभ किया है। हमारी केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्री जी ने 5000 मेगावाट कुसुम ए के तहत और दिये, लगभग 10 हजार मेगावाट कुसुम ए के तहत और कुसुम सी के तहत दिये। यह सोलर जिस दिन स्थापित हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में प्रत्येक किसान को दिन में 6 घंटे बिजली मिलेगी, इसका काम भी प्रारंभ हो गया है। लगभग 500-700 मेगावाट बिजली का तो सोलर स्थापित हो गया है और आने वाले आठ महीने में आप देखना पूरे राजस्थान में प्रत्येक जीएसएस पर ढाई-तीन मेगावाट का सोलर स्थापित मिलेगा, जिससे आने वाले समय में बिजली की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे मुख्य मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी ने रबी की फसल में पीक लोड को ध्यान में रखते हुए 20,700 मेगावाट से 6 घंटे किसानों को बिजली देने के लिये पर्याप्त मात्रा में बिजली अपने पास रखी है, ताकि किसानों को बिजली दे सके। आज राजस्थान में कोई यह नहीं कह सकता है कि किसानों को 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। बिजली भी अनइंट्रेप्टेड मिल रही है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। इस पीक सीजन में हमेशा जो किसानों को बिजली का संकट रहता है, लेकिन आज की तारीख में आपको यह शिकायत कहीं नहीं मिलेगी कि किसानों को 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है।

दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस बजट में हमने सभी विभागों को कवर किया है। आप कृषि बजट देखें, हैल्थ में देखें, हर विभाग में हमने बढ़-चढ़ कर काम करने

की कोशिश की है, ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। रोड सैक्टर में पहले बजट में भी मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा कराई, उसके बाद रिप्लाई में घोषणा की और उसके बाद फाइनेंशियल बिल में उन्होंने घोषणा की, वह सब काम आज चल रहे हैं। रोड सैक्टर में 21000 किलोमीटर ऐसी रोड हैं जो बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रत्येक विधान सभा में 10-10 करोड़ रुपये देने का इसमें प्रावधान रखा है। मरुस्थलीय क्षेत्र जहां दूरियां ज्यादा हैं, वहां 15-15 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। लगभग 5000 करोड़ की लागत से स्टेट हाईवे की स्ट्रेंथनिंग, उसका चौड़ाईकरण, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, आर.ओ.बी., आर.यू.बी. बन रहे हैं। चिकित्सा में मां के तहत 3500 करोड़ रुपये रिजर्व रखे हैं। निशुल्क जांच व निशुल्क दवाओं के लिये बजट रखा गया है, ताकि आमजन की अच्छी जांच हो सके। हमारे एएनएम या नर्सिंग स्टाफ की पोस्टें खाली थीं, अभी कुछ ही दिनों में लगभग 8500 से ज्यादा जीएनएम की भर्तियां हुई हैं। लगभग 4500 से ज्यादा एएनएम की भर्ती हुई है। लैब टेक्निशियन की भर्ती हुई है। राजस्थान में जुलाई से लेकर अब तक हमने लगभग 60 हजार युवाओं को नौकरियां दी हैं और 1,75,000 पाइप लाइन में हैं, जिनमें धीरे-धीरे एग्जाम करा कर और नौकरियां देंगे। आने वाले साल में नौजवानों को रोजगार देने के लिये लगभग सवा लाख भर्तियों का बजट में हमने प्रावधान रखा है। लगभग डेढ़ लाख स्किल्ड लेबर, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, उनको भी रोजगार देने की सरकार ने बजट में गारंटी दी है।

सभापति महोदय, इस बजट की मैं जितनी प्रशंसा करूं, उतनी कम है। आने वाले समय में यह राजस्थान में मील का पत्थर साबित होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री शान्ती धारीवाल।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, एक तो जब आप इस आसन पर विराजते हो...

श्री सभापतिः अच्छा लगता है ना आपको?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): तो मन प्रसन्न होता है।

श्री सभापतिः धन्यवाद। आप बोलते हो, तब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बोलिए माननीय सदस्य।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सबसे पहले मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, राज्य भाषा विभाग का यह आदेश है कि समस्त सरकारी विभागों में हिन्दी का काम होगा और हिन्दी का कार्य हिन्दी यूनीकोड मंगल फोंट में होगा। सारे विभागों में हो रहा है, आपकी असेंबली में भी यही मंगल फोंट चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक वित्त विभाग में नहीं हो रहा है। सवाल यह आता है कि आपके ऐक्सपेंडीचर और रिसीट के करीब 900 से लेकर 1000 कागज बनते हैं, कौन देखेगा? कोई भी सदस्य उसको देख कर यह मालूम नहीं कर सकता कि चिकित्सा में कितना पैसा दिया, शिक्षा में कितना पैसा दिया, सर्च ही नहीं कर सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आप सरकार से कहें, वित्त मंत्री जी से कहें कि जो भी सरकारी दस्तावेज यहां

पेश करते हैं, वो हिन्दी के यूनीकोड मंगल फोंट में पेश करें, यह मेरा सुझाव है।

mdp/20.02.2025/14:50/2h

सभापति महोदय, मैंने माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी का भाषण बहुत तसल्ली से सुना। क्या पता आप कहां से आंकडे ले आए? मेरे हिसाब से राजस्थान के इस बजट में न तो कोई विकास है, न कोई प्रगति है और न ही कोई विजन है। मुझे तो नजर नहीं आया, कतई नजर नहीं आया। बेरोजगार, गरीब, जनता, युवा, किसान, मजदूर की बहबूदी की बात होनी चाहिए थी। इसमें एक भी शब्द इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। राहत की तो बात ही छोड़िए आप। सरकार नये विचारों से बिलकुल खाली है। वही पुराने ढर्रे पर चलती रहना चाहती है। असल में देखा जाए तो इच्छा शक्ति है ही नहीं इस सरकार के पास, कोई इच्छा शक्ति नहीं है।

सभापति महोदय, 2023-24 में जब पूरे देश की जीडीपी वृद्धि दर 9.60 परसेंट थी, तब हमारे कार्यकाल में राजस्थान में जो वृद्धि हुई, वह 12.56 परसेंट थी। हमारे प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी के पिछले दस साल के कार्यकाल में जीडीपी की विकास दर 7.4 परसेंट थी, जो कि इन दस सालों में अगर एवरेज देखें तो सिर्फ 6 परसेंट आता है। ये वही आंकडे हैं जो आपकी किताबों के द्वारा ही दिये गये हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की आपने, कहां गये पुष्पेन्द्र जी, कांई करा वाको, 2018-19 में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 19 हजार 368 करोड़ रुपये का था, 2018-19 में, जिसको 2023-24 में हमने बढ़ाकर 34 हजार 843 करोड़ रुपये का रख दिया, लगभग दुगुना है। 10 जुलाई, 2024 को गत बजट में पैरा 188 पर आपने बड़ी वाहवाही लूटने के लिए कहा कि 2023-24 में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 26 हजार 646 था, जिसे हमने 65.59 परसेंट बढ़ाकर 44 हजार 216 करोड़ रुपये कर दिया। आपने इस पवित्र सदन में बिलकुल मिथ्या बोला है। वह मिथ्या इसलिए बोला है कि मैं आपको आंकडे, ये आप ही के द्वारा जो छापे गये आंकडे हैं, वह दे सकता हूं। यह देखिए आप, साफ लिखा हुआ है कि 348435133, यह लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है। कितना गलत बोलते हैं आप। डाक्यूमेंट जो आपने रखे हैं, इस सदन के पटल पर रखे हैं उसमें 2023-24 में आर.ई. में कैपिटल एक्सपेंडिचर 34 हजार 843 करोड़ रुपये आपने बता दिया। आप ही ने बताया है कि हमारा इतना था और बोल कुछ और रहे हैं। 26 हजार बता रहे हैं। आप ही के दिये हुए कागज 34 हजार से भी ऊपर बता रहे हैं।

आज की तारीख में एक्चुअल फिगर आ गये। उसके अनुसार 2023-24 में राजस्थान पर 5 लाख 60 हजार, 59 करीब है, जिसको 60 ही मान लीजिए आप। 5 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है। अब राज्य सरकार का कर्जा हो जायेगा 7 लाख 26 हजार 385, दो साल में राजस्थान की सरकार ने डेढ़ लाख करोड़ रुपये का कर्जा ले लिया। सभापति महोदय, मेरा तो यही निवेदन है इस सरकार से कि इनके जाते-जाते ये राजस्थान पर 10 लाख करोड़ रुपये का कर्जा छोड़कर जाएंगे। जाना तो तय है और 10 लाख करोड़ का कर्जा भी तय है।

कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका 44 हजार 216 करोड़ रुपये का प्रावधान था। दिसम्बर, 2024 में वह घटाकर आपने 22 हजार करोड़ रुपये का रख दिया, यानी 52 परसेंट और आर.ई. में 44216 को जो किया आपने सिर्फ 15 परसेंट कम कर दिया। ये टारगेट भी कभी पूरा नहीं होगा। कम करने के बावजूद भी आपका ये टारगेट पूरा नहीं होने वाला। बावजूद इसके इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचयर में 53 हजार 686 करोड़ रुपये का प्रोविजन कर दिया। बताइए, वह तो पूरा हो नहीं रहा कम करने के बाद भी। सिर्फ आपने 15 परसेंट कम किया तो भी कुछ नहीं हो रहा और अब आपने क्या कर दिया कि 53 हजार 686 करोड़ रुपये का प्रोविजन कर दिया। शेखचिल्ली की बातें। पैसा आयेगा कहां से? ये आंकडे हैं आपके। आपके समझ में आ जाए तो भेज दूं आपके पास। भेज दूंगा, अभी दे दूंगा।

हालात क्या है आज? हालात ये हैं कि लोग अपना सोना गिरवी रखकर अपना खर्चा चला रहे हैं। बातें करते हैं हम ये बनाएंगे, वह बनाएंगे। एकतरफ मंगलसूत्र को छीनने की बात करते हैं तो वाकई मंगलसूत्र तो आप ही छीन रहे हैं और कौन छीन रहा है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल-निकाल कर जा रहे हैं। केन्द्र सरकार का बजट आया। केन्द्र सरकार का जो बजट आया तो केन्द्र की सरकार ने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, शहरी विकास पर, एग्रीकल्चर पर, ग्रामीण विकास पर, सोशियल वेलफेयर पर, सब पर बजट घटा दिया। ये क्या इंडीकेट करता है? ये इंडीकेट करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसको आप बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। हालत ये है।

शराब माफियाओं को पनपाने में लगे हुए हैं। फिर ठेकेदारों का वार चालू हो जाएगा, जिस तरीके की पॉलिसी आपने बनायी है। 2024-25 में खराड़ी साहब बैठे हुए हैं, 2024-25 के बजट में आदिवासी उपयोजनार्थ, टी.एस.पी. जिलों के लिए टी.एस.पी. फंड 1500 करोड़ का प्रावधान किया था। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक नया पैसा भी उसमें नहीं डाला गया और आपका स्टेटमेंट है ..(व्यवधान)... ये आपका खुद का स्टेटमेंट है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। आपका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, यह आपका है। चाहे तो ले लीजिए आप। ..(व्यवधान)... आपने यह कहा कि हमने सरकार को लिखा है कि पैसा जारी कीजिए। हमने ये कहा कि सरकार पैसा जारी करो, जारी करो, लेकिन आया नहीं। 1500 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा गया, लेकिन एक पैसा भी आदिवासी पर खर्च नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी./आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लड़कों को 30 हजार छात्रों को कोचिंग देने का लक्ष्य आपने रखा पिछले बजट में, 30 हजार लड़को को देंगे। अभी तक तो कोचिंग संस्थाओं का चयन ही नहीं किया आपने कि किसमें करना है, किसमें नहीं करना है। ..(व्यवधान)... सूचीबद्ध ही नहीं किया उसको, बंडलबाजी।

श्री सभापति: शांत रहिए, आप सब। बोलने दीजिए, वरिष्ठ सदस्य हैं। आप तो इस तरफ बोले साहब, मंत्री जी से बाद में बात कीजिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मदन दिलावर जी चले गये। डाक्टर अम्बेडकर आर्थिक

पिछड़ा वर्ग उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एक भी छात्र को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया। एक भी छात्र को। 46 हजार रुपये देने का प्रोविजन है। एक को भी नहीं दिया गया।

Ans/rtm 15.00 2j 20.02.2025

प्राथमिक शिक्षा के बजट का हाल देखिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अभी सरकार ने दी है, देख लीजिए एक बार। आपने बंद कर दी थी, सारी हमने दी है। दे रहे हैं अभी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): खराड़ी साहब, जब आपके मंत्री बोलते हैं तो मैं कभी बीच में नहीं बोलता। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आपके द्वारा छोड़ी हुई छात्रवृत्तियां भी हमारी सरकार दे रही है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अभी पुष्पेन्द्र जी बोले, मैं एक बार भी नहीं बोला। हालांकि मैं उनसे एग्री नहीं कर रहा था लेकिन एक बार भी नहीं बोला।

प्राथमिक शिक्षा के बजट का हाल देखिये। पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति का बजट अनुसूचित जाति के लिए 16 करोड़ रुपये रखा गया था, उसमें साल भर में डेढ़ करोड़ रुपये बांटे हैं। एसटी के लिए 18 करोड़ रखे गये और सिर्फ सवा करोड़ बांटे गये। सहरिया, जनजाति, ओबीसी, सफाई से जुड़े हुए व्यवसाय वाले बच्चों को एक रुपये की भी मेट्रिक में छात्रवृत्ति नहीं दी गई।

मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पाना लोगों का अधिकार है लेकिन डबल इंजन की सरकार में 45 से 50 दिन का रोजगार भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। मनरेगा के बजट में कटौती और कर दी। मनरेगा में हमने 9 हजार 355 करोड़ रुपये रखे थे, आपने मनरेगा में इस साल सिर्फ 5 हजार 18 करोड़ रुपये रखे हैं। वह भी खर्च करोंगे कि नहीं करोंगे?

बेरोजगारी कम करने के लिए जैसा अभी आपने कहा, शहरी रोजगार योजना जल्दी चालू कर देते तो शायद हम यहां नहीं वहां बैठते। कभी की हो चुकी थी, शायद आपके यहां नहीं हुई होगी, क्योंकि यह नगर निगम के माध्यम से होती है और नगर निगम काम नहीं करना चाहता होगा इसलिए नहीं हुई होगी, बाकी यह वक्त पर पूरी हो चुकी थी। आज क्या हुआ, शहरी रोजगार योजना तो चल रही है लेकिन आपने उसमें बजट कितना दिया यह देखो। ग्रामीण रोजागर योजना जो हमने चालू की थी वह तो आपने बंद ही कर दी, उसके लिए एक पैसा नहीं दिया, रोजगार के प्रति आपकी सरकार का यह रुख है।

ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए राजस्थान में लोजिस्टिक सर्विस डिलिवरी कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा की गई थी और उसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई। घोषणा हमने की, चुनाव से कम से कम 6 महीने पहले कर दी थी, उसके बाद भी अधिसूचना जारी नहीं की। पिछले बजट में मैंने इसी बात को लेकर तीन सवाल लगाये और हर बार मुझे यही जवाब मिला कि गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मैं उम्मीद करता हूं,

कम से कम इसका गठन तो करवा दो। गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी व वेलफेयर के लिए भी हमने एक्ट बनाया, इसके लिए भी आपने अभी तक नियम नहीं बनाए। इस पर भी आप प्रायोरिटी से ध्यान दे, लाखों लोगों का फायदा होगा।

अन्नपूर्णा रसोई के लिए आपने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई हमने बंद कर दी और तीन साल तक चालू नहीं की। साहब, दूसरे साल ही चालू हो गई इंदिरा गांधी। अन्नपूर्णा ग्रामीण के लिए बजट में 7 करोड़ 17 लाख थाली उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया था, इसके लिए 120 करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया था। मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि 2 करोड़ 64 लाख थालियां ही उपलब्ध हुई हैं। 7 करोड़ के बजाय 2 करोड़ ही। इस साल उसका बजट भी घटाकर 107 करोड़ रुपये कर दिये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आपस में बातें नहीं करें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं।

श्री सभापतिः आपके पास समय है, आप बोलो। अभी पर्याप्त समय है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैंने गांव में शौचालय बनाने का सवाल पूछा। विधान सभा में जो रिपोर्ट रखी गई उसमें तो यह बताया गया कि व्यक्तिगत शौचालय 26 हजार 436 बनाये हैं, जबकि प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया कि 01 लाख 21 हजार 355 बना दिये हैं, वह असत्य है या सरकार असत्य है। सामुदायिक शौचालय के लिए बताया गया कि 2002 बना दिये, जबकि रिपोर्ट में लिखे हुए हैं कि 334 ही बनाये।

आपने जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। पिछली बार 2100 करोड़ रूपये रखे गये। यह एलिवेटेड रोड़ बनाएंगे, यह आरओबी बनाएंगे, यह बनाएंगे, वह बनाएंगे, एक भी बना? सिर्फ 165 करोड़ के टेंडर हुए हैं, बाकी सब डीपीआर है। कई तो कैंसिल कर दिये।

आप मेट्रो की बात करते हो, मेट्रो की चार बार डीपीआर बन चुकी है। मुझे कोई भी सदस्य यह बता दो कि मेट्रो सीतापुरा से चालू होगी तो अम्बाबाड़ी, पानीपेच कैसे पहुंचेगी, कहां से किस रास्ते से पहुंचेगी, आप मुझे बता दे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्यों बताये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरा चेलेंज है, आप बता दो, आप बना ही नहीं सकते। जिस तरीके से आपने अम्बेडकर सर्किल से एलिवेटेड रोड ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बैठे-बैठे नहीं बोले।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पिछली बार एयरपोर्ट तक बनाने की बात की थी और फिर बाद में विदड्रा कर लिया कि यह सम्भव नहीं है, जेएलएन मार्ग सारा बिगड़ जाएगा। उसी तरीके से आपकी मेट्रो का सत्यानाश होगा। बड़ी चौपड़ तक तो हमने पहुंचा दी थी। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक काम शुरू हुआ था वह भी चार महीने से बंद पडा हुआ है। ...(व्यवधान)... हमने मेट्रो बनाई और टाइम पर बनाकर दी और चालू की है, हम जानते हैं कि मेट्रो किस तरीके से बनती है, मेट्रो बातों से नहीं बनती है।

सभापति महोदय, मैं आखिर में यही कहूंगा कि सरकार का बजट बिलकुल घोषणाओं का

बजट है और डीपीआर का बजट है। इस डीपीआर वाले बजट के कारण सत्ता पक्ष के अधिकांश लोग डिप्रेशन में चले गये। ...(व्यवधान)... साइकोलोजिस्ट की जरूरत है यहां।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): थोड़ा देखो, शरीर को देखो, शरीर को।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जिस चीज के लिए पूछते हैं उसके लिए कहते हैं कि स्वीकृति जारी हो गई, डीपीआर बन रही है, हो जाएगा, हो जाएगा चिंता मत करो। आदमी डिप्रेशन में जाता ही है और कई डिप्रेशन में चले गये। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): धारीवाल जी, आपके राज में डीपीआर नहीं बनी और शिलान्यास हो गया। डीपीआर ही नहीं बनी। आपके मंत्रियों ने की है, मैं आपको सबूत लाकर दे सकता हूं। खाली फर्जी बातें करेंगे क्या ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मानीय सदस्य, विराजें। आप भी शांत रहें, बोलने दें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): डीपीआर क्या होती है, यह भी जानते हो कि नहीं जानते। ...(व्यवधान)... कभी बनाई है क्या डीपीआर? मैं इसका पुरज़ोर विरोध करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री जयदीप बिहाणी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत विद्वान है लेकिन बहुत नीरस भाषण है कोई मतलब नहीं है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय प्लीज विराजिये।

श्री जयदीप बिहाणी (गंगानगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान बजट 2025-26 के पक्ष में बोलने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी द्वारा बजट प्रस्तुत कर, बजट 2025-26 में हमारे राज्य के विकास और समृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं।

VPS-RTM-20.02.2025-15.10-2k

माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए पेयजल, ऊर्जा, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा एवं औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना के विकास की महती आवश्यकता होती है। राजस्थान का बजट 2025-26 में इन सब क्षेत्रों पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। इससे पहले मैं अपना आगे आपको पढ़कर सुनाऊं, मैं कांग्रेस सरकार के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि जो घोषणाएं इन्होंने अपनी अंतिम समय में आनन-फानन में कीं, ये यह बात समझ लें कि-

'दौर हमेशा हवाओं का ही चलता है,
आंधियां तो कुछ समय बाद खतम हो जाती हैं।'

राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि विविधताओं से भरपूर है। यहां के सांस्कृतिक,

ऐतिहासिक और पारंपरिक उद्योगों ने राजस्थान को देश-विदेश में एक विशेष स्थान दिलाया है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इनका संरक्षण एवं इनकी उन्नति केवल तब ही संभव है जब राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस बजट में सरकार ने वह ही करने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगर निकायों में पेयजल आपूर्ति के लिए 5123 करोड़ रुपये के कार्य से एवं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना से पेयजल की समुचित व्यवस्था होगी एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को समयबद्ध रूप से पेयजल मिलेगा। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में, मैंने गंगानगर का नाम इसीलिए लिया कि गंगानगर की जनता ने मेरे को विधान सभा में बोलने का मौका दिया है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में जल आपूर्ति के गुणात्मक संवर्धन, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का निवारण करने के लिए एक हजार ट्यूबवैल व 1500 हैंडपम्प का प्रावधान किया गया है। बजट में 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, अबकी बार ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट के कारण लोगों की समस्याओं को देखते हुए यह जो नये प्रावधान माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में वित्त मंत्रीजी ने किये हैं, यह आमजन से भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव दर्शाता है। अंतिम छोर पर बैठे उन लोगों को भी लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार ने यह प्रावधान किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत सुधारों की दिशा में बजट में जो एलान किये गये हैं, उसमें राजस्थान विद्युत के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करेगा। पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से सोलर प्लांट लगाया जायेगा। नि:शुल्क बिजली की, आप सुन लीजिए, आप अपनी बातों में मत मस्त होइये। जो यूनिट 100 आपके समय में थी, हमारी वर्तमान सरकार ने उस मुफ्त यूनिट को बढ़ाकर 150 यूनिट प्रति माह करने का प्रावधान कर दिया है, इससे मध्यमवर्गीय एवं गरीबी रेखा से नीचे के लोग प्रभावित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, आगामी वर्ष 2025-26 में 6400 मेगावाट से भी अधिक बिजली के अतिरिक्त उत्पादन किये जाने का प्रावधान और रबी फसल हेतु 20 हजार 700 मेगावाट बिजली सप्लाई का प्रावधान, 50 हजार नये कृषि एवं 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन देना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। संवेदनशील सरकार हमेशा संवेदनशील निर्णय लेती है।

माननीय सभापति महोदय, नॉन पेचेबल सड़कों के लिए विपक्ष वाले भी सुन लें, 200 के 200 विधान सभा क्षेत्रों को ध्यान में रखकर, हमने पार्टियों में राजस्थान की जनता को नहीं बांटा है, सभी विधायकों को दस करोड़ रुपये तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रदेश के विकास को नई गति देगा। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के सपने को साकार करते हुए सड़कों का जाल बिछाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी

शर्मा द्वारा 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से कार्य करने की योजना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष स्टेट हाईवे, बाईपास रोड, फ्लाई ओवर, एलिवेटेड रोड, आर.यू.बी., आर.ओ.बी., ब्रिज आदि के निर्माण, उनकी मरम्मत तथा उन्नयन के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में आजकल फोर व्हीलर का ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिसके घर में दो टू व्हीलर है, उसके घर में एक फोर व्हीलर हो गया है। हमारी संवेदनशील सरकार ने इस बात पर प्रमुखता से ध्यान दिया है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में हैवी ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से राहत दिलवाने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण हेतु डी.पी.आर. के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री भजन लालजी शर्मा ने रखा है।

माननीय सभापति महोदय, शहरी क्षेत्रों में वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट आज सारे हिंदुस्तान में एक गम्भीर समस्या बन गया है। इसके डिस्पोजल पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। यह माननीय मुख्य मंत्री भजन लालजी शर्मा की संवेदनशील सरकार है जिसने पर्यावरण को भी ध्यान में रखा है। वेस्ट डिस्पोजल एक बड़ी समस्या है, इसके लिए गंगानगर सहित प्रदेश के अन्य शहरों के लिए बजट में किया गया प्रावधान निश्चित ही इस समस्या के समाधान में मील का पत्थर स्थापित होगा।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए धड़ाधड़ नये जिले तो बना दिये परंतु यह नहीं सोचा कि इन जिलों में आधारभूत ढांचा कैसे खड़ा होगा? हमारी सरकार ने नये जिलों के लिए एक हजार करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए रखा है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि अब प्रदेश के गरीब अतिक्रमणकारी नहीं कहलाएंगे क्योंकि माननीय श्री भजन लालजी की सरकार ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत दो लाख परिवारों को नये पट्टे देने का प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, युवा विकास एवं कल्याण के लिए राजस्थान रोजगार नीति, 2025 का निर्माण, 500 करोड़ रुपये से विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना, सरकारी विभागों में एक लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां एवं निजी क्षेत्र में जब यह एम.ओ.यू. होगा तो निजी क्षेत्र में एक लाख 50 हजार रोजगार सृजन युवाओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करता है।

माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, पहले राम मन्दिर का निर्माण, अब त्रिवेणी के संगम का स्नान, इसने हमारी सनातन परंपरा को जगाया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत 6000 नागरिकों के लिए हवाई यात्रा तथा 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ए.सी. चेयरकार की यात्रा का प्रावधान कर सरकार ने वरिष्ठजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है।

माननीय सभापति महोदय, सनातन धर्म की आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के उत्थान के लिए 101 करोड़ रुपये, यह सनातन है। 101 करोड़ रुपये जिसमें पुजारियों के लिए 7500 प्रति माह मानदेय, यह मानदेय पहले 5000 रुपये ही था, जिसको बढ़ाकर 7500 रुपये

प्रति माह किया है और विराजमान ठाकुरजी के भोग के लिए 3000 रुपये प्रति माह का प्रावधान कर आस्था के प्रति सम्मान व्यक्त किया है।

SSY/RTM/20.02.2025/15.20/2I

माननीय सभापति महोदय, प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र स्वस्थ जीवन है। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण विषय है। पहला सुख निरोगी काया के ध्येय के प्रति यह माननीय मुख्य मंत्री आयुष्मान योजना बजट में निशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3500 करोड़ के कोष की स्थापना से स्वास्थ्य के प्रति अपनी गहरी सोच दिखाता है। जहां कांग्रेस शासन में वृद्ध जनों को दवा लेने के लिए कतारों में लगना पड़ता था वहीं हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा की सरकार ने वृद्धों के प्रति सम्मान दिखलाते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों हेतु जेरियाटिक केयर पैकेज एवं घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध करवाने की घोषणा एक नींव का पत्थर साबित होगी। प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 10 बेड के डायलिसिस केन्द्र की व्यवस्था, डे केयर सेंटर, डॉक्टर एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों का सृजन चिकित्सा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करेगा। यह स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार की जागरूकता को दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, समावेशी समाज में दिव्यांग जन को भी विशेष महत्व दिया जाना जरूरी है। श्रीमान, इस बजट में 1 लाख दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंगों का प्रावधान तथा शोध हेतु 20 करोड़ का बजट सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, डिजिटल इंडिया के दौर में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय, आज का दौर डिजिटल दौर हो गया, हर बच्चा इंटरनेट, डिजिटल एजुकेशन से जुड़ना चाहता है, प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय के ब्रॉडबैंड कनेक्शन से सूचना का आदान-प्रदान सुगम ही नहीं होगा वरन डिजिटल शिक्षा से जुड़कर विद्यार्थी लाभान्वित भी होंगे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है। वर्तमान बजट में प्रत्येक ब्लॉक में उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्र की स्थापना कर इस प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, नौनिहालों का स्वास्थ्य, नौनिहाल आज समाज की धरोहर हैं, राष्ट्र की धरोहर हैं। नौनिहालों के स्वास्थ्य के प्रति उनके पोषण के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सप्ताह में 5 दिन दूध की व्यवस्था की गई है, जो कि छोटे बच्चों के समग्र विकास हेतु एक लाभकारी कदम है।

माननीय सभापति महोदय, पत्रकार बंधुओं के लिए पत्रकार कल्याण राशि 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तथा एक्सपोजर टूर की व्यवस्था का प्रावधान कर पत्रकारों के कल्याण के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पत्रकारों के प्रति सरकार की भावना है।

माननीय सभापति महोदय, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा प्रारंभ पंच गौरव योजना को गति देने के लिए 550 करोड़ के विकास कार्यों के बजट का प्रावधान इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, महाराजा गंगासिंह स्टेडियम, श्री गंगानगर के उन्नयन के लिए बजट प्रावधान विधान सभा श्रीगंगानगर क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय का मैं कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत सारे राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए जन हितैषी लोक कल्याणकारी इस सरकार द्वारा 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प राजस्थान सरकार की पर्यावरण के प्रति सजगता को दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने बजट में जन प्रतिनिधियों का भी ख्याल रखा है। जन प्रतिनिधि पक्ष में भी हैं तो विपक्ष में भी बैठे हैं। इसके लिए आप तो ताली बजा दो, आप तो मेजें थपथपा दो। आपके 10 पर्सेंट बढ़ गये ना। देखिये, आपको जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। मस्ती से घर बैठते हो, मजे लेते हो। 5 साल का आनंद अब ले रहे हो। लेकिन जनता का ध्यान रखते हुए प्रत्येक विधान सभा में जन सुनवाई केन्द्र बनाने के लिए 10 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र में बजट की घोषणा की है ...(व्यवधान)... जगह भी मिलेगी।

श्री सभापतिः शांति रखें।

श्री जयदीप बिहाणी (गंगानगर): श्रीगंगानगर में एलसी 119 पर आरयूबी निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान, बनेगा, इसका बजट भी जारी हो गया। गंगानगर की जनता मेरे को करने दो, आप ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो, आप अपने क्षेत्र का ध्यान रखो। वहां के लिए कुछ लिखकर दो ताकि हम भी मदद करें। जनता का कल्याण हो। 30 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया। आपने तो यह प्रोजेक्ट कैंसिल करवाने में भी कसर नहीं छोड़ी थी। जब बनेगा तब आपको मैं फोटो भेज दूंगा तो बुला लेना।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): बनेगा तब फोटो भेजोगे ना।

श्री जयदीप बिहाणी (गंगानगर): हां, बन जायेगा। एक साल में बनेगा। फोटो देख लेना। विधान सभा में मेरी यही सीट है। मेरा 58 नंबर है।

श्री सभापतिः आप इधर देखिये, माननीय सदस्य। इधर देखिये।

श्री जयदीप बिहाणी (गंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं जिस श्रीगंगानगर जिले से आता हूं वह कृषि बाहुल्य जिला है। वहां के किसान प्रदेश का ही नहीं बल्कि सारे देश का पेट भरने के लिए अन्न उपजाते हैं। बजट में धरती पुत्र किसानों के लिए की गई अनेकानेक घोषणाओं के लिए मैं श्रीगंगानगर का जन सेवक होने के नाते माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया दिया कुमारी जी का आभार प्रकट करता हूं। 75 हजार किसानों को तार बंदी के लिए

अनुदान देने, गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने, पीएम किसान सम्मान निधि 9 हजार रुपये करने, कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपये के कार्य करने, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राज्य की तरफ से प्रावधान करने एवं 2000 किसानों को पॉली हाउस, शैडलेट हाउस आदि के लिए जो 225 करोड़ का अनुदान करने की घोषणा किसान एवं खेती का कायाकल्प कर देगी।

माननीय सभापति महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के अंतर्गत सीवरेज, ड्रेनेज एवं सेनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल हेतु लगभग 12050 करोड़ रुपये की लागत से 7 वर्षों में कार्य क्रियान्वित किये जायेंगे। इसी के तहत मेरे श्रीगंगानगर शहर में जल भराव क्षेत्रों में बरसाती पानी के ड्रेनेज सिस्टम हेतु बजट की घोषणा किये जाने पर मैं माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

प्रदेश में किसानों के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रदेश में कृषि विस्तार करने ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में भंडारण करने की दृष्टि से 500 मैट्रिक टन क्षमता के 100 और 250 मैट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का ग्राम सेवा क्रय विक्रय सहकारी समितियों में निर्माण कार्य हेतु 33 करोड़ का अनुदान सहकारी समितियों को मजबूत करेगा। मंडी प्रांगणों में समर्थन मूल्य पर किसानों द्वारा लाई गई जिंसों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए मंडियों में पावर क्लिनिंग मशीनों की स्थापना के लिए 10 करोड़ का बजट किसान के हित में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुज्ञाधारी श्रमिकों को दो पुत्रियों की सीमा तक विवाह हेतु सहायता राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाना सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदना को दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, गंगा कैनाल के सीसीबी लाइनिंग के लिए 300 करोड़ के बजट की घोषणा की गई, जो की पानी की छीजत को रोकने एवं किसान के हितार्थ हेतु अत्यंत लाभकारी होगी।

माननीय सभापति महोदय यह बजट केवल एक वित्तीय योजना नहीं है, वरणीय समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक दस्तावेज है।

spp/rtm/20.02.2025/15.30/2m

जिसका क्रियान्वयन अतिशीघ्र होगा और विपक्ष भी इस पर अपनी मेजें थपथपायेगा। अंत में एक बात बोलते हुये मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।

'उम्मीदों की किरणें अब चमकने लगी है,
राजस्थान के हर कोने में नई रोशनी दिखने लगी है।
अब मेहनत के फूल भी मोती बनेंगे,
हर आंगन में खुशहाली के दीप जलेंगे।
भजनलाल-दिया कुमारी ने किया यह कमाल,

कि सपने हकीकत में खुद छलेंगे।'

धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय श्रीराम।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, यह दूसरी बार है जब वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान में बजट दिया। इस बजट में ना तो कोई दिशा है, ना कोई दशा है। नजर नहीं आ रही, बिलकुल निराशाजनक बजट है। दलित, आदिवासी,गरीब, ओबीसी, एमबीसी और यूथ के लिये इस बजट में कुछ भी नहीं है। पिछले बजट में आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किये थे, नई आबकारी एक्ट लेकर आएंगे, आया क्या? राजस्थान रीजनल एण्ड अरबन प्लानिंग बिल 2024 आएगा, आया क्या? जयपुर वॉल सिटी हैरिटेज डवलपमेंट प्लान आएगा, आया क्या? राजस्थान खेल नीति बनी क्या? माटीकला एक्सीलेंस का बोर्ड बना क्या? एक हजार इलेक्ट्रिकल व्हील्स माटीकला वालों को मिली क्या? काली भील स्कूटी योजना में किसी बच्ची को स्कूटी मिली क्या? श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना में 500 करोड़ किसी जिले को मिले क्या? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी में 300 करोड़ रुपये किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला क्या? यह तो आपके बजट की थोथी घोषणाएं थीं, जो पिछली बार की थीं।

एक माननीय सदस्य: और कई सारी हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं तो अभी सिर्फ इसमें से 10 प्रतिशत निकाली हैं। जब अशोक गहलोत जी की सरकार गयी 2014 में, तो टोटल हम जो लोन छोड़कर गये थे वह 01 लाख 29 हजार 910 करोड़ का लोन छोड़कर गये थे। पुष्पेन्द्र जी, ठीक है न? जब आपकी सरकार गयी ..(व्यवधान).. बोल रहा हूं, बोलने तो दो न। आप बहुत जल्दबाजी करते हो। जब 2008 में आप मंत्री थे, जब आपकी सरकार गयी तो आप 03 लाख 09 हजार 985 करोड़ का लोन छोड़कर गये थे। मतलब आपने 5 साल में 01 लाख 80 हजार करोड़ का लोन लिया। 2024 में जब वापस अशोक गहलोत जी की सरकार गयी तो 5 लाख 71 हजार 638 करोड़ का हम लोन छोड़कर गये थे, उसमें दो साल कोरोना के थे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनोमी had a downtrend of 10 per cent. उनको भी उतना ही लोस हुआ था। फिर भी हमने कितना-सा लोन लिया, 2 लाख 62 हजार करोड़ का हमने लोन लिया। 2026, जो यह साल है, 2025-26 का बजट पेश किया है न, 7 लाख 26 हजार 384 करोड़ का आप ऑलरेडी लोन ले चुके होंगे। मतलब दो साल में आपने 01 लाख 55 हजार करोड़ का लोन ले लिया। ..(व्यवधान).. आप मुझे मत समझाओ। FRBM एक्ट को भी आपको समझा देता हूं। ठीक है, उसकी भी आप चिंता मत करो। मेरे को मत समझाओ कि FRBM एक्ट क्या होता है। FRBM एक्ट में कोरोना के टाइम जो 0.5 प्रतिशत आपको छूट मिली थी न, हमको मिली थी और आपको इस साल मिली है। इस साल भी मिली है, आप सेंट्रल का बजट पढ़ लीजिएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं ऊर्जा की ही बात कर रहा हूं। आप अंग्रेजी में उसको एनर्जी कह दो। मैं ऊर्जा की ही बात कर रहा हूं तो भी आपको 0.5 मिली है, जिसको

आपको 9 हजार 918 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा मिले। यह आपके हाल हैं कि 2 साल में आप इतना घी पी लोगे कि जब तक चार साल होंगे, आप इसको 10 लाख करोड़ पर ले जाओगे। क्या आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है?

2024-25 में आपने कहा GSDP का प्रोजेक्शन 17 लाख 81 हजार 078 करोड़ का आपका था और वास्तव में क्या हुआ? अभी पुष्पेन्द्र जी, आपने कहा था न 19 लाख करोड़ का, वह भी मैं बताता हूं, कैसे करोगे? एक्चुअल प्रोजेक्शन है 17 लाख 04 हजार 339 मतलब, you are down by 77 thousand crores. आपका GSDP, जो आपने प्रोजेक्ट किया था, उससे 77 हजार करोड़ रुपया कम दिया है और आप लोग वाहवाही कर रहे हो। यह वाहवाही करने की जगह नहीं है। पहले आप अपने फिगर्स देखो कि आपने क्या किया है। 77 हजार करोड़ से कम हमारी GSDP की ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर, जब आपकी वित्त मंत्री ने यहां पर बजट दिया है।

इसी तरह से अब आपका प्रोजेक्शन आया है 19 लाख 89 करोड़ का। आपको पता है, the Indian economy in 'real terms' is only growing. रियल टर्म्स का मतलब होता है 'inflation plus growth', and which is only 10.1 per cent. आप उससे ज्यादा ग्रोथ तो नहीं कर सकते ना? इंडियन इकोनोमी से ज्यादा तो आपकी ग्रोथ नहीं है, इस साल भी उससे कम है आपकी ग्रोथ। 10.1 प्रतिशत की यदि आप ग्रोथ करोगे तो आपकी ग्रोथ आयेगी 18 लाख 74 हजार। यह इस डाकुमेंट में लिखने से नहीं हो जाता कुछ। आपके इस डाकुमेंट में आप लिख दो कि हम 22 प्रतिशत से ग्रोथ करेंगे, कुछ नहीं होता है। फिर आर.ई. में आकर आप कहते हो कि 7 प्रतिशत बिलो ग्रोथ हो गयी। आपकी ग्रोथ आयेगी 01 लाख करोड़ कम की GSDP, यह असत्य का पुलिन्दा मत दीजिए। यहां पर वह पुलिन्दा दीजिए जिसमें सच लिखा हो। यह मिथ्या भाषण देने से कुछ नहीं होगा। पढ़िये कि आप क्या कर रहे हैं? किस तरह से आप राजस्थान की रोज बरबादी कर रहे हैं। जब तक आप पॉवर में रहेंगे, राजस्थान बरबाद होगा।

आपने रेवेन्यू डेफिसिट की बात की। 25 हजार 758 करोड़ का आपने रेवेन्यू डेफिसिट बताया। नाइंथ मंथ में जब दिसम्बर के आपके फिगर्स आये, अन-आडिटेड फिगर्स आये तब आप आलरेडी 30 हजार करोड़ पर आ चुके हो। 5 हजार करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट आप बढ़ा चुके हो। इस साल जब तक आप खत्म करोगे, यह करीब-करीब 32 हजार करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा, कहां से पूरा करोगे? आपने 1.4 से रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ा दिया 1.9 प्रतिशत पर। यह मजाक थोड़े है। आप फिर बजट क्यों बना रहे हो? बजट मत बनाओ न। Who has told you that, बजट बनाओ? जब सभी चीजें आप उसमें गलत लिख रहे हो तो बजट क्यों बना रहे हो? फिर आर.ई. में जाकर चेंज कर लेते हो। अब तो आर.ई. से ज्यादा आ गया है। गर्ग साहब, एक एक्चुअल आ गया है, आप भले ही उधर समर्थन कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल आ गया है। एक्चुअल में और कम कम देते हैं। जब यह अप्रेल में फिगर्स देते हैं न तो एक्चुअल शब्द यूज कर देते हैं और आर.ई. को हटा देते हैं। पहली बार

हो रहा है राजस्थान में, जब आर.ई. को हटाकर एक्चुअल कर दिया जाता है। ..(व्यवधान).. बैठो, हमीर सिंहजी। आपकी जी.एस.टी., आपने क्या कहा लास्ट बजट में(जी.एस.टी. की प्रोडेक्टिव ग्रोथ आपने बतायी 16 प्रतिशत। 55 हजार 800 करोड़ आपने बतायी जी.एस.टी., क्या इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा की ग्रोथ ले आओगे क्या? ग्रोथ कितनी आयी 16 प्रतिशत की ग्रोथ दिखायी अपने इन्हीं पुलिन्दों में। इन्हीं पुलिन्दों से निकाली हुई 16 प्रतिशत की ग्रोथ दिखायी। पुष्पेन्द्र जी आपने बोला था अभी कि 16 प्रतिशत की ग्रोथ है। इंडियन गवर्नमेंट की जो ग्रोथ हो रही है वह सिर्फ 10 प्रतिशत की हो रही है। आपने क्या किया, अभी आपकी जो ग्रोथ आ रही है वह 9 प्रतिशत की आयी है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 13 हजार करोड़ ज्यादा है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप सुनो तो सही। 55 हजार 800 की कहते हो, आया है 52 हजार 100 करोड़। You are down by 7 per cent. एक्चुअल ग्रोथ क्या आयी, 16 में से 7 निकाल दो तो 9 आयी। इसीलिए कह रहा हूं कि यह असत्य के पुलिन्दे हमारे को दिखाने बन्द करो।

इसी तरह से आपने बात कही कि हम ग्रोथ करेंगे 22 प्रतिशत की। पूरे भारतवर्ष में जी.एस.टी. की ग्रोथ सिर्फ 10 प्रतिशत की है इस साल भी, जो रेवेन्यू ग्रोथ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं, वह 10.11 प्रतिशत के हैं और आप क्या कह रहे हो, 22 प्रतिशत की ग्रोथ कर देंगे। यह कोई बाबाजी का राज थोड़े ही चल रहा है, यह गप्पों का पुलिन्दा थोड़े ही चल रहा है, यह बजट चल रहा है।

jyg/rtm/20.02.25/15.40/2n

मजाक तो मत करो। ...(व्यवधान)... बाबाजी, आप बैठे हो ना? आप ही का तो राज है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): बाबाजी का राज तो यूपी में चला है जहां आपके 'जीरो' हैं, 'जीरो'। यहां आ गया बाबाजी का राज तो यहां भी आपके 'जीरो' ही होगा। ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सेल्स टैक्स और वैट में आपने क्या किया? आपने कहा कि हम 29 हजार करोड़ रुपये की ग्रोथ, टोटल प्रिडिक्शन आया आपका 29 हजार करोड़ रुपये और एक्चुअल कलेक्शन क्या है? 27 हजार करोड़ रुपये। You are again down by 7 per cent. प्रोजेक्टेड ग्रोथ वापस क्या ली? जो पहले 10 परसेंट की ग्रोथ थी, नेक्स्ट ईयर आपने 2026 में क्या ग्रोथ ली, 12 परसेंट की ग्रोथ ले ली। ...(व्यवधान)... कुछ तो शर्म करो। पिछले साल का तो आप बजट पूरा नहीं कर पा रहे हो, वापस ग्रोथ ले लेते हो 12 परसेंट की। दिखाने के लिए कि जिससे आंकड़े फिट हो जायें, आंकड़े फिट इसलिए हो जायें कि रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट हमारा बराबर कर लें हम, विदिन एफआरबीएम एक्ट, यह नहीं है एफआरबीएम लिमिट का मतलब कि मैं प्रोजेक्शन कर दूं जो कभी अचीव ही नहीं कर सकूं और उसको फिर मैं आपको फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट में बराबर करके लूं, यह

क्या कर रहे हो? इसी तरह से आपने जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ की, किसमें, 14 परसेंट आपने प्रोजेक्टेड ग्रोथ की, दिस ईयर अगेन वो 14 परसेंट आपने वापस इस बार ग्रोथ की उसी तरह से।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

अब आप एक्साइज पर आ जायें, द टोटल प्रोजेक्टेड इनकम आपने बतायी 17 हजार 100 करोड़ की, कलेक्शन का इस बार आपने क्या किया, बडी होशियारी से काम किया, कलेक्शन आपने किया 17 हजार करोड़ रुपये का, यह दिखाया कि we are only down by one per cent. जबकि ऐसा नहीं था। जो आपके नाइन मंथली फिगर थे, उसमें आपका टोटल कलेक्शन हुआ था 10 हजार 723 करोड़ रुपये, यदि उससे extrapolate करते हैं तो आपकी टोटल इनकम आती 14 हजार 300 करोड़ रुपये। आपने क्या दिखाया 17 हजार, वो कैसे दिखाया? आपने जो 2025-26 का पैसा था, वो 2023-24 में जमा करा लिया, 5 परसेंट आपको जो इन पर सेस लेना था और एक्साइज का नया, and you have taken 5 per cent. जो लाइसेंस फीस का पैसा था वो आपने एडवांस में ले लिया 2026 का, यह दिखाने के लिए हमने तो 17 हजार करोड रुपये की ग्रोथ कर ली। पहले एडवांस का, लास्ट ईयर का पैसा इस साल में आपने अकाउंट फोर कर लिया। आप यह अकाउंटेंट्स वाली जग्लरी तो मत करो। अगले साल क्या करोगे फिर? अगले साल फिर इसमें डाउन आ जाओगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें। उधर आपस में मत उलझो, आप अपनी बात रखिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, आसन को ही सुना रहा हूं। आपकी तरफ ही चल रही है मेरी आंख। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की बात की। आज मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की बात की। मंत्रीजी यहां बैठे हैं। मंत्रीजी, कितना बजट था? 3500 करोड़, कितना कलेक्शन आया, 3100 करोड़, कितना डाउन फाल था? 13 परसेंट। इस बार आपकी ग्रोथ कितनी थी, 2900 करोड़, पिछली बार कितनी ग्रोथ थी, आपने 3100 करोड़ किया, आपने वापस 4000 करोड़ से अपना टार्गेट बढ़ा दिया। आप कभी नहीं कर पाओगे। वापस आप कहोगे कि the growth is down by 13 per cent. तो फायदा क्या है? अपने को ऐसे देने से फायदा क्या है? अपन वो चीज दें बजट के अन्दर जो एक्चुअली में हो। ऐसा काम करने से क्या फायदा है? यह मैंने कहीं से नहीं निकाले, आप ही के बजट के पेपर्स में से पढ़-पढ़कर निकाले हैं, कहीं और से नहीं निकाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, आप राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे थे, पता नहीं किस-किसकी आपने बात की। जो हमारा शेयर था एग्रीकल्चर का, पूरे राजस्थान की इकोनॉमी में वो हमारे टाइम में था 26.74 परसेंट और आपके टाइम

में क्या हो गया? वो 26.72 परसेंट, यानी वो कम हो गया। इसी तरह इण्डस्ट्री में यह हुआ। इण्डस्ट्री में हमारे टाइम की ग्रोथ थी 27.90 परसेंट और आपके टाइम की ग्रोथ आ गयी 27.16 परसेंट। आपने जो भी बढ़ाया अपना वो इनसर्विस सेंटर में बढ़ाया, वो भी by only 6 per cent and as compare to 2023-24, यह फिगर्स मैं वो दे रहा हूं, डबल इंजन की सरकार थी, हम तो सोचते थे कि इधर से पैसा ले आयेगी, उधर से पैसा ले आयेगी, हम तो यही ख्वाब में थे कि डबल इंजन की सरकार आयेगी, पैसा बहुत आयेगा।

धौलपुर जिले को एक करोड़ रुपये दिया है इस बजट के अन्दर, धन्यवाद। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, दोनों का धन्यवाद, एक करोड़ रुपये मिला है धौलपुर को ...(व्यवधान)... हां, एक करोड़ रुपये, पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट को।

डिजास्टर मैनेजमेंट फण्ड आता है, 2024-25 में डिजास्टर मैनेजमेंट फण्ड था 1878 करोड़ रुपये का, 2025-26 में क्या हुआ? 1800 करोड़ रुपये कर दिया, डबल इंजन की सरकार। रूरल लोकल बॉडी में, इस बार आपके प्रधानों को और जिला प्रमुखों को पैसा कम मिलेगा, मानकर चलियेगा 15वें वित्त आयोग का, आपको मिलना था 3775, जब अपनी सरकार थी, इस बार मिलेगा 3087 करोड़, मतलब 700 करोड़ रुपये तो कम किये हैं, डबल इंजन की सरकार है। इसी तरह से अरबन लोकल बॉडी का, हमारे को 2023-24 में मिला 2877 करोड़ रुपये, इस बार क्या मिलेगा 1818, मतलब, you are down by almost thousand crore rupees in the Urban Local Bodies. सिर्फ, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। हेल्थ ग्रांट्स के अन्दर हमारे टाइम में मिला 152 करोड़ रुपये, इस बार क्या मिल रहा है, 0/0, यह है डबल इंजन की सरकार।

माननीय सभापति महोदय, अब अपन हेल्थ बजट पर आ जाते हैं। इस साल के हेल्थ बजट का आपने प्रोजेक्शन दिया है कि हेल्थ पर हम खर्चा करेंगे 13,888 करोड़ रुपये, हमारे गजेन्द्र सिंह जी नहीं, क्या दशा हो रही होगी, मैं समझ सकता हूं। लास्ट ईयर आपने इनको दिया था 27,707 करोड़ रुपये, मतलब 50 परसेंट लेस, 50 परसेंट यानी हम खर्च ही नहीं करेंगे, लोगों की बीमारियों पर खर्च ही नहीं करेंगे? ...(व्यवधान)... मैं नेक्स्ट इयर की बात कर रहा हूं, विश्नोई जी। विश्नोई जी, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। पढ़ो, पहले बजट पढ़ो। मंत्री हो, इसलिए बजट पढ़ो। ...(व्यवधान)... पहले पढ़ लो बजट, यह बजट के फिगर्स हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, आपस में बात नहीं करें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): छह महीने का बता रहे हो क्या?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): छह महीने का बजट दिया है क्या आपके मंत्री ने? ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, आपस में न उलझें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): और दूसरी स्टेट्स खर्च करती हैं 6.2 परसेंट, पूरे भारत की एवरेज है 6.2 परसेंट। आपकी क्या एवरेज आयी, 3.7 परसेंट। तो मतलब आपको राजस्थान की जनता का दुख-दर्द आप अपने झेले में नहीं ले सकते हो बजट में, क्योंकि बीमार ही नहीं

होती राजस्थान की जनता, राजस्थान की जनता तो बिलकुल ठीक ही रहती है, बीमार ही नहीं होती। ...(व्यवधान)...

In agriculture, we are spending 4.4 per cent जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 4.4 परसेंट। पूरे भारत देश का जो एवरेज है, सब स्टेट्स का एवरेज है दैट इज 6.3 परसेंट। जो बात कर रहे थे न हम कि किसानों के लिए यह कर रहे हैं, हम किसानों केलिए वो कर रहे हैं। तो आपने 2 परसेंट लेस दिया है बजट।

इर्रिगेशन में हम 2.9 परसेंट खर्च कर रहे हैं और एवरेज है 3.4 परसेंट का, ...(व्यवधान)... ।

अब मैं आपकी बात करना चाहता हूं। युवा सम्बल योजना, जो मैंने कहा था कि आपने क्या किया, युवा सम्बल योजना में आपका बजट था 867 करोड़ रुपये का, आपने खर्च कितना किया, 448, आधा, करीब-करीब आधा, यह बजट का हाल है। मैंने कहा न कि बजट की सिर्फ विण्डो ड्रेसिंग है, अन्दर कुछ भी नहीं है। यह मैं प्रूव कर रहा हूं आपको। इसी तरह से कल के न्यूज पेपर में, एक पीएलएफएस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्वे कम्पनी है, अनएम्प्लायमेंट पर सर्वे करती है। उनका कल सर्वे था इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें यह कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अनएम्प्लायमेंट है तो, we are third in this Country. हमारे यहां अनएम्प्लायमेंट इज 9.73 परसेंट, यह कल की रिपोर्ट है। यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का ऑर्गेनाजेशन है, जिसकी रिपोर्ट है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। ...(व्यवधान)...

आपने सड़कों पर बजट दिया लास्ट टाइम, मैंने उप मुख्य मंत्री से कुछ क्वेश्चन पूछे थे तो वो मेरे से चिढ़ गयी थी कि आप गलत कह रहे हो।

MLS/RTM/20.02.2025/15:50/2o

आपको बनानी थीं 11,755 किलोमीटर की नयी सड़कें। दिसम्बर तक कितनी बनीं, क्योंकि अभी प्रतिवेदनों में फिगर्स मुझे दिसम्बर तक की ही मिली हैं, 5635, 48 परसेंट, जबकि बन जानी थीं 75 परसेंट। कैपिटल आउटले है ही नहीं तो कहां से बनेंगी? पैसा खर्च कर चुके हैं। जो पुरानी लायबिलिटी थी, वह नयी लायबिलिटी में एडजस्ट कर दी। अब वे और इससे ज्यादा बनेंगी भी नहीं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): जुलाई से दिसम्बर तक कितना हो गया?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, जुलाई नहीं, अभी दिसम्बर की बात कर रहा हूं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): बजट तो जुलाई में आया था।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सरकार, अभी की बात कर रहा हूं मैं। ये सड़कें आपने कौन-सी बनायी हैं, are you even aware? क्योंकि आपने जो पैसा दिया है, आप पैसा दिखा रहे हैं कि पूरा खर्च हो गया, that means, हमारे टाइम की सड़कें आपने अभी बनायी हैं। ये उसके टाइम की नहीं हैं, पर यह तो सिर्फ किलोमीटर एडजस्ट करने के लिए आपने बोला है। आप समझ लीजिये। इसी तरह जो सुदृढ़ीकरण हुआ है रोड्स में, जो आपको बनानी

थीं 25,528 किलोमीटर की सड़कें, आपने उसमें बनाईं 13,495 किलोमीटर की सड़कें, सिर्फ 52 परसेंट। सुदृढ़ीकरण किया, नवीनीकरण किया सिर्फ 52 परसेंट।

सबसे बढ़िया चीज क्या हुई, साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि जयपुर में 7 आरओबीज, फ्लाई ओवर्स, आरयूबीज, सब बनेंगे। हमने भी कहा साहब, बहुत जबरदस्त काम है। ए एंड एफ 2 की ही निकलीं। टेंडर 1 के भी नहीं हुए। फरवरी हो गया, मार्च खत्म हो जायेगा। जबरदस्त बजट। क्या बात है?

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या उप मुख्य मंत्री जयपुर से ही हैं?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हां, लगता यही है। आपने गरीब आदमियों के लिए शहरी अन्नपूर्णा योजना जो थी वह शुरू की। हमारे टाइम में राजीव गांधी थी, आपने अन्नपूर्णा कर दी। ...(व्यवधान)... इन्दिरा गांधी थी, आपने अन्नपूर्णा कर दी। आपको 250 करोड़ रुपया खर्च करना था और 18 फरवरी तक आपको 921 लाख थालियां देनी थीं। आपने सिर्फ 4 लाख 55 हजार थालियां परोसी हैं इन गरीबों को। बड़ी-बड़ी बातें की थीं न, मिलेट्स देंगे, यह देंगे, यह बढ़ा देंगे। यह हाल है आपका। आपने लोगों का खाना बन्द कर दिया। गरीब आदमियों की रोटी पर भी मार मार दी। ऐसी सरकार है आपकी।

इसी तरह से, शहरी नरेगा की अपन बात करें, हमारे टाइम बजट था 600 करोड़, हमने खर्च किया 534 करोड़। आपने बजट को घटा दिया 300 करोड़ तो। बहुत अच्छी बात है। 3.20 लाख फैमिलीज को आपको इसमें मस्टर रोल देनी थी, आपने रोजगार देना था, आपने कितना रुपया खर्च किया दिसम्बर तक, 113 करोड़। कितना जबरदस्त है, साहब, 50 परसेंट भी नहीं पहुंचे। कोशिश कर रहे हैं कि 3 महीने में 50 परसेंट तो पहुंच जाएं। यह आप सोचते हैं कि किस तरह से आप यूथ को इम्प्लॉयमेंट देंगे, किस तरह से आप गरीब आदमी को इम्प्लॉयमेंट देंगे, यह सोच है आपकी? आपने पिछले बजट में बात की थी, हम हजार इलेक्ट्रिक बसेज देंगे। ए एंड एफ कितनी निकली, रोड्स पर 6 महीने में कितनी बसें आईं, उसमें तो नहीं लगता न टेंडर में टाइम, एक भी नहीं आयी। ए एंड एफ निकली 675 बसों की, टेंडर हुआ, नहीं हुआ।

इसी तरह से आप इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को और ले लें। 5804 करोड़ का आपका बजट था, दिसम्बर तक आपने 2816 करोड़ रुपया खर्च किया, 48 परसेंट पैसा खर्च किया। यमुना का इन्होंने बजट दिया था डीपीआर का 50 लाख रुपये, यमुना से पानी आ रहा है आपके सीकर में। खर्च कितना हुआ, अण्डा, जीरो। परवन में हमारा बजट क्या था, 750 करोड़, खर्च कितना हुआ, 63 करोड़। धौलपुर लिफ्ट इर्रिगेशन में, जो इस बार लिखा न बड़े-बड़े लैटर्स में 950 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, धौलपुर लिफ्ट इर्रिगेशन का बजट 150 करोड़ और खर्च कितना, 41 करोड़। नौनेरा बांध, बजट कितना, 150 करोड़, खर्च कितना, 64 करोड़। ईआरसीपी का बजट 250 करोड़, खर्च कितना, 2 करोड़। यह 14 जिलों की स्कीम है न। क्यों, गर्ग साहब, 14 जिलों की स्कीम है और खर्च कितना, 2 करोड़ 22 लाख रुपया। माही अपर कैनाल, जो ट्राइबल एरिया का प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारा, 550 करोड़ रुपया दिया इन्होंने बजट

में, कितना खर्च किया, 135 करोड़। कालीतीर, 275 करोड़ का बजट, खर्च कितना किया, 94 करोड़।

सभापति महोदय, सबसे अच्छा हाल इन्होंने क्या किया, वह आपको बताना चाहूंगा। एक स्वामी विवेकानन्द योजना थी, जिसमें गरीब बच्चे बाहर पढ़ने को जाते थे, दो साल ऑलरेडी जा चुके थे। इस बार तो एक भी बच्चे को इन्होंने बाहर नहीं भेजा, उनके दो सेमेस्टर निकल गये, उनका रिजल्ट ही नहीं निकाला।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): यह गलत जानकारी है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): कितना है?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 200 बच्चे ई1 में निकल गये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): नहीं निकली। दो सेमेस्टर निकल चुके हैं। आपने जुलाई सेमेस्टर में नहीं भेजा, जनवरी सेमेस्टर में नहीं भेजा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): गुमराह मत करें आप। आप टेबल करें। आप टेबल करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): नहीं, बिलकुल गलत है। आप जवाब दिलवा देना मंत्री से।

श्री सभापति: प्लीज, आपस में नहीं। ...(व्यवधान)... प्लीज सदस्य, इधर चेयर को सम्बोधित करें, उधर नहीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, 225 करोड़ रुपये में से सिर्फ 81 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। बच्चों के कितने सेमेस्टर मिस हुए, वह नहीं बोल रहे हैं। कितने सेमेस्टर बच्चों के मिस हुए?

श्री सभापति: रोहित जी, सम्बोधित इधर करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): देवनारायण योजना थी, 371 करोड़ का बजट था, दिसम्बर तक क्या खर्च किया, 180 करोड़ रुपये। ...(व्यवधान)... इससे ज्यादा खर्च करते हैं क्या? काली भील योजना, जहां हम बच्चियों को स्कूटी देते थे। ...(व्यवधान)... कालीबाई भील योजना, 198.48 करोड़ का बजट...

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बजट ही अलॉट किया है, दी नहीं हैं स्कूटीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): नहीं दी न, स्कूटीज नहीं दी हैं, खुद ही कह रही हैं। आपका बजट था, मेरा बजट नहीं है। हम तो डेढ़ साल से नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, आपस में नहीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): एक था इनका राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, साहब। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। 167.44 करोड़ रुपया खर्च करना था राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान में। खर्च कितना हुआ, सोचो आप। 167 करोड़ रुपये में से कितना खर्च हुआ, इमेजिन करो, 4.13 करोड़। सैंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना था बच्चों का, 10 करोड़ का बजट। खर्च कितना, जीरो। शोध संस्थान, 10 करोड़ रुपये का बजट। अनाउंसमेंट कराये थे न, ये अनाउंसमेंट कराये खूब सारे। 10 करोड़ का बजट, खर्च कितना, जीरो।

पीएचडी पर रिसर्च फैलोशिप, 8 करोड़ का बजट, खर्च कितना, जीरो। व्यावहारिक प्रशिक्षण

कौशल, 8 करोड़ का बजट, खर्च कितना, जीरो। मेधावी स्कूटी योजना, यह तो मैंने एक पढ़ा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज शान्त।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): वो देखिये, वो बात कर रहे हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य, आप वहां बोलते हैं, इधर डिस्टर्ब हो रहे हैं सब।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अपनी जगह पर जाओ।

श्री सभापतिः प्लीज, आप इधर बोलिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, आप बोल रहे थे, इसलिये।

श्री सभापतिः मैं बैठा हूं।

Bhs/Rtm/20.02.25/16.00/2p

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेधावी स्कूटी योजना बच्चों की, 56 करोड़ का बजट, खर्च कितना? जीरो। ...(व्यवधान)... नामांकन, एक सेकंड, बच्चों का नामांकन कॉलेजेज में कितना हुआ? ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज। प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): लड़कों का नामांकन 1.03 प्रतिशत घट गया। इतनी अच्छी सरकार और बच्चियों के नामांकन का क्या हुआ, वह भी सुन लें साहब। बच्चियों का नामांकन 2.83 प्रतिशत घट गया। हमारे बड़े साहब ने बोला था। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बोल रहे हैं न। आप शान्त रहिये। वे बोल रहे हैं। सब अच्छा बोल रहे हैं। आप सुनते रहें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): विद्या सम्बल योजना में हमारे को बोला गया कि कोई टीचर नहीं हटेगा। हम भी बड़े खुश थे कोई टीचर नहीं हटेगा। मेरी कांस्टीटयूएंसी में मनिया मरेना, राजाखेड़ा में जितने विद्या सम्बल के टीचर लगे थे वो निकाल दिये गये हैं। सूरजमल यूनिवर्सिटी ने निकाल दिये हैं उनको वापस नहीं ले रहे हैं। बच्चे पेपर नहीं दे पायेंगे क्योंकि कोर्सेज ही पूरे नहीं हुए। यह मेरा नहीं है यह बच्चों के भविष्य से आप खेल रहे हो। कोई राजाखेड़ा में नहीं है यह सब जगह हुआ है सिर्फ भरतपुर के अलावा। यह पूरे भरतपुर सम्भाग में हुआ है सूरजमल यूनिवर्सिटी से जितने जुड़े हुए हैं सबका हुआ है यह हमारे का ही नहीं है और यह जब जवाब दें तो इस पर जवाब दिलवा दें, सभापति महोदय।

अब मैं आपको वुमन एंड चाइल्ड और थोड़ा सा बता देता हूं फिर फटाफट कर देता हूं बस। किसान बालिका योजना 13.34 करोड़ का बजट खर्च 5.52, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना जो कि सबसे बड़ी उनकी योजना है 406 करोड़ खर्च कितना? 216 करोड़। राष्ट्रीय पोषण योजना 144 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 14 करोड़। न्यू आंगनबाड़ी में दिसम्बर तक 29 करोड़ का बजट था, खर्च कितना? जीरो। इन्दिरा महिला शक्ति योजना 20 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 1.74, इन्दिरा मातृत्व पोषण योजना 150 करोड़ का बजट, खर्च

कितना? 67 करोड़ और सबसे बड़ी चीज... ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके टाइम का भी बताओ। ...(व्यवधान)... चाइल्ड योजना में 1198 करोड़ का बजट था ...(व्यवधान)...आपने 381 करोड़ खर्च किया। सी.ए.जी. की रिपोर्ट है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज। प्लीज मंत्री महोदय। जवाब दे देंगे। प्लीज। मंत्री महोदय।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सी.ए.जी. की रिपोर्ट आ ही नहीं सकती अभी। सी.ए.जी. की रिपोर्ट है 2023-24 की। जरा देखिये कौनसे साल की बात कर रहे हैं।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके टाइम की है ...(व्यवधान)... आपके टाइम की बात है। ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हमारे टाइम की बात मत करिये। आप पहले पढ़िये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर उलझो मत।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बीच में डिस्टर्ब मत करिये।

श्री सभापति: रोक दिया उनको।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सी.ए.जी. की 2023-24 की रिपोर्ट है अभी आ जायेगी क्या? साल खतम नहीं हुआ सी.ए.जी. की रिपोर्ट आ जायेगी? आप पहले पढ़िये।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके टाइम की है। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): गलत पढ़ लिया उन्होंने।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): गलत पढ़ लिया, कोई बात नहीं। अभी आंगनबाड़ी दूध योजना, कल-परसों उप मुख्य मंत्री ने अनाउंस किया कि हम 250 करोड़ का बजट सैंक्शन करते हैं। पिछले साल कितना था, 50 करोड़, खर्च कितना हुआ? जीरो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): दिल्ली में कांग्रेस की कितनी सीटें आईं? जीरो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): लाडो प्रोत्साहन योजना में सौ करोड़ का बजट ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सौ करोड़ का बजट और खर्च कितना हुआ? पच्चीस करोड़ तो ये तो इनके हाल है। एक्साइज पॉलिसी ये लेकर के आ गये। एक्साइज पॉलिसी में पूरे साल इनसे 200 दुकानें नहीं उठी। करीब-करीब नुकसान हुआ गवर्नमेंट एक्सचेकर को 5 सौ से 6 सौ करोड़, who is responsible? कौन सा ऑफिसर रिस्पोंसिबल है? आपने क्या एक्शन लिया? क्यों नहीं उठी ये 200 दुकानें? who is responsible? कोई एक्शन नहीं। सॉफ्टवेयर आपने ऐसा ले लिया अक्टूबर में जो अभी तक चाहिये। किसी का चालान होता है, किसी का माल चला जाता है। यह तो आपके हाल हैं। आपने अभी बहुत जोर-शोर से पेपर में न्यूज निकलवाई कि हमने 88 प्रतिशत दुकानों का ऑक्शन कर दिया शराब की दुकानों का। मतलब तीर मार लिया। उसमें रेवेन्यू कितनी थी? 60 प्रतिशत। जो 12 प्रतिशत की रेवेन्यू थी वो मिलती करीब 40 प्रतिशत क्योंकि अब आपने समूह बना दिये, वार्ड बना दिये तो ये

88 प्रतिशत से भी कम हो जायेंगी दुकानें क्योंकि उसमें भी कैंसीलेशन होगा। यह आपने ऐसी पॉलिसी बना दी और आपने क्या कर दिया, दस रूम के होटल को यदि ट्रेड लाइसेंस है तो होटल वेदर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बना, नहीं बना, कुछ हुआ, नहीं हुआ, आपने उसमें कह दिया शराब परोसो तो ये दुकान वाले क्या करेंगे? चना भूनेंगे क्या बैठे हुए?

सभापति महोदय, अब राइजिंग राजस्थान की बात और कर लेते हैं। राइजिंग राजस्थान, जबरदस्त 35 लाख करोड़ के एम.ओ.यू. शानदार सफलता। इसमें अस्सी परसेंट सोलर के हैं। जिसमें न तो राजस्थान सरकार को कोई रेवेन्यू होगी और न राजस्थान सरकार को ट्रांसमिशन का पैसा मिलेगा क्योंकि वह पॉवर ग्रिड का है, न रोजगार मिलेगा। हम अपना क्या देंगे? हम अपनी जमीनें, जो जैसलमेर से विधायक आये हुए थे वो उस दिन भी यह कह रहे थे, गरीब किसानों की जमीनें हम सस्ते में हम लुटा देंगे। किसको? बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को। हमारे को क्या मतलब? यदि हमने पी.पी.ए. साइन किया हो तो हम आपके साथ हैं। जहां पी.पी.ए. साइन किया है वहां आप सोलर लगाओ। जहां राजस्थान सरकार का पी.पी.ए. नहीं है फिर हमें सस्ती जमीनें क्यों देनी हैं, कौन ऐसा इन्सान है जो अपनी सस्ती जमीन दे देगा, लुटा देगा, जिसमें उसको एक पैसा नहीं मिले ...(व्यवधान)... 13 लाख करोड़ आयेंगे यू.ए.ई. फंड के सबसे बड़ी चीज तो वह है यू.ए.ई. फंड के 13 लाख सोवरेन फंड का पैसा आना। कहानी तो यह है राइजिंग राजस्थान के पीछे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इससे रोजगार कितना मिल रहा है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): रोजगार आप देखो। ...(व्यवधान)... बैठो-बैठो। वह भी बता रहा हूं।

श्री सभापति: प्लीज, मंत्री महोदय।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सुनो, सौ मेगावाट पर एक रोबोट लग जाता है। सौ मेगावाट पर एक रोबोटिक सिस्टम सैट हो जाता है आपको एक आदमी रखने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? आपको डवलपमेंट करना था तो आपकी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी थी उसके आप पेट्रो कैमिकल डाउनस्ट्रीम पेट्रो कैमिकल यूनिट्स लगाते वो तो आपसे हुआ नहीं और अपनी सस्ती जमीनें ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपस में नहीं। प्लीज इधर सम्बोधित करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप अपनी सस्ती जमीनें लुटा रहे हो। जो आपको करना था पेट्रो कैमिकल आपका प्लांट लग रहा था उसमें आपको लगानी थी पेट्रो कैमिकल डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपको लगते डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के अन्दर ...(व्यवधान)...

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): यह आंकड़े कहां से लेकर आये ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह आप ही की सरकार के आंकड़े हैं। आप ही की सरकार है किसी और के नहीं हैं। मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में एस्कॉर्ट्स कुबोटा का नया प्लांट आ रहा था। 19 जुलाई को उन्होंने अपना ई.ओ.आई. कैन्सिल किया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिख

कर। क्यों किया? न अलवर में जमीन मिली, जिसमें 20 हजार आदमियों को रोजगार देने की बात थी। न जमीन मिली, न बिजली सस्ती मिली, बिजली भी महंगी मिली। उन्होंने अपना ई.ओ.आई. कैन्सिल कर दिया तो यह हाल है आपकी सरकार के। बड़ी-बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। ...(व्यवधान)... एस्कोर्ट कुबोटा दे रहा था उसको आपने कैन्सिल कराया, आप जमीन नहीं दे पाये उनको टाइमली। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): हाउस के अन्दर ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): ...(व्यवधान)... +++ मत करिये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, सदस्य।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): ...(व्यवधान)... क्या मतलब है उससे?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बिलकुल मतलब है।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरा कोई मतलब नहीं है।

श्री सभापति: प्लीज, सदस्य।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मतलब क्या है? ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप बैठिये। आपको जवाब देना मेरा नहीं है ...(व्यवधान)... इसी तरह से ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप आपस में नहीं। प्लीज सदस्य, विराजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): ...(व्यवधान)... +++ करते हैं ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप करते होंगे +++ आप पत्रकार हैं आपने +++ से ही काम किया है। बातें आ रही हैं आपको ...(व्यवधान)... बात कर रहे हैं। बैठिये आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इन्क्लूड नहीं होगा।

(अध्यक्ष पीठ द्वारा हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश दिये।)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: प्लीज सदस्य। विराजिये। आपस में उलझ क्यों रहे हो? यहां नोट कर रहे हैं उनको जवाब देंगे मुख्य मंत्री जी। आदमी बैठा रखे हैं। ये जो भी जवाब दे रहे हैं वह नोट कर रहे हैं और जब यहां बोलेंगे रिप्लाई में जवाब दे देंगे। आपस में न उलझें। मुझे पता है समय का। मुझे पता है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... आपत्तिजनक शब्द डिलीट किये जायें।

श्री सभापति: प्लीज। प्लीज, अपनी बात कहें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ...(व्यवधान)... +++ का शब्द है वह डिलीट किया जाये। +++ का शब्द डिलीट करवाओ उसमें से। ...(व्यवधान)...

mkd/rtm/20.02.2025/16:10/2q

श्री सभापतिः आप विराजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पॉइंट ऑफ इंफार्मेशन।

श्री सभापतिः आप विराजिये। कोई ऐसा शब्द हो तो उसको इंक्ल्यूड न करें। वो बोल दिया, अब विराजिये। आप समाप्त कीजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इसी तरह डाइकिन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। डाइकिन इंडस्ट्रीज जापान की एक इंडस्ट्री है, जिसने यहां प्लांट लगा रखा है, बहरोड़ के पास। उनके यहां आदमी गये कि आप हमारे यहां इंवेस्टमेंट करा दीजिये, राजस्थान में इंवेस्टमेंट कर दीजिये। आपने इंवेस्टमेंट वहां नहीं करा, आप आंध्र प्रदेश चले गये इंवेस्टमेंट करने, जिस कम्पनी का यहां पर प्लांट था, वह यहां से छोड़कर आंध्र प्रदेश चला गया। क्यों गया? क्योंकि आपकी लैंड इतनी महंगी और आपने बिजली इतनी महंगी दी, इसलिए चला गया।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, आपस में नहीं उलझें। सुभाष जी मील।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने देख लिया यह बजट विंडो ड्रेसिंग बजट है और कुछ भी नहीं है।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय सभापति महोदय, बजट पर वाद-विवाद और बहस के लिए मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस शानदार बजट के लिए हमारी वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा को हमारी तरफ से और प्रदेश की आठ करोड़ जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी, सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला विशेष तौर से किसानों और युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला और एक आम आदमी को राहत देने वाला बजट, इस सदन के अन्दर हमारी सरकार द्वारा पेश हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जो पहला बजट पिछली बार सरकार ने दिया, जो स्वर्णिम बजट सरकार ने दिया था। अबकी बार इसी सरकार ने सोने पर सुहागा जैसा बजट देने का काम इस प्रदेश की जनता को किया है, इसके लिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार देख रहे हैं, जब सरकार ने पिछला बजट दिया और उसकी लगभग सभी योजनाओं को, कामों को पूरा करने का काम किया और जब कल बजट पेश होने के बाद हम जब क्षेत्र में प्रोग्रामों में गये तो एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि जो इतना बड़ा बजट आपने दिया, आप क्षेत्र के लिए भी इतने काम लाये, आज वे काम पूरे हो चुके हैं और दूसरा बजट पेश होने से पहले हो चुके हैं तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि यह प्रदेश के ऐसे पहले मुख्य मंत्री हैं, जिनका कोई व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडा

नहीं है, यह अपना पूरा समय प्रदेश की जनता को समर्पित करते हैं, इसलिए प्रभावी मॉनिटरिंग के द्वारा जो पिछला बजट था, वह पूरा करने का हम सबको मौका मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसी वजह से एक प्रभावी मॉनिटरिंग और समर्पित रहने की वजह से पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का शानदार आयोजन किया गया और लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किये गये, जिनमें से ज्यादातर अब धरातल के ऊपर आ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी मैं विपक्ष के साथियों का बजट पर वाद-विवाद सुन रहा था, मुझे विरोधाभास देखने को मिला। एक सदस्य यह कह रहा था, आपने डेढ़ लाख करोड़ रुपये प्रदेश के ऊपर कर्जे के लाद दिये। दूसरा सदस्य खड़ा होकर कह रहा था कि अधिकतर योजनाओं में आपने एक जीरो रुपया खर्च किया है। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि आपको सदन में क्या बोलना है, इसके लिए कम से कम पांच मिनट आपस में चर्चा तो कर लीजिये। यहां पर लोग देखते हैं। हम जो भी बोलते हैं। एक सदस्य एक बात कह रहा है, उसके विपरीत उसी पार्टी का सदस्य कह रहा है।

मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हम सदन में कोई भी आचरण करें या सदन के बाहर कोई आचरण करें तो जनता हमारा एनालेसिस करती है। हर चीज को बड़ी गौर से देखती है, इसलिए जब बजट पेश करने के लिए माननीया वित्त मंत्री जी यहां पर पहुंचीं, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर पहुंचे तो विपक्षी के सारे सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। भाई, आपके आचरण में सुधार कर लो। इन्हीं वजह से आज आप विपक्ष में बैठे हैं और अगर यही हाल रहा तो दो लाइनें आपके लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ना जमीं पे होगा, ना आसमां पे होगा, अब तुम्हारा वजूद केवल दास्तां में होगा।

इसलिए, जब भी कोई प्रदेश की बात आती है, जब प्रदेश के विकास की बात आती है, प्रदेश के विकास की बात हम करते हैं, विपक्ष का दायित्व है, हो सकता है कि हमारा किसी क्षेत्र में ध्यान न जाये, हम कोई सर्वज्ञानी नहीं हैं। अगर किसी क्षेत्र में हमारा ध्यान नहीं जाता है तो आपका दायित्व है कि उसकी तरफ आप सरकार का ध्यान आकर्षित करें, ना कि सरकार के कामों में आप व्यवधान पैदा करें।

आप सदन में खड़े होकर कितना ही असत्य बोल सकते हैं, लेकिन जनता हमको देखती है। जनता सरकार के कामकाज की तुलना करती है। जब आपको पिछले पांच साल में मौका दिया, आपको काम करने का मौका दिया, आपने क्या काम किये और हमें जो आज मौका दिया है, हम क्या काम कर रहे हैं, वह देखती है। आप लोग हवाई जहाज में बैठें, कहां जाने के लिए, जैसलमेर में होटल में जाने के लिए और हम लोग हवाई जहाज में बैठे, कुम्भ में स्नान करने जाने के लिए। यह फर्क है, आपमें और हममें। इसलिए, अगर आप यह सोचते हैं कि जनता को कुछ पता नहीं है तो साथियों में आपको कहना चाहता हूं कि जनता खुली नजरों से सब कुछ देख रही है और यही वजह है कि आज पूरे देश के अन्दर, अभी कह रहे थे आपके सदस्य, जीरो-जीरो-जीरो और फिर हमारे साथी ने जवाब दिया कि दिल्ली में क्या

हुआ तो फिर उन्होंने कहा, फिर जीरो। यही हालात अगर रहे तो साथियों सुधार होने वाला नहीं है, मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं।

बजट के ऊपर सबसे पहले मैं पेयजल के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी को, जिन्होंने राजस्थान में जहां पानी की समस्या, जो लोगों का दर्द है, उस दर्द को समझा और जल जीवन योजना को 2028 तक बढ़ाने का काम जिन्होंने किया, इसके लिए हम सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, सब लोग जानते हैं। आप प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में चले जाइये। किसी भी विधान सभा क्षेत्र में चले जाइये। अगर आप एक साधारण से साधारण व्यक्ति को पूछेंगे कि जल जीवन में पिछले पांच साल में कैसा काम हुआ तो जो ज्यादा नहीं जानता है, वह भी बता देगा कि जल जीवन में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं किया तो पिछली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन के अन्दर किया और लोगों को जो उनके हक का पानी था, जो लोगों के घरों में पानी जाना चाहिए था, वह लोगों के घरों तक पानी नहीं जा पाया।

माननीय सभापति महोदय, ये आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि इस एक साल के अन्दर 1 हजार 301 करोड़ रुपये के कार्यादेश और 41 हजार 621 करोड़ के टेंडर हमारी सरकार ने जल जीवन योजना के अन्दर जारी किये हैं, मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आगामी एक साल के लिए 20 लाख घरों में नल के कनेक्शन देने का लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया है और उसकी घोषणा की है और साथ ही 183 नगर निकायों के लिए 5 हजार 123 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। जो शहरी क्षेत्र हैं, उनमें लोगों की भावना को देखते हुए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी को प्रारम्भ करने की घोषणा इस सदन के माध्यम से, इस बजट के माध्यम से बजट में की गई है, इसके लिए मैं शहरी निकायों के लोगों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं।

Kas/rtm/20.02.2025/16.20/3a

माननीय सभापति महोदय, यह एक ऐसा सुखद प्रयास है, इसके द्वारा 5,830 करोड़ रुपये के कार्य चरणबद्ध रूप से शहरी निकायों में किये जायेंगे। साथ ही ग्रीष्म ऋतु के लिये 1000 ट्यूबवैल और 1500 हैंडपम्प और 142 करोड़ रुपये के कंटींजेंसी प्लान की घोषणा इस बजट में की गई है, ताकि गर्मी में हमारे प्रदेश की जनता को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उनको आसानी से पीने का पानी मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, कल बजट पेश हुआ, उसके बाद में विपक्षी पार्टी के मुखिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर एक बात कही कि यह केवल आंकड़ों का जाल है, एक रुपया खर्च

नहीं किया जायेगा। कोई काम नहीं होगा, केवल इधर से उधर घुमा रहे हैं। मुखिया जी, मैं इस सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं पिछले कई सालों से राजस्थान की जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने इस दिशा में बड़े स्तर पर काम करना शुरू किया। ईआरसीपी, जिसे अब हम राम जल सेतु लिंक परियोजना बोलते हैं, उसके लिये काम करना प्रारंभ किया। यमुना जल के लिये डीपीआर बनाने का काम शुरू किया। यह पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं, जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए, जो लोग कहते थे कि राजस्थान में पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, उसके लिये दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए इस पर काम करना प्रारंभ किया। केन्द्र सरकार से और दूसरे प्रदेश की सरकारों से समन्वय स्थापित कर के समझौते किये और यह लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं। इसको केवल यह डीपीआर बता रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हजार किलोमीटर की यात्रा करने के लिये भी पहला कदम रखने की जरूरत होती है। इसी प्रकार से बड़ी योजना बनाने के लिये डीपीआर की भी जरूरत होती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहता हूं कि हमारी नीति और नियति पर किसी को शक नहीं होना चाहिये। हमने कदम बढ़ाये तो हैं। मैं दो लाइनों के माध्यम से विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि

हमें मंजिल मिल ही जायेगी, जरा रुक कर ही सही।
तुम तो वो मुसाफिर हो, जो घर से कभी निकले ही नहीं।

हमने काम करना शुरू तो किया है, हो सकता है किन्हीं कारणों से इसमें दो दिन की देरी हो सकती है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्री जी, सब लोग मिल कर इस प्रदेश की जनता के लिये पानी की समस्या का समाधान करने के लिये कटिबद्ध हैं, यह मैं इस सदन के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राम जल सेतु लिंक परियोजना के लिये जो लोग आरोप लगा रहे थे कि यह हमारी पहली सरकार के किये हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 9,416 करोड़ रुपये के कार्यादेश तथा 12,064 करोड़ रुपये के टेंडर इस सरकार ने एक साल में जारी किये हैं तथा 12,807 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां अब जारी हो चुकी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप आरोप कितने भी लगाइए, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग हमारी मंशा को देख रहे हैं कि हां, यह सरकार कुछ करने वाली है। हां, यह सरकार लोगों के दुःख-दर्द को समझती है, हर वर्ग के दुःख-दर्द को समझती है। माननीय सभापति महोदय, विभिन्न जल परियोजनाओं के संचालन के लिये, इनकी प्रभावी मोनेटरिंग के लिये सरकार ने राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना करने की घोषणा की है, जिसके माध्यम से आगामी वर्ष में 4,000 करोड़ रुपये कार्य किये जायेंगे, यह मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बजट में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिये 1,250 करोड़ रुपये की सब्सिडी की घोषणा की गई है। साथ ही जल समस्या को देखते हुए, लोगों

की समस्याओं को देखते हुए 25 हजार फार्म पोंड, 10 हजार डिग्गियां और 50 हजार सौर पम्प संयत्रों व पाइप लाइन के लिये 900 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इसके द्वारा प्रदेश के लगभग 4 लाख किसानों को फायदा होगा, यह मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हम तो पहली बार आये हैं, हम तो नये लोग हैं, हमको इस सदन में बैठने का पहली बार मौका मिला है, लेकिन जो आचरण हम विपक्ष का देख रहे हैं, जो सहयोग की भावना होनी चाहिये, उस जगह पर ये लोग विरोध कर रहे हैं। बजट में युवाओं के लिये भर्तियों की जब घोषणा हो रही थी, जब सवा लाख भर्तियों की घोषणा माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अपने बजट में की, तो सामने से विपक्ष के लोग विरोध की बातें कर रहे थे, यह शर्म की बात है। प्रेस कांफ्रेंस में इनके मुखिया जी कल एक बात और कह रहे थे, उस ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन्होंने यह कहा कि इस सरकार ने जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो युवा साथी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिये एक भी घोषणा नहीं की है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है 1,000 की जगह 900 भर्तियां निकाल दें, लेकिन 900 के 900 वो युवा साथी लगेंगे, जिन्होंने मेहनत की है। आपकी सरकार में तो पेपर लीक की बात होती, तब भी अलग बात होती, आपकी सरकार ने भर्ती के समय यह तय कर दिया कि यह 1,000 हमने नौकरियां निकाली हैं तो किन लोगों को यह नौकरी दी जायेगी, यहां तक आप लोगों ने पहले तय कर दिया था।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने प्रदेश के नौजवानों के लिये राजस्थान रोजगार नीति, 2025 की घोषणा की है और इसके सफल क्रियान्वयन के लिये 500 करोड़ रुपये की विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष की स्थापना की है। जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को काउंसलिंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटर्नशिप, एग्जामिनेशन सेंटर और रोजगार शिविर लगाकर लाभान्वित किया जायेगा, यह बात मैं कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के 25 हजार एससी, एसटी महिला उद्यमियों को केंद्रीय बजट के माध्यम से उद्यमिक रोजगार, नये उद्योग धंधे लगाने का मौका दिया जायेगा और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के द्वारा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 परसेंट ब्याज की सब्सिडी और 5 लाख रुपये की मार्जिन मनी उपलब्ध करवाई जायेगी, यह मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं। प्रदेश के युवाओं के लिये 1,500 नये स्टार्टअप की घोषणा बजट में की गई है। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं इनमें से 750 स्टार्टअप के लिये फंडिंग उपलब्ध करवाई जायेगी, जिससे प्रदेश के युवाओं को बेहतरीन मौके मिलेंगे। आगामी साल में 50 हजार युवाओं को स्किल डवलपमेंट का कोर्स कराया जायेगा, जिससे निश्चित रूप से उनके रोजगार की राह आसान होगी और साथ ही 150

करोड़ की लागत से कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जायेगा, जिससे निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य बेहतर बनेगा, यह मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 500 विद्यालयों में अटल टिंकरिग लैब की स्थापना, अलवर, अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटोरियम और भरतपुर, कोटा, अजमेर व बीकानेर के साइंस सैक्टर में इनोवेशन हब की स्थापना करने की घोषणा निश्चित रूप से आने वाले समय में युवाओं को बेहतरीन मौका देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह लोग किसानों की बातें करते हैं। बड़ी जोर आवाज में किसान की बात बोलने का प्रयास करते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं पिछले पांच साल में ऐसी कौनसी योजना आप लोग लाये, जिससे किसान का भला हुआ? मैं बताना चाहता हूं कि इस एक साल के कार्यकाल में माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी ने प्रदेश के किसानों की पीड़ा को समझते हुए, इनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हुए जो 6000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को दिये जाते हैं, उसको बढ़ा कर पहले साल में 8000 किया और अबकी बार उसको 9000 रुपये करके प्रदेश के किसानों की समृद्धि के रास्ते खोलने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, मैं यह बात कहना चाहता हूं।

Msk/rtm/20.02.25/1630/3b

माननीय सभापति महोदय, 50 हजार कृषि कनेक्शन आने वाले एक साल के अन्दर किसानों को दिये जायेंगे और प्रदेश के 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर लंबी तारबन्दी के लिए 225 करोड़ रुपये सरकार उपलब्ध करायेगी, जिससे आवारा पशुओं से उनकी खेती की रक्षा हो सके। 1 लाख हैक्टेयर में नैनो यूरिया, नैनो डीआरपी छिड़काव करने के लिए 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर का अनुदान प्रदेश के किसानों को दिया जायेगा और किसानों को संबल देने के लिए केसीसी की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में काम करके दिखाया है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये बिना ब्याज के वितरित किये जायेंगे, जिसके द्वारा 768 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदेश के किसानों को दी जायेगी, मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री सुभाष मील (खंडेला): सर, मैं लास्ट एक मिनट आपका लेना चाहूंगा। सड़कों के अन्दर 5 हजार करोड़ की सड़कें बनायी हैं। मैं काफी कुछ कहना चाहता था, समय की

पाबन्दी है, डेढ़ सौ यूनिट फ्री बिजली, जिनको सौ यूनिट आज वर्तमान में मिल रही है, उन परिवारों को सौर पैनल के माध्यम से डेढ़ सौ यूनिट बिजली फ्री में दी जायेगी। सर, मैं आपकी एक-दो मिनट लेना चाहूंगा। आप जिलों की बात कर रहे थे। माननीय श्रवण जी, सबको पता है, जिलों का निर्माण किसलिए हुआ? जिलों का निर्माण बिना लोगों की राय लिए आपने अपने नेताओं को निपटाने के लिए कर दिया।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये। माननीय घनश्याम जी।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में दो लाइनों के साथ में मेरी बात को खतम करुंगा। मुख्य मंत्री जी की तरफ से दो लाइनें कहना चाहूंगा।

जब आंखों में अरमान लिया,
मंजिल को अपना मान लिया,
है मुश्किल क्या, है आसान क्या,
जब ठान लिया तो ठान लिया।

धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की जनता में इस बजट से बहुत निराशा छायी हुई है। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, बड़े दु:ख के साथ बोलना पड़ रहा है कि इस बजट में पूर्वी राजस्थान को कुछ नहीं मिला।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): निराशा का भाव लग रहा है, दो-चार साथी बचे हैं, मेरे लिए...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय भजन लाल जी भरतपुर से ही आते हैं, वहां जनता को बहुत निराशा हाथ लगी है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूं। गांव में एक रामलीला आयी। उस रामलीला में ...(व्यवधान)... आप तो मेरा ही गांव मान लो। जब रामलीला चल रही थी तो बीच में एक दिन रामलीला ड्रॉप हो गयी। गांव के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि रामलीला करो। रामलीला वालों ने कहा कि साहब, आज तो हमारे हनुमान जी को ताव चढ़ रहा है, बुखार आ रहा है, इसलिए आज रामलीला नहीं होगी। गांव के लोगों ने कहा कि गांव इकट्ठा हो गया, आपको रामलीला करनी है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह कौनसा बजट पर भाषण है?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): जोगाराम जी, सुनिये, एक मिनट सुनिये। हुआ क्या था? उन्होंने कहा कि गांव में कोई मोटा आदमी हो तो उसको ले आओ, हम उसको हनुमान जी बना देंगे। गावं वालों ने ढूंढकर उनको बताया कि हमारे गांव में भोलू हलवाई है। जब उस भोलू हलवाई से जाकर पूछा तो उसने कहा कि मैं तो सौ रुपये लूंगा। मेरे को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरे को सौ रुपये दे दो, हनुमान जी का पार्ट कर दूंगा। तो हलवाई को वहां ले आये। हलवाई ने कहा कि मुझे करना क्या है? कि भई तेरे को तो यहां हुप, हुप

करना है। तो वह तख्त पर हुप, हुप करने लगा और जब पर्दे के अन्दर से रावण आया तो उसने कहा कि यह बन्दरी का बच्चा क्या कर रहा है? कि देख भाई महाराज, मैं तो सौ रुपये में आया हूं, मेरे को मत मारे तू, मेरा कोई लेना-देना नहीं है। यह इस बजट में जो स्थिति हुई है +++ मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि भोलू हलवाई की स्थिति ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसे डिलीट कराइये, मेरा आपसे निवेदन है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह क्या कह रहे हैं, ऐसी घटिया सोच है, इनकी। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, इनकी कितनी घटिया सोच है? यह कांग्रेस की सोच है।

श्री सभापति: यह हिस्सा परिपेक्ष्य में नहीं आना चाहिए। ...(व्यवधान)... प्लीज सदस्य, प्लीज सदस्य, ऐसे शब्द न बोलें, हमारे इसमें एंट्री करने में दिक्कत आये। हो गया।

(माननीय सभापति महोदय द्वारा इशारे के माध्यम से हटाने को कहा)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय आप नोट कर लें, आपके विधायक का यह स्तर रह गया है। बजट पर बोल रहे हैं, शर्म पर आनी चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अब शान्त रहो, मैं वहीं आता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): भोलू हलवाई को ये भी समझ गये, सब समझ गये, अब कहने की क्या जरूरत है। सब समझ जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इस बजट से किसानों में, युवाओं में और सारी जनता में बड़ी ...(व्यवधान)... यह तो आपको पता लगेगा।

श्री सभापति: प्लीज सदस्य।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आज जो हालात प्रदेश में हो गये हैं, आप किसानों की स्थिति देखेंगे तो किसानों को आप चार घंटे बिजली नहीं दे पाये और प्रदेश में जिस तरह की हालत हुई है, हर तहसील में जो दो-तीन सौ ट्रांसफार्मर की जो डिमांड है, वह आप लोग पूरी नहीं कर पाये। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): असत्य बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हमारे यहां चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली है। मैं आपको सही बता रहा हूं, चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दे सके।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): श्रवण जी, आपने कहा कि नहीं कहा कि पूरी बिजली मिल रही है। श्रवण जी, बोलो। ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): ज्यादा हीरो मत बनो। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप शिक्षा दे रहे हैं, आप क्यों खड़े हो, आप बैठ जाओ। आप पहले बैठ जाइये, आप बीच में नहीं करे, नो। आप काफी देर से कर रहे हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, हाउस को कंट्रोल में लेकर आयी है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप क्यों उचक रहे हो?

श्री सभापति: प्लीज। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप नहीं बोल सकते ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, आप बैठिये। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ज्यादा उचकने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): संसदीय मंत्री जी, आप हमें तो तब कहना, पहले आप कृपलानी जी को तो समझा लो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। अपने उद्बोधन में ऐसा कोई शब्द नहीं बोलें, जिससे उत्तेजना हो। जब सदस्य बोल रहे हैं तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं। प्लीज।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप रोक ही नहीं रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप आसन पर दबाव मत बनाइये। अपने कृपलानी जी को समझाइये। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यहां रामायण बोल रहे हैं, कम से कम अपना स्तर तो समझिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मंत्री महोदय, मेरे को बोलने दो, जब भी मेरा नंबर आता है, आप लोग विवाद खड़ा कर देते हैं।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात रखिये। आपका समय जा रहा है, आठ मिनट हो गये हैं।...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है। आज आप रोजगार की बात करते हैं। अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम सवा लाख रोजगार देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये, सब बैठे हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप किस आधार पर रोजगार देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम सवा लाख नौकरियां देंगे? सवा लाख नौकरियों का आपने यह नहीं बताया कि किस डिपार्टमेंट ने नौकरी देंगे? क्या आप नरेगा के मजदूरों को नौकरी का आधार बतायेंगे या हमने जो पिछली बार जो भर्ती की थी। पिछली बार बजट में भी आपने सवा लाख नौकरियां देने का वादा किया था, आप एक नौकरी आज तक नहीं दे पाये हैं। आज प्रदेश में युवाओं की जो हालत है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार जिम्मेदार है। आज बेरोजगारी जिस हालत में है। इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मजदूरों की बात करते हैं। आपने कहा कि किसानों को हम छह घंटे बिजली देंगे। आप छह घंटे बिजली नहीं दे पाये। युवाओं को आप नौकरी नहीं दे पाये। आप एसटी के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे पाये,जो कि भारत सरकार पैसा भेजती थी। वह आज तक आपने नहीं भेजा। प्रदेश में इस तरह के हालात पैदा हो गये हैं कि आप

लोगों से जनता का विश्वास इस एक साल में ही उठ चुका है।

mdp/20.02.2025/16:40/3c

माननीय मंत्री जी, अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बाई-इलेक्शन में आप लोगों को पता लग गया। कहां गये ईंट से ईंट बजाने वाले, ...(व्यवधान)... कहां गये गमछा हिलाने वाले।

श्री सभापतिः प्लीज, विराजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): क्या हुआ दिल्ली में? ...(व्यवधान)... क्या हुआ हरियाणा में? क्या हुआ महाराष्ट्र में? हो गयी बहुत चिक-चिक।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): भाजपा सरकार स्वास्थ्य के मामले में, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार में 25 लाख रुपये की ...(व्यवधान)... मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना थी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): संसदीय मंत्री जी, अध्यक्ष के बाद में आपकी जिम्मेवारी होती है। ...(व्यवधान)... माननीय संसदीय मंत्री जी, सदन को चलाने के लिए अध्यक्ष के बाद आपकी जिम्मेवारी होती है और आप ही खड़े हो गये।

श्री सभापतिः प्लीज, सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मेडिकल डिपार्टमेंट पर बात करूंगा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार में 25 लाख रुपये की चिरंजीवी योजना थी। उसको आपने घटाकर 5 लाख कर दिया। उसमें भी कोरोना के समय पर जो वैक्सीन लगी थी, उसमें आप लोग कितने करोड़ रुपये खा गये। आज नकली वैक्सीन लगने से ...(व्यवधान)... नकली वैक्सीन लगने से।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप बताइए कौन खा गये? उस वक्त किसकी सरकार थी? ...(व्यवधान)... सरकार किसकी थी, नाम लीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप अभी बैठे हैं, ...(व्यवधान)... मोदी जी की वैक्सीन की मेहरबानी है, जो आप सदन में बैठ रहे हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, बैठ जाइए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सभापति महोदय, इनको रोकिए। ...(व्यवधान)... वैक्सीन लगने के कारण गांवों में आज नये-नये बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है। इस पर आपको और सरकार को सोचने की जरूरत है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आज 20-20 और 25-25 साल के बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है। इसका कोई कारण है और ये कारण सिर्फ और सिर्फ नकली वेक्सीन है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)... इसके कारण से जो हालात पैदा हुए है, आर.जी.एच.एस. योजना के तहत कर्मचारी/अधिकारियों को जो इलाज देते थे, वह आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बंद कर दिया है। पूरी तरह से आज उनको

न दवाई मिल रही है, न जांच हो रही है। प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरह की लूट हो रही है, उससे आम आदमी कितना परेशान है। जिस तरह के हालात प्रदेश में पैदा हो गये हैं, इनको सुधारने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में आप सिर्फ मोदी जी और भजन लाल जी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। जनता में जाकर काम करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... इनके नाम से ही काम नहीं चलने वाला, सिर्फ मोदी जी और मुख्य मंत्री जी के नाम से ही काम नहीं चलने वाला। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आपको पानी देना पड़ेगा, आपको बिजली देनी पड़ेगी। आप पानी की व्यवस्था करते हैं। आप जल जीवन मिशन के तहत देखिए।

श्री सभापतिः श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): टंकिया बना दी, वहां कोई आदमी नहीं है। आपकी मिस-प्लानिंग है।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। श्री छगनसिंह जी राजपुरोहित।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): सभापति जी, ये घनश्याम जी बाहर मेरे से तारीफ कर रहे थे बजट की और कह रहे थे कि मेरे ऊपर प्रेशर है।

श्री सभापतिः प्लीज, मंत्री महोदय। प्लीज, आपको पूरे दस मिनट दिए हैं।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सदस्य को यह ध्यान होना चाहिए कि माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणाएं तो पूरी होती हैं, ...(व्यवधान)... बजट में आये या नहीं आये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का बजट आया, इस बजट को पक्ष और विपक्ष दोनों ने सुना। बड़ी शांति से सुना अबकी बार। जब बजट आया तो इन्होंने एक बात की। इन्होंने सबने एक बात की कि ये सरकार घोषणा कर रही है और घोषणा करके वाहवाही लूट रही है। जब विपक्ष के साथियों ने इस प्रकार की बात की।

श्री सभापतिः प्लीज, आपस में बात मत कीजिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): आज मुझे बड़ा दु:ख हुआ माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य की बात सुनकर। हम इनको बहुत इंटेलीजेंट समझ रहे थे कि वित्त विभाग की इनको बहुत ज्यादा जानकारी है। जब ये बोलते थे तो हम सुनते भी थे लास्ट बार। इस बार इन्होंने जब बजट एट ग्लांस पर जो बोला है कि इस पर कितना खर्च किया, जीरो, इस पर कितना खर्च किया 20 करोड़, इस पर कितना खर्च किया, 50 करोड़, कम से कम ये आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। जिनको जानकारी नहीं थी, वह बोलते तो ठीक लगता। आपने जिस प्रकार से बात की है ये ठीक नहीं है। आपको बैठना पड़ेगा। आपको ये बात सुननी पड़ेगी।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको बात सुनकर जाना पड़ेगा।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज, आसन को संबोधित कीजिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापतिमहोदय, पूर्व वित्त मंत्री के बेटे, हम समझ रहे थे कि बहुत इंटेलीजेंट हैं। इस प्रकार से इन्होंने सदन को गुमराह करने का काम किया। जो भी बजट घोषणा होती है, जुलाई में बजट आता है, उसको हम जब लागू करते हैं, उसका टेंडर निकलता है, उसका प्रोसेस होता है। तीन-तीन महीने टेंडर की प्रक्रिया होती है। दिसम्बर तक कार्यादेश होते हैं। जब हम बजट -एट ग्लांस जारी करते हैं, तो उसमें व्यवस्था को छोड़कर कम ही खर्च होगा। हमने हिसाब बताया कि अभी तक हमने इतना खर्च किया है, पूरा खर्च नहीं किया है, लेकिन इतने तक हम आ गये। ये बात बताई है। आपने क्या कहा आपने क्या किया, इसमें जीरो, जीरो तो आपने दिल्ली में कमाया है। हम लोगों ने तो कमाया है, सरकार लायी है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सीनियर, उन्होंने भी बजट को नीरस बताया। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इन्होंने बजट को नीरस बताया, आपने देखा होगा कि किसानों के लिए कृषि बजट लाया गया था, लास्ट बार और माननीय मुख्य मंत्री जी यहां से बजट पढ़ते थे और वे यह कहते थे कि अबकी बार हम बिजली सरप्लस कर रहे हैं और वह भी 2021 से। हमने तो राजस्थान में बिजली देखी ही नहीं। सरप्लस की तो बात अलग, राजस्थान में बिजली चार साल तक आयी ही नहीं। ये तो भला हो माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा का, इस बार भी प्रोविजन है बजट में, 6400 मेगावाट नयी बिजली उत्पादित करेंगे। ये काम किया है। किसानों के लिए सिर्फ बात करने का काम करते थे, काम कुछ नहीं किया।

देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने पहली बार अन्नदाताओं को 6 हजार का सम्मान देने का काम किया किसान सम्मान निधि से और उसी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने पिछले साल 2 हजार बढ़ाया और इस बजट में 8 का 9 हजार कर दिया। ये कोई कम बात नहीं है। पहले अन्नदाताओं की सिर्फ बात होती थी। किसानों के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आ जाते थे। किसानों की चिंता नहीं की। पिछली वसुन्धरा राजे जी की सरकार थी, हम लोगों ने 10 हजार रुपये अनुदान दिया था, बिजली बिल पर। इन्होंने तीन वर्ष तक उस अनुदान को बंद करके चौथे वर्ष उसको 12 हजार किया। 30 हजार रुपये का नुकसान किसानों का इन्होंने करने का काम किया था।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से कुछ सवाल इन्होंने शुरू में किये थे। मैं उन सवालों पर थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये बात कहते हैं कि इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। सरकार जनता का भला करने के लिए आयी है। हम नुकसान में रहकर जनता का भला करेंगे, हित में कर रहे हैं। गरीब का कल्याण कैसे हो? गरीब कल्याण में प्रधान मंत्री आवास योजना के लाखों मकान बन रहे हैं। इनके विधान सभा क्षेत्रों में भी बन रहे हैं। एक-एक ग्राम पंचायत में 100-100 व 50-50 अभी स्वीकृत हुए हैं। ये जानकर

उनको पूछते हैं, आपके प्रधान मंत्री आवास योजना है, हमने स्वीकृत कराएं हैं, खुद अपने मुंह से कहते हैं और यहां पर आकर, सदन में आकर दूसरी बात करते हैं।

सभापति महोदय, मैं इनका कुछ बातों को लेकर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किसान सम्मान निधि की बात की, प्रधान मंत्री आवास योजना की बात की। आपने देखा होगा कि सरकार आते ही हम लोगों ने पेट्रोल-डीजल पर वेट कम किया। पास के गुजरात में, हरियाणा में, हमारे पड़ौसी विधान सभा के लोग पेट्रोल-डीजल खरीदने वहां जाते थे। हमारे किनारे-किनारे जिले के सिरोही के जो पेट्रोल पम्प थे, वह बंद हो गये थे। आज ये स्थिति है कि वापस बराबर भाव हो गये हैं। ...(व्यवधान)... कुछ रुपये का अंतर है, वह भी ठीक हो जायेगा। मैं कह रहा हूं 15-15 रुपये का फर्क था।

Ans/rtm 16.50 3d 20.02.2025

हमने कम करने का काम किया है। आपने देखा होगा एनएफएसए में गेंहू तो देते ही है 80 करोड़ लोगों को, उसके साथ राजस्थान के लोगों को भी दे रहे हैं। जब लास्ट टाइम बजट की घोषणा हुई थी आपने यह भी देखा होगा कि हमने कहा था कि हम 450 रूपये में रिफिलिंग कराएंगे गेस सिलेण्डर को, यह राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने काम किया है, इसके लिए आपको मेज थपथपानी पड़ेगी, यह काम किया है। आप लोग केवल आँकड़ों के जाल में हो कि इसमें 21 करोड़ हुए, इसमें 300 करोड़ रूपये हुए।

ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है इसकी चर्चा आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने 100-100 मेगावाट नई बिजली उत्पादन शुरू करने के काम की बजट में घोषणा की है। एक और बड़ी बात की है आपने देखा होगा, हम सब चर्चा करते हैं। लास्ट टाइम गर्मियों में बिजली नहीं आ रही थी, मैंने पूछा बिजली क्यों नहीं आ रही है, मंत्री जी से पूछा तो कहा कि इन्होंने बैंकिंग की हुई है, बैंकिंग में सस्ते में उधार ली और मंहगे दाम में वापिस देनी पड़ी। अब की बार यह व्यवस्था हम लोगों ने बंद की। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि बैंकिंग व्यवस्था बंद करने का काम किया। आने वाले समय में ज्यादा मंहगी नहीं लाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी। बिजली की कटौती गर्मियों में 18-18 घंटे होती थी, गाँवों में बिजली नहीं आती थी। पिछले पांच वर्षों तक हम फोन करते रहे, अधिकारियों से बात करते रहे, लेकिन इस बार हमारे मंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता से लेकर बिजली विभाग में सुधार किया है, मुख्य मंत्री जी भी कर रहे हैं। उन्होंनें 765 केवी जीएसएस खोलने की घोषणा की, 400 केवी जीएसएस की घोषणा की, 220 के 13 जीएसएस खोलेंगे, 132 के 28 जीएसएस खोलेंगे तथा 33/11 के 133 केवी जीएसएस खोलेंगे, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व वित्त मंत्री जी का खूब-खूब धन्यवाद करुंगा, इससे गाँवों में बिजली की समस्या आ रही है पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से बिजली आएगी। मैं भी चाहूंगा कि मेरे 33 केवी जीएसएस के कुछ गांव जोड़े जाए, कवला, भैसवाड़ा, कूण और आईपुरा। मुझे पता है 133 केवी जीएसएस हमारे 40 की आपने घोषणा की है उसमें और जुड़ जाएंगे, मुझे

विश्वास है कि इस प्रकार के 33 केवी के जीएसएस भी बनेगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने देखा होगा निशुल्क बिजली, अभी सोलर प्लांट पर, जिनके अभी 100 यूनिट फ्री है अब आने वाले समय में जो सोलर पैनल लगेगा 150 यूनिट तक फ्री देने का काम हमारी सरकार करेगी, मुख्य मंत्री का मैं इस पर भी धन्यवाद ज्ञापित करुंगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): सड़कों की बात करें। सड़कों में बाईपास, हाईवे, फ्लाईओवर, आरओबी के 05 करोड़ के काम होंगे। एक बड़ी घोषणा की है कि प्रत्येक विधान सभा में 10 करोड़ रूपये से नॉन पेचेबल रोड़ को किया जाएगा। अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य धोलपुर के लिए कह रहे थे, धौलपुर में एक करोड़ रूपये दिये हैं। आपके धौलपुर में कितनी विधान सभा है, चार तो होगी, चार का हिसाब करो तो चालीस करोड़ तो खाली सड़कों पर ही हो जाते हैं विधायक मद से विधान सभा क्षेत्र पर। पांच करोड़ विधान सभा मद से, यह कोई आपके घर से नहीं आता यह भी सरकार का ही पार्ट है। 20 करोड़ हो, 40 करोड़ हो, 60 करोड़ दिये जा रहे हैं।

हमारे बजट में आंगनबाड़ी की घोषणा की थी। प्रत्येक विधान सभा में 5-5 आंगनबाड़ी खोलने का किया था और खोलकर आपको देने का काम किया है। मैंने राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य से कहा तो उन्होंने कहा कि यह आपने थोड़े ही की है यह तो केन्द्र सरकार ने की है, तो डबल इंजन का यही तो है, हम दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। प्रधान मंत्री आवास योजना भी बनाएंगे, आंगनबाड़ी केन्द्र भी खोलेगे और किसान सम्मान निधि भी देंगे, हमने यह काम करने का प्रयास किया है।

जल जीवन मिशन की भी चर्चा कर रहे थे। माननीय सदस्य, जल जीवन मिशन की हालत आपने जो की थी, जब हम 2018 में चुनाव जीतकर आये थे, गाँवों में घूमते थे तो पूछते थे कि हर गांव पानी है या नहीं तो वह कहते थे कि हमारे गांव में हर घर नहीं है, हम तो एक जीएलआर पर पानी आता है वहां से भरते हैं। पूरे गांव वाले रात को एक बजे भी खड़े रहते थे। एक बजे पानी भरते थे। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी धरातल से छोटे से कस्बे से निकले हुए, उनको पता था कि गाँवों में क्या-क्या समस्या रहती है तो उन्होंने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन को पूरे भारत में लागू किया। राजस्थान में भी लागू किया लेकिन राजस्थान में जल जीवन मिशन की ऐसी दशा करी। हमारे कन्हैयालाल जी मंत्री टेंशन में थे कि समय नहीं बढ़ाया तो मेरा क्या होगा, बहुत तकलीफ होगी। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी व वित्त मंत्री जी का वास्तव में धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने 2028 तक तिथि बढ़ाई। यह काम छोटा नहीं है। मेरे विधान सभा में 100 गाँवों में आज भी हर घर पानी नहीं था। हर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन जैसी योजना है। आज हर गांव में बड़ी-बड़ी टंकिया बन रही है उच्च जलाशय की। हम लोगों ने काम करने का काम किया है, आप लोगों को इसकी बड़ाई करनी चाहिए। विपक्ष

का काम है जो गलत हो रहा है उसका विरोध करो ना कि परदे के पीछे बात हो रही है उसकी यूं ही मंच पर आकर बात करो। सत्ता पक्ष का काम होता है काम करने का, विपक्ष का काम होता है जो गलतियां है उसको बताओ। आप लोग गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह नहीं करें। हमारे सब मंत्री गंभीर रूप से बैठे रहते हैं, अगर यहां नहीं बैठे तो अपने कक्ष में बैठकर सुनते हैं, आप कोई भी विषय बताते हैं तो गंभीरता से सुनते हैं और पूरा-पूरा उसको ठीक करने का भी प्रयास करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करुंगा कि सत्ता पक्ष संवेदनशील है। हमारे मुख्य मंत्री जी संवेदनशील है। आप सभी से निवेदन करुंगा कि हम सब इसको आगे बढ़ाए। राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम सब साथ मिलकर काम करें।

भाजपा की सरकार में इससे पहले गौरव पथ बना था, उसकी की नकल करते हुए आपने विकास पथ नाम रखा। हम विपक्ष में बैठे थे, आपने घोषणा की कि हम चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाएंगे, मेज़ भी थपथपाई। हम लोगों को भी खुशी हुई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौरव पथ जैसा विकास पथ बनेगा। उस विकास पथ का क्या हुआ, आप सबको पता है। एक विकास पथ का काम शुरू किया और उस विकास पथ की दुर्दशा की। हमें भी दु:ख होता है, हम उस रोड़ से निकलते हैं तो। मैंने कहा कि मेरे से फण्ड लेकर कोई उसको ठीक करवा दो, बड़ा दु:ख होता है। पूरे पांच वर्षों में विकास पथ के नाम से एक पथ बनाया और दूसरा काम नहीं किया। आपको जानकारी देते हुए खुशी होगी कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने पहले साल अटल प्रगति पथ की घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत जिसकी दस हजार से ऊपर है वहां हम अटल प्रगति पथ बनाएंगे। अटल प्रगति पथ चार करोड़ के लगभग बन रहा है और तीन किलोमीटर का बन रहा है। दस हजार आबादी को, मेरी विधान सभा में भी दो का शिलान्यास हुआ है। उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री जी ने उसको पांच हजार की आबादी पर किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। अटल प्रगति पथ प्रत्येक पंचायत में धीरे-धीरे बनेगा लेकिन पांच हजार की आबादी का किया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): पांच करोड़ की सड़क आपको लास्ट टाइम दी थी।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। गणेश जी घोगरा।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, कुछ विषय तो रखने दीजिए।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। 2025-26 के बजट की घोषणा की है, मुझे तो लगता है कि यह बजट महलों में बैठकर बनाया है। जब बच्चा पालने में रोता है तो उसका रोना बंद कराने के लिए मां झुनझुना पकड़ा देती है, उस झुनझुने को देखकर बच्चा चुप हो जाता है।

VPS-RTM-20.02.2025-17.00-3e

उसी तरह से यह सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, वित्त मंत्री ने जो बजट घोषणा की है तो वह राजस्थान की जनता को झुनझुना पकड़ा दिया है। उस झुनझुना से यह जनता खुश हो जायेगी, यह बजट है। इस बजट में कुछ नहीं है। न आदिवासियों के लिए है, न महिलाओं के लिए है, न गरीब के लिए है, न पिछड़ों के लिए है, खाली थोथी घोषणाएं हैं, इस बजट घोषणा में।

माननीय सभापति महोदय, मैं जे.जे.एम. की बात करूंगा। आज गांवों में जे.जे.एम. की यह स्थिति है कि पूरे जो रोड बने हुए थे, वह रोड खोद दिये हैं और घरों में अभी तक पानी की एक बूंद तक नहीं गयी है, यह जे.जे.एम. की व्यवस्था है। भले ही शहरों में कहो, हमारे डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी जे.जे.एम. की टंकी नहीं बनी है किसी घर तक और ये घर-घर नल की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, लेकिन एक भी घर में एक बूंद पानी तक नहीं गया है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपके टाइम में तो आपने एक-एक खम्भे के लिए भी धरना दिया था। बिजली के खम्भे के लिए धरने पर बैठे थे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज। आपका नम्बर आये तब आप बोल देना। इनको बोलने दें। ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दो। आपका नम्बर आये तब आप जवाब दे देना। ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10-10 हैंडपम्प और पांच-पांच ट्यूबवैल की घोषणा की थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज तक एक हैंडपम्प का ठूंठा तक नहीं लगा है। यह है इनकी घोषणा। ये अभी जो बात कर रहे हैं, एक हजार ट्यूबवैल खोदेंगे और 1500 हैंडपम्प खोदेंगे तो पहले जो दिये हुए हैं उनको तो खोदो एक बार, उसके बाद तुम 1500 और हजार खोदो, मैं यह कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज हर पंचायत में हैंडपम्प मिस्त्री की आवश्यकता है लेकिन एक भी हैंडपम्प मिस्त्री नहीं है तो प्राइवेट लोगों को बुलवाकर गांवों में हजार, दो-दो हजार में ठीक करवाने पड़ते हैं तो मैं यह चाहता हूं कि इस बजट घोषणा में इनको हैंडपम्प मिस्त्री की भर्ती अलग से करनी चाहिए थी लेकिन यह हैंडपम्प मिस्त्री का इन्होंने कोई हवाला नहीं दिया है।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई की बात करते हैं, किसानों को पानी मिलना चाहिए लेकिन इसमें आदिवासी, दलित, गरीब और माइनोरिटी के प्रति इनके मन में यह भावना ही नहीं है कि आदिवासी आगे बढ़े लेकिन हमारे माही का पानी, जाखम का पानी, जयसमंद का पानी, सोम-कमला-अंबा का पानी जवाई ले जा सकते हैं, जालोर ले जा सकते हैं, चित्तौड़ ले जा सकते हैं लेकिन वह डूंगरपुर जिले में, जो कि वहां से बहुत नजदीक ही है, पचास किलोमीटर पर ही है, उनको नहीं दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, एक मिनट। एक मिनट।

एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति भवन पहुंचा दिया और कहां पहुंचाना है आदिवासियों को?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्या मन्दिर का उद्घाटन हुआ था, तब उनको बुलाया था क्या? मन्दिर के उद्घाटन पर उनको बुलाया था क्या आपने? राम मन्दिर के उद्घाटन में बुलाया था क्या आदिवासी को? ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): जो स्थानीय वहां के मूल निवासी हैं, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज। ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, पहले जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग जो टी.एस.पी. एरिये के हैं, उनके लिए कार्ययोजना बननी चाहिए थी। उनको पानी मिलना चाहिए था और उसके बाद बाहर वाले दूसरे जिलों को पानी मिलना चाहिए था।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): राम मन्दिर का शिलान्यास एक हरिजन, सफाई कर्मी के हाथ से करवाया था। चौपाल। ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, इस बजट घोषणा में एक एनिकट की चर्चा नहीं हुई। एक तालाब की चर्चा नहीं हुई और हमारे वहां पर टी.एस.पी. एरिया में बारिश बहुत होती है, ज्यादा होती है लेकिन वह पानी बहकर गुजरात में चला जाता है लेकिन यह कार्ययोजना नहीं बनाई कि हम वहां पर तालाब बनाये, वहां पर एनिकट बनाये, उस पानी को रोकें और किसानों को फायदा दें, यह इनकी कार्ययोजना नहीं बनाई।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि पुराने कुएं हमारे हैं, उनको गहरा करवाया जाये। उनकी मुँडेर बनाई जाए, नये कुएं खुदवाये जाएं, लेकिन यह कोई कार्य योजना इस सरकार ने नहीं बनाई। यह सरकार आदिवासियों के प्रति, दलित के प्रति इनकी यह भावना नहीं है कि ये भी आगे बढ़ें।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात करूंगा। अभी विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने बात कही कि हमारे समय में बिजली अभी खूब चौबीस घंटे आ रही है तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंगल फेस चार घंटे बिजली नहीं आ रही है, चौबीस घंटे की बात तो दूर रही, सिंगल फेस चार घंटे बिजली नहीं आ रही है और आप कृषि की तो बात ही छोड़ दो थ्री फेस की तो, वह पांच मिनट में ही ट्रिप होता है। पांच मिनट में ही ट्रिप होता है, क्यारी में पानी नहीं पहुंचता है, उससे पहले ही लाइट चली जाती है और फिर ये कहते हैं कि कटौती हो गयी, पावर कट आ गया तो इसका कोई अता-पता ही नहीं है कि बिजली कब आ रही है, कब जा रही है लेकिन हर महीने अब बिल आना चालू हो गया है। बिलों में करंट दौड़ना चालू हो गया है लेकिन बल्ब में, घरों में लाइट, बिजली वहां पर नहीं आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, अब माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट घोषणा में यह कहा है कि पचास हजार नये कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे। मैं वित्त मंत्रीजी से यह जवाब चाहूंगा कि हमारे बिछीवाड़ा ब्लॉक में 24 अप्रैल से डिमांड जमा है, 350 फाइलें किसानों की जमा है, आज तक उनको कृषि कनेक्शन नहीं दिया गया है लेकिन यह प्रावधान है कि एस.टी. को तीन महीने

में कनेक्शन दिया जाये और आप बात कर रहे हैं कि पचास हजार हम कृषि कनेक्शन दे देंगे। माननीय सभापति महोदय, यह कथनी और करनी में बहुत अंतर है।

माननीय सभापति महोदय, 220 के.वी. जी.एस.एस. हमारी सरकार में, गहलोत सरकार में सेंक्शन हो चुका है, डूंगरपुर के लिए जी.एस.एस. स्वीकृत हुआ है 2022 से लेकिन आज तक उसको चालू नहीं करना चाहते हैं। अगर यह 220 के.वी. जी.एस.एस. चालू हो गया तो हमारे यहां पर पावर कट कम हो जायेगा और बिजली की समस्या कम हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सड़क की बात करूंगा। सड़क के लिए कहा कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दस-दस करोड़ रुपये की हम नॉन पेचेबल सड़कें देंगे। हमारे साथ पक्षपात करते हो आप और यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करते हो। पहले भी आपने मिसिंग लिंक की पांच करोड़ की दी थी, पर अभी तक रोड बनी नहीं है और यहां बात करते हो? आपके घर से यह पैसा नहीं है, जनता का पैसा है यह, लेकिन विधायक से आप, उनसे अनुशंसा नहीं मांग रहे और आप बात करते हो कि हम हर विधायक को दस-दस करोड़ की सड़कें दे रहे हैं? इतना पक्षपात करते हो आप और बात करते हो? ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, इस बजट सत्र में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने दस-दस करोड़ रुपये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को दिये हैं, लेकिन टी.एस.पी. एरिये को माननीय वित्त मंत्री महोदय को देखना चाहिए। आपने मरुस्थल के लिए तो 15 करोड़ रुपये किये हैं लेकिन टी.एस.पी., जनजाति, अशिक्षित, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है वह, पिछड़ा हुआ है, उसके लिए भी 15 करोड़ रुपये करने चाहिए थे, लेकिन आपकी भावना से यह पता चलता है कि आपकी भावना आदिवासियों के प्रति नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बात करूंगा, 1500 करोड़ का अगले साल का तो कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। मंत्रीजी तो पता नहीं रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, मंत्रीजी के पास पावर ही नहीं है, रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, मैं साफ कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी बजट घोषणा में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 1750 करोड़ की घोषणा की है, इसमें यह भी लिख दिया है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अब यह पता ही नहीं पड़ रहा है कि यह अनुसूचित जाति के लिए है या अनुसूचित जनजाति के लिए है? ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): यह कहां पर खर्च करेंगे अब? इसका कोई अता-पता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो एस.टी. का पैसा है, वह जनजाति पर ही खर्च होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं यह आकड़े लेकर आया हूं। इनकी सरकार में यह एक हजार करोड़ का ही बजट था, 283 ही अलॉट हुआ था और...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः मंत्री महोदय, आपका नम्बर आये तब आप उस टाइम बोल देना। ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): भर्तियां होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, आप विराजिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): टी.एस.पी. क्षेत्र में अलग से विज्ञप्ति निकलनी चाहिए और अलग से भर्तियां होनी चाहिए और जनसंख्या के आधार पर हमको आरक्षण मिलना चाहिए, यह हमारे क्षेत्र की मांग है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दस मिनट मेरे हुए नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, एस.बी.पी. गवर्नमेंट कॉलेज हमारे डूंगरपुर जिले का एक बड़ा महाविद्यालय है। उसमें आठ हजार छात्र-छात्राएं, विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन वह बिलकुल जर्जर अवस्था में है। कभी भी वह गिर सकता है। कभी भी हादसा हो सकता है लेकिन यहां पर इस बजट में भवन के लिए कोई घोषणा नहीं की गयी है।

आज स्कूलों की हालत ऐसी हैं टी.एस.पी. एरिया में कि बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, कमरे नहीं हैं, जर्जर है लेकिन शिक्षा के लिए, भवन के लिए कोई बजट की घोषणा नहीं की है। इसमें पांच हजार के लगभग स्वयंपाठी विद्यार्थी भी आते हैं एग्जाम देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा की ये बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, आप समाप्त कीजिए। समाप्त कीजिए।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मनरेगा में कच्चे काम नहीं निकल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री विकासजी चौधरी।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): लोगों को पचास दिन भी काम उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है। उनको पलायन करना पड़ रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री विकासजी चौधरी।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मनरेगा में टी.एस.पी. एरिया में 200 दिन किया जाये और उनकी न्यूनतम मजदूरी चार सौ रुपया की जाये। माननीय सभापति महोदय, 2022-23 की स्कूटी भी अभी तक बाकी है देने की। ...(व्यवधान)...

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापतिः सॉरी, आपका नहीं है। इधर से श्री केसारामजी चौधरी का है। श्री केसारामजी चौधरी।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, 2022-23 की स्कूटी नहीं दी है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

SSY/RTM/20.02.2025/17.10/3f

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट केसाराम जी, एक मिनट ...(व्यवधान)... मंत्री जी से निवेदन है कि इनके 2 गाड़ी भिजवा देना, धरने पर नहीं बैठें। खुद की सरकार में भाई को धरने पर बैठना पडा था 2 पोल के लिए।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज। श्री केसाराम जी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप यही करोगे, दूसरा काम नहीं है आपके पास।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी सरकार का विजन होता है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान प्रदेश को किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगी, उसका सबसे पहला उदाहरण राजस्थान में जेजेवाई योजना का जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने बंटाधार किया, ऐसे चौपट किया, आज आकर देख लीजिए। इस तरह की इससे बढ़कर कोई भी योजना ग्रामीण जन के लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती थी। उस योजना की किस तरह से बर्बादी की उसका कोई उदाहरण देखना है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आकर देख लीजिये। पाइप भेज दिए, ना मालूम किधर टूटियां भेज दी, आज भी वहां पानी बह रहा है। उसको ठीक करने के लिए मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि उन्होंने 2028 तक की योजना को आगे बढ़ा करके राजस्थान की जनता को, गांव की जनता को पेयजल के लिए व्यवस्था आगे बढ़ाई है, उसके लिए हम उनके बहुत-बहुत आभारी हैं।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण पेयजल योजना के तहत मारवाड़ जंक्शन के फुलाद बांध पर रैपिड ग्रेविटी से पानी सुलभ कराने के लिए हमारे मंत्री जी ने जो काम किया है, 5 करोड़ 90 लाख रुपए देकर के फुलाद में छह गांवों के लिए पेयजल की योजना की स्वीकृति जारी की, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसके साथ ही मारवाड़ जंक्शन को जॉर्डन से जवाई बांध का पानी उपलब्ध कराने के कार्य 13 करोड़ 8 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की उसके लिए जल संसाधन मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। इसके लिए मैं, मेरी क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

इसके साथ ही ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना करने के लिए 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंड पंप देने का जो आपने इस बजट में प्रावधान किया है, निश्चित रूप से गर्मी के अंदर ग्रामीण लोगों को जहां तकलीफ है उसे तत्पता से दूर करने का काम किया है। ...(व्यवधान)... बिल्कुल, श्रवण जी, आपने किया होता ना तो बोलना ही नहीं पड़ता। आज आपने इस राजस्थान को इस स्थिति तक पहुंचा दिया था उसी का प्रतिफल है कि आज हमें इस काम को करना पड़ रहा है। 65 साल तक राज करने वाली कांग्रेस का आज दिल्ली के अंदर जाकर पूछो ना क्या हाल हुआ है? जिला परिषद् और पंचायत समिति में क्या हाल हुआ है? स्थिति को देखो जाकर, यही कारण है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहना

जानते नहीं, इसलिए मेहरबानी करके आप गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए।

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य, आपस में नहीं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जल जीवन मिशन में समुचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों की संविदा कैडर बनाते हुए 1050 पद स्वीकृत किए जाने की घोषणा का स्वागत करता हूं, ताकि वह जल जीवन मिशन का काम सही तरीके से हो सके। उसको सही क्रियान्वित करके, आज कहीं तो पाइप पड़े हैं, कहीं पर एक फिट खुदे हुए हैं, कहीं पाइप बाहर पड़े हैं, ऐसी स्थिति है माननीय सभापति महोदय कि हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। इन्होंने किस तरह से पाइप बेचे, किस तरह से ई.डी. का छापा पडा। पाइपों की खरीद में घोटाला किया। घटिया पाइप खरीदे। पानी डालते हैं, एसआर से पाइप जोड़ते हैं तो पाइप फट जाते हैं। ऐसी स्थिति इन्होंने की है। आज हमको इस योजना को ठीक रूप से सुचारू करने के लिए, एक कनेक्शन के पीछे एक ढाई सौ ग्राम की पीतल की टूटी लगानी थी मगर पाइप खुले पड़े हैं, पानी बह रहा है इसके लिए आप कोई जिम्मेदार नहीं है? इसलिए तो आपको उधर बैठना पड़ रहा है।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): एक साल में आपने क्या किया?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हमारी यह सरकार गांव की सरकार, मुझे डिस्टर्ब मत करिये। मैं एक-एक चीज का जवाब दूंगा।

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप चिंता मत करिए आप बीच में बोलोगे तो मैं भी आपके बीच में बोलूंगा, फिर मत कहना कि व्यवधान करते हो।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने बिजली के मामले में भारतीय जनता पार्टी के राज में साढे 6 घंटे बिजली दिन में और रात में साढ़े 7 घंटे बिजली हमारी पूर्ववर्ती सरकार में वसुंधरा जी ने दी थी। मगर इनके आते ही मात्र 5 घंटे बिजली देकर के पूरे राजस्थान के किसानों की बुरी हालत कर दी और डिमांड सारे निकाल करके भर दिए, कनेक्शन आज दिन तक हमारी सरकार कर रही है। मैं ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उसे आपूर्ति करके जो पैंडिंग जमा डिमांड थे उनके सारे कनेक्शन अभी पूरे होने वाले हैं।

हमारी सरकार कृत संकल्प है कि किसानों को साढ़े 6 घंटे बिजली देंगे और आने वाले समय में दिन में किसानों को बिजली देकर के उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। यह हमारी सरकार का विजन है। प्रदेश वासियों को बिजली की सुचारु व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए 225 विद्युत वितरण की पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जानी प्रस्तावित करके किसानों को फसल के समय नॉन ट्रिपिंग बिजली मिल पाएगी, इसके लिए भी हमारी सरकार पूरे-पूरे प्रयास में लगी हुई है। आगामी वर्ष 50 हजार नए कृषि तथा 50 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। यह भी हमारी सरकार ने घोषणा की है।

इसके साथ ही अधिक दर पर अन्य राज्यों से बैंकिंग करने की व्यवस्था जो की थी

आपने उधार में बिजली दी और वापस कब देनी है उसका कोई पता नहीं, हमारी सरकार को उस बिजली की भरपाई करनी पड़ी उसी के कारण आपके खामियाजे के कारण इस सरकार को इस मुसीबत से उबरने के लिए हमारे ऊर्जा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरह से पूरी बिजली देने की व्यवस्था की है।

इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए, 10 गीगावॉट ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य भी हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में 220 किलो वाट के 13 जीएसएस का निर्माण कार्य किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री जी, 220 किलो वाट के जो जीएसएस बना रहे हैं, उसमें मारवाड़ जंक्शन में 132 के तीन जीएसएस के सेंटर में और ऊपर से लाइन भी निकल रही है, बहुत ही कम खर्च में 220 किलो वाट का जीएसएस बन सकता है इसलिए मेहरबानी करके मेरे मारवाड़ विधान सभा क्षेत्र को भी 220 किलो वाट का जीएसएस दिलाने की मेहरबानी करायें।

इसके साथ ही क्षेत्र में सड़कों के विकास की बात करें, मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी और पीडब्ल्युडी मंत्री व उप मुख्य मंत्री जी दिया कुमारी जी का कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में सबसे महती सड़क पनौता से लेकर के सामेसर तक, 46 करोड़ रुपये देकर के गेनड़ी की नदी पर पुल देकर के मेहरबानी की है, उसका काम शुरू हो गया। यह बजट की घोषणा थी और उस काम को चालू कर दिया है। यह आप लोग कहते हो कि कहां धरती पर काम है? भाइयों, 6 महीने हुए हैं बजट रखे हुए, आने वाले समय में देखना यह गाड़ी पटरी पर चढ़ चुकी है और तेज गति से दौड़ती हुई विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का यह जो मोटो है कि ग्रामीण विकास सबसे पहले, उस मोटो को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सड़कों के मामले में अरावली से मारवाड़ एवं मेवाड़ को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से चार सड़कें निकलती हैं। जिसमें एक सड़क देसूरी की नाल वाली, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा एक्सीडेंट अगर कोई हुआ तो उस सड़क के अन्दर हुआ। क्या कांग्रेस सरकार उसकी सुध नहीं ले सकती थी? उनके जमाने में एक्सीडेंट हुआ था। अभी भी प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का कि जिन्होंने मौके पर जाकर के देखा कि इसमें एक्सीडेंट किस कारण से हो रहे हैं, उसकी कैसे रेमेडी की जाए, उसके लिए उन्होंने खुद जाकर के मौका देखा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार के दिल में यह है कि जो भी कमियां हैं उसको कैसे पूरा किया जाए उसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का बहुत ही तह दिल से आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं।

spp/rtm/20.02.2025/17.20/3g

दूसरा रास्ता दिवेर की नाल वाला है, जो भी मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ता है, उसमें भी आज दिन तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। मगर उस सड़क की चौड़ाईकरण करके रास्ते को

शुरू कर दिया जाये तो निश्चित रूप से पाली से उदयपुर की दूरी 20-25 किलोमीटर कम हो जाएगी।

इसके साथ ही काली घाटी का, जो बहुत ही खतरनाक रोड था। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला रास्ता था। मगर आये दिन दो-दो फीट के गड्ढे होने के कारण दुर्घटनाएं होती थीं, आपने उसको दुरूस्त नहीं किया, फोरेस्ट से एन ओ सी नहीं ली, उल्टी शिकायत की आपके विधायक ने, कि यह एन ओ सी के बिना सड़क बन रही है। हमारी सरकार का मैं धन्यवाद देता हूं, फोरेस्ट मंत्रीजी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फोरेस्ट से एन ओ सी दिलाकर उस सड़क को दुरूस्त करवाया। आज की तारीख में उसके मुकाबले कोई सड़क नहीं है और वहां पर रास्ता सुगम हो गया है।

इसके अलावा भी करमाल चौराहे से काली घाटी, झामुंडा से बिराखण होते हुए भीम का रास्ता, जो मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर और भीम तीनों विधायकों के मध्य होता है, जो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है, वह भी रास्ता करीब आधा तो सैंक्शन हो गया है, मगर शंकर सिंहजी के लिये थोड़ी सी कमी है पांच-सात किलोमीटर की, अगर वह पूर्ति हो जाती है तो यह भी रास्ता मेवाड़ और मारवाड़ के लिये अच्छा हो जाएगा। मेरा निवेदन है और मेरी मांग है कि इस बजट में मुझे एक भी सड़क नोन पेचेबल के अलावा नहीं मिली है, कृपया मुझे दो उपखण्ड, दो नागरिक तथा नव ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली एम.डी.आर. सड़क मारवाड़ जंक्शन से रानी तक की स्वीकृति जारी करने के लिये मेहरबानी करने की कृपा करें। मेरी ऐसी मांग है। ..(व्यवधान).. आप देखिए, आपके कारनामे बता रहा हूं।

श्री सभापतिः चौधरी जी, आप तो अपनी बात रखिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हमारी सरकार ने वसुन्धरा जी के राज में 4 स्थानों के लिये सार्वजनिक प्रभुदास जी का मन्दिर विकास जीर्णोद्धार विस्तार 50 लाख रुपये, सार्वजनिक काजलवास का मन्दिर विकास जीर्णोद्धार 50 लाख रुपये, सार्वजनिक बाहेड़ा भैंरू मन्दिर विकास जीर्णोद्धार विस्तार के लिये 50 लाख रुपये, सार्वजनिक कोटड़ा जी का मन्दिर जीर्णोद्धार के लिये 40 लाख रुपये स्वीकृत किये थे। इनका शिलान्यास हो चुका था। इनकी स्वीकृतियां जारी हो चुकी थीं, वित्तीय स्वीकृतियां भी निकल गयी थीं, शिलान्यास भी हो गये, मगर आपकी सरकार ने आते ही न मालूम वे पैसे खा गये, मंदिरों का पैसा था। वहां पर लगाते तो आपको क्या तकलीफ होती? मगर वह पैसा हमारी वसुन्धरा जी की सरकार में सैंक्शन हुआ था, इसलिए आपने रोक दिया या आपने उठा लिया या खा लिया, यह आप ही जानते हो।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): आप इसकी जांच खुलवा दो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां तो करेंगे न। छोड़ेंगे थोड़ी।

श्री सभापतिः प्लीज आपस में नहीं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह 22.6.2017 की स्वीकृति है। ए.एस.और एफ.एस. दोनों जारी हो चुकी थी। राज्य में विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 01 करोड़ रुपये

का तथा राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के लिये 60 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जाने की योजना प्रस्तावित की है। मंदिरों में भोग की राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह किया है। आप क्या देते थे?

श्री सभापतिः प्लीज सामने आसन को सम्बोधित करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप मंदिरों की बात करते हैं। कभी कुंभ की बात करते हैं। कभी हनुमानजी के लिये कुछ बोल देते हैं। भगवान के लिये तो कुछ बख्शो। हनुमानजी को हलवाई बना देते हैं। इनके तो राम ही निकल गये।

एक माननीय सदस्यः हम तो जय सीताराम बोलते हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जय सीताराम बोलते तो ऐसी बात नहीं करते। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पुजारियों के मानदेय को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया है। पूरे मंदिरों की पूजा को सुव्यवस्थित करने का काम किया है इसलिए भगवान भी राज़ी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन पर भगवान भी मेहबान है और राज भी मेहरबान है, दिल्ली की सरकार भी मेहरबान है उसके कारण से यह राजस्थान प्रगति के पथ पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जो सरकार का विजन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना अन्तर्गत आगामी वर्ष 6 हजार वरिष्ठों को हवाई मार्ग से ..(व्यवधान)..

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): यह योजना किसने चलायी थी?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप तो रजिस्ट्रेशन करवा देना, आपको भेजेंगे।

श्री सभापतिः प्लीज अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपको मालूम नहीं। हाथी के दाँत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। यह खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिये प्रभावी नियंत्रण। इसके लिये हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशाला स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आपके राज में रानी में..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः प्लीज समाप्त कीजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): घी की नकली फैक्टरियां चलती थीं। उनकी जांच की। बाद में सैम्पल पास हो जाता है। न मालूम कहां से घी आता है, इतना दूध भी नहीं है। रानी में तीन फैक्टरियां चल रही थीं।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): आपकी सरकार है, जांच कराओ।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसीलिए तो यह प्रयोगशाला लगा रहे हैं। यह प्रयोगशाला लगेगी न, तो यह कौन लोग है, यह पता लग जायेगा कि आपके लोग कैसे-कैसे घटिया काम कर रहे हैं।

श्री सभापतिः आप बिराजें। विकास जी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आपने बजट 2025-26 के सामान्य वाद-विवाद पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं

आपका आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही आभार प्रकट करता हूं हमारे सदन के नेता, प्रतिपक्ष का और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कि मुझ नौजवान विधायक को बजट पर प्रथम दिन बोलने का अवसर प्रदान किया।

माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने गोपालदास नीरज की पंक्तियां पढ़ीं, उन पंक्तियों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं-

कि नफरत गले लगाने वालों,
सब पर धूल उड़ाने वालों,
कुछ मुखड़ों की नाराजगी से,
दर्पण नहीं मरा करता।
कुछ सपनों के मर जाने से,
जीवन नहीं मरा करता।'

निस्संदेह इन दो बजटों से राजस्थान के जवान और किसान के सपने जरूर मरे हैं, लेकिन वह अभी जीवित हैं और वह जीवित है इस कांग्रेस पार्टी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से टकटकी लगाये देख रहे हैं कि फिर से ये लोग आयेंगे, फिर से जवान और किसान में खुशहाली आयेगी। आशाएं टूटी हैं, पिछला बजट धरातल पर नहीं उतरा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के साथियों ने इस बजट में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जी एस डी पी में 16.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या जनता इन आंकड़ों पर विश्वास कर पायेगी? जबकि हम देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। सच्चाई यह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 70 हजार करोड़ के लगभग था, लेकिन इस वर्ष राजकोषीय घाटा आपने 70 हजार करोड़ से बढ़ाकर 84 हजार करोड़ रुपये कर दिया अर्थात् सरकार राजकोष पर 14 हजार करोड़ का वज़न दे दिया। इसी कारण मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वजनलाल सरकार कह दिया तो आप लोग नाराज हो गये।

माननीय सभापति महोदय, सत्ताधारी लोगों को बड़ी सोच रखनी चाहिए। प्रतिशोध की राजनीति न करके समावेशी सोच और विकास की राजनीति करनी चाहिए तभी जाकर गांव, गरीब, किसान और नौजवान का वास्तव में भला हो सकता है। लेकिन इनकी सोच काफी इससे दूर है। माननीय सभापति महोदय, आपने पिछले बजट में किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में, जोकि मेरा विधान सभा क्षेत्र आता है, टाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क के बजट की घोषणा की। मैं पूछना चाहता हूं उस वादे का क्या हुआ, जो पिछले बजट में आपने किया था? इसी प्रकार किशनगढ़ के जिला अस्पताल में आपने उसके भवन निर्माण की घोषणा की, आज तक वहां पर नींव का पत्थर नहीं लगा। उस बजट के वादे का क्या हुआ? मैंने दो-चार मांगें रखी थीं कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र मार्बल मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसमें लगातार ट्रेफिक जाम हो जाता है। मैंने एक रिंग रोड मांगी, वह आपने नहीं दी। मैंने अराई में, जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां मैंने एक अग्निशमन यंत्र मांगा, एक उपकेन्द्र मांगा, आपने वह भी

नहीं दिया। कोई बात नहीं, न किशनगढ़ को दिया और न ही इस आसन की शोभा बढ़ाने वाले अजमेर में दिया।

jyg/rtm/20.02.25/17.30/3h

आदरणीय सभापति महोदय, ये सब बातें बताती हैं कि मेरी पूर्व पार्टी के लोगों की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। वित्त मंत्रीजी कह रही थी कि मैं हर वादा दिल ने निभाती हूं, मैं उस बात को बशीर बद्र की कुछ पंक्तियों से उनको कहना चाहता हूं,

तेरी मजबूरियां दुरुस्त,
मगर तुमने वादा किया था,
याद तो कर, याद तो कर।

आदरणीय सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने प्रधान मंत्रीजी का नाम लिया, मुख्य मंत्रीजी का भी नाम लिया, लेकिन मुख्य मंत्रीजी का नाम का आंकड़ा 12 पर आकर अटक गया और आप और हम सनातनी लोग हैं, 12 का आंकड़ा कभी सही नहीं हुआ। जनता में जो परसेप्शन है वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री के लिए, परसेप्शन इस आंकड़े के साथ सही होता हुआ नजर आ रहा है।

खैर, आपकी पार्टी की बात है। आप 11 बार लो या 12 बार, आपकी सरकार की अंतर्कलह से इस डबल इंजन की सरकार के कारण इस इस डबल इंजन के बीच में राजस्थान का गांव, गरीब, नौजवान पिसता हुआ नजर आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये दो बजट बड़े निराशाजनक बजट हैं। इस बजट में आपने कृषि के लिए 52 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान समेकित निधि के लिए किया, यह राशि पिछले बजट में 65 हजार करोड़ रुपये की थी, इस प्रकार आपने किसान भाइयों का भला न चाहकर 13 हजार करोड़ रुपये की राशि कम खर्च करने का जो प्रावधान किया वो किसानों के प्रति आपकी सोच को और आपकी दूरदर्शिता को दिखाता है। कम से कम बढ़ाते नहीं तो किसानों के बजट को आपको कम नहीं करना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र की तर्ज पर इस बार स्मार्ट सिटी योजना के तहत 900 करोड़ रुपये का कोष गठित कर क्लीन एण्ड ग्रीन इको सिटीज की बात की गयी। हमारे किशनगढ़ को भी उसमें आपने शामिल किया, पर आप और हम कैसे भूल सकते हैं कि प्रधान मंत्रीजी ने 2022 तक 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करके 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाने का जो वादा किया, आज उन स्मार्ट सिटीज की क्या स्थिति है, वो आप और हम से छुपी हुई नहीं है। देश जानता है, सांसद गांव में जाकर गांव गोद लेते थे, आज वो गांव सांसदों की गोदी में बैठे हैं, उनका भला कतई हुआ नहीं है। केन्द्र की तर्ज पर आप लोग भी जनता को शब्दों के जाल बिछाकर उसमें फंसाने का काम कर रहे हो। कभी आपने इस बजट में आपने 'अपग्रेड' लिख दिया, कभी 'उन्नयन' लिख दिया, कभी आपने 'नवीनीकरण' लिख दिया पर इस बजट में आपकी स्पष्टता दिखायी नहीं दे रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं, सत्ता पक्ष जो सरकार है, पूरी जनता उनको देख रही है, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपने कोई नयी भर्ती निकाल कर दी हो तो बताओ। जोगारामजी, आपने कोई नयी भर्ती निकाल कर नियुक्ति दी है तो बताओ। आपने बजट में सामाजिक सुरक्षा की बात की है तो बताओ, आपने महिला अत्याचार मुक्त राजस्थान की बात की है तो बताओ, आपने सशक्त युवाओं वाले राजस्थान की बात की है तो बताओ। राइजिंग राजस्थान की बात करने वालो, समृद्ध किसान की बात आपने की है तो बताओ, आपने 5 हजार राजीव गांधी युवा मित्रों के समायोजित करने की बात की है तो बताओ। आपने केवल और केवल इधर-उधर की बात की है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था, तब देश में रेल का बजट आता था तो लोग टकटकी लगाये देखते थे, जब देश का आम बजट आता था तो लोगों को उम्मीद जगती थी और जब प्रदेश का बजट आता था तो शहर ठहर जाते थे, थार से सौंधी खुशबू आती थी, मारवाड़ से मेवाड़ के नौजवानों में एक आशा की उम्मीद की किरण जग जाती थी, किसानों के जज्बात उभर कर आते थे लेकिन इस बार वित्त मंत्रीजी के मुंह से महंगाई का 'म' तक नहीं निकला।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की जनता कह रही है कि राजस्थान का बजट नहीं, यह मात्र एक बैलेंस शीट है, मात्र एक बैलेंस शीट है। बजट तो पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया था, जहां सामाजिक सुरक्षा की बात थी, जहां कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात थी, नरेगा की बात थी, जहां शिक्षा के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की बात थी, जहां चिकित्सा के लिए चिरंजीवी जैसी योजना की बात थी। रोजगार की गारंटी की बात थी, स्वास्थ्य की गारंटी की बात थी, शिक्षा की गारंटी की बात थी, जहां सूचना के अधिकार की गारंटी की बात थी। मैं इस सदन में बड़े दावे के साथ कह सकता हूं और यह जनता की आवाज है कि अगर गरीब आदमी को महंगे अस्पताल में खड़े करने का किसी ने हौसला दिया तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिया इसलिए जनता उनको आज भी याद करती है। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपने क्या दिया, आदरणीय कृपलानीजी, आपने क्या दिया? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित कीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, उन्हें पता नहीं, शायद वो भूल रही हैं कि एक गृहिणी को घर चलाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब वो कढ़ाई में सब्जी चढ़ाती है और तेल डालती है तो उसके जो आंसू आता है तो वो उम्मीद का आंसू गिरता है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये। विराजिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज जाकर पूछिये, दूध,

दाल, साग-सब्जी का क्या भाव है?

श्री सभापति: श्री धर्मपालजी।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। आपका समय हो गया 10 मिनट।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का मौका दिया, निश्चित रूप से मैं आप और मेरी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत-बहुत शुभकामना देना चाहता हूं इस पूरे बजट के लिए पूरे प्रदेश को और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं इस देश और इस प्रदेश की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं,

पीर हो गयी है पर्वत सी, अब यह पिघलनी चाहिए,
हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए,
जो आग मेरे दिल में है, वो हर दिल में जलनी चाहिए,
हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मैं चाहता हूं कि मेरे इस देश और प्रदेश की
तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए।

तस्वीर और तकदीर सिर्फ किसी के भाषणों से नहीं बदलती है। जन कल्याणकारी कामों से बदलती है, अच्छी सोच से बदलती है और वो सोच इस बजट में देखी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत लम्बी-चौड़ी बात ना करके और आंकड़ों के मायाजाल में न फंसकर मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में दो प्रमुख समाचार पत्र हैं। उनके नाम उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता लेकिन आज एक प्रदेश लेवल के समाचार पत्र में मैंने पढ़ा, सुबह-सुबह पढ़ा तो मुझे बड़ा हर्ष का विषय हुआ कि आज तक मैं बजट के बारे में पढ़ता आया हूं, पूरे राजनीतिक जीवन में पढ़ता आया हूं, बचपन से पढ़ता आया हूं, हर अख़बार में लिखा जाता था, ऊँट के मुंह में जीरा लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पहली बार इस बजट को देखकर राजस्थान के प्रतिष्ठित अख़बार ने लिखा, ऊँट के मुंह में 'शीरा' यानी हलवा, पहली बार मैंने यह पढ़ा तो मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि अख़बार हमारा नहीं है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी राजनेता का नहीं है। और दूसरा शुभ संकेत मैं बताता हूं, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, जब भी कोई यज्ञ होता था और जब भी कोई अच्छा काम होता था तो ईश्वर खुश होकर पुष्प वर्षा किया करते थे, आज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कल के बजट के बाद भगवान ने पुष्प वर्षा की जगह जल वर्षा करके अभिषेक किया, इस बजट का अभिषेक किया, इस राजस्थान के कल्याणकारी बजट का अभिषेक

किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं आंकड़ों के मायाजाल में ना फंसकर, आप लोगों का काम है विरोध करना, इसीलिए विरोध में बैठे हो और मैं खुशनसीब हूं कि 16वीं विधान सभा का सदस्य हूं और आप सभी इस पक्ष के खुश नसीब सदस्य हो क्योंकि आज तक का, अब तक का सबसे बड़ा विपक्ष देखने को मिल रहा है। आगे कांग्रेस नाम की एक प्रजाति लुप्त होने के लिए जा रही है, इतना बड़ा विपक्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। बजट के भाषण के दौरान आपने देखा होगा कि बजट भाषण में जब एक-एक घोषणा हो रही थी, एक-एक माननीय सदस्य उठ-उठकर अपनी लॉबी में जा रहे थे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन में कभी सोचना नहीं कि खड़े होकर बजट पढ़ेंगे, आप आगे बैठकर बजट सुनने लायक भी नहीं बचोगे क्योंकि आपने 60 साल में इस देश को दिया क्या है? हिन्दुस्तान को और इस देश को आपने दिया क्या है? राज तो आपने ही किया है, कैसे आंकड़ों का मायाजाल इसमें 'जीरो', उसमें 'जीरो', यह कहकर सदन को गुमराह नहीं करते हैं। देश का और प्रदेश का बजट है, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर गौर से पढ़ोगे तो हम लोगों ने, हेमाराम चौधरीजी ने कहा था, बजट भाषण पर, आपके अशोकजी गहलोत ने बजट भाषण पढ़ा था।

MLS/RTM/20.02.2025/17:40/3j

उन्होंने कहा था, लास्ट के 6 महीनों में अगर इस जनता को आप सोने से भी तोल देंगे तो आपको वोट नहीं देगी। मैं मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे राजनीतिक दल को मैं निवेदन करता हूं कि पहली बार, पहले ही साल में हमने जो काम करके दिखाया है और जो बजट पेश किया है, जो अकसर आज तक आजादी के बाद अन्तिम साल में और अन्तिम 6 महीनों में बजट पास हुआ करता था, यह आग्रह करता हूं, कांग्रेस के साथियों,

जमीन पर खड़े होकर सितारों की बात करते हो,
गुफा में पड़े हुए किनारों की बात करते हो,
जेब में धेला नहीं और हजारों की बात करते हो।

मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह बजट एक जन कल्याणकारी बजट है। अगर इसका एक-एक आंकड़ा पढ़ूंगा तो मैं भी आंकड़ों के मायाजाल में आपको गुमराह करना नहीं चाहता हूं, मैं इस मौके पर बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया है। आग्रह मेरा इतना है कि जो चीजें अन्त में हुआ करती थीं, पहली बार मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि हमने विजन को देखते हुए जो 35 लाख करोड़ के एमओयू किये हैं, ये अन्तिम साल में भी प्रदेश को गुमराह करने के लिए किये जा सकते थे, लेकिन हमने प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं किया और पहली बार हम लोगों ने शुरू में यह काम करने की योजना बनायी।

मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस देश को, इस प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए कोई इतनी छोटी सोच भी, आप लोगों के इतना छोटा-सा काम भी कोई बजट में हाथ में ले सकता है। मैंने उस बात को नोट किया है कि प्रत्येक पंचायत में आप लोगों को 1 लाख रुपये के बर्तन, जो प्लास्टिक मुक्त पंचायत बनानी है, उसके लिए 1 लाख रुपये के बर्तन देकर इतनी बड़ी सोच का जो परिचय दिया है। आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, किसान के लिए जो जमीन की बुवाई के समय जब किसान सेठ-साहूकार के चक्कर लगाता है और अपनी खाद और बीज के लिए बनिये की दुकान पर अंगूठा टेकता है, मुश्किल से उसे खाद-बीज का पैसा मिलता है। उसके लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने सोचा और शुरू में 6 हजार रुपये देकर किसान का मान और सम्मान बचाया।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने पहले 2 हजार बढ़ाकर और फिर 1 हजार बढ़ाकर 9 हजार करके किसान का मान और सम्मान बढ़ाया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश में 150 यूनिट बिजली का उत्पादन, 150 यूनिट बिजली फ्री देकर जो किसान का घर रोशन किया है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुंचाना, पैंशन बढ़ाने का काम, एक से एक बढ़कर सौगातें इस ऐतिहासिक बजट में मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने दी हैं।

अगर मैं अपने व्यक्तिगत क्षेत्र की बात करूं तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 3 दिसम्बर को जब हमारा एक साल पूरा हुआ था तो मैंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड विधान सभा में पेश किया था, जो पूरे 12 महीने का मेरा रिपोर्ट कार्ड था 3 दिसम्बर से दूसरे 3 दिसम्बर तक। उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में सवा दो सौ करोड़ के काम, जिनकी फैक्ट फाइल मैंने विधान सभा के लोगों के सामने रखी थी। अगर सवा दो सौ करोड़ के काम एक ही विधान सभा क्षेत्र में होते हैं तो मैं निवेदन करता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, पूरी विधान सभाएं 200 हैं, उनमें कितने काम हुए होंगे।

आंकड़ों का मायाजाल दिखाकर प्रदेश के बजट को, सिर्फ रटी-रटायी बात करके, ''यह निराशाजनक बजट है, यह लोक कल्याणकारी बजट नहीं है, यह गरीब को गरीब करने का बजट है'', ऐसा करके अगर हम लोग इस सदन को गुमराह करेंगे तो मैं समझता हूं, कुछ काम होने वाला नहीं है। आप भी काम कीजिये, हमें भी काम करने दीजिये और अच्छे काम के लिए धन्यवाद निश्चित रूप से दीजिये। जब यहां माननीया दिया कुमारी जी कह रही थीं, जब हम सवा लाख नौकरियां देने की बात करते हैं तो भी विपक्ष के सदस्य मेज नहीं थपथपाते हैं। हम डेढ़ लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने की बात करते हैं तो भी विपक्ष के सदस्य मेज नहीं थपथपाते हैं। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। प्रदेश की तरक्की से आपका कोई लेना-देना नहीं है।

एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने कहा था कि जाते-जाते आप लोग यह काम कर जाएंगे, वह काम कर जाएंगे, मैं इस सदन को कहना चाहता हूं और मेरे विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं जा रही है और पूरे देश में

2047 तक इस देश का नव-निर्माण करके, इस प्रदेश का नव-निर्माण करके यह सरकार यहां तक रुकने वाली है। आग्रह इतना करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी इस देश के और प्रदेश के नव-निर्माण में सहभागी रहेंगे। मैं आग्रह करता हूं आप लोगों से, एक निवेदन करता हूं कि सब लोग साथ देंगे तो एक प्रदेश मिलेगा आपको और आप लोगों को एक अच्छे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति मिलेगी, इसलिए मेरा निवेदन इतना ही है कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मेरा आग्रह सुना, उसके लिए मैं पूरे सदन को और अपने राजनीतिक दल को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको राम-राम, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रतन देवासी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जब रतन देवासी जी का नम्बर आया, तभी आपने समय क्यों बढ़ाया?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): इतना भेदभाव तो चलेगा।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति जी, दो मिनट मेरे एक्सट्रा होंगे। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान बजट को लेकर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी है। निश्चित रूप से हां पक्ष वाले हमारे जितने भी साथी हैं, मित्र हैं, माननीय सदस्य हैं, सबने अपनी बातों से, अपने रूप में इस बजट की तारीफ की और बजट के बारे में बताया। निश्चित रूप से जो हां पक्ष में बैठता है, अधिकतर सदस्य जो हैं, हम थे तो हम भी वही करते थे, मगर पिछला बजट जो है 2024-25 का और 2025-26 का यह जो बजट है, अगर सारे सदस्य इसकी तुलना करें, खुद के क्षेत्र का, राज्य का, जिले का और अभी का तो मेरे ख्याल से आपको काफी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।

हमारे काफी सदस्यों ने बजट के बारे में बता दिया। मैं पांच-छह बिन्दु ही समय के अभाव के कारण सरकार और सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं, जो न केवल राज्य के लिए, बल्कि जो माननीय सदस्य हैं, उनके हितों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं उनके विधान सभा क्षेत्रों में। जब पिछला बजट आपने पेश किया था तो उसमें

आपने 2047 के विजन के बारे में बताया था। उसमें 10 बिन्दु आप लोगों ने उल्लिखित किये थे कि इन 10 बिन्दुओं के हिसाब से हम लोग चलेंगे। उसमें मुख्य जो थे, चूंकि वित्त मंत्री जी ने बजट पढ़ा है, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, सस्टेनेबल डवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और विशेषकर सोशल सिक्योरिटी, इन 10 में ये 4 बिन्दु जो थे, उनका उल्लेख आपने उस समय किया था।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे काफी साथियों ने जल जीवन मिशन के बारे में उल्लेख किया और बहुत तारीफ की कि 2028 तक उसे बढ़ाया गया है। मैं भी धन्यवाद देता हूं कि 2028 तक बढ़ाया है, निश्चित रूप से जो काम आपने हाथ में लिये हैं, वे काम पूरे होने चाहिये। जो आपने उल्लेख किया है, उसके हिसाब से काम में और समय लगेगा, 2028 से भी आगे जायेगा, मगर 2028 तक आपने किया, ठीक है। पहले काम हुए, नहीं हुए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के तहत जो काम आज भी चल रहे हैं, अगर उन पर हम लोगों ने केन्द्रित होकर ध्यान नहीं दिया तो जो स्थितियां बनी हुई हैं, ढाणियों में पाइप लाइन लग गयी है, पानी नहीं आ रहा है, वह स्थिति आगे भी बनेगी। मेरा आग्रह है कि आपने 2028 तक बढ़ाया है तो कम से कम जहां काम हो गया या काम चल रहा है, वहां लोगों को ढाणियों में पानी बराबर मिल जाये, उसे आप सुनिश्चित कराएं तो मैं समझता हूं कि 2028 तक आपने इसे आगे बढ़ाया है तो वह भी आपके काम आयेगा।

दूसरा, बजट की बिन्दु संख्या 3 के पेज 10 में स्व. प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आपने एक बात लिखी है। आपने सड़कों के बारे में उसमें लिखा है 'कनेक्टिविटी'। वाजपेयी जी को याद करते हुए आपके कहने का मकसद यह था कि डिजिटल कनेक्टिविटी तो है ही, मगर कनेक्टिविटी गांवों के बारे में कैसे हो और सड़कों में कैसा काम हो। बहुत सारे माननीय सदस्य 10 करोड़ की जब घोषणा हुई तो सबने मेज थपथपाईं कि एक विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ के काम होंगे। किस चीज के लिए होंगे? नॉन-पैचेबल सड़क के लिए। नॉन-पैचेबल सड़कों में आज नहीं, पहले भी कितने ही बजट आप उठाकर देखें, पीडब्ल्यूडी का बजट आप उठाकर देखें, नॉन-पैचेबल सड़कें हमेशा मांगी जाती थीं और एक विधान सभा क्षेत्र में एवरेज 4 से 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ के काम होते आये हैं आज तक। उसमें कोई नयी बात नहीं है।

मैं समझता हूं, पहले भी मैंने गवर्नर के अभिभाषण में कहा, पिछले बजट में भी कहा और आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और यह निवेदन कर रहा हूं कि ये 10 करोड़ जो हैं, हमने भी उस समय मांग की थी, इसको मेहरबानी करके आप मिसिंग लिंक से जोड़ें। कनेक्टिविटी कैसे होगी? दो रेवेन्यू विलेजेज हैं, दो गांव हैं, उन दोनों के बीच में डामर की सड़क नहीं है। मिसिंग लिंक में आप देंगे, विधायक अनुशंसा करेगा कि इसको जोड़ना जरूरी है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तब जाकर वे गांव जुड़ेंगे और तब जाकर वाजपेयी जी के बारे में जो आपने लिखा है कि कनेक्टिविटी होगी, तब यह बात साकार होगी।

mkd/rtm/20.02.2025/17:50/3k

मैं चाहता हूं, मेरा सुझाव है, आप इसमें सुधार करिये। पेचेबल, नॉन-पेचेबल सड़कें जो हैं, वह डिपार्टमेंटल हो जाएगी। आप अनुशंसा मंगाइये, मगर मिसिंग लिंक को जोड़िये और 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ करिये। हां पक्ष के जो साथी बने, हम भी बैठते थे, हम भी सदन के नेता को आग्रह करते थे। आप लोगों से भी निवेदन है, आप सदन के नेता को आग्रह करें, वित्त मंत्री जी को आग्रह करें कि यह जो 10 करोड़ हैं, उसको मिसिंग लिंक करो। 10 की जगह 15 करोड़ करो, ताकि हमारे क्षेत्र में जो भी सड़कें कनेक्ट नहीं हुई हैं, गांव कनेक्ट नहीं हुए हैं, डामर सड़कों से उनको कनेक्ट कर सकें। आपने बजट भाषण में वाजपेयी जी का जो लिखा हुआ है, उनको स्मरण करते हुए वह बात जो है, वह पूरी हो सके।

तीन-चार मुद्दे और हैं। आपने रूरल टूरिज्म के बारे में बात की। रूरल टूरिज्म में, आप बात कर रहे हो, मगर रूरल टूरिज्म में आप उनको सारी छूट दे दो, ताकि रूरल टूरिज्म में जो भी उनको परमिशन चाहिए, प्रक्रिया का बिल्कुल सरलीकरण करो, ताकि उस प्रक्रिया के तहत उनको जल्दी से जल्दी जो है, वो काम मिल जाए।

इसके अलावा अपने सिरोही में टूरिज्म के तहत, जो हमारे वहां के आराध्य देव हैं, सारेणसर जी मन्दिर, यहां काम करने की आपने बात कही है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं, इसी तर्ज पर जालौर जिले में श्री आपेश्वर महादेव का मन्दिर है, पर्यटन विभाग के थ्रू धार्मिक टूरिज्म में जो है, वह काम किया जाए।

इसके अतिरिक्त आपने दादू दयाल घुमंतू संस्कृति और योजना के तहत 25000 पट्टे देने की बात की है। मैंने गवर्नर अभिभाषण में भी यह बात कही थी। पट्टे देने हैं, पट्टे कैसे देंगे, 25000 पट्टे का आपने कहा है, घुमंतू-अर्द्ध घुमंतू को, वो लोग गोचर में बैठे हैं। वहां आप पट्टे दोगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का राइडर है, उसमें फैसला है, तो मैं यह चाहता हूं कि कैबिनेट में बिल लाया जाए और उसमें एक स्पेशल परमीशन मांगें, जरूरत पड़े तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं कि हम जब दूसरी जमीन आरक्षित करने को तैयार हैं, लोग बस गए हैं इनका कल्चर, इनका रहन-सहन पुराने जमाने से गांव के बाहर होता था, पशु के साथ रहते थे। भले वे कोई भी जाति के लोग हों, घुमंतू-अर्द्धघुमंतू, तो उनको हम उसी जगह दे देंगे और दूसरी जगह को हम जो है, गोचर में आरक्षित कर लेंगे।

आज शिक्षा के अलावा, चिकित्सा के अलावा हो नहीं पाती है। अगर यह होगा तो आपका बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा। यह जो अपने 25000 पट्टे देने की बात की, वह लोगों को मिलेंगे और वह लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको धन्यवाद भी देंगे और असल मायने में सोशल सिक्योरिटी, जो आपने पिछले बजट में बोला है, वह लाभ जो है, लोगों को मिलेगा।

देव नारायण योजना में आपने छात्रावास किये। मगर देव नारायण योजना में जो एमबीसी की जातियां आती हैं, वे या तो पूर्वी राजस्थान में अधिकतर हैं या फिर मारवाड़ या मेवाड़ में हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने इसमें पूर्वी राजस्थान के जो स्थल लिए हैं, मगर मारवाड़ में हमारा चौहटन है, बाकासरका बेल्ट है, रामसीन है, इस इलाके में नहीं आया है,

तो आप एक आवासीय विद्यालय, उस इलाके में भी हमको देवें, ताकि देव नारायण योजना के तहत हमको भी वह लाभ जो है, वह प्राप्त हो सके।

कृषि में, आपने कृषि बजट पूरा पढ़ा। मेरा एक निवेदन है कि कृषि कार्य करते समय जिसकी मृत्यु हो जाती है, पिछली बार पैसे बढ़े दो-तीन साल पहले उसके बाद नहीं बढ़े तो मेरा निवेदन है कि कृषि कार्य करते समय काश्तकार की मृत्यु होती है, उसको कम से कम 10 लाख रुपए का आप उसके माध्यम से मुआवजा दिलायें, ताकि उस किसान परिवार के जो है, वह काम में आएगा।

दो-तीन बातें और थीं। आपने पिछले बजट में ऊंट की बात की थी, 15 से 10-20 हजार रुपये किए थे। आपके राज्य का पशु है। उसके बारे में ठोस योजना आप नहीं लाये। मैं समझता हूं कि जब आपकी डिमांड आएगी, तब आप उसके बारे में जो है या जवाब में एप्रोप्रिएशन बिल के समय भी आप जो है, उसको लायें।

दूसरा ट्राइबल के साथ में, एक बात और है, मैं लास्ट दो बातें हैं, वह निवेदन करना चाह रहा हूं, आपने विधायकों के लिए 10 लाख रुपए से भवन की बात की है। मैं उसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। मगर एक बार जरूर कहता हूं, पिछली बार नवाचार पर हमको बात करनी थी सदन चल नहीं पाया था, हम बोल नहीं पाए। मैं आपसे दो बातों का निवेदन करता हूं कि एक तो विधायकों को आपने किया, आपने एमएलए लैड से कह दिया तो 10 लाख में क्या बनता है, अगर एमएलए लैड से ही खर्च करना है तो उसको 25 लाख कर लो और सरकार पूरा दे दे तो धन्यवाद है, नहीं दे तो कम से कम आप यह कह दो कि 10 लाख रुपए जो है, वह गवर्नमेंट दे देगी, ऊपर का जो है, वह एमएलए लैड से हो, तो कम से कम जिस विधायक के लिए वह हॉल बनना है, उसके हॉल में सारे संसाधन लगने हैं फर्नीचर लगना है, वह कम से काम ढंग से तो काम हो जाए। एमएलए लैड से, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को खुद को करना चाहिए और एमएलए लैड में रिवाइवल होना चाहिए कि क्या-क्या चीज हम..। (समय समाप्ति सूचक घंटी) 2 मिनट में पूरा करुंगा, हमको जो है वह एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए।

इसलिए मेरी एक मुख्य मांग है, यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, आप सबको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों की तरफ से एक विधायक नवाचार निधि बननी चाहिए। जो काम एमएलए गाइडलाइन में नहीं है, जो काम हो नहीं सकते, वो एक करोड़ रुपया आप साल का दीजिये, ताकि विधायक नवाचार निधि के तहत हम लोग वह एक्सपेंस कर सकें, जो किसी भी गाइडलाइन में काम नहीं आता और लोगों को उसकी सुख-सुविधा मिल सके।

अंत में, दो ही बात करता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो-तीन काम है, एक तो एईएन ऑफिस और यह जो सीएचसी बनाई है, यह प्रक्रिया में थी, मैंने भी निवेदन किया था, 15-20 बिन्दु में, उसका धन्यवाद देता हूं। मगर सरनव में उप तहसील है, बड़गांव, मालवाड़ा में सीएचसी है, इसके अलावा कई सारे ट्रोमा सेंटर हैं, उनको करें। दो बातें और हैं, अन्त में एक

मिनट में मैं मेरी बात पूरी करता हूं।

आपने बजट में लिखा है कि माउंट आबू में पोलो ग्राउंड के रिवाइवल के लिए, रिवाइवल की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार 18 करोड़ रुपये बजट में स्वीकृत हुए थे, उसका काम शुरू नहीं हुआ है, इतना बड़ा ग्राउंड है, एनपीए एक जमाने में नेशनल पुलिस एकेडमी वहां चलती थी। 18 करोड़ आपने किया, उसको 25 करोड़ करके और शुरू करें।

धार्मिक टूरिज्म में, पिछली बार मंत्री जी ने अर्बुदा माता शक्तिपीठ और अचलेश्वर महादेव का उल्लेख किया था, राशि भी आवंटित की थी, आज तक कोई काम शुरू नहीं किया है। आप गौमुख को इसमें जोड़ें।

वेडिंग डेस्टिनेशन के तहत आपने जो बात की है, उदयपुर, नाथद्वारा, उसके साथ में माउंट आबू को जोड़ते हुए, आप वेडिंग डेस्टिनेशन में इस काम को पूरा करायें।

अंत में, महाराणा प्रताप जी को हम सब याद करते हैं, धार्मिक टूरिजम के तहत महाराणा प्रताप जी का जो स्मारक वहां सेर गांव में है, जो सबसे ऊंचाई पर है, पूरे राजस्थान प्रदेश में, जहां पैदल ही जाना पड़ता है, उनके जो स्मारक पुराने वहां बने हुए हैं, धार्मिक टूरिज्म के तहत और ट्राइबल टूरिज्म को तो आपने जोड़ा है, उसके तहत महाराणा प्रताप जी के स्मारक को भी उसमें देखा जाए, उसका उल्लेख किया जाए, उसको करा जाए तो मैं समझता हूं, यह बढ़िया होगा।

मैं समय देने के लिए बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद आभार।

श्री सभापति: श्री ललित मीना।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने आय-व्ययक बजट 2025-26 बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

मैं इस सदन को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा और सबको मैं यह कहूंगा की बहुत उम्मीद और अपेक्षा से हम सबको यहां भेजा है। हम सब लोग इस प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाएं, इसके लिए हम सब लोग बैठकर यहां चिंतन करें और दोषारोपण से बढ़िया है कि हम सब सुझाव दें।

मैं इस बजट के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी को हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस प्रदेश को पिछले बजट में और इस बजट में नए आयाम देने का काम उन्होंने किया। जो बजट लास्ट के चौथे साल में या पांचवें साल में, जो सरकारें देने का काम करती हैं, वह पहले साल में देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया।

जो बजट 19 तारीख को पेश किया गया, उसमें सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए किसान वर्ग, युवा वर्ग, महिला, सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए, कैसे उनको आगे लेकर जाया जा सके। उनको लेकर इस बजट में अवधारणा रखी।

मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा और मेरे प्रतिपक्ष के भाई भी कई बार कटाक्ष करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि 2013 से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, जब से लेकर आज 2025 तक, आप यह देख लीजिए कोई एक भी घोटाला नहीं हुआ और हमने

2012 में 2011 में देखा, जब यूपीए की सरकार थी और यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्या घोटाले हुए, इस पूरे देश में वह आपके सामने हैं।

मैं थोड़ा-सा बताऊंगा, कोल घोटाला आपको ध्यान होगा, इस सदन को। मैं कहूं 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी उस समय तात्कालिक जो थे, उन पर भी छींटे लगे। इसके साथ-साथ कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें आपके सुरेश कलमाड़ी जी, जो उस समय के तात्कालिक इसके चेयरमैन थे, वह जेल में गये तो देश को कई घोटालों की सौगात उस दौरान मिली, पिछले 60 साल में।

आज मैं आपसे कहूंगा पिछले 12 साल में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत नेतृत्व के रूप में नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आज तक एक भी घोटाला नहीं हुआ और तो और मैं कहूं पूरे विश्व में भारत एक छवि के रूप में उभर कर सामने आया है। मैं इसलिए कहूंगा, क्योंकि अमेरिका देश है, कहता था कि इस व्यक्ति को हम वीजा नहीं देंगे, आज वह पलक-पावड़े बिछाकर हमारे देश के स्वागत के लिए अभिनंदन के लिए खड़ा है। मैं आज कहूं कि इस देश को मजबूत करने में आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और मजबूत नेतृत्व दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में दी और राज्य में जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 2003 से 2008 में रही, 2013 से 2018 में रही और अभी 2023-24 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।

मैं आपसे इसलिए कहना चाहूंगा कि 2014 में जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी बने, उस समय पूरे भारत का जो वर्षों से चला हुआ मुद्दा धारा 370 का, उसको लोकसभा में पेश करके धारा 370 को खत्म करके, उस राज्य में शांति स्थापित करने का काम किया और आज वर्तमान में शांतिपूर्ण चुनाव कराने का काम किया। वहीं राम मन्दिर, जिससे हम सब लोगों की आत्मा जड़ी हुई है, इस देश को 1991 में, उस समय यूपी में दंगे हुए राम के लिए।

Msk/rtm/20.02.25/1800/3l

भगवान रामलला का मन्दिर आज आप सबके बीच बनकर तैयार है। वहां सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं। मैं इसके साथ ही यह कहना चाहूंगा कि हमारे स्टेट में हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, आज उससे हमारा किसान, हमारा युवा, हमारा महिला वर्ग, आज सबको सशक्त करने का काम किया है। आज मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों, जिनको 6 हजार पीएम सम्मान निधि मिलती थी, आज वह पीएम सम्मान निधि बढ़ाकर 8 हजार की, फिर 9 हजार किया। आज इस बजट में आपने देखा होगा कि किसान को कहीं न कहीं सीधा खाते में पैसा जाता है तो उसका लाभ मिलता है। इसके साथ-साथ गेहूं की डेढ़ सौ रुपये एमएसपी बढ़ाने का काम किया। इसके साथ-साथ हमारे गांवों में तालाब होते हैं, उनके लिए 50 हजार तालाब की घोषणा इस बजट में हमारे मुख्य मंत्री जी ने की है। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने अभी बजट में किसान के लिए तीन लाख से पांच लाख की केसीसी

की। हम भी और आप में से कई लोग भी इस पृष्ठभूमि के हैं, काश्तकार आज केसीसी से अपना काम ऋण लेकर चलाता है।

इसके साथ-साथ मध्यम क्लास का ध्यान रखा। केन्द्र सरकार ने इनकम टैक्स को चार लाख से बढ़ाकर बारह लाख। इसके लिए तो मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहिए। इसके साथ-साथ, मैं यह कहूं कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं यहां हूं और आम जन ने मुझे यहां भेजा है, मेरा विधान सभा क्षेत्र और पूरा बारां जिला **रेसपिरेसरी** जिले में आता है। पूरे भारत के जो जिले हैं उनमें बारां जिला, मैं आदिवासी सहरिया विधान सभा से आता हूं। मेरी विधान सभा में मैं कहूं, जब सरकार 2024 में बनी उस दिन, पहले दिन से मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री जी ने जन-मन के माध्यम से आज हमारे सहरिया गरीब परिवारों को, जिनको आवास के लिए छत नहीं थी, उनको घर देने का काम किया है। 13 हजार घर आज वर्तमान में बनकर तैयार हो चुके हैं और 13 हजार की सेंक्शन अभी केंद्र सरकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरे सहरिया भाइयों के लिए आ चुकी है। इसके साथ-साथ आज वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री आवास का, आप और हम सब लोग वोट मांगने जाते हैं, गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मेरे घर नहीं है, मेरा घर जुड़वाओ। आप नहीं जुड़वा सकते, लेकिन आज केन्द्र सरकार ने उसका पोर्टल भी खोल दिया। पोर्टल खोलकर आज उसका सर्वे हो रहा है। उसमें मेरे एससी का, ओबीसी का, जनरल का, सभी वर्गों का आज उसमें सर्वे हो रहा है। खाद्य मंत्री जी यहां विराजे हैं। हमारा भाई गांव में जाता है तो धरातल की बात है, गरीब-परिवार का कहता है कि, साहब गेहूं दिला दो, मेरा राशन कार्ड चालू करा दो। इसलिए मैं केन्द्र एवं राज्य सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारा उसका सर्वे चल रहा है। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुल गया है। 9 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी वापस ले ली, लेने के बाद आज पोर्टल खुला है तो आज उनसे आवेदन मांगे जा रहे हैं, आज सर्वे का काम चल रहा है। जो धरातल से जुड़े हुए हैं, हमारा प्रधानमंत्री आवास और खाद्य सुरक्षा का काम, आज वर्तमान में नीचे गांव में, सर्वे काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में और पूरे राजस्थान एवं भारत में चल रहा है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जन-मन के अंतर्गत मेरे जो 13 हजार घर आये हैं, उनकी जो बस्तियां हैं, उनमें लाइट लगाने का काम, उनमें पानी की व्यवस्था का काम, रोड का काम, ये वर्तमान में पिछले एक साल में चालू हो चुका है और वर्तमान में पूरा भी हो चुका है। इसके साथ-साथ पीएम जन-मन के अंतर्गत दो गांव सम्मिलित किये, जिनके घर बनकर तैयार हो गये, उनके घरों का उद्घाटन तक हमने जाकर वहां पर किया है।

इसके साथ-साथ मैं हमारे मुख्य मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 17 तारीख को ईआरसीपी में रामपुर और महलपुर बैराज की आधारशिला रखी, उस रामपुर और महलपुर बैराज का डैम मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही बन रहा है। आज लाभान्वित होने वाले ईआरसीपी के 13 जिले हैं, उनकी आधारशिला हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे

जी ने उस समय रखी। आज भगीरथ के रूप में हमारे मुख्य मंत्री जी इसको आगे बढ़ाकर इस बजट में 450 करोड़ मेरे विधान सभा क्षेत्र में केलवाड़ा और समरानिया को इरिगेशन एवं पेयजल के लिए पानी देकर उन्होंने इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की उम्मीद और अपेक्षाएं पूरी की हैं।

इसके साथ-साथ, मेरे नाहरगढ़ में पिछली बार बजट में 50 लाख रुपये देकर डेम बनाने के लिए डूंगराज एवं महलपुर में मदद की है। इसलिए आज उस क्षेत्र को, जो पिछड़ा हुआ था, आज फरवरी चल रहा है, पेयजल के लिए साढ़े चार सौ फीट तक पानी नहीं मिल पाता, आज इस डैम के माध्यम से, रामगढ़ और महलपुर के माध्यम से, ईआरसीपी से जुड़ने से मेरे विधान सभा क्षेत्र को आने वाले समय में पेयजल के लिए पानी मिलेगा और सिंचाई की सुविधा होगी। इसके साथ-साथ इसी ईआरसीपी योजना से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो लिंक कैनाल बनेगी, उससे हमारे कई सारे तालाब, हमारे पीएचईडी मंत्री विराजे हैं, सेमली फाटक डैम और हमारा नारायण खेड़ा डैम, ये सब डैम जो उस समय बनाकर आये, वे सब आज उस योजना से कनेक्ट होंगे तो आम जन को उसका लाभ मिलेगा।

इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले बजट में जो पुलियाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा, उसके लिए पिछले बजट में अथाह पैसा दिया। यहां हमारे ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। मैं हमारे ऊर्जा मंत्री जी और हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछले बजट में जो दो 132 जीएसएस दिये। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि छह महीने में बजट दिया, पर छह महीने का जो बजट है आज वह धरातल पर दिख रहा है। जमीन अलॉट हो गयी, जमीन अलॉट होकर मेरे वहां मौके पर काम चालू हो गया है। जो सेमली फाटक 132 जीएसएस था और रेलावड़ का जीएसएस था, दोनों चालू हो गये। पिछले पांच साल में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस समय एक भी 132 जीएसएस का काम नहीं हुआ। 220 जीएसएस ने पांच साल में अब जाकर गति पकड़ी है। इसके साथ-साथ हमारे यहां जो 33 केवी जीएसएस दिये हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे ऊर्जा मंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा।

इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में जेजेएम के काम जो पिछले पांच साल में चल रहे थे, वे पाइप रोड खोदकर डाले थे, रोड खुदे हुए पड़े हुए हैं। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो ईडी में, जेजेएम के घोटाले हुए हैं, उनकी जांच चल रही है। वर्तमान में उसका लाभ लोगों को मिले, इसकी जांच करायें। लोगों को राहत मिले। जलदाय मंत्री जी बैठे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी से दिक्कत आने लग गयी है तो उसकी जांच करायें, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसकी और उनको दुरुस्त करायें।

इसके साथ-साथ मैं सदन के माध्यम से मेरे विपक्ष के भाइयों को बताना चाहूंगा कि बारां जिला, ऐसा जिला है कि आप यहां दोषारोपण कर रहे हैं। इस सदन को 2021 की बात बताऊं, पूरे भारत में ही नहीं, इस बारां जिले का हमारा जो कलेक्टर था वह भ्रष्टाचार में ट्रैप हुआ है। मेरे हिसाब से पूरे भारत में आज दिन तक 60 साल तक, जब से आजाद हुए हैं, तब से ऐसा कहीं किसी जिले में नहीं हुआ। जिस जिले का कलेक्टर और उसका पीए भ्रष्टाचार

में ट्रैप हुआ हो, पकड़ा गया हो। यह बहुत बड़ी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आपको उपलब्धि गिना रहा हूं। उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया। इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ईआरसीपी में मुख्य मंत्री जी ने इस बार जो बजट दिया है, वर्तमान में 12 हजार 807 करोड़ की निविदा जारी हो गयी। मेरे यहां रामगढ़ और महलपुर में काम भी चालू हो गया है।

इसके साथ-साथ मेरे किशनगंज-शाहबाद में चिकित्सा के क्षेत्र में अभी इसी बजट में आपने उप जिला चिकित्सालय की घोषणा केलवाड़ा और समरानिया में की है। हमारे नाहरगढ़ की भी मैंने डिमांड की थी, तो उसके भी बेड बढ़ाने का काम किया है। मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके साथ-साथ एमटीसी वार्ड, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, मेरे सहरिया परिवार के, उन परिवारों, जब 2013 से 2018 सरकार थी, तो हर सीएचसी, पीएचसी पर 10 बेड के, हमारे कुपोषित बच्चों के लिए न्यूट्रीशन की डबल डाइट के रूप में 220 रुपये में उस माता-पिता को मिलते थे, वे पिछले पांच साल में बन्द हो गये हैं। मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि सहरिया जनजाति क्षेत्र से, जिससे मैं आता हूं, इसको अपन क्रमोन्नत करके, जो पिछली सरकार ने बन्द किया, पिछली सरकार में आठ पीएचसी, सीएचसी पर चलता है, अभी वर्तमान में तीन सीएचसी पर चल रहा है, इसको हमारे बच्चों को, जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए एमटीसी वार्ड दोबारा चालू करवाने का काम करें।

इसके साथ-साथ, मैं सरकार को और हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पांच हजार की आबादी पर जो अटल प्रगति पथ किये हैं, इसमें हमारे कई कस्बे और रोड सम्मिलित हो जायेंगे। इसलिए मैं सदन के माध्यम से बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में पिछले पांच साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वह कतई ध्वस्त हो गया था। इस एक साल में जो घोषणाएं और ऊर्जा के क्षेत्र में हम जो नये नवाचार कर रहे हैं, उसके लिए मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को और हमारे मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि डेढ़ सौ यूनिट आज सौलर ऊर्जा के माध्यम से, कहीं न कहीं आदमी उधर डाइवर्ट होगा और उसको अच्छी बिजली मिलेगी। आज पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत 33 केवी जीएसएस से जो कनेक्ट होगा, जब हम गांव में जाते हैं तो किसान आप सबको और हम सबको कहता है, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, सबको कहता है कि हमको दिन में बिजली दो, हमारा फीडर चेंज कराओ, आज 33 केवी से कुसुम योजना के अन्तर्गत प्लांट जुडेगा तो उससे किसान भाई को बहुत बड़ा लाभ होगा।

mdp/RTM/20.02.2025/18:10/3m

इसके साथ-साथ नये कृषि कनेक्शन देने की जो घोषणा की है वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नये 50 हजार कृषि कनेक्शन और घरेलू कनेक्शन भी 5 लाख देने की जो घोषणा की है, वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में किसान को राहत देने का काम करेगा।

वहीं हमारे पिछले 2013 से 2019 के कार्यकाल में 765 का एक जीएसएस बारां बना।

हमारा वह बनकर तैयार हुआ और उससे बारां जिले को लाभ मिला और आसपास संभाग को भी मिला। आज 765 के एक जीएसएस की और घोषणा, 220 बनाने की घोषणा 400 जीएसएस की, 33 केवी जीएसएस के 138, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा हमार लाइट का, सौर ऊर्जा से कनेक्टिविटी के माध्यम से और 33 केवी के माध्यम से, इस राजस्थान के किसान को, आम जन को नीचे हम अच्छा लाभ दे पाएंगे और अच्छी लाइट मिल पायेगी।

इस सदन के माध्यम से बहुत बड़ी डिमांड करना चाहूंगा कि जो हमारी पुलिस है, आज पुलिस की भी घोषणा की है कि एक हजार पुलिस वाहन और 350 नये पद स्वीकृत किए हैं, इसके साथ ही मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि पुलिस की भी डीपीसी होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट में एक डीपीसी होती है, उसके अकार्डिंग प्रमोशन होते हैं। उसी के आधार पर हमारे यहां पर पुलिस में भी डीपीसी की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले बजट में जो जुलाई में बजट पेश हुआ, जो घोषणाएं थीं, वह धरातल पर आज मौके पर दिख रही है। जो अभी बजट में मेरी विधान सभा के लिए घोषणाएं की हैं, इसके लिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी का, मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सदन को ये निवेदन करूंगा कि हम दोषारोपण की जगह अच्छे सुझाव दें कि राजस्थान को हम कैसे आगे लेकर जाएं और कैसे इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम सब लोगों के पास समय सीमित है। 60 महीने का समय है, उस 60 महीने में कुछ लोग यहां आयेंगे और कुछ लोग नहीं आ पायेंगे इस सदन में। हम जनता की आवाज और अपने इलाके को आगे ले जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का काम करें। सभापति जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री पितराम सिंह काला।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आय-व्ययक 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको और मेरे दल के नेताओं को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक दक्षिणी भारत के बहुत बड़े संत और स्वामी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि देश की बरबादी के लिए वह हर व्यक्ति जिम्मेदार है जिसको ये लगता है कि शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा से महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दे होते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब सदन बोलता है तो केवल दो बात कहता है। पहली बात, मोदी चालीसा पढ़ना कि मोदी जी ने ये किया, ये किया और दूसरी बात कहता है कि विपक्ष ने क्या किया। ये क्या किया, उसी की बानगी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एजेंसी है, जो हर साल अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है, उसके अन्दर जो भारत है, भ्रष्टाचार के बारे में वह 93वें नंबर पर था। भ्रष्टाचार के दलदल में हम तीन कदम आगे बढ़ गये। छोटे-छोटे देशों से भी हम आगे बढ़ गये। ये एक साल के अन्दर हुआ है।

सभापति महोदय, इसी के साथ वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अन्दर हमारी स्थिति 105वें नंबर

पर है। जो देश सबसे ज्यादा टैक्स देता हो, वर्ल्ड के अन्दर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला यदि कोई देश है तो वह भारत है और वह 105 हंगर इंडेक्स के अन्दर है। आज हमारे पड़ोसी देश चाहे वह पाकिस्तान हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, चीन हो, म्यांमार हो, वह भी भूख के अन्दर हमसे बैटर स्थिति के अन्दर हैं। यह आज हमारे देश की हकीकत है। इसी के साथ वर्ल्ड शांति का जो इंडेक्स है, उसमें हमारी रैंकिंग 116 नंबर है। दिल में शांति तो तब होगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान समृद्ध होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, एस.सी./एस.टी. के आगे बढ़ने के प्रमोशन होंगे। ये सारी चीजें गौण हो गयी हैं। आज हमारी ये स्थिति है।

इसी के साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है, माननीय सभापति महोदय, उसमें हम 126वें नंबर पर पहुंच गये हैं। 125 देश हमसे ज्यादा हैप्पी, उन्हें खुशी महसूस है। हमारी 11 साल के अन्दर ये प्रगति हुई है। लैंगिक असमानता, पूरे विश्व के अन्दर हम 129वें नंबर पर चले गये। 128 देश हैं जहां लैंगिक असमानता हमसे बहुत कम है। विश्व शांति और सुरक्षा के अन्दर हम 148वें नंबर पर चले गये हैं। 147 देश हमसे बेहतर है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रेस, जिसको चतुर्थ स्तंभ हम कहते हैं, उसके अन्दर हमारे भारत की रैंकिंग 159 है, 158 देश हमसे आगे हैं।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि ये बार-बार मोदी चालीसा पढ़ते हैं। आज हमारा देश 10 शक्तिशाली देशों की श्रेणी से बाहर हो गया है और यही नहीं, जब ट्रम्प यहां गुजरात आये थे, नमस्ते ट्रम्प के नाम से 100 करोड़ रुपये खर्च किये थे। उन्हीं ट्रम्प ने अमेरिका के सैनिक हवाई जहाज में, उसके अन्दर हमारे 104 नागरिकों की क्या हालत करके भेजी थी। हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर महिलाओं को, चार साल के बच्चे को यहां भेजा था। इसके बाद में विदेश मंत्रालय ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद में दूसरी फ्लाइट आयी, उसके अन्दर भी यही स्थिति थी। इससे अच्छे तो दूसरे देश थे, उन्होंने ससम्मान कहा कि आपको डिपोर्ट करना है तो कीजिए, हम हमारे देश का अपमान नहीं सहना चाहते, हम सम्मान से उन नागरिकों को लेना चाहते हैं। सभापति महोदय, ये तो मोदी चालीसा की बात थी। अभी मैं बजट पर बात करना चाहूंगा। ..(व्यवधान)... मैं आपकी प्रगति बता रहा हूं।

अब मैं बजट पर आता हूं, वह भी सुन लीजिए आप। आज पानी की यह स्थिति है कि पिछले गत वर्ष माननीय दिया कुमारी जी ने कहा था कि अपना वादा, हर वादा मैं दिल से निभाती हूं। पिछले बजट के अन्दर हमें 5 ट्यूबवेल दिए थे, माननीय पीएचईडी मंत्री बैठे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे 5 ट्यूबवेल भी अभी तक स्वीकृत नहीं किए। इसी के साथ इन्होंने पिलानी के अन्दर मीटिंग की थी। तीन जिलों के अधिकारियों को बुलाया था और कुम्भाराम लिफ्ट के बारे में इन्होंने ये कहा था कि मेरी रिपोर्ट दो। उस कुम्भाराम लिफ्ट का पानी मैं आपके यहां पहुंचाऊंगा। आज वह 35.8 करोड़ की डीपीआर भी आपने नहीं बनायी, माननीय मंत्री महोदय। आज पिलानी का कही जिक्र नहीं है इसके अन्दर। आज ये 120 पेज का जो बजट है, उसके अन्दर। आप बैठ जाइए। आप अपना जवाब दें तब बता

देना। 168 पैरा के अन्दर पिलानी का कहीं एक शब्द भी नहीं है, एक शब्द किसी भी क्षेत्र के अन्दर। आज जिस यमुना जल की आप बात करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय, चुनावों के अन्दर गये थे, बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये और कह रहे थे कि शेखावाटी के अन्दर।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सभापति महोदय, ...

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): आप बैठिए, आपका टाइम नहीं है। Sit down please. You are not allowed. Sit down. You are not allowed. I will speak and this is my time. I will speak so please sit down.

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): ये आदेश नहीं दे सकते।

श्री सभापति: बैठिए।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): सभापति महोदय, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि उस यमुना जल ...(व्यवधान)... के बारे में एक शब्द इस 120 पेज के अन्दर नहीं कहा गया। Please sit down. You are not allowed. Please sit down. This is not your time, this is my time and I will speak. Dr. Ambedkar has allowed us to speak in this highest Assembly. So please sit down and don't disturb me. Please don't disturb me.

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): आपको इसमें डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बोलूंगा, उसके बाद में माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे, आप इनको बैठाइए।

सभापति महोदय, आज उस यमुना जल के बारे में बता रहा था। उस यमुना जल के बारे में एक शब्द भी 120 पेज की किताब में नहीं लिखा गया है कि उसका क्या हुआ? उसके नाम पर वोट लिये गये। वह चुनाव जीता गया। लोक सभा के अन्दर कहा गया। आज उस शेखावाटी के लिए एक शब्द ही नहीं कहना, इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात हो ही नहीं सकती।

Ans/Rtm 18.20 3n 20.02.2025

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पिछले बजट में कहा था कि पिलानी विधान सभा के अन्दर जितने भी ड्राई टयूबवैल हैं वह सारे के सारे सैंक्शन करूंगा, आज तक माननीय मंत्री महोदय ने एक टयूबवैल सैंक्शन नहीं किया। राजस्थान के अन्दर 200 विधान सभा है, पिलानी विधान सभा के अन्दर एक भी कार्य सैंक्शन नहीं किया है, चाहे पानी का हो, चाहे ऊर्जा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, इससे बड़ी बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना राजस्थान के इतिहास में आप कहीं नहीं देख सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा।

हम ऊर्जा की बात करते हैं। 440 केवी, 120 केवी की बात करते हैं, पिलानी विधान सभा

के अन्दर सबसे ज्यादा घनत्व किसानों का है, वहां सबसे ज्यादा टयूबवैल किसानों के हैं, सबसे ज्यादा जीएसएस की आवश्यकता वहां है। माननीय मंत्री महोदय, आपने 11 केवी का भी एक सैंक्शन नहीं किया है, जबकि आपके पास एसई ने प्रस्ताव भेज रखे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या होगा कि जिस विधान सभा में एक 11 केवी तक का ट्रांसफार्मर भी सैंक्शन नहीं हो। आज चिकित्सा की बात करते हैं। चिकित्सा के अन्दर बड़े हॉस्पिटल की बात नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य की बात नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र है वह भी एक सैंक्शन नहीं किया, यह चिकित्सा की हालत है। शिक्षा तो कहना ही क्या। किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि जिस देश के अन्दर मंदिरों की छतें सोने से ढकी हो और विद्यालयों की दीवारों में पानी टपकता हो वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। इन्होंने तो 450 स्कूलें बंद कर दीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): गलत बयान कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय मंत्री महोदय, आप बैठिये ...(व्यवधान)... you are not allowed. आप नीचे बैठिये, जब आपका नम्बर आये तब बात करना। मैं एक भी तथ्य गलत नहीं कह रहा हूं। You are not allowed.

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण राम। अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)... विराजिये।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): 000

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): गलत बयान कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये, मंत्री महोदय। श्री लक्ष्मण राम। ...(व्यवधान)... गोपाल जी, श्रीचंद जी विराजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स):000

श्री सभापति: आपका समय आये तब बोलना। लक्ष्मण जी का समय चालू हो गया, उनको बोलने दे। लक्ष्मण राम जी बोलिये। आप विराजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 000

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण राम। माननीय गोपाल जी, बैठिये। अंकित नहीं होगा।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 000

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): सभापति महोदय, बजट 2025-26 पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस मौक़े पर मेरे दल के नेताओं का, मेड़ता की जनता का आभार प्रकट करता हूं। माननीय हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने शानदार, जानदार पिछला बजट पेश किया। सिर्फ 07 महीनों में बजट पेश करके इतनी सारी योजनायें थी वह धरातल पर आ गईं, उनकी ज़मीनें सारी अलॉट हो गई। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनकी एफएस भी जारी हो गई। मैं यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय व वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सबकी फ्रिक में खुद को मिटाती हूं, हर वादा अपना दिल से निभाती हूं। उन वादों के जरिये हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।

हर समाज व हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया। ह

मारे विपक्ष के साथी बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिया, मैं कहना चाहूंगा कि आपने कुछ देखा नहीं। आप क्षेत्र में नहीं गये। जब राजस्थान विधान सभा में बजट पेश होता है तो समस्त 200 विधान सभा क्षेत्र का बजट पेश होता है। मुझे लगता है कि आप अभी तक क्षेत्र में गये ही नहीं। पिछला बजट सात महीनों में क्रियान्वित हुआ, हमारे मुख्य मंत्री व मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र है कि जनता का ध्यान रखा गया।

आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश विशेष रूप से हर क्षेत्र में प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार कल बजट पेश किया गया, मैं हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मोदीजी के विकसित भारत के संकल्प को, बीते एक वर्ष में प्रदेश में विकास हेतु अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। इस बार बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्पों, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं आपणों अग्रिम राजस्थान की परिकल्पना को जमीनी स्तर पर फलित कर मजबूत रोडमैप बनाया है। ...(व्यवधान)... इस बजट में गरीब का कल्याण, अन्नदाता के उत्थान, मातृ शक्ति का सम्मान, नौजवानों की मुस्कान समाहित है। आदरणीय उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी ने प्रदेश हित के लिए जो बजट सदन पटल पर रखा निश्चित तौर पर खुशहाल राजस्थान को समर्पित इस बजट की सराहना प्रत्येक प्रदेशवासी, गांव-ढाणी के लोग, अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति कर रहा है। बजट के बाद हम गांव में शादियों में गये थे तो आम आदमी के चेहरे पर खुशी थी, शाबाशी दे रहे थे, राजस्थान के इतिहास में पहली बार पहला बजट पेश हुआ और दूसरा बजट भी उतना ही शानदार पेश हुआ, तो सब लोग धन्यवाद दे रहे थे हमारे मुख्य मंत्री महोदय का।

एक दौर था जब बिजली कनेक्शन के लिए गांव-ढाणी के लोगों को कांग्रेस शासन में भटकना पडता था। हमारी सरकार ने उनके हित की चिंता की और इस बजट में पांच लाख घरेलू कनेक्शन और धरती का सीना चीरकर जो अन्न पैदा करता है उन किसानों को 50 हजार कृषि कनेक्शन देने का निर्णय लिया। हमारी सरकार ने किसानों, पशुपालको के लिए बेहतरीन तरीके से बजट में सम्मान किया है। 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान हर गांव-ढ़ाणी में किसान सम्मान निधि बढ़ाने का वादा किया था उस वादे को पूरा किया। आदरणीय मोदी जी किसानों को 6 हजार रुपये किसान निधि के तौर पर देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुये हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने तीन हजार रूपये की और घोषणा की, मैं समझता हूं किसान अपने आपको ठीक समझता होगा। 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। गोपाल क्रेडिट योजना के माध्यम से प्रदेश के करीब 2 लाख 50 हजार पशुपालकों को ब्याज मुक्त लोन का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। हम सब किसान परिवार से आते हैं, हमें पता है जब घर में पैसों की जरूरत थी हम लोग सेठ-साहूकारों के पास जाते थे और दो रुपये प्रति सैकड़े से पैसा लेते थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की असीम सोच थी कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की। हमारे मोदी जी ने तीन लाख से पांच लाख तक का ऐतिहासिक फैसला लिया, निश्चित तौर से राजस्थान का किसान इससे बहुत खुश है।

युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, दिल में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। उन्हीं युवाओं के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश के कोने-कोने में बैठे प्रत्येक बेरोजगार का भविष्य संवारने, सुधारने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 01 लाख 25 हजार सरकारी नौकरियां और 01 लाख 50 हजार नौकरियां निजी क्षेत्र में देने का निर्णय लिया है।

VPS-RTM-20.02.2025-18.30-3o

मैं यह समझता हूं कि प्रदेश का युवा इससे बहुत ज्यादा खुश है, आगे बढ़ेगा, उनको रोजगार मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्री महोदय को।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में उप जिला अस्पताल, आई.टी.आई., कॉलेज, कृषि मंडी विस्तार, मेड़ता रोड को नगरपालिका सहित विभिन्न सौगात देने का ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्य मंत्री महोदय को। पिछले बीस सालों से हम बड़ी मांगें करते थे। मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के गोटन में जो राजकीय कॉलेज, पेयजल व्यवस्था हेतु ग्राम डोटोलाई, बासनी सेजा, लूणियास आदि के लिए 9 करोड़ रुपये की राशि और जसनगर में पुलिस थाना बनाने की घोषणा की, उसके लिए धन्यवाद देता हूं और मेरे लाम्बा जाटान में जो 220 के.वी. का नया जी.एस.एस. स्वीकृत हुआ, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रियांबड़ी ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की मैं मांग करूंगा और एक विद्युत विभाग का ए.ईएन. ऑफिस मेड़ता में खोलने के लिए निवेदन करूंगा। हमारे ऊर्जा मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, एक ए.ईएन. ऑफिस खोलने की मांग सदन के माध्यम से करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछले कुछ वर्षों में वर्षा के कारण काफी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करीब 6 हजार करोड़ रुपये से चरणबद्ध तरीके से करवाये जाने की घोषणा की है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के माध्यम से।

यह बजट राजस्थान के विकास और विश्वास का बजट है। यशस्वी मुख्य मंत्रीजी एवं उप मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के उत्थान, समग्र विकास को समर्पित यह राजस्थान का बजट 2025-26 प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा और साथ ही जन-जन के लिए जीवन में खुशहाली का नया अध्याय जोड़ेगा।

चिकित्सा के क्षेत्र में मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी दिया मेड़ता को बहुत ज्यादा। राजस्थान में बहुत बड़ा बजट दिया चिकित्सा के क्षेत्र में क्योंकि निरोगी काया होगी तब ही राजस्थान आगे बढ़ेगा, तो बहुत ज्यादा दिया है। कृषि बजट में भी किसानों के लिए कहा था, जो किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की है, तीन हजार रुपये हमारी सरकार ने किसानों को देने का काम किया है। निश्चित तौर से यह जो 30 हजार किलोमीटर की तारबंदी जो हम समझते हैं, किसान परिवार से हम आते हैं। जब जंगली पशु फसल को कितना नुकसान करते

हैं तो उनके लिए भी हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने और हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो बात रखी, किसानों को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

पर्यावरण के मामले में निश्चित रूप से हम सबको यह पता है और हमारी आने वाली पीढियों के लिए पर्यावरण कितना काम आने वाला है, तो 250 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जो हरियालो राजस्थान, पहाड़ियों पर जब यह बजट लगेगा, यह पौधे लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढियों के लिए यह बहुत बड़े फायदे का काम होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब, मेरे को दस मिनट तो दें।

श्री सभापतिः हो गया। दस-दस मिनट कर गये। आप समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): सर, मैं एक मिनट लूंगा। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमारे सदस्य अभी यह बता रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने स्कूलें गोचर भूमि पर बना दी, गोचर में काफी स्कूलें बनी हुई हैं, श्मशान गोचर भूमि में बने हुए हैं तो मैं यह सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा कैबिनेट में निर्णय लें ताकि स्कूलों और श्मशान भूमियों का और जो घुमन्तू परिवार के लोग अभी भी गोचर भूमि में बसे हुए हैं, हम उनकी व्यवस्था कैसे करें, उनको मुख्य धारा में कैसे लाये, यह हम सबका परम दायित्व एवं कर्तव्य बनता है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय मेड़ता।

श्री सभापतिः श्री मनीष यादव। आप विराजिये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, कोई भी सरकार को, जब बजट किसी प्रदेश का आता है तो प्रदेश की जनता टकटकी लगाकर यह देखती है कि प्रदेश की जनता को क्या मिलने वाला है। जनता को खुशहाली की आस रहती है। जनता को बड़ी-बड़ी उम्मीदें रहती हैं लेकिन यह जो बजट यहां पर दूसरा बजट भाजपा की सरकार ने, वित्त मंत्रीजी ने जारी किया है, मैं यह कहना चाहूंगा कि अब आने वाले समय में प्रदेश की जनता बजट से उम्मीदें नहीं रखेगी क्योंकि भाजपा का यह बजट ऐसा बजट है जिसका मैं उदाहरण भी आपके सामने पेश करूंगा, यह केवल आकड़ों का मायाजाल है और ऐसी बातें जो वास्तव में क्योंकि बजट का, कोई भी बजट प्रदेश सरकार देती है तो वह आय-व्यय का एक अनुमान होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक दस्तावेज के साथ बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान की आठ करोड़ की जनता जिस बजट के साथ अपने सपने जोड़कर रखती है, वह एक पीड़ा के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी यह कह रही थीं कि पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीजी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प उन्होंने लिया है और प्रदेश में पांच हजार करोड़ की सड़कें बनाने का जो उन्होंने आने वाले समय में

काम हाथ में लिया है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जो 1098.97 करोड़ की 25 सड़कें जो सी.आर.आई.एफ. फंड की है, उनकी वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति 2024-25 के अंतर्गत 03 जनवरी, 2025 को जारी हो चुकी है और इनकी एन.आई.टी. भी जारी हो चुकी है और जिसका पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आपने अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 में, बजट घोषणा में उसको लिया है। केवल श्रेय लेने के लिए, केवल ऐसी बात असत्य पेश करने का काम, राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम आपने किया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी एक सड़क जो बजट पर 14वें नम्बर पर है, NH 248 A से ढोढसर NH 57 तक, यह 38.5 किलोमीटर की सड़क है, 35 करोड़ से यह बनने वाली है और 03 जनवरी को पी.डब्ल्यू.डी. ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। एन.आई.टी. 10 फरवरी को जारी हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का 03 जनवरी, 2025 का आदेश मैं सदन के सामने पढ़कर सुना रहा हूं-

"Administrative & financial sanction for 27 No. work under Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) for year 2024-25 in Rajasthan.

I am directed to convey Administrative & financial sanction on behalf of the Governor of Rajasthan for following 27 works under Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) scheme for total approval cost amounting Rs. 1154.47 Crores."

यह किस तरीके से आपने मिथ्या बात, असत्य बात बजट में 2025-26 के अनुमान में कही है, वह बिलकुल असत्य है, बिलकुल गलत है, प्रदेश की जनता के साथ यह अन्याय है जो विपक्ष किसी भी तौर पर यह सहन नहीं करेगा। इस प्रकार के असत्य आकडों की बातें जिस प्रकार से आप करते हो, यह राजस्थान की जनता आपका चेहरा देख रही है।

आप बजट में यह घोषणा कर रहे हैं 1.25 लाख को नौकरी देंगे। राजस्थान के नौजवान को आप नौकरी की बात करते हो और राजस्थान की जनता के पैसे से विज्ञापन देते हो कि हमने एक लाख नौकरियां अभी तक दे दी हैं। आप यह बताओ, आप यह सदन के सामने रखो कि सरकार के गठन होने के बाद में आपने कितने भर्ती विज्ञापन निकले, इसकी जानकारी आप दो। वित्त मंत्रीजी यह कहती हैं, विवेकानंदजी का कोट अभी माननीय विधायकजी भी कर रहे थे कि युवा वह होता है जिसके हाथ में शक्ति होती है, जिसके पैरों में गति होती है, हृदय में ऊर्जा होती है, आंखों में सपने होते हैं। यह ठीक बात है लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार युवाओं के हाथ से उसकी शक्ति छीन रही है, उसके पैरों की गति छीन रही है, नौजवान की ऊर्जा खतम कर रही है, उनके सपनों को चूर-चूर कर रही है। ये केवल आकड़ों की बात करके, आपने सरकारी नौकरियों का वर्गीकरण यहां पर नहीं बताया। जो कोविड हैल्थ असिस्टेंट जिन्होंने कोरोना के समय अच्छा काम किया, वे आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पांच हजार युवा मित्रों का आपने रोजगार छीन लिया। किस तरीके की बात करके आप राजस्थान के नौजवान के साथ छलावा करना चाहते हैं? आप जब सरकार में नहीं थे तो तब आप यह कहते थे कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें हम घटाएंगे। आज हरियाणा और

राजस्थान में पेट्रोल का 10-11 रुपये का अंतर है। आपके बजट में एक शब्द डीजल-पेट्रोल सस्ता करने और वैट हटाने, महंगाई कम करने पर नहीं आया है। माननीय, आप सुनिये, सुनने की क्षमता रखिये। यह हकीकत है जो राजस्थान की जनता तक जानी चाहिए। आप असत्य बोलकर इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते।

SSY/RTM/20.02.2025/18.40/3p

आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): यह जोर से बोलकर के जनता को बरगलाना चाहते हैं। जनता को बहकाना चाहते हैं। मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1150 से बढ़कर आपने 1250 करने की बात कही, पिछली कांग्रेस की सरकार में राजस्थान मिनिमम गारंटी एक्ट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति वर्ष 15 फीसदी बढ़ाने का प्रावधान किया था, अगर उसके हिसाब से आप बढ़ाते तो 1323 रुपए आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती। आप यह जिस तरीके की बात कर रहे हैं यह राजस्थान की जनता के साथ छलावा है।

आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हो, लेकिन आप पेड़ लगाकर के सेल्फी लेने की बात करते हो, आप 7 करोड़, 10 करोड़ पेड़ लगाओगे, यह राजस्थान में आपने पिछले बजट में कहा था कि 7 करोड़ पेड़ आपने लगाये, कहां पर हैं? आज जहां पर ट्री गार्ड नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, यह जनता को बहकाना, बरगलाना बंद कीजिए, जिस तरीके का आप यह जो राजस्थान की जनता के सामने विकास का आईना दिखा रहे हैं यह बिलकुल असत्य है।

आप किसान की आय को दुगना करने की बात कर रहे हो, लेकिन आपके बजट में उसमें एक शब्द नहीं आता। मैं कहना चाहता हूं, मैं किसान परिवार से आता हूं, आज किसान आजीविका चलाता है सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, पत्ता गोभी ब्रोकली, ककड़ी, खीरा, प्याज, लहसुन, आलू, मूली, गाजर और जो पशुपालन की एक फसल है जिसको हम दूध के रूप में जानते हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य इन सब्जियों पर, दूध पर लागू करे ताकि किसान को उसका फायदा मिले। किसान की आजीविका चल सके। आज जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है कोई प्रभावी बीमा पॉलिसी नहीं है राजस्थान की सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, अभिभाषण की चर्चा के दौरान यह भी बात आई हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा, बीकानेर में जहां शिक्षा का हमारा सबसे बड़ा मुख्यालय है वहां पर किस तरीके से टांके में डूब करके तीन बच्चियों की मौत हो गई। बड़ी शर्मिंदगी की बात है प्रदेश के लिए, हमको सोचना पड़ेगा। कोटपूतली में बच्ची और दौसा में ट्यूबवेल में बच्चा फंस गया। आज हम सबको यह महसूस करना पड़ेगा कि एक ठोस नीति बनायें ताकि राजस्थान

का विकास हो सके और इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके।

मानननीय सभापति महोदय, यह आज के समाचार पत्र की खबर है दलित दूल्हे को उतार कर घोड़ी ले गये दबंग, मैं दबंग नहीं कहता, यह दबंग नहीं हैं, माननीय यह ऐसे लोग जिन्होंने प्रदेश में आज कानून व्यवस्था का मखौल भाजपा सरकार के समय उड़ा रखा है आज हर जगह पर, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए भी कहना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): वह कांग्रेसी थे, उनको ठीक करेंगे।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मदन जी, आप बैठिये, सच्चाई सुनने का माद्दा रखिये। कल बीते दिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गरीब परिवार की 23 मवेशी चोरी हो गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में देवन गांव की घटना है। ठोस कानून व्यवस्था राजस्थान में चाहिए। इसके लिए ठोस नीति बनानी पड़ेगी। 12 हजार रुपये किसान सम्मान निधि देने का वादा किया था। आपने उसको 9 हजार रुपये कर दी। वाहवाही लूट रहे हो? संकल्प पत्र में 12 हजार कहा था और यह किसानों के साथ अन्याय है। आपको 12 हजार देना पड़ेगा, 12 हजार रुपये किसानों के लिए करना पड़ेगा।

श्री सभापति: शांत रहें।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मैं एक बात कहना चाहता हूं, मजलूमों के हक में कभी खड़ी होती, मजलूमों के हक में कभी खड़ी होती, सच का हाथ पकड़ कर कभी अड़ी होती, चीख-पुकार के बीच सत्ता खामोश रही, पछताएगी काश कि बोल पड़ी होती। आप सबको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): सभापति महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं सुषमा स्वराज जी का भाषण मैं सुन रहा था कि जब-जब देश में करेंसी गिरती है देश की प्रतिष्ठा गिरती है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे उस समय के, उन्होंने कहा था, क्या कारण है रुपया पतला होता जा रहा है। जब मनमोहन सिंह जी ने देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में सौंपी एक डॉलर 58 रुपये था, आज आप देखिए एक डॉलर 87 रुपए है। आज देश की और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा नहीं गिर रही? आपको सबको समझना पड़ेगा।

हम सब लोगों को आपके विधायक कहते हैं कि कांग्रेस का नामोनिशान डूब जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। कांग्रेस का नामोनिशान इस देश में, इस देश की जड़ों में है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): कांग्रेस इस देश में हमेशा रहेगी। मैं अंत में दो बात कहते हुए कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात।

श्री सभापति: हो गया आपका समय। तय समय में ही बोलें आप।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा मनोहरपुर में परिवहन की व्यवस्था की जाये। मनोहरपुर खेजरोली में सह शिक्षा का महाविद्यालय खोला जाये।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह जी।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण 2025-26 पर चर्चा का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, कल हमारी वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता के हित को देखते हुए जो एक शानदार बजट पेश किया सदन में उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में लोग ढोल नगाड़े बजाकर के, आतिशबाजी कर करके स्वागत कर रहे हैं। हर गांव में, हर गली में, हर शहर में इस बजट की चर्चा है।

इस बजट में हर वर्ग को चाहे किसान हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे राज्य के अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हो, हर क्षेत्र में चाहे सिंचाई के लिए पानी हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, हर क्षेत्र में इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। चाहे मंदिरों के जीर्णोद्धार का मामला हो, चाहे रख-रखाव हो, मंदिरों की साज सज्जा हो, पुजारियों की वेतन वृद्धि हो, वृद्धावस्था, विधवा अवस्था, एकल नारी पेंशन में वृद्धि, इस तरह की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कल हमारी वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने इस सदन में करी थी।

मैं, मेरी ओर से और मेरी आसींद हुरडा विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी और भजन लाल जी शर्मा की पूरी कैबिनेट का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी विधान सभा में भी कल बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं।

सभापति महोदय, अभी विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, सुबह से इस सदन में चर्चाएं हो रही है। विपक्ष का काम होता है हर काम में अडंगे अड़ाना, विरोध करना, यही इन्होंने किया है। कोई रामायण पर, रामलीला पर तंज कस रहा है, कोई हनुमान जी पर तंज कस रहा है।

सभापति महोदय, एक हमारे विद्वान साथी जो अभी इस सदन में नहीं हैं, बजट पर वह इस तरह की चर्चा करके गए आधे घंटे की उनकी चर्चा थी, बहुत सारे आंकड़े उन्होंने बताए थे। आंकड़े इस तरह से पेश किए गए जैसे कि उन्होंने केंद्र सरकार का जो बजट आया उसमें भी उन्होंने उंगली उठाई। इस तरह के विद्वान साथी वह हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि आप में अगर इतनी योग्यता है, आप इतने विद्वान है और आपका गणित इतना मजबूत है तो पूरे 5 साल तक जो आपकी सरकार थी उसमें भी वित्त मंत्री बनते। आप वित्त मंत्री बनकर के चर्चा करते। पूरे 5 साल तक हम भी उधर बैठे थे।

आदरणीय सभापति महोदय, हम सब लोगों ने उस सरकार का जो मंजर था हमने बहुत नजदीक से देखा है। कोरोना की महामारी थी। 2 साल कोरोना भी आया था। हम लोग उधर बैठकर के चिल्लाते थे। आज यह कह रहे हैं 5 बोरवेल आये हैं वह खुदे ही नहीं है, हैंडपम्प हमको दिये नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं हमने 5 वर्ष तक इसी सदन में

उस तरफ बैठ करके चिल्ला-चिल्ला करके, हमने मांग की थी इन्होंने हमको एक हैंडपम्प तक नहीं दिया था उस समय। मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान में मैं पहला एक सदस्य था जो उस सरकार के खिलाफ आसींद एसडीएम कार्यालय के बाहर सड़कों को लेकर के, नालियों को लेकर के 25 दिन तक धरना दिया था और उस समय सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। उस समय हमने धरने दे करके काम करवाये थे। आज यह बातें करें बहुत बड़ी-बड़ी, आज मोदी जी की चर्चा करें, एक विद्वान साथी हमारे, जो हमारे मित्र हैं, वह यह तक कह गये की वैक्सीन के पैसे खा गये। वैक्सीन के पैसे आपने दिये थे? आपकी सरकार थी उस समय। मोदी जी ने वैक्सीन पूरी दुनिया में बांटी थी और फ्री में बांटी थी। आप उसके ऊपर भी आज उंगली उठाकर चले गए हो। वैक्सीन के ऊपर आप राजनीति कर रहे हो।

आपको मालूम नहीं है। आपके पास आंकड़े नहीं हैं। आप जानते नहीं हैं। आपको कुछ समझ में आता नहीं है। सदन में बैठकर के कुछ भी बोल देते हो। हाथ में पेपर लो, आंकड़े लो, आपके राज में जो भ्रष्टाचार हुआ था, आज हमारे जो एक सदस्य बोल रहे थे, वह आंकड़े पेश कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े यहां पेश किये। उन्होंने कहा था कि फलां योजना में 147 करोड रुपए आया था, आपने लगाया 52 करोड रुपए, आप क्या चाहते हैं?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब नहीं हैं, इस प्रदेश के भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जनता की गाढी कमाई का पैसा, एक-एक रुपया सोच समझकर के लगाया जाएगा। वह चाहे 12 महीने में लगे, चाहे 6 महीने में लगे लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर यह सरकार एक रुपया नहीं देगी। एक-एक पैसे को ईमानदारी से लोगों के लिए लगाया जाएगा और धरातल पर उतारा जायेगा।

spp/rtm/20.02.2025/18.50/3q

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विद्वान साथियों को यह निवेदन करना चाहूंगा आप बातें बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार चल रही है, आप मोदीजी की क्यों बात कर रहे हैं? अब आपका दोष नहीं है, आपको मोदी फोबिया हो चुका है। आप हर समय मोदीजी को कोसते रहते हैं। भजन लाल जी शर्मा को कोसते रहते हैं क्योंकि यह बजट ही ऐसा है। माननीय सभापति महोदय, जुलाई में हमारा पहला बजट आया था। छह महीने में वह बजट धरातल पर उतरा है। लगभग 70 प्रतिशत उस बजट का काम हो चुका है और बहुत सारी जगह काम चालू हैं। पूरे राजस्थान में चालू हैं। विपक्ष के साथी न जाने कहां से आंकड़े लेकर आये हैं, क्या बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। हमने देखा ही नहीं कि धरातल पर उतरा है। आंखों से कोई अंधा हो, कानों से कोई बहरा हो, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। यहां पर केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान की जनता देख रही है। रानीवाड़ा से आने वाले हमारे साथी की सदन में प्रशंसा करना चाहता हूं। उन्होंने यह

बातें कही हैं। वास्तव में विपक्ष में बैठकर इस तरह की बातें होनी चाहिए। सरकार को संज्ञान में लाना चाहिए और सरकार की कहीं कमी है तो बताना चाहिए, राय देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए। रानीवाड़ा से आने वाले हमारे साथी ने अभी जो राय दी थी, मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार के साथ मिलकर आपने पांच साल में जो कबाड़ा किया है, उसका भुगतान हमको करना पड़ रहा है। पांच साल में आपने कुछ किया नहीं है, धरातल पर कोई काम उतरे नहीं हैं। आपके लोगों ने उस समय भ्रष्टाचार के रिकार्ड तोड़ दिये थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के साथ बैठकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग मिलकर राजस्थान की प्रदेश की इस 8 करोड़ जनता के लिये हम क्या कर सकते हैं, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बजट भाषण 2025-26 में जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम्। जय श्रीराम।

श्री सभापतिः श्री भगवाना राम सैनी।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, बजट 2025-26 में बोलने के लिये अवसर दिया, आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इससे पहले जो बजट आया और इस बजट में, दोनों में मैंने देखा बहुत गौर से, उदयपुरवाटी का कहीं नाम भी नहीं है। हो सकता है आपकी पक्ष-विपक्ष के लिये परम्परा होगी, लेकिन जनता यह देख रही है कि बजट में कुछ मिले और उसके लिये आस बनाये बैठी है। मेरा उदयपुरवाटी की सबसे गंभीर समस्या है वह पानी की है। वैसे हमारे माननीय सदस्य ने बोल दिया लेकिन मजबूरी है और मुझे भी यहां बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरा एरिया पहाड़ी बैल्ट आता है, जहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है। या तो पानी के ट्यूबवैल सूख गये या फिर उनमें पानी कम हो गया। पिछली गर्मी का समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से निकला था। अब की बार भी हालात यही हैं कि हमको पांच ट्यूबवैल दिये थे, दस हैण्डपम्प दिये थे पिछले बजट में, लेकिन वहां धरातल पर न तो कोई ट्यूबवैल लगा और न ही कोई वहां पर हैण्डपम्प लगा।

इसके अलावा, वहां के लिये पिछली बार कहा था कि सूखे के विरुद्ध ट्यूबवैल को गहरा करायेंगे और उससे पानी की सप्लाई हो जाएगी। मेरे उदयपुरवाटी में मात्र दो ट्यूवबैल्स को गहरा किया गया है अभी तक और रिप्लेसमेंट के नाम पर, मैं आपको बताऊं 15 महीने में वहां 200 मीटर केबल नहीं आयी, 100 फीट पाइप नहीं आये। लगभग जितने भी सरकारी ट्यूबवैल हैं उनमें कोई व्यवस्था नहीं है। हालात यह हैं इस गंभीर मौसम में भी, कुछ दिनों के बाद गर्मी आएगी तो आप उसको कैसे काबू कर पाओगे? यह मुझे समझ में नहीं आता। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछली सरकार ने यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जनता को पानी तो चाहिए। सरकार किसी की भी हो, उम्मीद रहती है जनता को और उस सरकार को प्रबन्ध करना पड़ता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इस पर ध्यान कैसे नहीं दे रहे? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे गंभीरता से लें, क्योंकि आने वाली गर्मी में बहुत बुरी हालत होने वाली है। इसके लिये आपसे निवेदन है

कि आप इस पर ध्यान देंगे।

अभी हमारे मुख्य मंत्रीजी चुनावों में वहां गये थे और वहां पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगे थे यमुना जल के पानी के बारे में। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह दिया गया था कि इस पर काम चल रहा है। इस बजट में कोई नाम ही नहीं लिया गया उस बारे में। आज झुन्झुनूं जिला पूरा ड्राई हो रहा है, वहां सिंचाई के पानी की ही नहीं पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। चाहे पिलानी हो, चाहे सूरजगढ़ हो, चाहे उदयपुरवाटी हो या खेतड़ी हो, मेरा मानना यह है कि मंत्री महोदय इस पर कुछ ध्यान दिया जाये। पानी की बहुत बड़ी विकट समस्या वहां पर आने वाली है।

इसके साथ ही सड़कों में, 10 से 30 तक सड़कों का विवरण दिया गया है। पांच फीट रोड न तो पिछले बजट में आयी, न इस बार के बजट में आयी। मेरा कहने का मतलब है कि इस पर भी कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं आपको चिकित्सा के बारे में कहना चाहता हूं। चिकित्सा मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वहां पांच-छह सी.एच.सी. और पी.एच.सी. तो ऐसी हैं जिसमें 12 महीनों से कोई डॉक्टर नहीं हैं। आपने बताया था कि 58 हजार डॉक्टर्स लगाये। मेरा निवेदन है कि उनको चालू रखने के लिये कम से कम एक-दो डॉक्टर तो वहां पर लगायें। वहां हॉस्टल बंद पड़े हैं, 12 महीनों से बंद पड़े हैं। सी एच सी और पी एच सी में तो फिर भी एक-दो डॉक्टर मिल जाएंगे। हमारे वहां बड़ा गांव है जहां सी एच सी में एक डॉक्टर है। 60 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर है। वहां पर इतनी गंभीर समस्या है। मैं ट्रोमा की बात कह रहा था तो मेरे उदयपुरवाटी में एक ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहां किसी की सी.टी.स्केन हो सके। वहां पर हजारों की आबादी है। हमारे पूरे उदयपुरवाटी की ऐसी स्थिति है, तो इसे गंभीरता से लें। मैं इसके बारे में दो-तीन बार बोल चुका हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप लिस्ट दे देना, करा देंगे।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। यह बड़ी समस्या है। इसके अलावा, आप किसान के बारे में बात करते हैं, किसानों के लिये यह किया, वह किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरे गुढा गौड़ेजी बड़ा कस्बा है और उसके दोनों साइड से हमारे बाईपास निकल गये। उन किसानों को अब तक 90 प्रतिशत काम हो चुका, लेकिन अब तक उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनको मुआवजा दिलाया जाये। एक 2022-23 में हमारे वहां पर पाला पड़ने से 100 प्रतिशत फसलें नष्ट हो गयी थीं, उनका सर्वे भी हो चुका है, गिरदावरी भी हो गयी और 40 प्रतिशत किसानों को मुआवजा भी मिल गया। इसके अलावा 69 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, तो उनको मुआवजा दिलाया जाये, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

इसके साथ ही, आप किसानों की बात करते हैं, मैं अब जो बोलूंगा वह सत्य है कि हमारे उदयपुरवाटी में जो उचित मूल्य की क्रय-विक्रय की दुकानें होती हैं उन पर कम से कम किसानों की मूंगफली की बिक्री होती थी, वह दो हजार किसानों को होती थी। अब की बार

केवल पांच किसानों की बिक्री हुई है, सिर्फ पांच किसानों की और मेरी बात गलत लगे तो आप रिकार्ड मंगवा लेना कि सिर्फ पांच किसानों की मूंगफली बिकी है अब की बार। बाद में तो पोर्टल ही बन्द कर दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है। इस बार का हमारा यूरिया खा गये। तीन-तीन हजार यूरिया के बैग मिला करते थे, अबकी बार केवल सात हजार बैग मिले हैं। आप किसानों के लिये कह रहे हैं तो किसानों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे।

इसके साथ ही, मेरी कुछ मांग है कि हमारा जो अस्पताल है उसको जिला अस्पताल बनाया जाये। हमारा उदयपुरवाटी बड़ा कस्बा है और वहां पर डीवाई. एस.पी. आफिस और एक कृषि विश्वविद्यालय के लिये मांग करता हूं। राजकीय महाविद्यालय उदयपुरवाटी और गुढा गौड़जी को स्नातकोत्तर करके अन्य संकाय दिये जायें। हमारी शाकम्बरी माता है और हमारी मनसा माता के बड़े मन्दिर हैं, इनको पर्यटन स्थलों का दर्जा दिया जाये। मनसा माता कंजर्वेशन सेंटर की चारदीवारी, यह मेरा बहुत बड़ा गंभीर विषय है। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी भोजन-पानी के और बिना दीवार बनाये वहां पर पैंथर छोड़ दिये गये। मैं यह बार-बार बोल चुका हूं कि वहां हमारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वहां जो प्रमुख धंधा है किसानों के लिये और भेड़-बकरी चराकर अपना जीवनयापन करते थे, तो मेरा निवेदन है कि हमारी जो फोरेस्ट की लैंड है, जहां पैंथर छोड़े गये, वहां पर चारदीवारी बनाने का काम किया जाये जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था हो सके।

इसके साथ ही, गुढा गौड़ेजी में उप खण्ड कार्यालय खोलने की मैं मांग करता हूं।

jyg/rtm/20.02.25/19.00/4a

वहीं गुढा गौड़जी पंचायत समिति और छापोली ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की मैं मांग करता हूं। उदयपुरवाटी में जो जर्जरावस्था में सड़कें हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। इसके साथ ही मेरी नगरपालिका उदयपुरवाटी 1952 से नगरपालिका है, उसमें कम से कम 40-50 हजार की पापुलेशन है और यह पुरानी आबादी में बसी हुई है, इसके बाद जो नगर पालिकाएं बनी हैं, वहां पर सीवरेज की लाइनें पड़ चुकी हैं लेकिन उदयपुरवाटी में अभी भी मेरी नगरपालिका में कोई सीवरेज नहीं पड़ी है, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा चुंगी नम्बर 3 से सब्जी मण्डी तक बरसात के दिनों में इतना पानी भरता है कि वहां पर लोग निकल नहीं सकते। तो उस पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट के लिए विशेष बजट आवंटन करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं।

शहरी क्षेत्र में मृत पशु निस्तारण के लिए कोई भूमि नहीं है। इनके निस्तारण के लिए तकलीफ होती है, किसानों के पशु मरने पर पालिकाकर्मी उन्हें भूमि उपलब्ध कराने को कहते हैं, ऐसे लोगों की समस्या मुक्ति हेतु मृत पशु निस्तारण हेतु भूमि आवंटन करने हेतु आपसे

निवेदन करता हूं।

पौंख नगर पालिका हमारी ऐसी नगरपालिका है जहां पर गुढा और पौंख दोनों को मिलाकर एक नगरपालिका बनी थी, इसमें गुढा को तो शामिल कर दिया पौंख में, गुढा ढहर को शामिल नहीं किया जो गुढा में ही शामिल था, तो वो दोनों को मिलाकर, उसमें गुढा ढहर को और मिलाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा जिला सैनिकों का जिला है। वहां पहले तो सैनिकों की भर्ती हटाकर अग्निवीर बनाया, अब अग्नि वीर को कहां लेकर जाओगे पता नहीं। उनको हमारे क्या है कि सीमा पर काम कर चुके सैनिकों को पुलिस और जेल विभाग में अग्नि वीरों को फायर सर्विस में आरक्षण किया गया है। माननीय सभापति महोदय, उनको अब और आगे कहां लेकर जाओगे हमारे जवानों को? पहले उनको अग्नि वीर बना दिया, अब उनको इसमें आरक्षण दिया है, फिर और कहीं दे दोगे, मेरा कहने का मतलब है कि उनको कोई ढंग की जगह पर लगाओ। उनका मान-सम्मान करना सीखो, क्योंकि यह बहुत बड़ा वर्ग झुंझुनूं जिले में है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री शंकर सिंह जी।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार।

देश के यशस्वी प्रधान मंत्री महोदय, आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय, आदरणीय भजन लाल जी एवं वित्त मंत्री महोदया, आदरणीय दिया कुमारी जी ने कल 19 फरवरी को पेश किये गये बजट, विकसित और खुशहाल राजस्थान के बजट पर आपने बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, कल जब हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान और अग्रणी राजस्थान का बजट पेश किया उसके बाद पूरे प्रदेश की 8 करोड़ जनता में खुशी की लहर छायी हुई है, सिर्फ विपक्ष के साथियों को छोड़कर। यह बजट राजस्थान की आठ करोड़ जनता के हितों को पूरा करने वाला बजट है, यह राजस्थान के आम गरीब और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के सपने को पूरा करने वाला बजट है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। इसमें मोदीजी का विजन और भजन लाल जी का मिशन साफ तौर पर दिखायी दिया है। इस बजट में हमारी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं जो राजस्थान को देश में प्रथम स्थान पर ले जाने में सहायक साबित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट इतना शानदार और जानदार है कि विपक्षी साथी भी मन ही मन प्रशंसा तो कर रहे हैं पर उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको भूमिका विपक्ष की

निभानी पड़ती है, बाहर नहीं ला पा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। ...(व्यवधान)... कुल मिलाकर यह बजट कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में 2019 से 2023 तक इनकी सरकार थी। महिला अत्याचार, दुष्कर्म और अपराध के आंकड़े 2019 में 42740 मामले दर्ज हुए, 2020 में 35963 मामले दर्ज हुए, 2021 में 42757 मामले दर्ज हुए, 2022 में 47105 और 2023 में 46348 मामले दर्ज हुए।

माननीय सभापति महोदय, इनकी सरकार में कानून-व्यवस्था लगातार बिगड़ी है और हमारी सरकार आने के बाद कानून-व्यवस्था में हमेशा सुधार करने का काम किया है। दुष्कर्म के साथ हत्या के मामलों में 26.67 प्रतिशत की कमी आयी है। हत्या के मामलों में 15.25 प्रतिशत की कमी आयी है। डकैती के मामलों में 13.33 प्रतिशत की कमी आयी है। लूट के मामलों में 30.36 प्रतिशत की कमी आयी है। चोरी के मामलों में 34 प्रतिशत की कमी आयी है। दुष्कर्म के मामलों में 34 प्रतिशत की कमी आयी है। माननीय सभापति महोदय, ये आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद में सुशासन आया है।

माननीय सभापति महोदय, आज पेपर में मैंने पढ़ा हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री माननीय गहलोत साहब और डोटासरा जी का स्टेटमेंट सुनकर आज मोदीजी के वादों पर झुठलाया जा रहा है। मैं आपको इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी मिथ्या टिप्पणी आपके लिए शोभा नहीं देती है क्योंकि आप अपने कार्यकाल में जो शर्मनाक कृत्य हुए उनको छुपाये जा रहे हैं। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपकी सरकार के कार्यकाल में 4148 घोषणाओं में से आधी भी 1921 घोषणाएं भी अपूर्ण हैं, वो पूरी नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, आज जल जीवन मिशन को देखिये, आपके कार्यकाल में जल जीवन मिशन में प्रदेश सम्पूर्ण देश के अंतिम पायदान पर खड़ा था, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे थे, कार्य की गति धीमी थी इस कारण मात्र 2025 में जेजेएम की समाप्ति पर लाखों घर इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते, अगर माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने केन्द्रीय बजट में से जेजेएम की अवधि बढ़ाकर 2028 तक नहीं की होती तो। ...(व्यवधान)... ताली तो बजा दो, ...(व्यवधान)... है ही नहीं कोई, कौन बजायेगा? ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा अंतिम समय में इनकी सरकार ने जो थोथी घोषणाएं की, किसानों से इनके जो भावी प्रधान मंत्री बनने वाले थे, उन्होंने आकर राजस्थान में घोषणा की कि दस दिन में सम्पूर्ण कर्ज माफी का वादा, इनकी सरकार, इनके सपनों में, इनके संकल्प में कहा गया था कि किसानों का ऋण माफ, युवाओं को 3500 रुपये घर बैठे मिलेंगे, मिल गये क्या? आज तक नहीं मिले। इस प्रकार की थोथी घोषणाएं इनके द्वारा की गयी। हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया था किसान निधि के लिए उसको बढ़ाकर दो गुना करने के लिए आज उस कदम पर पहले 8 हजार हुआ और कल 9 हजार रुपये की घोषणा हो गयी है और ये मैं उनको कहना चाहता हूं ऐसे स्टेटमेंट देने वालों को कि आप सब्र रखिये, इसी कार्यकाल के अन्दर किसानों से मोदीजी का वादा पूरा होगा और यह भजन

लाल जी की सरकार है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए 12 हजार निश्चित तौर पर किसानों को मिलेंगे, आप तसल्ली और धैर्य रखें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने ईआरसीपी की डीपीआर बनायी और आपकी सरकार के समय में ईआरसीपी को लटकाया, भटकाया गया और अटकाया गया, हमारी सरकार ने इस परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियांवित करने का संकल्प लिया है।

माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा कि आपकी सरकार के समय में पेपर लीक, भू माफिया, जिस प्रकार से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया था, आपके समय में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, हमने इस सम्बन्ध में एसआईटी का गठन किया, सैंकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया और हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से हो, परीक्षाएं समय पर हो और सफल अभ्यर्थी को शीघ्र नियुक्ति मिले, हम पांच साल में चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में आगे बढ़ रहे हैं।

MLS/RTM/20.02.2025/19:10/4b

मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपने बिना गुण-अवगुण के आधार पर जल्दबाजी में नये जिले बना दिये। ठीक आचार संहिता लगने के समय वह घोषणा की। आपने इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान भी नहीं किया। हमारी सरकार ने 8 जिलों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर 1 हजार करोड़ का कल बजट जारी कर दिया। रिफाइनरी में क्यों विलम्ब हुआ, आपको इसकी जानकारी सदन को देनी चाहिये, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। आपकी सरकार ने 5 बरस तक अपनी कार्य प्रणाली के कारण रिफाइनरी का पूरा काम नहीं किया और लटकाते रहे, अटकाते रहे। हमारी सरकार ने आते ही इस काम को गति दी। जल्दी ही हम रिफाइनरी का काम प्रारम्भ करेंगे। हमारी सरकार ने कार्य भार सम्भालते ही आपके समय पेट्रोल, डीजल और वैट की दरों में 7 रुपये 80 पैसे की रेट घटायी है। आपको याद होगा, आपके इलाके में पेट्रोल-डीजल की जो दरें थीं, उनको भी घटाया गया है।

कांग्रेस शुरू से ही देश में हिन्दुत्व को मिटाने का काम करती आ रही है। देश को विकसित भारत बनाने के लिए नहीं, आजादी के बाद से ही जब-जब भी इस देश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब-तब इनकी सरकार में कोई न कोई मुसलिम भाई देश का शिक्षा मंत्री बना है। इस कारण से पहली कक्षा से लगाकर कॉलेज तक देश के हर बच्चे के मुंह से यही निकलता है, मुहम्मद गोरी, अकबर और बाबर बहुत महान थे। हमारे समय अजमेर में, जन्मस्थली दिल्ली के बादशाह अन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान बने। 16 बार मुहम्मद गोरी को धूल चटायी। 17वीं बार धोखे से पकड़े जाने के बाद में भी उनके जो वजीर थे चन्द बरदाई, उनको कहा कि अब हमें गिरफ्तार कर लिया है और मेरी आंखें इन्होंने सलाखों से फोड़ दी हैं, अब बचने का कोई उपाय बता।

चन्द बरदाई ने कहा, हुकम, आपको तीरन्दाजी का अनुभव है और मैं कहता हूं, आप

शब्दभेदी बाण चलाएं। चन्द बरदाई ने कहा, मैं जाकर परमिशन लेकर आता हूं। वे बादशाह के पास में गये, मुहम्मद गोरी को कहा कि हुकुम, अब ये आंखें तो आपने फोड़ दी हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो वैसे ही मर जाएंगे तो आप इनके पास में एक कला है, वह कला ले लीजिये। उन्होंने कहा, यह कला क्या है। चन्द बरदाई ने कहा, ये शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं। आप सात दीवारों के अन्दर चारों तरफ तवे लगाएं। एक तीर मारेंगे तो वह सातों तवों के अन्दर से होकर निकलेगा। उसने कहा, ऐसा भी कोई है क्या शब्दभेदी बाण तो चन्द बरदाई ने कहा हां। उसको डर आया। मुहम्मद गोरी सातवें माले पर जाकर बैठा।

सम्राट पृथ्वीराज चौहान नीचे बैठे हुए थे। आंखें फोड़ दी गईं। चन्द बरदाई ने तीर-कमान देने के बाद कहा, हुकुम,

''चार बांस चौबीस गज, अंगुल अष्ट प्रमाण,
ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान।''

सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तीर को कमान छोड़ा और मुहम्मद गोरी के गले में लगा। एक मिनट में ढेर ही हो गया सामने। इस प्रकार के योद्धा को छिपाया गया है। आज तक इतिहास में भी कहीं न कहीं वे देश के अन्तिम हिन्दू प्रधान मंत्री के रूप में रहे थे, इसलिए उनको इतिहास में भी छिपाया गया है। ये इनके काम हैं।

कांग्रेस सरकार में हमेशा से ही जनता शिक्षा से वंचित रही है। ये कहते हैं अकबर महान। इनके राज में इन्हीं को महान बताया गया था। अभी हमारा सरकार से निवेदन है कि इसमें सुधार करने की अति आवश्यकता है। अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राजस्थान का बच्चा-बच्चा अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करे, नयी ऊंचाइयों पर पहुंचे, यह प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आवाज है। हमारी सरकार ने इस बजट में शिक्षा के लिए अनेकों घोषणाएं की हैं। मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी एक मांग है, राजस्थान में खनिज फेल्सपार के मामले में जितने भी उद्योग चल रहे हैं, ब्यावर हो, उदयपुर हो, राजसमन्द हो, सीकर, अजीतगढ़, किशनगढ़, गंगापुर, अन्य जगहों पर से रॉ मैटेरियल गुजरात जाता था, अन्य स्टेटों में जा रहा है, उसके ऊपर पिछली सरकार में भी हमने रोक लगवाने के लिए मांग की थी। रोक लगायी भी गयी, लेकिन चोरी-छिपे माल हमेशा जाता रहा है और यहां के जितने भी हजारों की तादाद में उद्योग लगे हुए हैं, लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, वे बन्द होने की कगार पर हैं। मेरा उसमें एक सुझाव है कि इस रॉ मैटेरियल की रॉयल्टी को 6 गुणा अगर बढ़ा दिया जाये तो सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी और रॉ मैटेरियल बाहर जाने से रुक जायेगा और राजस्थान में जितने भी ये उद्योग हैं, उन्हें वापस जीवनदान मिल जायेगा और वे चलने लग जाएंगे। इससे राजस्थान की जनता को रोजगार भी मिलेगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसमें बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे तो इसका जरूर जवाब दें। आपको एक बात और याद दिला दूं। कांग्रेस के समय में आपकी प्रधान मंत्री माननीया इन्दिरा जी थीं। वे जब विदेश गयी थीं इटली और इजराइल, तब वहां पर जाकर देखा कि ये हरे-हरे

पौधे, इनको पानी कितनी बार पिलाना पड़ता है तो उन्होंने कहा कि मैडम, इनको पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये बिना पानी के जिन्दा रहने वाले हैं और 12 महीनों तक हरे रहते हैं। ओहोहोहो, तो हमारे राजस्थान में और हमारे देश में तो सूखा पड़ा हुआ रहता है और पूरी हरियाली होनी चाहिये हमारे देश में तो हरियाली के लिए वे वहां से बीज लाये और बीज लाकर पूरे देश में छिड़काव किया। आज हर गांव के अन्दर, आप किसानों के हितैषी बनने की बात कर रहे हैं, अगर किसी गांव में किसान दुःखी है तो सिर्फ और सिर्फ उस विलायती बबूल से दुखी हैं।

अगर उसके लिए सरकार अभियान चलाकर काश्तकारों को सुखी करने के लिए, सालभर तक भी कोई काश्तकार उस खेत पर नहीं हल चलायेगा तो जेसीबी लाकर उन बबूलों को निकलवाने के लिए उस काश्तकार को इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यह सज़ा काश्तकारों को कांग्रेस की देन है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारी सरकार से आग्रह है कि इनको कहीं न कहीं पंचायतों में नरेगा के द्वारा जड़ से नष्ट करने के लिए कार्यवाही करें। हमारा काश्तकार सुखी होगा। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जितना अच्छा सुधार करने के लिए हो जाये, बजट के अन्दर सुधार करना चाहिये।

जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है,
हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है।
अभी तो नापी है मुट्ठीभर जमीन हमने,
अभी तो सारा आसमान बाकी है।।

श्री सभापतिः श्री भीम राज भाटी।

श्री भीम राज भाटी (पाली): आदरणीय सभापति महोदय, वर्तमान बजट में विधायक कोष को 5 करोड़ से 10 करोड़ करने के लिए मैं सभी विधायकों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। 10 लाख रुपये आपने देकर, विधायकों के बैठने के लिए जो जगह प्रोवाइड कर रहे हैं एसडीएम कोर्ट में ...(व्यवधान)... नहीं वो एमएलए फंड से दे रहे हैं, मैं वही बात बता रहा हूं ...(व्यवधान)... चलो कोई नहीं, छोड़ो। मान्यवर, इस बजट में 1 हजार ट्यूबवैल्स और 1500 हैंडपम्प्स देने के लिए पूरे राजस्थान में वादा किया गया है, लेकिन राजस्थान में इतने डार्क जोंस हैं, राजस्थान में पानी इतना गहरा चला गया है कि उस ट्यूबैल से और उस हैंडपम्प से कोई पानी निकलने वाला नहीं है। अंडरग्राउंड पानी अवेलेबल ही नहीं है राजस्थान में, इसलिए ये जो उम्मीद कर रहे हैं कि 1 हजार ट्यूबवैल्स और 1500 हैंडपम्प्स की वजह से पानी की सप्लाई हो जायेगी तो बहुत मुश्किल काम है।

रहा सवाल जल जीवन मिशन योजना का, बहुत अच्छी योजना है, गांवों और ढाणियों में पाइप लाइंस तो डाल दी गयी हैं, पर उनमें अभी भी पानी नहीं आ रहा है और कई ढाणियां और काश्तकार, जो ग्रामीण हैं, जो वहां दूर-दराज में बस रहे हैं,

mkd/rtm/20.02.2025/19:20/4c

जल जीवन मिशन योजना में पानी से जुडने के लिए वे अभी भी वंचित हैं। माननीय, ये ढाणियों आज भी पाइप लाइन से जुड़ने से वंचित हैं। मान्वयर, अगर इन ढाणियों को नहीं जोड़ा गया तो आने वाले समय में, अभी तो सर्दी है, अभी गर्मी आने वाली है, जब गर्मी आयेगी तो पीने के पानी की भंयकर समस्या हो जायेगी।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, श्री अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।, यहां विधायकों द्वारा, याचिकाओं का एक रटा-रटाया सेट जवाब आता है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर सोचा जायेगा, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर इसका निस्तारण किया जायेगा तो यह सेट जवाब है। इसका मतलब याचिका लगाने का और याचिका से कोई भी रिजल्ट प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है।

रहा सवाल, इन्दिरा आवास योजना का, इन्दिरा आवास योजना की बहुत तारीफ की जाती है, लेकिन इन्दिरा आवास योजना में हजारों किसान, मेरे एरिया में कम से कम सैकड़ों किसान इन्दिरा आवास योजना से वंचित हैं। उनके पैसे, मुझे पता है, मैं फीगर दे सकता हूं। लेकिन इंदिरा आवास योजना की जो किश्तें हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अब नाम दूसरा है, नाम संशोधन करो। इन्दिरा आवास तो पुराने जमाने में था।

श्री भीम राज भाटी (पाली): हां, जो भी, प्रधान मंत्री आवास योजना कह लो। एक ही बात है। वे भी तो प्रधान मंत्री जी थे। इन्दिरा जी भी तो प्रधान मंत्री थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा में मैट लगाने के लिए आज भी इतना भारी भ्रष्टाचार है कि असरदार आदमी चाहे जिसको मैट लगवा देता है, कोई लेडीज को लगाना, कोई पढ़ी-लिखी बच्ची को लगाना, वह आज भी संभव नहीं है। उसमें जो ग्राम सेवक है, ग्राम विकास अधिकारी है, वह व्यवस्था करता है, वह उसको दबाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में भी कई घोषणा की गई थी, कई कामों की घोषणा की गई थी। माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं जोराराम जी साहब। जोराराम जी साहब को पता है कि जवाई बांध से जोधपुर 194 किलोमीटर की जो नहर थी, उसको पक्की करने का वादा किया गया था, 2280 करोड रुपए दिया गया था, लेकिन आज दिन तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन आज भी एक कदम भी उस काम के लिए आगे नहीं बढ़ा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): वे सिर्फ घोषणाएं थीं, इसलिए कुछ नहीं हुआ।

श्री भीम राज भाटी (पाली): नहीं, वह तो आपकी घोषणा थी, मेरी घोषणा थोड़े ही थी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): डीपीआर के लिए पैसा दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चार मिनट ज्यादा हो गये हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अशोक गहलोत साहब के समय में 2500 करोड़ की घोषणा हुई थी जवाई के लिए, उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ वह घोषणा थी।

श्री भीम राज भाटी (पाली): नहीं-नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपके पहले बजट की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आपका समय हो गया है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाली विधान सभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उसमें भी रोहिट पंचायत समिति सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। ना वहां कृषि के कुएं हैं, जिससे सिंचाई हो सकती है, ना वहां पीने के पानी के लिए कुएं हैं, जिससे पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है। इतना खारा पानी उन कुओं में है, अगर कोई चिड़िया भी पी ले तो चिड़िया भी तुरन्त मर जाती है, इतनी गंभीर स्थिति है।

इसलिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके यह सर्दी का मौसम है। जोगाराम जी आपको पता है, माननीय जोगाराम जी साहब आपको पता है, 1200 बच्चियां हैं उस नया चंढ आश्रम में, उन 1200 बच्चियों के पीने के पानी के लिए कितनी मुसीबत वे लोग देख रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहते हैं पाइप लाइन टूट गई, रिपेयर करना है, वो करना है, कोई आदमी अवेलेबल नहीं है तो इस सर्दी में भी अगर यह हाल है तो मुझे पता नहीं गर्मी में क्या होगा। मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं जोगाराम जी साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी पधारे थे। आपने भी उनको वादा किया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है इस बात का कि मेरा पाली शहर और रोहिट पंचायत समिति पर्यावरण और प्रदूषण से बहुत ज्यादा दुखी है। किसानों की हजारों बीघा जमीन खराब हो गई है, उनके कुएं खराब हो गए हैं, वह कमाने खाने लायक भी नहीं रहे हैं, लेकिन इस बजट में पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। पर्यावरण में प्रदूषण को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा। इसकी कोई कार्य योजना भी नहीं बताई गई है।

कौन-सा बजट दिया है, यह पड़ी है ना किताब, यह भाषण पडा है, इसलिए मेहरबानी करके जो प्रदूषण की वजह से जमीनें खराब हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा पाली शहर बदबू मारता है। जब पाली शहर में घुसो, आप नदी के ऊपर से जैसे ही निकलो या जैसे ही पाली शहर की तरफ बढ़ो, म्युनिसिपिलिटी लिमिट्स में बढ़ो, तो बदबू से आपका सिर दर्द करने लग जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रदूषण के लिए मेहरबानी करके करें, उससे किसान भी पीड़ित है और उद्योगपति भी पीड़ित है। उद्योगपतियों को नए-नए कानूनों की वजह से भ्रष्टाचार में तकलीफ उठानी पड़ती है। उद्योगपतियों को भी, काश्तकार तो बर्बाद हुए जो हुए ही हैं, लेकिन उद्योगपतियों को भी बहुत भारी समस्या है।

मान्यवर, आपकी घोषणा पत्र में वादा था कि पेट्रोल और डीजल में वैट कम करेंगे। पेट्रोल और डीजल में वेट कम किया मामूली वेट कम किया कोई कंसीडरेबल अमाउंट नहीं उसमें

घटाया गया।

इसलिए मेरा निवेदन है कि मेहरबानी करके आपकी घोषणा है, मेहरबानी करके पेट्रोल और डीजल में वेट कम करके उसको जो पड़ोस के राज्य हैं पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, उनके बराबर लाने चेष्टा करें।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पाली शहर में सीवरेज की इतनी भारी समस्या है कि सीवरेज का जो गंदा पानी है, वह लोगों के अंडरग्राउंड वॉटर सम्प में घुस रहा है और मोहल्ले में लोग आपस में अड़ोसी-पड़ोसी सब झगड़ रहे है। सीवरेज के बारे में कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, पूरे शहर के लोग, अलग-अलग बस्तियां के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। इसलिए, मैं निवेदन करुंगा कि सीवरेज के बारे में भी राज्य सरकार कुछ करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है चंढा में पिछले साल आपने एक पीएचसी को सीएचसी में कंवर्ट करने का वादा किया था। पिछले साल पीएचसी, सीएचसी में कंर्वट हो गई, वे रोहिट वाले असरदार आदमी थे, तो रोहिट की वह पीएचसी, सीएचसी में कंर्वट हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा काबिलियत और सबसे ज्यादा जरूरत है वह चंढा पीएचसी को सीएचसी में कंवर्ट करने की जरूरत है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा।

दूसरा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है सरदार समन्द बांध, खारड़ा बांध, गरला बांध, पाली जिले में सबसे ज्यादा इर्रिगेशन के डैम हैं। उन इर्रिगेशन के बांधों की जो नहरें हैं, वे कच्ची हैं, उन कच्ची नहरों की वजह से इतना पानी खराब होता है। तीस साल बाद सरदार समन्द बांध भरा, लेकिन उस बांध के भरने के बावजूद जो नहरें कच्ची हैं, उसकी वजह से जो सिंचाई का पानी है, जो पीने के काम में भी आता है, वह पानी इतना वेस्ट हो रहा है। उन कच्ची नहरों की वजह से कि मैं बयां नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, हो गया टाइम। आपका टाइम है, आपने 7.17 पर शुरू किया, 7.27 हो गया, 10 मिनट का टाइम दे रखा है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): मैं देख रहा हूं, घड़ी बोल रही है। मैं खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः घड़ी तो मैं भी देख रहा हूं।

श्री भीम राज भाटी (पाली): हां, 9 मिनट हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पाली और रोहिट के बीच में और पाली और जोधपुर के बीच में निमली में एक इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, डीएमआईसी का, डीएमआईसी इंडस्ट्रियल एरिया में 9 गांव की हजारों बीघा जमीन काश्तकारों की ली जा रही है। उन काश्तकारों को जो डीएलसी रेट है, वह डीएलसी रेट मात्र 35 हजार रुपये हैं।

श्री अध्यक्षः श्री आदू राम मेघवाल।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः बार-बार घन्टी बजा रहा हूं, चार बार बजा चुका हूं। 28 हो गये, साढ़े 28 हो गये। अंकित नहीं होगा।

श्री भीम राज भाटी (पाली): 000

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट के ऊपर लोकतंत्र के पवित्र मंदिर गरिमामय में सदन में बोलने का सुअवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी ने देखा प्रदेश की उन्नति को समर्पित वित्तीय वर्ष 2025-26 वाला बजट विकसित राजस्थान, समर्थ राजस्थान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सामूहिक प्रयास वाला बजट। प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के एहसास वाला बजट। एक ऐसा बजट जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास के तमाम आधार लिखेगा। एक बजट जिसमें प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ दिखेगा। एक बजट जिसमें जन समस्याओं के समाधान के मजबूत इरादे हैं। एक बजट जिसमें बांध, नहर एवं घर नल के जल तक मजबूत वादें हैं। एक बजट, जिसमें बिजली, सोलर, जीएसएस का निर्माण है। जिसमें सड़क बाइपास एक्सप्रेस हाईवे मार्ग बताए हैं।

Msk/rtm/20.02.25/1930/4d

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सड़कें ही नहीं, पूरे यातायात पर हमारा ध्यान है, इसलिए तो हमारी सरकार महान है। प्रदेश के चहुंमुखी विकास की घोषणा उसी का परिणाम है। यह बजट बेहतरीन बनायेगा, प्रदेश के हरेक बच्चे की शिक्षा, यह बजट बेहतरीन बनायेगा, प्रदेश के हरेक क्षेत्र की चिकित्सा। हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, सारे बेहतरीन उपाय, निश्चित रूप से निखेरेंगे, ग्रामीण तथा शहरी निकाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग धंधों को लगेंगे, नवीन पंख, प्रदेश में बजेगा, नवीन सूर्योदय का शंख। बजट में हमारी प्राचीन संस्कृति, धरोहर को संजाने और संवारने की बात थी। जी हां, बजट में किसान व कृषि उत्थान की बात थी। निश्चित रूप से प्रदेश पर्यावरण व संरक्षण के महा अभियान की बात थी। बजट में विकसित भारत के सुनहरे भविष्य की बात थी, खेल क्षेत्र के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की बात थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह बजट ही पेश नहीं कर रही थी, हमारी सरकार, हम तो बना रहे थे, स्वर्णिम प्रदेश के आधार। यकीन मानिये, बिल्कुल बेहतरीन परिणाम देखेंगे। हम सब एक सर्वश्रेष्ठ सशक्त राजस्थान देखेंगे, श्रेष्ठ राजस्थान देखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की देव तुल्य जनता ने कांग्रेस के जंगल राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाकर प्रदेश के बेहतरीन भविष्य के लिए सरकार चलाने का जनादेश दिया, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार 'सर्वजन हिताय' की भावना से संकल्पित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रदेश के नागरिकों को यह विश्वास दिलाता है कि हर वर्ग के उत्थान व उज्ज्वल भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास करेगी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उन्नत काम करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस सीमावर्ती विधान सभा क्षेत्र चौहटन से सदस्य चुनकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र के पवित्र सदन में प्रतिनिधि के रूप में आया हूं। इस सीमावर्ती क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तथा

देव तुल्य जनता को बजट की घोषणा 2025-26 में बहुआयामी उपहार देने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी, प्रदेश की उप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्य मंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जन-जन के कल्याणकारी और प्रदेश के उत्थान को समर्पित माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने 1 वर्ष के अपने संपूर्ण कार्यकाल में एक स्वर्णिम राजस्थान के आधारशिला की नींव रखी है। हमारी सरकार लोकलुभावन वादों, अंगूर खट्टे एवं मीठे जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती है, बल्कि मजबूत इरादों व धरातल पर विभिन्न कार्यों की सफल क्रियान्विति पर विश्वास करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण प्रदेश में कांग्रेस के कुशासन, संकीर्ण सोच व तुष्टिकरण की नीति से चारों ओर अंधकार के घोर काले बादल छा गए थे। चारों दिशाओं में कुशासन रूपी काली घटाओं का दृश्य था, परंतु जन-जन के कल्याणकारी उत्थान को समर्पित प्रदेश के चहुंमुखी विकास में तल्लीन हमारी भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार आमजन के ह्रदय में आशा रूपी मोती पिरोकर प्रदेश के सुनहरे भविष्य के सपने को साकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमारी सरकार की उज्ज्वल व स्पष्ट कार्य शैली से उगते हुए सूर्य की लालिमा की तरह दृष्टिगोचर है। इसमें कांग्रेस के कुशासन व भ्रष्टाचार के बादल फीके हुए हो चुके हैं, जिसका परिणाम संपूर्ण देशवासियों के सामने है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025- प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाना इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को चार पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा-

मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं,
इस पार कुछ, मगर उस पार बहुत कुछ हैं,
जिन शहरों में आपने खोली थीं, शीशे की दुकानें,
उन्हीं शहरों में पत्थर के खरीददार बहुत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस सीमावर्ती क्षेत्र से आता हूं। आज के दिन मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करुंगा, जिन्होंने राजस्थान ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, हमारे बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के अन्दर राजस्व गांव बने। प्रत्येक राजस्व गांव को जोड़ने के लिए उनकी सोच थी। 1990 के दशक के अंदर एक ऐसा वातावरण था, लोगों के अंदर एक ऐसी भावना थी कि वे अपने बालक और बालिकाओं को पढ़ना चाहते थे, गांव के अंदर वे सुविधाएं नहीं थीं और शहरों की तरफ लोगों का रुख हुआ करता था। खाता-पीता परिवार था, वह शहर की तरफ जाने को आतुर था। इसका कारण यह था कि शहरों के अंदर भी व्यवस्थाएं बनानी बहुत मुश्किल हो गई थीं। उस समय के अंदर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी कि गांव और दाणी तक यदि सड़क पहुंच जाएगी तो लोग शहरों की तरफ भगाना बंद कर देंगे। इसी को लेकर पश्चिमी राजस्थान में हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में सड़कों का जाल बिछा है, उसमें उनकी है सोच थी कि यदि गांव और ढाणी में सड़क पहुंचेगी तो सड़क के पास-पास में बिजली की लाइन

भी पहुंचेगी, पानी की लाइन भी पहुंचेगी, गांव और ढाणी में सब सुविधाएं हो जाएंगी तो लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आज हम जो देख रहे हैं, सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है, वह प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत है। नदियों को जोड़ने की सोच थी। हमारे ऐसे कई प्रदेश हैं, जिन प्रदेशों के अंदर जब बारिश होती है तो गांव के गांव नदियों के साथ बह जाते हैं। उनकी सोच थी कि यदि आपस में नदियां जुड़ जाएंगी तो जहां पानी है, राजस्थान क्षेत्र के अंदर पानी के नाम पर आंखों के अंदर पानी आता है। वहां तक भी आम आदमी को जल जीवन मिशन योजना के तहत...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना लागू करके आम ढाणी तक मीठा पानी पहुंचाने का काम किया और जिस तरह से जल जीवन मिशन का पानी गांव और ढाणी तक पहुंचा है, लोग खुशहाल हैं। उस जगह जहां पानी मिलता नहीं था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 2025-26 के बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि इसको आप स्टैंड के रूप में काम में मत लो, कागज उसी पर रखे हुए हैं। श्री सुरेश गुर्जर।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भजन लाल जी सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ है। माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने 120 पेज का बजट भाषण पढ़कर सुनाया। पूरे बजट में सरकार ने कांग्रेस के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा की है, ऐसा राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। सरकार ने जितनी भी बड़ी घोषणाएं कीं, वे सारी घोषणाएं सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में की हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने आपको बहुत उम्मीद से सत्ता की चाबी सौंपी थी, किंतु अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप प्रदेश के मुखिया की बजाय पार्टी के मुखिया की तरह भेदभाव कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बजट में थोथी घोषणाओं के साथ आंकड़ों की बौछार कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि यह बजट संकुचित सोच और भेदभाव की राजनीति का दस्तावेज है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह सरकार का दूसरा बजट है और दूसरे बजट में भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घोषणा नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मैं सड़कों और पुलियाओं की बात करूं तो सरकार ने सभी विधान सभा क्षेत्रों में 10 करोड़ के नॉनपेचेबल रोड दिए हैं और 5000 करोड़ की सड़कें आपने दी हैं।

mdp/20.02.2025/19:40/4e

परंतु 5 हजार करोड़ की सड़कों में मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक भी सड़क इस बजट में

नहीं दी है। जबकि मैंने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजे थे। लिम्बी से खड़ीकेडी रोड़, खड़ीकेड़ी से कांकरदा, भरतपुर से इस्लामपुरा, करणवास से अम्बाला और गागरोन से नोलाव और बरखेड़ा से बलाई रोड़ की मैंने मांग की थी। उच्च स्तरीय पुलियाओं की अगर मैं बात करूं तो खैरिया से पीपलिया नगा, उजाड़ नदी पर देवरिया से भराना के बीच की पुलिया, मरायता से मूंडला के बीच की पुलिया, मोहनपुर से खेलखड़ी के बीच की पुलिया, उजाड़ नदी पर भीमखेड़ा से कंवरपुरा के बीच की पुलिया, इन सभी उच्च स्तरीय पुलियाओं के निर्माण की आवश्यकता है। ये बरसात में कई दिनों तक रास्ते बंद हो जाते हैं। किंतु खानपुर विधान सभा में उच्च स्तरीय पुलिया बजट में नहीं दी, वहां के लोगों के साथ धोखा है।

चिकित्सा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं खानपुर विधान सभा क्षेत्र में दो मेगा हाइवे गुजरते हैं। बारां से झालावाड़ा और दूसरा धारा से आड़िया मेगा हाइवे। दुर्घटनाएं होने पर चिकित्सा सुविधाएं बारां या झालावाड़ में मिलती हैं, जो कि 40 किलोमीटर खानपुर से दूर है। ट्रोमा सेंटर और उप जिला चिकित्सालय की लम्बे समय से यहां के लोगों द्वारा मांग की जा रही है। यह भी घोषणा आपने इस बजट में नहीं की है। खानपुर विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर में प्रतिदिन 800 से 1000 की ओपीडी है, जबकि बकानी, रतलाई, परवाड़ और सारोला में 400 से 500 की ओपीडी है। वर्तमान में खानपुर में 50 बेड से 100 बेड बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बकानी, रटलाई, परवाड़ और सारोला में 30 बेड से 50 बेड करने की आवश्यकता है। सरकार से मेरी मांग है कि परिवर्तित बजट में इन सभी मांगों को आप पूरा करेंगे।

मैं नगरीय विकास की बात करूं तो खानपुर विधान सभा क्षेत्र, ऐसा विधान सभा क्षेत्र है, जहां पर एक भी नगर पालिका नहीं है। जबकि खानपुर ग्राम पंचायत और बकानी ग्राम पंचायत नगर पालिका बनने के पूरे मापदंड रखती है। खानपुर को नगर पालिका बनाने की मांग, बकानी को नगर पालिका बनाने की मांग वहां के सारे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन लम्बे समय से कर रहे हैं। फिर भी सरकार ने इस बजट में हमारी अनदेखी की है। सरकार से मांग है कि परिवर्तित बजट में आप खानपुर और बकानी को नगर पालिका बनाये।

अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बकानी में महाविद्यालय नहीं है। लम्बे समय से वहां के लोग महाविद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। झालावाड़, खानपुर विधान सभा क्षेत्र एक कृषि का क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा किसान कृषि पर आधारित है। खानपुर मुख्यालय पर एग्रीकल्चर कॉलेज की भी आवश्यकता है। वह खोला जाना चाहिए। सिंचाई व पेयजल की अगर मैं बात करूं सरकार ई.आर.सी.पी. का ढोल बजा रही है। आप 17 जिलों को पानी उपलब्ध कराएंगे। आपको पता है ये पानी कहां से बहकर आ रहा है? ये पानी हमारे झालावाड़ जिले में मेरी विधान सभा से गुजरने वाली परवन, कालीसिंध, आहूर और उजाड़ नदियों का पानी है। हमारे पानी से 17 जिलों की प्यास बुझेगी। किसानों को पानी मिलेगा, इस पर हमें गर्व है। सरकार ने इन 17 जिलों के लिए तो स्कीम बना दी, परंतु

खानपुर क्षेत्र के उन गांवों के लिए चिंता नहीं की, जिनमें जमीन डूब रही है। सिंचाई का पानी भी नहीं मिल रहा है। अतः सरकार से मेरी मांग है कि परवन सिंचाई परियोजना में आपने बजट में कुछ भी नहीं दिया। आपसे मेरी मांग है कि परवन सिंचाई परियोजना में छूटे हुए गांव ग्राम पंचायत करणवास, धारद, माननवास, धानोदा, बिशनगेड़ी और हारीगढ़ के लगभग 40 गांवों को सिंचाई परियोजना से जोड़ा जाए। राजस्थान की महत्वपूर्ण परवन सिंचाई परियोजना में बजट के अभाव में कई काम अटके पड़े हैं। जो गांव डूब क्षेत्र में आए, विस्थापित होने वाले किसानों मुआवजे के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कई गांवों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। राजकीय भूमि और चरागाह भूमि पर बसे हुए 537 मकानों के मुआवजे का प्रस्ताव भी सरकार के पास बजट के अभाव में लंबित पडा है। उन विस्थापितों को, कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक नहीं मिली है। आंशिक रूप से प्रभावित महुआखेड़ा, धोलाड़ा, अकावतकलां, अकावतखूंट, हानोती गांव को पूर्ण डूब घोषित करने की भी आपसे मैं मांग करता हूं।

मेरी विधान सभा क्षेत्र के बकानी ब्लॉक में ग्राम पंचायत आगरिया, कुशलखेड़ा, बरखेड़ा, घरवाड़ा में उपजाऊ भूमि नहीं है। कहीं खाल हैं, कहीं नालें हैं, पानी बहकर निकल जाता है। यहां खेती के अभाव में लोग पलायन कर जाते हैं। यहां पर छोटे-छोटे चैकडेम, एनिकट की मांग लम्बे समय से की जा रही है। मगर खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इसी प्रकार मंडावर बेल्ट में 8 ग्राम पंचायतें आती हैं, जहां पर लगभग 40 गांव होते हैं। एक तरफ भीमसागर डेम बना हुआ है, दूसरी तरफ कालीसिंध डेम बना हुआ है। यहां पर भी पानी की कमी है। पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध है। सरकार से मेरी मांग है कि लिफ्ट परियोजना के माध्यम से इन गांवों को जोड़ा जावे। आपने बजट में 20 लाख घरों को नये कनेक्शन देने की बात की है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले बजट में प्रत्येक विधान सभा में दस-दस हैंडपम्प आपने दिये थे और 5-5 ट्यूबवेल आपने दिये थे। राजनीतिक भेदभाव के चलते मेरी विधान सभा में आपने एक भी हैंडपम्प नहीं दिया। ये वहां की जनता के साथ और निर्वाचित जन-प्रतिनिधि के साथ अन्याय है। खानपुर में लम्बे समय से ए.सी.जे.एम. कोर्ट, ए.सी.जे. कोर्ट की मांग की जा रही है। बकानी में उपखण्ड कार्यालय और डी.एस.पी. कार्यालय की मांग की जा रही है। यह भी आपने इस बजट घोषणा में नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपको अवसर दिया है। आप राज्य के मुखिया हो। सभी जिलों का भेदभाव रहित होकर विकास करना चाहिए। राजस्थान की हर विधान सभा में न्यायपूर्वक विकास कार्य करवाना चाहिए। याद रखिए सरकारें आती हैं, जाती हैं, समय का चक्र घूमता है। आज आप सत्ता में हो, कल हम थे, कल हम आपकी जगह बैठेंगे, आप हमारी जगह बैठेंगे। समय का पहिया घूमता रहेगा। जब अवसर मिला तो हमने काम किया। आपको अवसर मिला है तो काम करिए।

पिछली सरकार को कोसने, बहाने बनाने, जवाबदेही या आरोप लगाने पर समय मत गवाइए। सरकार सुन ले, प्रदेश की 8 करोड़ जनता आपको देख रही है।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): सत्ता का नशा हमेशा नहीं चलता है। जनता का न्याय जरूर आता है। हम सदन में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे। खानपुर की मांगों की आपको घोषणा करनी पड़ेगी। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम साहब।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही दिनांक 21 तारीख को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 19:47 बजे शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

*****